राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 190

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 18 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

आइसीसी की वर्ल्ड इलेवन में शामिल हुईं भारत की मंधाना

>>14

सरोकार

बांस की तीलियों से खोल रहे संभावनाओं व समृद्धि के द्वार

जलपाईगुड़ी : बांस उत्पादन के मामले में देश दूसरे नंबर पर है, लेकिन बांस उत्पादों

के स्वदेशी बाजार पर चीन और वियतनाम का कब्जा है। भारत में बांस धीरे-धीरे ही सही, रोजगार के अवसर सृजित कर रहा है। अब नवोन्मेष, प्रोत्साहन और बेहतर बाजार की दरकार है। (पेज-11)

जागरण विशेष

-15 डिग्री तापमान में भी संवर रही केदारपुरी

रुद्रप्रयाग : केदारपुरी में तापमान -15 डिग्री तक जा पहुंचा है, किंतु केदारपुरी

को संवारने का कार्य रुका नहीं है। प्रयास है कि अप्रैल से शुरू होने वाले यात्रा सीजन की शुरुआत से पहले इसे पूर्ण कर दिखाया जाए। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

महाराष्ट्र विधानसभा में भिड़ गए शिवसेना-भाजपा विधायक

नागपुर : किसानों को सहायता दिए जाने के मुद्दे पर भाजपा और शिवसेना के विधायक मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में आपस में भिड़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि विधायकों ने और एक-दूसरे का कॉलर तक पकड़ लिया। वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों ने बीच-बचाव करके उन्हें अलग कराया। विधान परिषद में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ लिहाजा दोनों सदनों की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

उन्नाव कांड : कुलदीप सेंगर को अब 20 को सुनाई जाएगी सजा

नई दिल्ली : दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए विधायक कुलदीप सेंगर को सजा सुनाने के लिए तीस हजारी अदालत में मंगलवार को दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला 20 दिसंबर के लिए टाल दिया। उस दिन सेंगर के अधिवक्ता को उसके द्वारा 2017 के चुनाव में दायर किया गया संपत्ति का विवरण भी अदालत में दाखिल करना होगा।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

फास्टैग से 15 हजार करोड़ तक टोल संग्रह बढ़ने की उम्मीद

नई दिल्ली : फास्टैग की व्यवस्था वाहन चालकों को सुकून प्रदान करने के साथ-साथ टोल संग्रह बढ़ाने में भी सहायक साबित हो रही है। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो सभी टोल प्लाजा के फास्टैग अनुकूल होने तथा हाईवे पर चलने वाले सभी वाहनों में फास्टैग लगने से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के टोल संग्रह में सालाना 15 हजार करोड़ रुपये तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है।

कैरेबियाई चुनौती

दूसरा वनडे भारत vs वेस्टइंडीज

दोपहर 1:30 बजे से

स्थान : विशाखापत्तनम

प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

दिल्ली और बंगाल में उत्पात जारी

अराजकता ▶ नागरिकता कानून के विरोध में थानों में तोड़फोड़, रोकी गई ट्रेनें

जाफराबाद में पुलिस पर पथराव, 12 पुलिसकर्मी सहित 22 घायल

जेएनएन, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को लेकर दिल्ली और बंगाल में हिंसा थम नहीं रही है। मंगलवार को दिल्ली के जाफराबाद में प्रदर्शनकारियों ने दो बसों समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ की। कई मोटरसाइकिलों और एक मोबाइल शौचालय को फूंक दिया। उपद्रवी मौके पर लगे आठ सीसीटीवी कैमरे और एक एलईडी भी ले गए। घटना में 12 पुलिसकर्मियों समेत 22 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने पथराव करने के आरोप में पांच युवकों को हिरासत में लिया है। जामिया हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मुहम्मद खान सहित सात पर केस दर्ज किया है। वहीं, बंगाल में हावड़ा के मानिकपुर इलाके में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बम फेंके, जिसमें डीसीपी समेत तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। उपद्रवियों ने जगह-जगह ट्रेनें भी रोकी।

कांग्रेस नेता की थी रैली : कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद ने सीएए के खिलाफ मंगलवार को जाफराबाद में दिन में करीब 1:00 बजे रैली का आयोजन किया था। कुछ पुलिसकर्मी रैली की सुरक्षा में लगे हुए थे। करीब डेढ़ बजे जैसे ही प्रदर्शनकारी हटने लगे, कुछ उपद्रवियों ने पास में खड़ी एक क्लस्टर और एक निजी बस में तोड़फोड़ के साथ ही पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेजा गया, लेकिन तब तक भीड़ हिंसक हो चुकी थी। इसी बीच सीलमपुर पुलिस चौकी में घुसकर भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो वेलकम और जनता कॉलोनी में छतों से लोग पथराव करने लगे। रिजर्व पुलिस बल के मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ ही लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को काबू किया।

- बंगाल में पुलिस को निशाना बना कर फेंके गए बम, डीसीपी घायल
- जामिया ने केंद्र से नहीं की जांच की औपचारिक मांग
- जामिया मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक समेत सात पर केस दर्ज

दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पुलिस पर पथराव करती हिंसक भीड़। हरीश कुमार

सुप्रीम कोर्ट भी सख्त

- पुलिस कार्रवाई पर रोक नहीं : कहा, कोई पुलिस पर पत्थरबाजी करेगा तो क्या केस दर्ज नहीं होगा
- जांच कमेटी गठित करने से भी इन्कार : अलग-अलग जगह का मामला, एक जांच कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा
- संबंधित हाई कोर्ट में जाएं याचिकाकर्ता : सरकार और पक्षकारों को सुनकर हाई कोर्ट देंगे उचित आदेश

विस्तृत खबर पेज>>6

बंद रहे सात मेट्रो स्टेशन हिंसा के चलते दिल्ली मेट्रो ने वेलकम, जाफराबाद, मौजपुर-बाबरपुर, गोकुलपुरी, जौहरी एंक्लेव, शिव विहार व सीलमपुर स्टेशन के गेट बंद कर यात्रियों का आवागमन रोक दिया। यहां ट्रेने नहीं रुक रही थीं।

जामिया ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट जामिया विवि ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें हिंसा मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए औपचारिक मांग नहीं की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को निर्देश दिया है।

जामिया में हिंसा छात्रों ने नहीं, असामाजिक तत्वों ने फैलाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया हिंसा मामले में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक की जांच से पता चला है कि हिंसा में जामिया के छात्र शामिल नहीं थे। असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया था। गोलियां भी चलाईं। मौके से 7.62 बोर के खाली खोखे भी मिले हैं। उपद्रवियों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। प्रदर्शन में शामिल अधिकतर लोगों को यह मालूम नहीं था कि नागरिकता संशोधन कानून क्या है। स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने गवाही भी दी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जितने भी पुलिसकर्मी इलाके में तैनात थे उनमें किसी के पास हथियार नहीं थे, लेकिन, घटना के दौरान कई नेताओं व अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर पटना में हुए गोलीकांड की पुरानी वीडियो पोस्ट कर अफवाह फैलाई कि पुलिसकर्मियों ने गोलियां चलाई हैं। एक पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया गया कि उसने बस पर पेट्रोल उड़ेल आग लगाई। जबकि वह एक ठेली वाले से गैलन में पानी लेकर आग बुझाने आया था। जामिया विश्वविद्यालय के अंदर घुसकर छात्राओं की पिटाई करने की अफवाह फैलाई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता पूरी दिल्ली में दंगा कराने चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं।

सभी गिरफ्तार घोषित अपराधी : जामिया विश्वविद्यालय हिंसा मामले में गिरफ्तार दर्सों आरोपित घोषित अपराधी हैं। डीसीपी दक्षिणी-पूर्वी चिन्मय बिश्वाल ने बताया कि सभी के खिलाफ लूट, ऑर्म्स एक्ट, झगड़ा करने, सरकार कर्मचारी से मारपीट करने समेत अन्य संगीन धाराओं में अलग-अलग थानों में पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि सभी आरोपितों को 31 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

उप्र सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया सीएए के विरोध को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। मऊ, लखनऊ समेत अन्य जिलों में पुलिस ने अब तक 113 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। अलग-अलग जिलों में 18 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपितों को चिह्नित किया जा रहा है।

जितना चाहें कर लें नागरिकता संशोधन कानून का विरोध : शाह

नई दिल्ली : नागरिकता कानून के विरोध से अप्रभावित गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि विरोधी जितना चाहें कानून का विरोध कर सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैरमुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता हासिल हो और वे देश में सम्मान के साथ जी सकें। (पेज-5)

राष्ट्रपति से मिले विपक्ष के नेता कानून निरस्त करने की मांग

नई दिल्ली : सोनिया गांधी की अगुआई में 14 विपक्षी दलों ने मंगलवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मांग की कि वह सरकार से नागरिकता कानून को वापस लेने को कहें। (पेज-5)

सुबूत दें, बांग्लादेश वापस लेगा अपने नागरिक : गौहर रिजवी

कोलकाता : एनआरसी और सीएए के विरोध के बीच बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के सलाहकार गौहर रिजवी ने कहा है कि भारत सुबूत दे तो उनका देश गैरकानूनी तरीके से रह रहे अपने नागरिक वापस ले लेगा। (पेज-6)

हिम्मत है तो कांग्रेस पाकिस्तानियों को नागरिकता देने का एलान करे : मोदी

- सीएए, अनुच्छेद 370 और तीन तलाक कानून वापस लेने की भी पीएम ने चुनौती दी
- पीएम ने चेताया- युवाओं को बर्बाद करने का खेल बंद करें, गोरिल्ला राजनीति से बाज आएं

झारखंड के साहिबगंज जिले में मंगलवार को बरहेट में भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जागरण

राज्य ब्यूरो, साहिबगंज

नागरिकता संशोधन कानून पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को खुली चुनौती दी है। कहा- हिम्मत है तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल घोषणा करें कि वे पाकिस्तानी नागरिकों को यहां की नागरिकता देने को तैयार हैं। यह भी घोषणा करे कि वे सत्ता में आते ही नागरिकता संशोधन कानून, अनुच्छेद 370 और तत्काल तीन तलाक कानून को पलट देंगे।

मंगलवार को झारखंड के साहिबगंज के बरहेट में चुनावी सभा के दौरान पीएम ने कांग्रेस को चेताया कि वह देश के युवाओं से खेल खेलना बंद करे, झूठ बोलकर और भ्रम फैलाकर गोरिल्ला राजनीति से बाज आए। कहा कि यह कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति का ही नतीजा है कि आज देश में लाखों घुसपैठियों ने अपना घर बना लिया है। युवाओं, खासकर कॉलेज के छात्रों से भी पीएम ने आग्रह किया कि नागरिकता कानून के महत्व को समझें और इस पर विस्तार से चर्चा करें। विरोध हो तो लोकतांत्रिक तरीके से करें। लेकिन यह समझना होगा कि कहीं कुछ अर्बन नक्सली, कुछ दल या बुद्धिजीवी आपके कंधे पर बंदूक रखकर साजिश तो नहीं रच रहे। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बहुत सफाई से नागरिकता कानून पर बोलना बंद कर दिया है और अब परदे के पीछे से भ्रम फैला रही है। झामुमो, कांग्रेस, राजद व वामदलों को मोदी से नफरत है और इस चक्कर में वह देश को देख ही नहीं पाते हैं।

कोर्ट में जज के सामने हत्यारोपित की गोली मारकर हत्या

जागरण संवाददाता, बिजनौर

- उप्र के बिजनौर जिले में हुई दुस्साहसिक घटना, कोर्ट मोहर्रिर और दिल्ली पुलिस का सिपाही घायल
- तिहाड़ जेल से पेशी पर लाया गया था मारा गया बदमाश

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सीजेएम कोर्ट में जज के सामने ही तीन हमलावरों ने मंगलवार दोपहर हत्यारोपित शाहनवाज को गोलियों से भून डाला। इस दौरान कोर्ट मोहर्रिर और दिल्ली पुलिस का एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया। भरी अदालत में इस दुस्साहसिक वारदात को बसपा नेता हाजी एहसान के बेटे साहिल ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अंजाम दिया। तीनों हमलावरों को कोर्ट में ही पकड़ लिया गया। शाहनवाज के साथ तिहाड़ जेल से पेशी पर लाया गया उसका साथी जब्बार इस खूनखराबे के बीच कोर्ट से फरार हो गया।

बसपा के विधानसभा क्षेत्र प्रभारी व प्रॉपर्टी डीलर हाजी मोहम्मद एहसान और उनके भांजे शादाब की 28 मई को नजीबाबाद स्थित उनके कार्यालय में दिनदहाड़े गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड का आरोप कनकपुर निवासी शातिर अपराधी शाहनवाज अंसारी, जब्बार, दानिश व उब्बनवाल निवासी दानिश पर लगा था। शाहनवाज और जब्बार की मंगलवार को इस हत्याकांड में कोर्ट में पेशी थी। दिल्ली पुलिस के एसआइ हेतराम सिंह पांच सिपाहियों के साथ तिहाड़ जेल से शाहनवाज और जब्बार को पेशी पर बिजनौर लेकर आए थे। पुलिस ने दोपहर करीब पौने दो बजे दोनों बदमाशों को जज के सामने पेश किया। सीजेएम योगेश कुमार सुनवाई कर रहे थे, इसी बीच तीन हमलावर कोर्ट के अंदर घुसे और शाहनवाज पर पिस्टल से गोलियां बरसा दीं। शाहनवाज वहीं गिर गया लेकिन हमलावर गोलियां बरसाते रहे। कोर्ट मोहर्रिर मनीष और दिल्ली पुलिस के जवान संजीव भी गोली लगने से घायल हो गए।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मंगलवार को कोर्ट में जज के सामने हत्या करने के आरोपित (गले में लाल स्कार्फ) को बाहर ले जाते पुलिस अधिकारी। जागरण

गोली चलते ही भागने लगे लोग पेज>>7

देशद्रोह में मुशर्रफ को सजा-ए-मौत

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान की विशेष अदालत ने देशद्रोह मामले में पूर्व सैन्य शासक और कारगिल युद्ध की साजिश रचने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ को मंगलवार को सजा-ए-मौत सुनाई। वह मृत्युदंड पाने वाले पाक के पहले पूर्व सैन्य शासक हैं। तीन सदस्यीय पीठ ने पूर्व राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में दो-एक से फैसले का एलान किया। मुशर्रफ की पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कहा कि वह फैसले को चुनौती देगी।

2007 में पाकिस्तान पर आपातकाल थोपने और जजों को हिरासत में रखने के आरोप में मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में घिरते देख इलाज के बहाने मुशर्रफ 18 मार्च, 2016 को दुबई चले गए थे। तब से वह अपने मुल्क नहीं लौटे।

पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता वाली विशेष अदालत ने 76 वर्षीय पूर्व सेना प्रमुख मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित इस विशेष अदालत ने अभी अपना विस्तृत फैसला नहीं सुनाया है। विस्तृत फैसले का एलान आगामी 48 घंटों में किया जाएगा। इस अदालत ने गत 19 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ में जस्टिस सेठ के अलावा सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नजर अकबर और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम भी शामिल किए गए थे।

- पाकिस्तान में मृत्युदंड पाने वाले पहले पूर्व सैन्य शासक
- पूर्व राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में विशेष कोर्ट ने 2-1 से सुनाई सजा
- 2007 में आपातकाल लगाने और जजों को बंदी बनाने का मामला

परवेज मुशर्रफ की फाइल फोटो। प्रेट्र

आगे क्या है रास्ता

मुशर्रफ फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर सर्वोच्च अदालत विशेष कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है तो वह राष्ट्रपति से गुहार लगा सकते हैं। संविधान के तहत राष्ट्रपति को मौत की सजा पाए व्यक्ति को माफी देने का अधिकार है।

फैसले से पैदा हो सकता है टकराव पेज>>13

जस्टिस करीम बोले, नेक नहीं है सरकार का इरादा

फैसले वाले दिन सरकारी वकील की ओर से नई अर्जी दाखिल किए जाने पर जस्टिस करीम ने कहा, 'लंबी सुनवाई के बाद इस तरह की अर्जी दाखिल करने से जाहिर होता है कि सरकार का इरादा नेक नहीं है।'

सेना ने कहा, परवेज मुशर्रफ नहीं हो सकते गद्दार

विशेष अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान की सेना ने कहा कि पूर्व जनरल गद्दार नहीं हो सकते। सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, '40 साल से ज्यादा मुल्क की सेवा करने और कई युद्ध लड़ने वाले पूर्व सेना प्रमुख यकीनन गद्दार नहीं हो सकते।'

इस मामले में 28 नवंबर को आना था फैसला

विशेष अदालत ने अपना फैसला 28 नवंबर को सुनाने का एलान किया था। इसके बाद इमरान सरकार और परवेज मुशर्रफ के वकील फैसलों पर रोक लगाने की मांग को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए थे। इसके बाद अदालत ने देशद्रोह मामले में फैसले के लिए 17 दिसंबर की तारीख तय की थी।

एनबीसीसी करेगी जेपी इंफ्राटेक की अधूरी परियोजनाओं का निर्माण

जागरण संवाददाता, नोएडा : संकटग्रस्त जेपी इंफ्राटेक की अधूरी परियोजनाओं का निर्माण सरकारी कंपनी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) करेगी। हफ्तेभर चली वोटिंग में एनबीसीसी की बोली के पक्ष में 97.36 फीसद वोट पड़े। सुरक्षा रियल्टी की बोली बहुत पीछे रह गई। मंगलवार शाम आइआरपी ने इसकी औपचारिक घोषणा की।

जेपी इन्फ्राटेक के लिए खरीदार खोजने की प्रक्रिया में यह तीसरे दौर की बोली थी। दोनों में से किसी भी एक योजना की मंजूरी के लिए 66 फीसद वोटों की जरूरत थी। इसमें 11,699 होम बायर्स ने एनबीसीसी के पक्ष में वोट किया। 448 ने सुरक्षा रियल्टी के पक्ष में वोट किया। एनबीसीसी अब जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण कर प्रोजेक्ट का काम शुरू करेगी।

एनबीसीसी की पेशकश का सकल मूल्य 5,802 करोड़ रुपये था, जबकि सुरक्षा रियल्टी का 6,440 करोड़ रुपये। आरबीएस की ओर से प्रदान किए गए मूल्यांकन मैट्रिक्स के आधार पर बोलियों का विश्लेषण किया गया, जिसमें सुरक्षा ने 100 में से 29.143 स्कोर किया। दूसरी ओर एनबीसीसी को 26.41 का स्कोर मिला। 10 दिसंबर से शुरू हुआ मतदान 16 दिसंबर की आधी रात तक चला। होम बायर्स का पूरा धड़ा एनबीसीसी के पक्ष में शुरू से ही था, लेकिन वोटिंग शुरू होने के छह दिन तक बैंकों की ओर से वोटिंग नहीं करने पर संदेह होने लगा था। बहरहाल अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जेएंडके और एक्सिस बैंक ने सुरक्षा के पक्ष में वोटिंग की। इसके अलावा आइडीबीआइ, एलआइसी व आइएफसीआइ ने सुरक्षा को नकार दिया। वहीं, एनबीसीसी और आइएफसीआइ ने एनबीसीसी के पक्ष में वोट किया। आइसीआइसीआइ और श्रेई ने एनबसीसी के पक्ष में वोटिंग नहीं की। एनसीएलटी को 21 दिसंबर तक दोनों बिडर में किसी एक के नाम की औपचारिक घोषणा करनी थी। वोटिंग के आधार पर देर शाम को एनबीसीसी के नाम की घोषणा की गई। होम बायर्स को उम्मीद है कि कागजी कार्य पूरा होने के बाद एनबीसीसी जल्द ही अधूरी निर्माण साइटों पर कार्य शुरू करेगी।

पीड़ा का अंत

पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदुओं को नए कानून ने दिया खुशी का पहला मौका, असम में आधी सदी से भी ज्यादा समय से विभाजन और विस्थापन की पीड़ा का आईना है शरणार्थी कैंप

शरणार्थियों के अस्तित्व का पहला सूर्योदय है नागरिकता का कानून

संजय मिश्र, बोको (असम)

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक ओर जहां विरोध-प्रदर्शन जारी है, दूसरी ओर लाखों ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यह कानून देवदूत से कम नजर नहीं आ रहा। शरणार्थी बस्ती में दयनीय हालत में डर के साये में जी रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों की यह आबादी इस नए कानून में अपनी नागरिकता का सूर्योदय मान रही है।

आधी सदी से भी ज्यादा समय से विभाजन और विस्थापन की पीड़ादायक विरासत के साथ रोजाना शरणार्थी जीवन की संघर्षपूर्ण चुनौती से रूबरू होने वाले इन लोगों के लिए नागरिकता कानून उनकी जिंदगी में खुशी का सबसे बड़ा मौका है। वहीं इस पर विरोध प्रदर्शनों की हर खबर इन लोगों और इनके परिवारजनों को सहमा रही है। छय गांव के निकट बामुनिया गांव के चौधरीपारा हिंदू शरणार्थी कैंप में तमाम लोगों की निगाहें टेलीविजन पर नागरिकता कानून के विरोध-प्रदर्शनों और उससे जुड़ी खबरों की ओर ही लगी हैं। इस कैंप में रह रहे 110 परिवारों के अधिकांश सदस्यों का नाम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) में शामिल नहीं हुआ है। इस कैंप में 1964 और 1968 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू परिवार हैं। नए कानून के मुताबिक दिसंबर 2014 तक आए सभी गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। नागरिकता कानून इन सबको भारतीय पहचान देगी, फिर कैंप में खुशी की जगह खामोशी क्यों है? 60 वर्षीय श्यामपद चक्रवर्ती दरवाजे पर इकट्ठे तमाम लोग पहले तो इस सवाल को टाल देते हैं, फिर भरोसा दिलाने पर कहते हैं, 'नागरिकता कानून से बड़ी खुशी हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन असम के स्थानीय लोगों के साथ उनके दशकों पूर्व सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं और उन्होंने हमें आश्रय दिया है। आज वह इस कानून को लेकर दुखी हैं, तो हमारा खुशी का इजहार करना उचित नहीं है।'

कैंप में तमाम दूसरे लोगों ने भी ऐसी ही राय जाहिर की। साथ ही इसको लेकर वह सशंकित दिखे कि विरोध प्रदर्शनों के चलते अगर कानून में कोई बदलाव हुआ तो फिर उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। वह सब भारत के अलावा भला कहां जाएंगे। श्यामपद पांच साल की उम्र में अपनी मां और भाई-बहनों के साथ पूर्वी पाकिस्तान के तिलहट से यहां आए थे। अभी उनके परिवार में छह सदस्य हैं, लेकिन उनकी पत्नी बसंती के अलावा किसी का नाम एनआरसी में नहीं है। उत्तम कुमार देव भी तिलहट से बचपन में विस्थापित होकर आए। उनके पिता तो रास्ते में ही गुजर गए। मां ने उन्हें बड़ी मुश्किल से यहां लाकर पाला-पोसा। वे कहते हैं कि यहां आए सभी परिवारों की एक पीढ़ी खत्म हो रही है और हम भी जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। यदि किसी कारण से नागरिकता नहीं मिली, तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। यह सोच कर हर व्यक्ति की रूह कांप उठती है।

शरणार्थी जीवन में मुश्किलों का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के मेमन सिंह जिले से आई 56 साल की धाकेश्वरी वर्मन कहती हैं कि बचपन से आज तक संघर्ष और पीड़ा के अलावा हम सबने कुछ जिया ही नहीं। खुशियों का हमसे जैसे छत्तीस का रिश्ता हो। देर से ही सही नागरिकता कानून में खुशी का यह पहला मौका दिया है। अविवाहित वर्मन छह महीने की थीं, तो उनकी मां उन्हें भारत लेकर आई थीं। अब वे अकेले बची हैं और उनका नाम भी एनआरसी में नहीं है। विवाह नहीं करने के सवाल पर वह कहती हैं कि पूरा जीवन दो जून की रोटी के संघर्ष में ही बीत गया और पिता थे नहीं, ऐसे में उनकी शादी भला कौन करना। मेहनत मजदूरी कर जीवन बसर करने वाली बर्मन यह सवाल भी दागती हैं कि बताइए अब भारत और इस कैंप के अलावा उनका दूसरा जहां कहां होगा। 65 साल के निमाइल हजम और 70 साल के जाघव दाल समेत कैंप में चक्रवर्ती के घर के सामने जुटे दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने कहा कि शरणार्थी परिवारों की हालत बेहद खराब है। एक दिन कोई हजीरा (दिहाड़ी) न करे, तो खाना नहीं मिलेगा। जिंदगी में संघर्ष से हर पल रूबरू होने वाले हिंदू शरणार्थियों की दस्तान जाहिर करती है कि नागरिकता कानून का सही मायने में ऐसे शरणार्थी कैंपों में रहने वाले लोगों के लिए उनके मानवीय अस्तित्व का पहला वास्तविक सूर्योदय है।

बामुनिया गांव के चौधरीपारा कैंप में रह रहे 110 परिवारों के अधिकांश सदस्यों का नाम एनआरसी में नहीं

बामुनिया गांव के चौधरीपारा हिंदू शरणार्थी कैंप में रह रह लोगों के चेहरे पर नागरिकता संशोधन कानून बनने की खुशी अब साफ दिखती है। जागरण

5 फरवरी से शुरू होगा ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट। पहले दो दिन केवल मीडियापास धारकों को प्रवेश मिलेगा। इस दौरान नई गाड़ियों की लांचिंग होगी। सात से 12 फरवरी तक लोग अपनी पंसदीदा कारों के दीदार कर सकेंगे।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 18 दिसंबर 2019

न्यूज गैलरी

सीबीएसई की 15 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी। परीक्षाएं 15 फरवरी, 2020 से शुरू हो रही हैं। 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो रही हैं। वहीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा 20 मार्च, 2020 को खत्म होगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 30 मार्च, 2020 को खत्म होगी। 10वीं बोर्ड की कुल 77 विषयों एवं 12वीं बोर्ड की कुल 116 विषयों की परीक्षाएं होंगी। इनमें कौशल आधारित समेत भाषाओं व प्रमुख विषय भी शामिल हैं। बोर्ड ने छात्रों को परीक्षा के दिन सुबह 10 बजे से पहले परीक्षा केंद्रों में आने की हिदायत दी है। सुबह 10 से 10.15 बजे के दौरान उत्तर पुस्तिकाएं छात्रों को दी जाएंगी। इसके बाद 10.15 बजे प्रश्नपत्र दिया जाएगा। 10.30 बजे से छात्रों को परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने की अनुमति होगी। (जासं)

अस्पतालों में ठीक से नहीं हो रहा जैविक कचरे का प्रबंधन

नई दिल्ली : राजधानी के अस्पतालों में जैविक कचरे का निस्तारण ठीक से नहीं हो रहा है। गैर सरकारी संस्था टॉक्सिक लिंक द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट मंगलवार को विशेषज्ञों की बैठक में रखी गई। इस बैठक में जिलों की निगरानी समिति, अस्पतालों, मेडिकल काउंसिल के सदस्यों व संबंधित संस्थाओं के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सर्वे में कहा गया है कि अस्पताल अब भी निगम के कूड़े के साथ जैविक कचरा डाल रहे हैं। इससे संक्रमण होने का खतरा है। संस्था के मुख्य प्रोग्राम संयोजक प्रीति महेश ने अस्पतालों में जैविक कचरा प्रबंधन की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी 11 जिलों के 38 अस्पतालों में यह सर्वे किया गया। इनमें 25 निजी व 13 सरकारी अस्पताल शामिल थे। सर्वे में पाया गया कि सिरिंज व निडिल का निस्तारण भी ठीक से नहीं हो रहा है। 27.85 फीसद अस्पतालों में निडिल कटर नहीं है। डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के अनुसार हेपेटाइटिस बी से पीड़ित 37.6 फीसद, हेपेटाइटिस सी से पीड़ित 39 फीसद व एचआइवी से पीड़ित 4.4 फीसद स्वास्थ्य कर्मियों को निडिल से इंजरी के कारण संक्रमण होता है। (जासं)

विस अध्यक्ष की सजा का आदेश निलंबित

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू की विशेष सत्र अदालत ने विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल की अपील पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत से मिली छह माह की सजा को निलंबित कर दिया है। हालांकि अपील में सजा को निलंबित करने की दलील पर राज्य से जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई आठ जनवरी के लिए तय की है। निचली अदालत ने एक बिल्डर के घर में जबरदस्ती घुसने के लिए रामनिवास गोयल को दोषी करार देते हुए छह माह की सजा दी थी। अन्य आरोपितों को मारपीट करने के लिए सजा दी गई थी। यह मामला छह फरवरी 2015 का है। (जासं)

चुनावी जंग से पहले मैदान में दिखेंगे कांग्रेस के लड़ाके

तैयारी ▶ उम्मीदवारों की सूची तीन चरणों में जारी करेगी पार्टी

पहली सूची जनवरी की शुरुआत में घोषित किए जाने की संभावना

उम्मीदवारों के नामों पर विचार शुरू हो गया है। पहली सूची अगले 15 से 20 दिनों में घोषित की जा सकती है। टिकट इस बार उन्हीं दावेदारों को दिए जाएंगे जो इसके काबिल होंगे। भले वे नाम नए क्यों न हों। पहली सूची के बाद दूसरी और तीसरी सूची भी अगले कुछ ही दिनों में आ जाएगी।
–सुभाष चोपड़ा, अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव की जंग में इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार काफी पहले से मैदान में नजर आएंगे। नई परंपरा की शुरुआत करते हुए पहली बार पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची तीन चरणों में जारी करने की योजना बना रही है। पहली सूची जनवरी के पहले हफ्ते में घोषित कर दिए जाने की संभावना है।

गौरतलब है कि आमतौर पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची नामांकन शुरू हो जाने के बाद ही जारी की जाती रही है। इससे उम्मीदवारों को अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से जनसंपर्क बनाने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं मिल पाता। इसीलिए अगले वर्ष फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी पूर्ववर्ती स्थिति में सुधार की दिशा में काम कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) ने भी इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस को अपनी सहमति दे दी है। सप्ताह भर में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित कर दी जाएगी। इसके बाद अगले 15 दिन के भीतर 20 से 25 उम्मीदवारों की सूची स्वीकृति के लिए एआइसीसी को भेज दी जाएगी। वहां से स्वीकृति मिलते ही सूची के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार अगले 10-10 दिन के अंतराल पर कमोबेश इतने ही नामों की दो अन्य सूचियां भी जारी कर दी जाएंगी। चुनाव भले ही फरवरी के दूसरे सप्ताह में होने के आसार हैं, लेकिन पार्टी की कोशिश जनवरी महीने में ही सभी 70 उम्मीदवारों के नाम घोषित देने की है। :::

नेताओं के बच्चों को भी मिलेगा टिकट : पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार उन्हीं चेहरों पर दांव लगाया जाएगा जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र में पहले से मेहनत कर रहे हैं। जिनकी वहां अच्छी साख है और वहां वे जीतने की संभावना भी रखते हैं। इनमें कुछ उम्मीदवार फ्रंटल संगठनों जैसे सेवादल, महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस से भी लिए जाएंगे। इनके अलावा नेताओं के बच्चों को भी टिकट वितरण में तरजीह दी जाएगी।

मसलन, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र कालकाजी से बेटी शिवानी चोपड़ा को चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं। पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल चांदनी चौक से बेटे मुदित अग्रवाल को लड़वाना चाहते हैं। पूर्व सांसद महाबल मिश्रा भी द्वारका से बेटे विनय मिश्रा को मैदान में उतारना चाहते हैं।

अनशन टूटा लेकिन हौसले बुलंद हैं : स्वाति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद को मंगलवार को लोक नायक अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इसके बाद स्वाति जयहिंद ने ट्वीट कर कहा कि उनका शरीर अभी कमजोर है, लेकिन बेहतर महसूस कर रही हैं। उन्होंने लिखा कि अनशन तो खत्म हो गया, लेकिन हौसले बुलंद हैं। देश में दुष्कर्म के खिलाफ एक सख्त कानून बनवा के ही मानूंगी।

दुष्कर्म के आरोपितों को जल्द सजा दिलवाने के चलते राजघाट स्थित समता स्थल पर स्वाति ने तीन दिसंबर को अनशन शुरू किया था। लेकिन रविवार सुबह उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां तीन दिन तक चले उपचार के बाद मंगलवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई। इससे पहले उन्होंने सोमवार को निर्भया की 7वीं बरसी पर देशवासियों को पत्र लिखा था। इसमें कहा कि खौफनाक रात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अलग-अलग जगहों पर युवतियां उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं।

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जयहिंद ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों के साथ हुई कथित बर्बरता की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि विरोध हमेशा शांतिपूर्वक होना चाहिए। दिल्ली के छात्रों के साथ लाइब्रेरी तक में घुस कर पुलिस द्वारा बर्बरता से मारपीट करना दुखद है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। आशा करती हूं कि जल्द ही शांति का माहौल स्थापित होगा।

रेड और ब्लू लाइन की मेट्रो की बदलेगी रंगत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ 70 मेट्रो के 280 कोचों का किया जाएगा नवीनीकरण

▶ योजना पर करीब 71 करोड़ रुपये खर्च होंगे

पुरानी मेट्रो ट्रेनें रंगत खोती जा रही हैं। कई मेट्रो में एसी से पानी टपकने की समस्या है, तो कुछ का फर्श खराब होने लगा है। इसके मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने पुरानी मेट्रो के नवीनीकरण की तैयारी की है। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत 70 मेट्रो के 280 कोचों का नवीनीकरण किया जाएगा। इस योजना पर 71 करोड़ खर्च होगा। नवीनीकरण के बाद पुरानी मेट्रो ट्रेनें भी नई नवेली व अत्याधुनिक दिखेंगी। साथ ही मेट्रो में तकनीकी समस्या भी काफी हद तक कम होगी।

डीएमआरसी के अनुसार वर्ष 2002 में रोलिंग स्टॉक-1 के अनुबंध के तहत 280 कोच के साथ 70 मेट्रो खरीदी गई थीं। ये मेट्रो चार कोच की थीं। इनके उपयोग की अवधि 30 साल है, जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हो चुकी हैं। ये मेट्रो ट्रेनें मुख्य रूप से रेड लाइन (रिठाला-दिलशाद गार्डन- नया बस अड्डा गाजियाबाद) व ब्लू लाइन (द्वारका सेक्टर 21-नोएडा/वैशाली) पर रफ्तार भर रही हैं। इनके कोच में कई तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं। आने वाले दिनों में इनमें तकनीकी खराबी की समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए डीएमआरसी ने इन मेट्रो ट्रेनों के कोचों का नवीनीकरण कराने का फैसला किया है। इसके तहत सभी 280 कोच में नए सिरे से पेंटिंग की जाएगी। मेट्रो के 40 कोच में फर्श को ठीक किए जाने की जरूरत है। इसलिए उन कोच के फर्श की मरम्मत की जाएगी या कई कोच के फर्श के ढांचे को पूरा बदला जाएगा। यह कार्य इन मेट्रो ट्रेनों का निर्माण करने वाली मूल कंपनी की मदद से होगा। इसके अलावा सभी 70 मेट्रो के गैंगवे (दो कोचों के बीच का हिस्सा, जहां कोच जुड़े होते हैं) पुराने पड़ चुके हैं और गंदा दिखते है। इन मेट्रो में ऐसे गैंगवे की संख्या 420 है, जिन्हें बदलकर नया लगाया जाएगा। इसके अलावा इनमें 1120 सेकेंडरी सस्पेंशन नामक उपकरणों को भी बदला जाएगा। इससे मेट्रो में आने वाली तकनीकी खराबी की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी।

डीएमआरसी का कहना है कि नवीनीकरण का यह कार्य दो साल में पूरा होगा। दरअसल, रेड लाइन का नेटवर्क बढ़कर गाजियाबाद नया बस अड्डा तक हो गया है। वहीं ब्लू लाइन का नेटवर्क भी नोएडा सिटी सेंटर से बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक पहुंच चुका है। इसलिए मेट्रो में यात्रियों के दबाव के मद्देनजर ट्रेनों की जरूरतों को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से नवीनीकरण का काम होगा।

जंक फूड लगा रहे सेहत को जंग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ सीएसई ने नामी कंपनियों के 33 ब्रांडों के जंक फूड के नमूनों की जांच की

भागती दौड़ती जिंदगी और महानगरीय जीवन शैली में जंक फूड आज की पीढ़ी का पसंदीदा भोजन है। लेकिन जंक फूड सेहत को भी तेजी से जंग लगा रहा है। आलम यह है कि इस जंक फूड के खतरों से अनभिज्ञ युवा जानलेवा बीमारियों की गिरफ्त में जाते जा रहे हैं।

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) ने हाल ही में नामी कंपनियों के 33 ब्रांडों के जंक फूड के नमूनों की जांच की। डिब्बाबंद खाद्य सामग्री की श्रेणी में चिप्स के छह, नमकीन के चार, इंस्टेंट नूडल्स के तीन और सूप के तीन ब्रांडों के उत्पादों की जांच की गई। फास्ट फूड श्रेणी में बर्गर के आठ, फ्राइज के तीन, फ्राईड चिकन के एक, पिज्जा के चार और सैंडविच एवं रैप के तीन ब्रांड की जांच की गई। इन सभी में नमक, शर्करा, वसा और ट्रांस वसा की मात्रा स्वीकृत सीमा से अधिक पाई गई।

सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने मंगलवार को इंडिया हेबीटेट सेंटर स्थित अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि इन तरह के खाद्य पदार्थों के चलते हृदय रोग, मधुमेह और मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए ऐसे खाद्य पदार्थों के पैकेट पर चेतावनी वाला निशान लगाया जाना चाहिए। तंबाकू उत्पादों की तरह ही सेहत पर भारी पड़ने वाले खाद्य उत्पादों पर खतरे का निशान भी लगाया जाना चाहिए ताकि इसे खाने वाले लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। उन्होंने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) से खाद्य सुरक्षा नियमों को भी जल्द अधिसूचित किए जाने की मांग की।

सीएसई की फूड सेफ्टी और टॉक्सिन टीम के कार्यक्रम निदेशक अमित खुराना ने बताया कि सेहत पर खतरे को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि चिप्स के एक लोकप्रिय ब्रांड जिसका वजन 30 ग्राम है। उसमें नमक की मात्रा एक ग्राम है। जबकि एफएसएसएआइ द्वारा प्रस्तावित मानकों के अनुसार 100 ग्राम चिप्स में केवल 0.25 ग्राम नमक होना चाहिए।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि डिब्बाबंद खाद्य सामग्री और फास्ट फूड को नियमित करने की कोशिश 2013 से चल रही थी। एक समिति का गठन भी किया गया था जिसने खाद्य सामग्री के पैकेट पर लिखी जाने वाली जानकारी के बारे में अपनी सिफारिश की थी। अलग-अलग समितियों की रिपोर्ट के बाद एफएसएसएआइ ने इसी वर्ष नियमों का ड्राफ्ट जारी किया था। लेकिन, इसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

ईवीएम आरटीआइ के अधीन नहीं : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के अधीन बताने वाले केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दिया। सीआइसी के आदेश को चुनौती देने वाली निर्वाचन आयोग की याचिका पर न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने यह फैसला दिया। सीआइसी ने 12 फरवरी को कहा था कि निर्वाचन आयोग के पास मौजूद ईवीएम एक सामग्री है और यह आरटीआइ के तहत सूचना है। सीआइसी ने एक शिकायतकर्ता के आवेदन पर उक्त आदेश दिया था।

निर्वाचन आयोग की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि ईवीएम आरटीआइ के तहत नहीं आती। आरटीआइ के तहत सिर्फ दस्तावेज आते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा रखरखाव किए जाने वाले ईवीएम को कानून के तहत चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी निर्वाचन आयोग कुछ ईवीएम का रखरखाव करता है। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत ईवीएम को सुरक्षित रखा जाता है। सीआइसी ने राजस्थान निवासी रजाक के हैदर द्वारा किए गए आवेदन कर ईवीएम के संबंध में जानकारी मांगी थी।

भाजयुमो ने मोदी की रैली में आने का किया आह्वान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

रामलीला मैदान में 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में मोटरसाइकिल रैली निकाली। उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को उनके मकान व भूखंड का मालिकाना हक देने के फैसले के बारे में जानकारी दी और लोगों से प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए रामलीला मैदान पहुंचने का आह्वान किया।

भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव की अध्यक्षता में निकाली गई मोटरसाइकिल रैली में दिल्ली प्रदेश भाजपा प्रभारी श्याम जाजू, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी सहित अन्य नेता शामिल हुए। जाजू ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे 40 लाख लोगों को हमेशा अपना आशियाना उजड़ने की चिंता सताती रहती थी। मोदी ने उनका यह डर खत्म कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना रोककर यहां के गरीबों को आवास से वंचित रख रही है। मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार समाज के अंतिम वर्ग तक विकास की योजना पहुंचाने के लिए काम कर रही है। केजरीवाल सरकार दिल्ली के गरीबों को आशियाना से वंचित रखना चाहती है।

रामलीला मैदान में होने वाली भाजपा की रैली के लिए रामलीला मैदान में भूमिपूजन करते (बाएं से) दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, हवन पूजन कराते पंडित जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिल्ली भाजपा प्रभारी श्याम जाजू, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, विजय गोयल, केन्द्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन। जागरण

प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि केंद्र में दूसरी बार सरकार बनने के 100 दिनों के अंदर ही प्रधानमंत्री ने अपना वादा पूरा कर दिया। महामंत्री रविंद्र गुप्ता ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के मुद्दे पर पहले की सरकारें केवल घोषणाएं करती रही हैं। महामंत्री राजेश भाटिया ने कहा कि कांग्रेस व आप इस मुद्दे पर वर्षों से राजनीति करती रही हैं। भाजपा ने लाखों लोगों के साथ न्याय किया है।

रामलीला मैदान में भूमि पूजन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए 22 दिसंबर को रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रैली की तैयारी के लिए भाजपा नेताओं ने मंगलवार को रामलीला मैदान में भूमि पूजन किया। प्रदेश भाजपा प्रभारी श्याम जाजू, अध्यक्ष मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, राज्यसभा सदस्य विजय गोयल, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन आदि नेताओं ने हवन किया।

ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी जेवर एयरपोर्ट के लिए बनाएगी एसपीवी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए विकासकर्ता कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी कंपनी) बनाएगी। यह कंपनी जेवर एयरपोर्ट का निर्माण एवं संचालन करेगी। कंपनी का गठन होने के बाद उसे सिक्योरिटी क्लीयरेंस सुरक्षा जांच के लिए आवेदन करना होगा। जांच पूरी होने के बाद एसपीवी व नियाल के बीच जेवर एयरपोर्ट का कंसेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षर होगा।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को विकासकर्ता कंपनी के तौर पर चयनित किया गया है। नियाल के चेयरमैन एवं प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी के सीईओ डैनियल बर्चर को कंडीशनल लेटर ऑफ अवार्ड सौंपा है। स्विस कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी जेवर एयरपोर्ट के निर्माण एवं संचालन के लिए एसपीवी का गठन करेगी। कंपनी में क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से एसपीवी के गठन की कार्रवाई जनवरी में होगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंपनी के अधिकारी सिक्योरिटी क्लीयरेंस के लिए आवेदन करेंगे। गृह मंत्रालय विकासकर्ता कंपनी की जांच कराएगा। मंत्रालय से क्लीन चिट मिलने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी (नियाल) व एसपीवी के बीच जेवर एयरपोर्ट के निर्माण एवं संचालन को लेकर कंसेशन एग्रीमेंट होगा। औपचारिकता पूरी होने के बाद जेवर एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो जाएगा।

जेवर एयरपोर्ट से 2023-24 से व्यावसायिक उड़ान शुरू करने का लक्ष्य है। हवाई सेवाओं की शुरुआत दो रनवे के साथ होगी। सालाना एक करोड़ बीस लाख यात्री जेवर एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं का उपयोग करेंगे। प्रदेश सरकार को जेवर एयरपोर्ट से प्रति यात्री 400.97 रुपये का राजस्व मिलेगा।

विकासकर्ता कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को भारत के कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एसपीवी कंपनी का पंजीकरण करना होगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी नियाल के नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी व एसपीवी कंपनी दोनों को सिक्योरिटी क्लीयरेंस लेना होगा।

केजरीवाल-सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

जासं, नई दिल्ली : नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता की मानहानि शिकायत पर सीएम अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने दिल्ली सरकार व विजेंद्र गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।

आप नेताओं की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विकास पाहवा एवं अधिवक्ता अरूंधरी लायर ने कहा कि उनके मुवक्किल का ही शिकायत में नाम लिया गया, जबकि हजारों लोगों द्वारा लाइक किए गए ट्वीट को उन्होंने री-ट्वीट किया था। मोहम्मद इरशाद के माध्यम से दायर याचिका में आप नेताओं ने विजेंद्र गुप्ता की शिकायत को रद करने की मांग की। साथ ही निचली अदालत द्वारा उन पर आरोप तय करने एवं समन जारी करने के फैसले को चुनौती दी है। कहा कि निचली अदालत द्वारा समन जारी करने का आदेश मनमाना फैसला था। विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत में कहा था कि केजरीवाल एवं सिसोदिया उनकी छवि को खराब करने के लिए सोशल मीडिया के जरिये उन्हें बदनाम कर रहे हैं।

कोहरे में भी सुचारू होगा उड़ानों का संचालन

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता

▶ थर्मल इमेजिंग कैमरों की मदद से उड़ानों को सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट पर उतारा और उड़ाया जाएगा

▶ एयरपोर्ट पर पहली बार सोशल मीडिया कमांड सेंटर बनाया, अधिकारी सातों दिन 24 घंटे यात्रियों के सवालों के देंगे जवाब

एयरपोर्ट पर अतिरिक्त हेल्प डेस्क बनाई गई। (फाइल)

सर्दी के दौरान पड़ने वाले कोहरे की वजह से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आइजीआइ) पर उड़ानों पर ज्यादा फर्क ना पड़े इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नए एटीसी टावर और एयरपोर्ट पर लगाए गए अत्याधुनिक तकनीक की मदद से कोहरे में भी सुचारू तरीके से उड़ानों का संचालन किया जाएगा।

एयर ट्रैफिक कंट्रोल विभाग की ओर से दावा किया गया कि नए एटीसी टॉवर से ज्यादा संख्या में उड़ानों का संचालन किया जाएगा। वहीं, थर्मल इमेजिंग कैमरों की मदद से उड़ानों को सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट पर उतारा और उड़ाया जाएगा। उड़ानों की देरी के दौरान टर्मिनल में बढ़ी यात्रियों की संख्या के मदेद्नजर एयरपोर्ट पर अतिरिक्त हेल्प डेस्क सहित बैठने की जगह, खाने-पीने के आउटलेट के अलावा यात्रियों को संभालने के लिए अतिरिक्त अधिकारी व एयरलाइंस कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी।

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विदेह कुमार जयपुरियार ने बताया कि एयरपोर्ट पर पहली बार सोशल मीडिया कमांड सेंटर बनाया गया है। इसमें तैनात अधिकारी सातों दिन 24 घंटे यात्रियों के सवालों के जवाब के अलावा उनकी शिकायतों को दूर करेंगे। एयरपोर्ट पर फॉलो-मी वाहन भी तैनात किए जाएंगे। जीपीएस लगे इस वाहन से विमान को पार्किंग स्टैंड से रनवे के बीच लाने-ले जाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही रनवे संख्या 28, 29 और 11 को कैट-3बी लाइटिंग तकनीक से युक्त बनाया गया है। इन पर 50 मीटर से कम दृश्यता में भी उड़ानों का संचालन संभव हो सकता है। इसके अलावा आपात स्थिति में बचाव के लिए क्रैश फायर टेंडर की तैनाती की गई है। इसके अलावा टर्मिनल के अंदर विमानों के संबंध में जानकारी के लिए डिजिटल सूचना तंत्र लगाए जाने के अलावा यात्रियों के बैठने के लिए अतिरिक्त कुर्सियां सहित खाने-पीने के आउटलेट की व्यवस्था की गई है। साथ ही फ्लाइट इंफोरमेशन डिस्पले सिस्टम की स्थापना की गई है, जिससे एमएटीवी स्क्रीन पर मौसम संबंधी जानकारी यात्रियों को मिलती रहेगी। इसके साथ ही सभी एजेंसियों के अधिकारी कोलेबोरेटिव डिसीजन मेकिंग (सीडीएम) सिस्टम से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीएम) के महाप्रबंधक एसबी शर्मा ने बताया कि एयरपोर्ट पर इसी वर्ष अगस्त महीने में देशभर में सबसे ऊंचे एटीएटीसी टॉवर का शुभारंभ किया गया गया है।

102 मीटर ऊंचे इस टावर से एटीसी अधिकारी एयरपोर्ट के 90 फीसद हिस्से की निगरानी कर पा रहे हैं। वहीं, उसमें लगे अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से प्रति घंटे होने वाली विमानों की आवाजाही की संख्या भी बढ़ गई है। अन्य शहरों में रडार लग जाने से विभाग की अधिक दूरी तक पहुंच संभव हो गई है। आने वाले वर्षों में एटीसी की यह क्षमता और बढ़ती जाएगी। इससे कम समय में उड़ानों को उतारा और उड़ाया जा सकेगा।

एयरपोर्ट मौसम विभाग के प्रमुख विज्ञानी आरके जैनामनी ने बताया कि आम तौर पर मध्य दिसंबर और मध्य जनवरी तक एयरपोर्ट पर घना कोहरा पड़ता है। पश्चिमी विक्षोभ इसका प्रमुख कारण होता है। हालांकि गत वर्ष एयरपोर्ट पर काफी कम दिन कोहरा पड़ा था। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष 24 दिसंबर से एयरपोर्ट पर घना कोहरा पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग ने पुणे के भारतीय ऊष्णदेशीय मौसम विज्ञान (आइआइटीएम) और नोएडा के राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूए) से हाथ मिलाया है। इसके कारण विभाग अब कोहरे से पहले सटीक और कम समय में इसकी जानकारी देने में सक्षम है।

पड़ेगा भार

रेलवे ने सभी जन आहार केंद्र, रिफ्रेशमेंट रूम में खाने के सामान पर दस से लेकर 70 रुपये तक बढ़ा दिए हैं

रेलवे स्टेशनों पर मिलेगा महंगा भोजन

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

रेलवे स्टेशनों पर यदि आप कुछ खाना चाहते हैं तो इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे क्योंकि रेलवे ने सभी जन आहार केंद्र, रिफ्रेशमेंट रूम में खानपान महंगा कर दिया है। खाने के सामान पर दस रुपये से लेकर 70 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि चाय पहले की तरह दस रुपये में ही मिलती रहेगी। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इससे पहले ट्रेनों में खानपान की दरें बढ़ाई गई थीं, जिन्हें मार्च से लागू किया जाना है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2012 से रेलवे स्टेशनों पर खाने के सामान के दाम नहीं बढ़ाए गए थे। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) इसमें बदलाव की मांग कर रहा था। इसे आधार बनाकर खानपान के सामान को व्यावहारिक मूल्य पर उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। दरें बढ़ाने के साथ ही आइआरसीटीसी और सभी क्षेत्रीय रेलवे को खानपान की गुणवत्ता को सुधारने की हिदायत दी गई है। उन्हें नियमित रूप से खानपान के स्टॉल की जांच करने को कहा गया है, जिससे कि यात्रियों को शुद्ध सामान उपलब्ध हो।

नई दिल्ली स्टेशन स्थित टी स्टॉल। ध्रुव कुमार

पिछले महीने ट्रेनों में भी खानपान की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद से ही स्टेशनों पर मिलने वाले सस्ते खाने के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन की पैंट्री कार में मिलने वाले खाने की तुलना में स्टेशनों पर मिलने वाला सामान दस रुपये सस्ता होगा। ट्रेनों में मार्च से बढ़ी हुई दरें लागू करने को लेकर अधिकारियों का कहना है कि राजधानी, शताब्दी सहित अन्य ट्रेनों में लोग चार माह पहले आरक्षण करा लेते हैं। उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसे ध्यान में रखकर सर्कुलर जारी होने के 120 दिनों के बाद इसे लागू करने का फैसला किया गया है।

रेलवे स्टेशनों पर खानपान की दरें (जीएसटी सहित)

खानपान	पुराना शुल्क	नया शुल्क
नाश्ता (शाकाहारी)	25 रुपये	35 रुपये
नाश्ता (मांसाहारी)	30 रुपये	45 रुपये
भोजन (शाकाहारी)	45 रुपये	70 रुपये
भोजन (मांसाहारी)	50 रुपये	120 रुपये

रेलवे स्टेशनों के मेन्यू में अब ये भी शामिल

- भोजन अंडाकरी के साथ : 80 रुपये
- बिरयानी (शाकाहारी) 350 ग्राम : 70 रुपये
- बिरयानी (अंडा) 350 ग्राम : 80 रुपये
- बिरयानी (चिकन) 350 ग्राम : 100 रुपये

मार्च से ट्रेनों में जीएसटी के साथ होंगी यह दरें

- नाश्ता (शाकाहारी) : 40 रुपये
- नाश्ता (मांसाहारी) : 50 रुपये
- भोजन की थाली (शाकाहारी) : 80 रुपये
- भोजन की थाली (अंडाकरी) : 90 रुपये
- भोजन की थाली (चिकनकरी) : 130 रुपये

केजरीवाल बोले, बेघरों का खयाल रखना सरकार का धर्म

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली में अब यूरोपियन स्टाइल के वाटरप्रूफ और फायरप्रूफ रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं। स्थायी रूप से चल रहे 193 के अतिरिक्त 70 अस्थायी रैन बसेरे बनाए जाने का फैसला लिया गया है। इनमें से अभी तक 42 रैन बसेरे बन चुके हैं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से एक जनवरी से बेघरों के लिए इन रैन बसेरों में चाय, रस, अखबार और पानी भी अनिवार्य रूप से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रैन बसेरों की व्यवस्थाओं पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पहले हर साल दिल्ली सरकार को सर्दियों में रैन बसेरों की खस्ता हालत पर हाई कोर्ट की फटकार पड़ती थी। इन्हीं रैन बसेरों को हमने इतना अच्छा बना दिया है कि अब यहां गरीबों को सर्दियों में आराम से सोने की जगह मिलने लगी है। सबसे गरीब लोगों का ख्याल रखना सरकार का पहला धर्म है।

बोर्ड ने 15 नवंबर से शुरू किए गए इस अभियान में अभी तक 2700 बेघरों को रैन बसेरों में भेजा गया है। सरकार इन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए डाक्टरों की एक टीम लगाई गई है। बोर्ड के सदस्य विपिन राय का कहना है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि बेघरों को आराम से सोने का माहौल मिल सके। बेघरों को रैन बसेरों में लाने के लिए बचाव दल गठित किए गए हैं। बोर्ड का अपना एप भी है जिस पर लोग बेघरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डूसिब रैन बसेरा के नाम पर एप को लोड कर सकते हैं। एप पर बेघरों के बारे में सूचना दी जा सकेगी। संबंधित बेघर के बारे में फोटो खींचकर स्थान के बारे में सूचना देने पर बचाव दल वहां पहुंचकर बेघर को सड़क से उठाकर रैन बसेरे में लेकर आएगा।

1075 है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अफसरों की संख्या। हकीकत यह है कि मौजूदा समय में गृह मंत्रालय के पास इस पूल में अधिकारियों की संख्या 428 ही रह गई है।

मुसलमान विरोधी नहीं है नागरिकता कानून : राजनाथ

रक्षा मंत्री बोले ▶ मैं भारत के सभी मुसलमानों को अपना भाई मानता हूं, हमारी संस्कृति हमें नफरत करना नहीं सिखाती

कहा- राफेल से पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर हमला भारत से ही होगा

न्यूयार्क, प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका में भारतीय समुदाय को आश्वासन दिया है कि नागरिक संशोधन कानून (सीएए) मुसलमान विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि राफेल के आने से पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर हमला भारत से ही हो सकेगा।

राजनाथ सिंह ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन बिल अब कानून बन चुका है और वह मुस्लिम विरोधी बिल्कुल नहीं है। अगर कोई मुझे यह बता सकता है कि नागरिकता कानून मुस्लिम विरोधी है तो तब हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन अगर कोई इसके बारे में केवल अफवाहें उड़ा रहा है और गलतबयानी कर रहा है तो यह कतई काम नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि इस कानून का मकसद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना झेलने के बाद वहां से भाग कर 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर उन्हें सम्मानजनक

अमेरिका के न्यूयॉर्क में मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा भारतीय समुदाय के लिए आयोजित रिसेप्शन को संबोधित किया। प्रेट्र

जीवन देना है। उन्होंने कहा, इन तीनों पड़ोसी देशों को ही सीएए में इसलिए शामिल किया क्योंकि यह इस्लामिक देश हैं। यहां इस्लाम के मानने वालों को इन देशों में धार्मिक प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ता है। भले ही वहां उन्हें और किसी किस्म की प्रताड़ना का सामना करना पड़ता हो।

प्रवासी भारतीयों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राजनाथ सिंह ने कहा कि इसलिए धार्मिक प्रताड़ना के आधार की श्रेणी में हमने मुसलमानों को नहीं रखा है। अन्यथा हम लोग उनमें से नहीं हैं जो जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। हमारी संस्कृति हमें नफरत करना नहीं सिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व को वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश दिया है। मैं भारत में रह रहे सभी मुसलमानों को अपना भाई मानता हूं, वह मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं।

18 दिसंबर को वाशिंगटन में अमेरिका-भारत 2+2 मंत्री स्तरीय वार्षिक बातचीत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका दौरे पर न्यूयार्क सोमवार को पहुंचे हैं। बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पांपियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से क्रमशः एस.जयशंकर और राजनाथ सिंह मुलाकात करेंगे।

'बात क्या होगी, पीओके तो अपना ही है' : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के साहस और वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब जब भारत के पास राफेल जेट विमान होंगे तब आतंकी शिविरों को तबाह करने के लिए हमें विमान पाकिस्तान ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब यह काम हम भारत से ही कर सकेंगे। ध्यान रहे कि विगत अक्टूबर में 36 राफेल विमानों की पहली खेप लेने राजनाथ सिंह खुद फ्रांस गए थे। भाषण सुन रहे प्रवासी भारतीयों में से एक ने जब केंद्रीय मंत्री से उनके पीओके (गुलाम कश्मीर) संबंधी पुराने बयान के बारे में पूछा तो सिंह ने कहा कि अब बात क्या होगी, पीओके तो अपना ही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सैन्य ताकत बढ़ रही है, पर पाकिस्तान के संदर्भ में देश पूरी सतर्कता बरत रहा है।

राजनाथ बोले, देश कठिन आर्थिक हालात से जल्द उबरेगा : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत पर वैश्विक आर्थिक मंदी का कुछ प्रभाव पड़ा है। लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि देश कुछ ही महीनों में कठिन आर्थिक हालात से बाहर निकल आएगा। उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह बड़ी चिंता का विषय नहीं है। सरकार ने इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। साथ ही आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है।

टू प्लस टू वार्ता में हो सकते हैं दोनों देशों के बीच अहम समझौते

- भारत और अमेरिका के बीच आज होगी मंत्रिस्तरीय वार्ता
- विदेश मंत्री जयशंकर और राजनाथ करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

वॉशिंगटन, प्रेट्र : भारत और अमेरिका के मंत्रियों की अमेरिकी धरती पर होने वाली पहली टू प्लस टू वार्ता कारगर साबित हो सकती है। इसमें द्विपक्षीय सुरक्षा को मजबूती देने वाले कुछ अहम समझौते हो सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने यह बात कही। विदेश विभाग के फॉगी बॉटम मुख्यालय में बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मेजबानी उनके अमेरिकी समकक्ष विदेश मंत्री माइक पोंपियो तथा रक्षा मंत्री मार्क एस्पर करेंगे। पहली टू प्लस टू वार्ता नई दिल्ली में पिछले साल सितंबर में हुई थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में प्रणाली को मंजूरी दी थी।

बुधवार को होने वाली वार्ता से पहले इस साल मोदी और ट्रंप की चार मुलाकातें हुई हैं। इनमें सितंबर के महीने में ह्यूस्टन में दोनों का संयुक्त संबोधन शामिल है। यहां भारतीय राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि टू प्लस टू वार्ता भारत और अमेरिका के बीच सर्वोच्च स्तर की संस्थागत प्रणाली है, जो विदेश नीति, रक्षा तथा सामरिक मुद्दों पर हमारे विचारों को साथ लाती है। पहली बार अमेरिका में इस तरह का संवाद हो रहा है।

श्रृंगला ने टू प्लस टू वार्ता से पहले कहा कि दोनों देशों के बीच विदेश नीति तथा रक्षा क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई है तथा हम अत्यंत गुणवत्तापूर्ण मुलाकात के लिए आशान्वित हैं। दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए अमेरिका के उप सहायक रक्षा मंत्री जोए फेल्टर ने कहा कि बैठक हो रही है, यह तथ्य ही अपने आप में सफलता की ओर इशारा करता है। यह इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका एवं भारत दोनों अपने समान हितों के लिए संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री ऐसे भविष्य की दिशा में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराना चाहेंगे जहां भारत एक बड़ी महाशक्ति के रूप में अपनी स्वाभाविक भूमिका समझता है।

सीबीआइ ने बर्खास्त आयकर आयुक्त श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने बर्खास्त आयकर आयुक्त संजय कुमार श्रीवास्तव को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। बर्खास्त अधिकारी ने अनुचित लाभ के लिए अपील पर पूर्व की तारीख में आदेश दिया था।

संजय कुमार श्रीवास्तव पर आरोप था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)में आयकर (अपील) आयुक्त के पद पर तैनाती के दौरान अनुचित लाभ लेने के लिए जून 2019 में 104 मामलों में पूर्व की तारीख में आदेश जारी किए। इसी आरोप में श्रीवास्तव को सरकार ने जबरन सेवानिवृत्त कर दिया था। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने जुलाई में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने संजय कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ आपराधिक साठगांठ, धोखाधड़ी और जालसाजी की आइपीसी की धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। सीबीआइ ने आरोप लगाया है कि सभी आदेश दिसंबर 2018 में जारी किए गए थे। इसके अलावा श्रीवास्तव ने 13 ऐसे मामलों का भी निपटारा कर दिया था जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे। सीबीआइ ने कहा है कि विभिन्न दस्तावेजों का अध्ययन करने से पता चलता है कि श्रीवास्तव ने सात जून 2019 को आदेश जारी किया था। इसके तीन दिनों बाद सरकार ने उन्हें 10 जून को सेवा से हटा दिया था।

एक ही दिन दो मामलों की सुनवाई से हटे सीजेआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कायम की नजीर
- दिल्ली के वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी अक्षय सिंह की पुनर्विचार याचिका पर नई पीठ करेगी सुनवाई
- जस्टिस आर भानुमति, अशोक भूषण और एएस बोपन्ना की तीन सदस्यीय पीठ गठित, आज होगी सुनवाई
- सजायाफ्ता नेताओं के पार्टी बनाने पर प्रतिबंध की सुनवाई से भी हटे मुख्य न्यायाधीश

एसए बोबडे फाइल फोटो

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने मंगलवार को दो मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इनमें एक मामला दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी की पुनर्विचार याचिका का था। दूसरा मामला सजायाफ्ता नेताओं के पार्टी बनाने पर प्रतिबंध से जुड़ा हुआ था। दोनों मामलों में अब नई पीठ सुनवाई करेगी।

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी अक्षय सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं को अलग कर लिया। अब बुधवार को याचिका पर नई पीठ सुनवाई करेगी। अक्षय सिंह ने फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।

मंगलवार को जस्टिस बोबडे, आर भानुमति और अशोक भूषण की पीठ ने सुनवाई शुरू की। तभी मुख्य न्यायाधीश का ध्यान इसी मामले में अन्य आरोपितों की ओर से दाखिल पूर्व याचिका में पेश हुए वकीलों पर गया। मुख्य न्यायाधीश ने एक वकील के बारे में पूछा जिस पर दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह वकील उस समय पीड़ित परिवार की ओर से पेश हुए थे, सरकार की ओर से नहीं। किसी पक्ष के आपत्ति नहीं उठाए जाने के बावजूद मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया। हालांकि, वकील का नाम नहीं लिया गया, लेकिन नियम के मुताबिक, अगर किसी मामले में सुनवाई कर रही पीठ के न्यायाधीश का रिश्तेदार पेश हो रहा होता है तो वह न्यायाधीश मामले पर सुनवाई नहीं करता। माना जा रहा है कि इस मामले में पहले पीड़ित पक्ष की ओर से मुख्य न्यायाधीश के रिश्तेदार वकील के तौर पर पेश हो चुके हैं, इसलिए मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में बुधवार को सुनवाई के लिए नई पीठ गठित की जाएगी। अब यह मामला बुधवार को जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगा है।

इसी तरह मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव लड़ने से वंचित सजायाफ्ता नेताओं के राजनीतिक दल बनाने या उसका अध्यक्ष बनने पर रोक के लिए दायर याचिका की सुनवाई से भी खुद को अलग कर लिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और सूर्यकांत के साथ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। यह जनहित याचिका किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होगी।

याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि इसी मामले में एक अन्य पीठ के समक्ष एक बार उनकी वकील पुत्री पेश हुई थी। उपाध्याय ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, जो राजनीतिक दल को पंजीकृत करने के निर्वाचन आयोग के अधिकार से संबंधित है। याचिका में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में सजा मिलने की वजह से चुनाव लड़ने के अयोग्य है, तो ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक दल गठित करने या इसकी अध्यक्षता करने की अनुमति देना अनुचित होगा।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले केंद्र और निर्वाचन आयोग को इस याचिका पर गंभीरता से विचार करने के लिए कहा था। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस समय हत्या, बलात्कार, तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, राष्ट्रद्रोह या डकैती जैसे संगीन अपराध में दोषी ठहराया गया व्यक्ति राजनीतिक दल गठित करके उसका अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी बन सकता है।

'समूचे देश की आबादी के संदर्भ में धर्म पर विचार किया जाना चाहिए'

- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा देने के खिलाफ खारिज की याचिका
- राज्यों की आबादी के आधार पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई थी

नई दिल्ली, प्रेट्र : उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने संबंधी केंद्र की 26 साल पुरानी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि समूचे भारत की आबादी के परिप्रेक्ष्य में धर्म पर विचार किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और सूर्य कांत की पीठ ने भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। उपाध्याय ने राज्य स्तर पर आबादी के आधार पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग की थी।

पीठ ने कहा, 'समूचे भारत के आधार पर धर्म पर विचार करना चाहिए। इसमें क्या परेशानी है, अगर कश्मीर में मुस्लिम बहुमत में हैं, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में अल्पसंख्यक हैं।' उपाध्याय ने अपनी याचिका में दावा किया था कि आठ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। लेकिन, उन्हें वहां अल्पसंख्यकों के लाभों से वंचित किया जा रहा है। पीठ ने कहा कि भाषाएं राज्य के आधार पर सीमित हैं। धर्म की तो राज्य सीमाएं नहीं हैं। हमें इस मामले में अखिल भारतीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। लक्षद्वीप में मुस्लिम तो हिंदू कानून का पालन करते हैं।

पीठ ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल के इस कथन का भी संज्ञान लिया कि शीर्ष अदालत के कई फैसले में कहा गया है कि किसी समूह के अल्पसंख्यक होने का निर्धारण उसकी अखिल भारतीय आबादी के आधार पर किया जा सकता है। अटार्नी जनरल इस मामले में न्यायालय की मदद कर रहे थे। उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पराशरण से पीठ ने ऐसे फैसलों के बारे में जानना चाहा, जिनमें कहा गया है कि राज्य की आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा देने पर विचार किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि हम नहीं समझते कि हमें इस पर विचार करना चाहिए। पीठ ने कहा कि राज्यों के सृजन के लिए भाषाओं को आधार बनाया गया है, लेकिन धर्म के मामले में ऐसा नहीं है। अतः राज्य की आबादी के आधार पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

स्वतंत्र विचारों का पोषण करने वाले स्थान के रूप में उभरें शिक्षण संस्थान : कोविंद

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बात पर जोर दिया कि देश के समक्ष उत्पन्न विशेष चुनौतियों के समाधान में विश्वविद्यालयों को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों को स्वतंत्र विचारों, अभिव्यक्ति का पोषण करने वाले स्थान के रूप में उभरना चाहिए।

- केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आइआइएसईआर तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के निदेशकों एवं कुलपतियों की बैठक को राष्ट्रपति ने किया संबोधित

जेएनयू के स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंस की डॉ. प्रतिमा को फील्ड रिसर्च में विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित करते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। प्रेट्र

राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विवादास्पद संशोधित नागरिकता कानून को लेकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं शोध संस्थान (आइआइएसईआर) तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के निदेशकों एवं कुलपतियों की बैठक को राष्ट्रपति ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों को हमारे देश और समाज के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के समाधान में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

कोविंद ने कुलपतियों से कहा, 'इनमें से अनेक चुनौतियों के लिए रचनात्मक एवं इनोवेटिव समाधान की जरूरत है। यह आपका सर्वोपरि दायित्व है कि परिसर स्वतंत्र विचारों, अभिव्यक्ति का पोषण करने वाले स्थान के रूप में उभरें, जहां प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए और विफलता की आलोचना की बजाए सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाए।'

राष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय ऐसी प्रयोगशाला बनें जहां ऐसी समस्याओं से रूबरू होने का मौका मिले जिनका राष्ट्र निर्माण में समाधान निकालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि छात्रों को विशिष्ट सामुदायिक भाव के साथ अकादमिक और पाठ्येतर कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा, 'मुझे यह पता है कि विश्वविद्यालय इस बारे में सजग हैं और इस दिशा में जरूरी कदम उठा रहे हैं, लेकिन हमें आत्म चिंतन करने की जरूरत है कि क्या हम पर्याप्त एवं सामयिक कदम उठा रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपके संस्थानों में पर्याप्त लैंगिक संतुलन हो, खासकर शिक्षक संवर्ग में।' राष्ट्रपति ने कहा कि नामांकन के लिए अकादमिक कैलेंडर का सख्ती से पालन, कक्षा, परीक्षा का आयोजन और परिणाम की घोषणा तथा डिग्री प्रदान करने के लिए समारोह जैसे छोटे-छोटे कदम उत्कृष्टता की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए कदम उठा सकते हैं।

राष्ट्रपति भवन में 'पांचवें विजिटर पुरस्कार' प्रदान करने के एक अन्य कार्यक्रम में कोविंद ने कहा कि अकादमिक समुदाय और स्थानीय उद्योग के बीच अर्थपूर्ण संबंध को विश्वविद्यालयों को शीर्ष प्राथमिकता देनी चाहिए।

सड़क की स्थिति जानने गए जज गाड़ी छोड़ ट्रेन में बैठे

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार के गया जिले की जर्जर सड़क को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के क्रम में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल वस्तुस्थिति से अवगत होने के लिए खुद अपनी गाड़ी से गया के लिए रवाना हुए। सड़क इतनी खराब थी कि उन्हें गाड़ी छोड़कर ट्रेन में बैठना पड़ा। उन्होंने सड़क की जर्जर स्थिति को बेहद ही शर्मनाक बताते हुए कहा,जो पर्यटक जो बोधगया और गया आते होंगे उन्हें क्या समस्या झेलनी पड़ती होगी, यह वही बता सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने एडिशनल सालीसीटर जनरल एसडी संजय, अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार, महाधिवक्ता ललित किशोर और नगर विकास विभाग के उच्चाधिकारी को कोर्ट में आकर सही स्थितियों के बारे में बताने को कहा है। उन्होंने कहा,अगर इस रास्ते को ठीक नहीं किया गया तो पर्यटन के लिए आने वाले लोगों को बेहद परेशानी होती रहेगी। शहर में प्रदूषण पर भी गंभीरता से सोचना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने सभी अधिकारियों को तत्काल कोर्ट में आने के लिए कहा था, लेकिन सरकारी अधिवक्ताओं ने विभाग से आने वाली रिपोर्ट के बिना तत्काल सही जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है।

केंद्र की चेतावनी, आइपीएस अफसर नहीं आए तो करेंगे पदों में कटौती

इंद्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

यह है स्थिति
- 1075 आइपीएस अफसरों का कोटा है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए
- 428 अफसर ही हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास
- 170 आइपीएस अफसरों का कुल कैडर पंजाब में
- 15 फीसद लीव रिजर्व निकालकर जो पोस्ट बचती हैं, उसका एक तिहाई डेप्यूटेशन पर होना जरूरी
- 44 अफसर केंद्र में डेप्यूटेशन पर होने चाहिए मौजूदा स्ट्रेंथ के हिसाब से
- 12 अधिकारी डेप्यूटेशन पर हैं इस समय केंद्र में
- 159 अफसर केंद्रीय व इंटर स्टेट डेप्यूटेशन को मिलाकर नियुक्ति पर हैं इस समय
- 11 पोस्ट खाली हैं पंजाब में आइपीएस अफसरों की

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब समेत देश के तमाम राज्यों को आइपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं किया गया तो सेंट्रल डेप्यूटेशन रिजर्व पोस्ट का कोटा 50 फीसद कम कर दिया जाएगा। इस समय पूरे देश में से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले आइपीएस अफसरों की गिनती 1075 है, लेकिन गृह मंत्रालय के पास 428 अफसर ही हैं। इन्हें सीआइएसएफ, सीबीआइ, आइटीबीपी, सीआइएसएफ समेत अन्य तमाम केंद्रीय सुरक्षा बलों में तैनात किया जाता है।

अफसरों की कमी के चलते इन सुरक्षा बलों में काम करने वाले अधिकारियों की ओर से यह मांग बढ़ती जा रही है कि उन्हें उन पदों पर तैनात किया जाए जो आइपीएस अफसरों के लिए रिजर्व हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर कहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों में उच्च पदों पर आइपीएस अफसरों के न आने से पद खाली पड़े हैं। अगर ये पद खाली रह जाते हैं, तो केंद्रीय डेप्यूटेशन कोटा 40 फीसद करते हुए इसे 1075 की बजाय 500 पद कर दिया जाए।

ये अधिकारी हैं डेप्यूटेशन पर : पंजाब के 12 अधिकारी डेप्यूटेशन पर हैं। इनमें एसके गोयल, पराग जैन, कपिल देव, राजीव अहीर, पीके राय, निलाभ किशोर, दिनेश प्रताप सिंह, अशीष चौधरी, हर्ष कुमार बंसल, धनप्रीत कौर, राहुल एस., बिक्रमपाल एस. भट्टी।

देश में वैज्ञानिकों की कमी नहीं हो रही खत्म

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वैज्ञानिकों को लुभाने की सरकार की कोशिशों के बाद भी देश के लगभग सभी शीर्ष शोध संस्थानों में वैज्ञानिकों की कमी बनी हुई है। मौजूदा समय में देश के 70 शीर्ष शोध संस्थानों में वैज्ञानिकों के 32 सौ से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। सबसे ज्यादा कमी बेंगलुरु के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) से जुड़े संस्थान में पाई गई है, जहां वैज्ञानिकों के 177 पद खाली हैं। पुणे स्थित सीएसआइआर से जुड़े राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में वर्तमान में करीब 123 वैज्ञानिकों के पद खाली हैं।

देश के शीर्ष शोध संस्थानों में यह स्थिति तब बनी हुई है, जब सरकार ने इन संस्थानों में वैज्ञानिकों के खाली पदों को भरने के लिए कई लुभावनी योजनाएं शुरू कर रखी हैं। इनमें रामानुजम फेलोशिप, ब्रिज स्कीम, इंस्पायर स्कीम और विधार्थी-वैज्ञानिक संपर्क योजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा महिलाओं को लुभाने के लिए अलग से एक महिला वैज्ञानिक स्कीम भी शुरू क गई है जिसमें लोगों को शोध के लिए अच्छी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसके साथ ही विदेशों में निवास कर रहे वैज्ञानिकों को स्वदेश लौटने पर भी आकर्षक पैकेज देने का प्रस्ताव किया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे जो बड़ा कारण माना जा रहा है, वह भरोसा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्हें अभी जो सुविधाएं आफर की जा रही हैं, वे आगे भी मिलती रहेंगी, इसकी भी गारंटी चाहिए।

शोध संस्थानों में वैज्ञानिकों की कमी को लेकर यह जानकारी हाल ही में संसद को दी रिपोर्ट में सामने आई है। इस दौरान वैज्ञानिकों की सबसे ज्यादा कमी सीएसआइआर के शोध संस्थानों में है। बता दें कि देश में अकेले सीएसआइआर के ही करीब 40 शोध संस्थान हैं। इसके साथ ही विज्ञान और तकनीक से जुड़े करीब 30 अन्य संस्थान हैं। सरकार देश भर में शोध को बढ़ावा देने में जुटी हुई है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

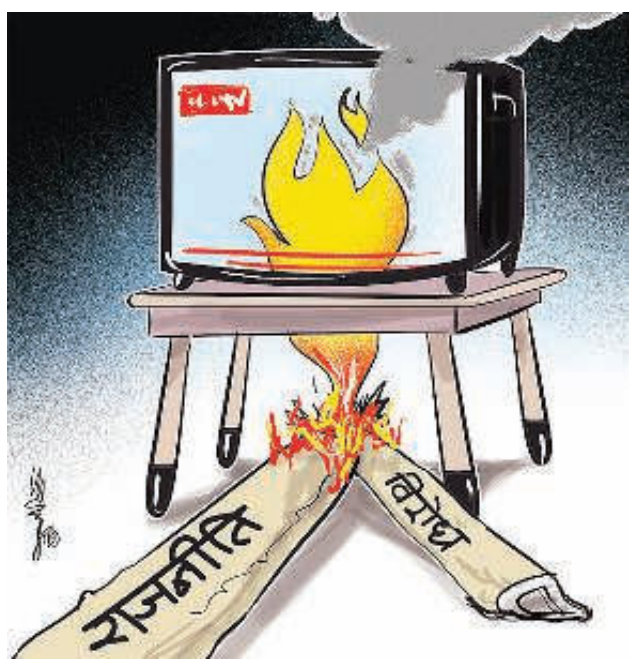

तीसरा चरण

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का तीसरा चरण लांच, 1.25 लाख किलोमीटर और बनेंगी ग्रामीण सड़कें, छह लाख किमी से अधिक लंबाई की बन चुकी हैं ग्रामीण सड़कें, योजना के पहले चरण की पुरानी सड़कों का उन्नयन भी होगा

ग्रामीण संस्थाओं को भी जोड़ेंगी पीएमजीएसवाई की सड़कें

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

1.25 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने का लक्ष्य तय किया गया है योजना के इस चरण में

60 और 40 फीसद हिस्सेदारी होगी केंद्र और राज्य सरकार की सड़क निर्माण में

प्रतीकात्मक फोटो

गांवों को परस्पर जोड़ने के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में अब ग्रामीण संस्थाओं के बीच भी संपर्क मार्ग बनाएगी। योजना का दायरा गांवों को चौतरफा जोड़ने तक बढ़ा दिया गया है। इस चरण में पीएमजीएसवाई में अब तक निर्मित सड़कों के उन्नयन को भी शामिल कर लिया गया है, ताकि पुरानी पड़ चुकी सड़कों को एक नया जीवन मिल सके। इस योजना के तहत 1.25 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिस पर 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा। योजना के तीसरे चरण के प्रावधान की घोषणा चालू वित्त वर्ष के बजट में की गई थी।

पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण में फंडिंग के प्रारूप में थोड़ी तब्दीली भी कर दी गई है। इसके तहत सड़कों के निर्माण में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60 फीसद और राज्यों की 40 फीसद कर दी गई है। हालांकि पूर्वोत्तर और अन्य हिमालयी राज्यों में यह योजना 90 फीसद और 10 फीसद के अनुपात में चलेगी। योजना के लिए स्वीकृत 80,250 करोड़ रुपये में से 53,800 करोड़ रुपये केंद्र खर्च करेगा, बाकी का बोझ राज्यों के कंधे पर होगा।

पीएमजीएसवाई 3.0 की शुरुआत करने के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा 'इससे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी, जो ग्रामीण विकास की गति को रफ्तार देगा।' तीसरे चरण का उद्देश्य गांवों को मंडियों से जोड़ने, हायर सेकेंडरी स्कूल और अस्पतालों को जोड़ना है। तोमर ने कहा 'गांवों के विकास में सड़कों की भूमिका को देखते हुए योजना के तहत गांवों को चौतरफा पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा।' उन्होंने राज्यों से इन सड़कों के रखरखाव की योजना बनाने की अपील की। उनका कहना था कि सड़कें बनाना कठिन है, जबकि रखरखाव बहुत आसान है, जिसे राज्य आसानी से कर सकते हैं। पीएमजीएसवाई की सड़कों को लोग अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते हैं। सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने जैसे कठिन काम को वाजपेयी ने करके दिखा दिया। उन्होंने कहा कि सभी गांवों को जोड़ना कठिन जरूर था, लेकिन असंभव नहीं, जिसे इसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए।

तथ्य यह है कि पीएमजीएसवाई के तहत 16 दिसंबर 2019 तक कुल 1.53 ग्रामीण सड़कें बना ली गई हैं, जिनकी लंबाई 6.08 लाख किमी हो गई है। इन सड़कों के मार्फत देश के 97.27 फीसद गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है। योजना में अभिनव प्रयोग भी किए गए हैं, जिसमें 36 हजार किमी से अधिक लंबाई की सड़कें ग्रीन टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं। इन सड़कों के निर्माण में वेस्ट प्लास्टिक और कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है।

THE STUDY
विश्व इतिहास
से नया वैच प्रारंभ
-मणिकांत सिंह
OPEN LECTURE
कल 8AM
210, VIRAT BHAWAN, NEAR POST OFFICE
MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009
9999516388, 9999278966, 42870015

65 सीटों पर मतदान हो चुका है झारखंड में। अब 20 दिसंबर को पांचवें और अंतिम चरण में 16 सीटों पर मतदान होना है। परिणाम 23 दिसंबर को आएंगे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 18 दिसंबर 2019

शिवसेना-भाजपा विधायकों ने महाराष्ट्र विस में पकड़ा एक-दूसरे का कॉलर

टकराव ▶ किसान मुद्दे पर उद्धव को बैनर दिखाने की कोशिश कर रहे थे भाजपा विधायक

शिवसेना विधायक ने किया बैनर छीनने का प्रयास, इससे बढ़ा हंगामा

महाराष्ट्र के नागपुर में विधान भवन में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस (सामने, नीली हॉफ जैकेट में) की अगुआई में भाजपा विधायकों ने शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित एक रिपोर्ट का बैनर लेकर उद्धव ठाकरे से किसानों संबंधी वादा पूरा करने के लिए प्रदर्शन किया। प्रेट्र

नागपुर, प्रेट्र : किसानों को सहायता दिए जाने के मुद्दे पर भाजपा और शिवसेना के विधायक मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में आपस में भिड़ गए और एक-दूसरे का कॉलर पकड़ लिया। वरिष्ठ और पूर्व मंत्रियों ने बीच-बचाव करके उन्हें अलग कराया। विधान परिषद में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ लिहाजा दोनों सदनों की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी।

मंगलवार को जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा विधायक अभिमन्यु पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समक्ष एक बैनर प्रदर्शित करने की कोशिश की। इस बैनर पर शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित एक रिपोर्ट का उल्लेख था, जिसमें उद्धव ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपये सहायता राशि की मांग की थी। भाजपा विधायक उद्धव को उनकी इस मांग के बारे में याद दिलाना चाहते थे जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले की थी। इसके बाद भाजपा विधायक वेल में चले गए और नारेबाजी करने लगे। उनकी मांग थी कि उद्धव ने मुख्यमंत्री बनने से पहले जो मांग की थी, वह अब उसे पूरा करें। इस बीच, शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने अभिमन्यु पवार से बैनर छीनने की कोशिश की और इस दौरान दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया। वरिष्ठ और पूर्व मंत्रियों ने उन्हें अलग कराया। स्पीकर नाना पटोले ने भाजपा विधायकों से सीटों पर लौटने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन इस दौरान कुछ और शिवसेना विधायकों ने भाजपा सदस्यों से बैनर छीनने की कोशिश की जिससे हंगामा बढ़ गया। भाजपा विधायकों ने सीटों पर लौटने से इन्कार कर दिया, लिहाजा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा तो स्पीकर ने कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी।

मैं अपना वादा पूरा करूंगा : उद्धव

दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित होने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, 'राज्य के किसानों से किया गया वादा उनके और मेरे बीच है और मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूं। विपक्ष को यह दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अगर आप कोई सवाल (सदन में) पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछने का एक तरीका होता है। आप शोर मचाकर और दूसरे की बात सुने बिना सवाल नहीं पूछ सकते।'

बुलंदशहर जिलाधिकारी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

माला दीक्षित, नई दिल्ली

- सिकंदराबाद ब्लाक प्रमुख मनीष भाटी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला
- भाटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
- ब्लाक प्रमुख का चार्ज डिप्टी कलेक्टर सिकंदराबाद को सौंपा गया
- सदन में शपथ न लेने वाले सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव कार्यवाही में भाग लेने और मतदान करने का उठाया गया था कानूनी मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट फाइल

क्या सदन की सदस्यता की शपथ न लेने वाले निवार्चित सदस्य ब्लाक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं और मतदान कर सकते हैं? इस कानूनी मुद्दे को उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विचार करने का मन बनाते हुए नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ब्लाक प्रमुख का चार्ज डिप्टी कलक्टर सिकंदराबाद को सौंपे जाने के बुलंदशहर जिलाधिकारी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।

यह मामला सिकंदराबाद ब्लाक प्रमुख मनीष भाटी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का है। हाई कोर्ट ने कानूनी मुद्दा पूर्ण पीठ के समक्ष लंबित होने के कारण मनीष भाटी की याचिका पर फिलहाल आदेश देने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद भाटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मंगलवार को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने भाटी के वकील जसबीर सिंह मलिक की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य को नोटिस जारी किया। पीठ ने बुलंदशहर के जिलाधिकारी के गत 13 नवंबर के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। जिलाधिकारी ने उस आदेश में भाटी के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को क्रियान्वित करते हुए ब्लाक प्रमुख का चार्ज डिप्टी कलक्टर सिकंदराबाद को सौंप दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जसबीर सिंह मलिक ने अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि सदन की शपथ न लेने वाले निवार्चित सदस्य कानूनन न तो अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा ले सकते हैं और न ही मतदान कर सकते हैं। इस मामले में कुल 143 सदस्यों मे सिर्फ 87 सदस्यों ने शपथ ली थी। उन्होंने कहा कि यह बड़ा कानूनी मुद्दा है और कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनने के बाद याचिका पर प्रति पक्षियों को नोटिस जारी किया। सिंह ने कोर्ट से चार्ज डिप्टी कलक्टर को सौंपने के जिलाधिकारी के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

मनीष भाटी सितंबर 2018 में सिकंदराबाद के ब्लाक प्रमुख निवार्चित हुए। 18 अक्टूबर 2018 को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और सात नवंबर को अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में अविश्वास प्रस्ताव में उन सदस्यों ने भी हिस्सा लिया जिन्होंने सदन की शपथ नहीं ली थी। उसका कहना है कि नियम 1994 के तहत उन लोगों को प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं था।

सियासी आंधी ने उड़ाए सबके तंबू, कोई यहां गिरा, कोई वहां

प्रदीप सिंह, रांची

जयप्रकाश के मुकाबले रामप्रकाश पटेल

बिहार से झारखंड को पृथक करने के लिए बड़ा आंदोलन चला। इस मुहिम का एक नामी चेहरा थे टेकलाल महतो। टेकलाल बाबू नहीं रहे तो उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे जयप्रकाश भाई पटेल के हाथ में आ गई। पटेल पिछला चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर जीते थे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रंग उनपर ऐसा चढ़ा कि अब वे भाजपा से प्रत्याशी हैं। उनके भाई रामप्रकाश पटेल ही उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यानी राजनीतिक विरासत के लिए दोनों भाई एक-दूसरे से जूझ रहे हैं। हालांकि, सत्ता के लिए ऐसा संघर्ष कोई अजूबा नहीं है। राजनीति ने अमूमन घरों के भीतर जूझने वाली देवरानी और जेठानी को धनबाद के झरिया में आमने-सामने खड़ा कर रखा है। यानी मशहूर सीरियल घर-घर की कहानी झरिया में सबकी जुबान पर है।

दूरदर्शन का मशहूर धारावाहिक उल्टा-पुल्टा आपको याद होगा। उसके सूत्रधार जसपाल भट्टी अगर आज होते तो झारखंड की मौजूदा राजनीति पर एक पूरी सीरीज जरूर बना डालते। महज एक से डेढ़ माह में क्या कुछ नहीं देखा यहां की राजनीति ने, वाकई सब कुछ उल्टा-पुल्टा की तर्ज पर। साथ चलने वाले दोस्त आमने-सामने आकर ताल ठोकने लगे। दल बदलने का ऐसा ट्रेंड चला कि भगवा झंडा ढोने वाला शख्स कांग्रेस में और कांग्रेस की दशकों तक राजनीति करने वाला भाजपा में। सब कुछ बेहतर संभावना की आस में। दलों के नारे तक दब गए चुनावी शोर में, रोटी, कपड़ा, मकान की बात तो छोड़िए, एक के बाद एक चरण का चुनाव जैसे-जैसे निपट रहा है झारखंड में, वैसे-वैसे तल्खी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह सवाल उठना भी लाजिमी है कि क्या राजनीति अवसरवादिता से ज्यादा कुछ नहीं? क्या विचारधारा बीते दिनों की बात हो चुकी है?

सालों से झारखंड की राजनीति में भाजपा और आजसू पार्टी साझीदार थे। आजसू कोटे से एक मंत्री भी भाजपानीत गठबंधन सरकार में था। दोनों के बीच चुनावी तालमेल पर बात आगे बढ़ती, इससे पहले ही गठबंधन की नैय्या डगमगाने लगी। आजसू ने 17 सीटें मांगीं तो भाजपा ने ठेंगा दिखा दिया। बिदके आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने इससे ठीक तीन गुना ज्यादा सीटें यानी 51 सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर दिए। भाजपा को इससे होने वाले नुकसान का आभास थोड़ी देर से हुआ, जिसे रणनीतिक तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यह कहते हुए संभाला कि चुनाव के बाद आजसू उनके साथ होगी। फिर गले मिलने के रास्ते दोनों दलों ने बंद नहीं किए। यानी दुश्मनी इतनी ही कि मौका मिले तो दोस्ती की गुंजाइश भी बाकी रहे। तभी तो भाजपा ने आजसू प्रमुख सुदेश महतो के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा तो आजसू ने भी मुख्यमंत्री रघुवर दास की सीट पर उम्मीदवार नहीं दिया। राजनीतिक विश्लेषक रवि प्रकाश कुछ इस तरह मौजूदा माहौल को आंकते हैं, सियासत में दलों का बदलना स्वाभाविक है, लेकिन झारखंड सरीखे अपेक्षाकृत छोटे राज्य में यह प्रवृत्ति तेजी से पनपी है। दरअसल मुद्दों के प्रति ऐसी उदासीनता बिरले ही दिखती है। इस परिस्थिति में भाजपा अपने स्थायी मुद्दों के प्रति ज्यादा ईमानदार दिखती है, लेकिन उन सवालों पर कांग्रेस की गंभीरता नहीं दिखती जो आम लोगों और उनसे जुड़े रहे समूह के लिए आवश्यक है। ऐसे में सबसे ज्यादा भागदौड़ उस दल में मचना आश्चर्य पैदा नहीं करता है।

कपड़ों की तरह दल बदले नेताओं ने : भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी अपनी पसंदीदा सीट संताल परगना के बोरियो से फिर चुनाव लड़ना चाहते थे। उनकी इच्छा जब सफल नहीं हुई तो वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। वहां भी जब दाल नहीं गली तो दूसरे दिन वे आजसू के दफ्तर में यह कहते हुए नजर आए कि इसी दल से उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा है। दरअसल, इस दफे झारखंड के चुनावी समर में योद्धाओं का पाला बदलना इस कदर हुआ कि सारे रिकार्ड ध्वस्त हो गए। विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक रहे राधाकृष्ण किशोर आजसू के हो गए। कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता मनोज कुमार यादव अब झारखंड की इंट्री प्वाइंट बरही सीट पर भाजपा का झंडा थामे खड़े हैं। वैसे इस राजनीतिक उठापटक में सबसे ज्यादा झटके कांग्रेस को लगे। कांग्रेस ने तीन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खोए। अमेरिका रिटर्न कुणाल षाडंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा का फ्रेश चेहरा थे, लेकिन उन्होंने चुनाव की घोषणा के ठीक पहले भाजपा में जाना ज्यादा सुरक्षित समझा।

आजसू नेता ने लिया था नक्सलियों से सहयोग!

दिलीप कुमार, रांची

महासमर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

- नक्सली राजदेव खेरवार ने पुलिस के समक्ष किया सनसनीखेज राजफाश

झारखंड के लोहरदगा में पिछले दिनों गिरफ्तार कुख्यात नक्सली रवींद्र गंझू के दस्ते के सक्रिय सदस्य राजदेव खेरवार ने एक सनसनीखेज जानकारी दी है। उसने पुलिस से कहा है कि विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी के एक नेता ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर 15 लाख रुपये के इनामी नक्सली रवींद्र गंझू से सहयोग लिया था। राजदेव खेरवार ने बताया है कि लोहरदगा के पेशरार का प्रमोद उरांव हर चार-पांच दिन में शाम या रात के समय बराबर बुलबुल गांव में आता और वहां रवींद्र गंझू से मिलता था। वहां वह रवींद्र गंझू को पुलिस की गतिविधियों की जानकारी भी देता था। जब रवींद्र गंझू की पत्नी जेल गई तो प्रमोद उरांव ने ही रवींद्र गंझू को अपने मोबाइल से उसके (रवींद्र गंझू) परिवार के सदस्य से बात कराई थी।

राजदेव ने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में भी रवींद्र गंझू ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा की थी। तब प्रमोद उरांव ने आजसू के एक बड़े नेता का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने (आजसू नेता ने) आपसे (रवींद्र गंझू से) अनुमति लेने को कहा है। उस नेता ने यह भी कहा है कि जो भी आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी, वे लोग पूरी तरह तैयार हैं। इसके बाद ही रवींद्र गंझू ने इलाके में चुनाव प्रचार की अनुमति दी थी।

गिरफ्तार राजदेव खेरवार लोहरदगा का रहने वाला है। उसने पूछताछ में बताया है कि उसका गांव जंगलों से घिरा है, जहां उग्रवादी गतिविधियां चलती रहती है। नक्सली ग्रामीणों को बुलाकर बैठक करते हैं और जो बैठक में शामिल नहीं होता, उसके साथ मारपीट भी करते हैं। राजदेव ने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद माओवादियों का रीजनल कमांडर रवींद्र गंझू अपने दस्ते के सदस्यों के साथ 31 मई की रात नौ बजे बुलबुल गांव में आया था। उसने दिलीप भगत के घर को घेरा और उसकी पिटाई के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिलीप की हत्या के बाद गांव के लोगों को पुलिस का काम नहीं करने की धमकी दी।

राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं होगा कोई भाजपा नेता : शाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- भाजपा अध्यक्ष ने किया साफ
- कहा, सरकारी धन से नहीं होगा मंदिर का निर्माण

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी संभालने वाले ट्रस्ट में भाजपा का कोई नेता शामिल नहीं होगा। भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है। शाह के अनुसार, राम मंदिर के निर्माण की सारी प्रक्रिया अगले तीन महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

अमित शाह ने उन अटकलों को खारिज कर दिया, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट में खुद शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल किए जाने की बात कही जा रही थी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रस्तावित ट्रस्ट में भाजपा का कोई नेता शामिल नहीं होगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि मंदिर के निर्माण में सरकारी धन का उपयोग कतई नहीं किया जाएगा।

सोमवार को झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान चार महीने के भीतर गगनचुंबी राम मंदिर बनाने के दावे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय समय सीमा से एक महीना अधिक बोला है। उनके अनुसार, अदालत के फैसले के मुताबिक राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने और मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम समुदाय को पांच एकड़ जमीन देने को लेकर काम चल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि तय समय सीमा के भीतर ही यह कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। ध्यान देने की बात है कि नौ नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मिति से अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने और मस्जिद के लिए अलग पांच एकड़ जमीन देने का फैसला दिया था। इस फैसले के खिलाफ दाखिल सभी पुनर्विचार याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते खारिज कर दिया था।

राहुल फंसे विवादों में, तब कांग्रेस ने उतारा प्रियंका को

राज्य ब्यूरो, रांची

- मेक इन इंडिया को रेप इन इंडिया बताने पर हुई थी फजीहत, चौतरफा हुआ विरोध, आयोग को शिकायत
- प्रियंका गांधी वाड्रा अंतिम चरण के प्रचार अभियान में उतरेंगी चुनाव मैदान में

प्रियंका गांधी वाड्रा फाइल

झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुकाबले प्रचार अभियान में पिछड़ी कांग्रेस ने अपना अंतिम दांव प्रियंका गांधी वाड्रा पर लगाया है। दरअसल, राहुल की अपेक्षा प्रियंका की ज्यादा मांग यहां आरंभ से थी, लेकिन कांग्रेसियों की दिल्ली दरबार में लगाई गई गुहार काम नहीं आई। राहुल गांधी भी दूसरे चरण में सक्रिय हुए, लेकिन ज्यादा प्रभाव जमाने में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उनकी अपेक्षा भाजपा की सभाओं में ज्यादा भीड़ उमड़ी।

राहुल गांधी ने अलग-अलग स्थानों पर पांच सभाएं की हैं। संताल में उनकी पिछली सभा विवादों में फंस गई। उन्होंने 'मेक इन इंडिया' को 'रेप इन इंडिया' बताकर फजीहत मोल ले ली। उनके इस बयान का न सिर्फ चौतरफा विरोध हुआ, बल्कि कांग्रेस समेत विपक्षी महागठबंधन को आभास हुआ कि इसका नुकसान हो सकता है। उधर, भाजपा ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की तो उपायुक्तों से रिपोर्ट तलब की गई है। इस बीच, फजीहत से बचने के लिए राहुल गांधी की पांचवें चरण में सभाएं नहीं की गईं, अलबत्ता प्रियंका को उनकी जगह उतारने का आग्रह आलाकमान से किया गया। हालांकि, कांग्रेस नेता प्रियंका की दो सभाएं कराना चाहते थे, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के स्टार प्रचारकों का मुकाबला किया जा सके, लेकिन अनुमति एक ही सभा की मिली। प्रियंका पाकुड़ से कांग्रेस प्रत्याशी आलमगीर आलम के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगी। उनकी सभा बरहरवा प्रखंड के श्रीकुंड में होगी। मंच पर उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी रहेंगे। संताल परगना में हावी होने की कोशिश में जुटा विपक्षी गठबंधन इसी बहाने भाजपा की काट में जुटा है। अंतिम चरण में यहां की 16 सीटों पर 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे।

अराजकता के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जिम्मेदार : योगी

जागरण संवाददाता, देवघर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को झारखंड के जामताड़ा के नाला फुटबॉल मैदान व देवघर के सारठ स्थित हरिपुर मैदान में चुनावी सभाएं कीं। यहां अयोध्या में राममंदिर निर्माण का संकल्प दोहराते हुए देश में अराजकता और अलगावाद के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि अयोध्या में राममंदिर का निर्माण होने वाला है। हम अयोध्या से आमंत्रण लेकर आपके पास आए हैं। भारत में रामराज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उसे विकास के रास्ते पर बढ़ाया। नागरिकता संशोधन कानून से विश्व में भारत का मान बढ़ा है। कांग्रेस, आरजेडी व जेएमएम इसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं गिनाईं और कहा कि इससे आमजन व गरीब का कल्याण हुआ है। देश में अब घुसपैठियों के लिए जगह नहीं है। भरोसा दिलाया कि देश से आंतकवाद और नक्सलवाद जड़ से खत्म होगा। हमने देश में एक प्रधान एक विधान का सपना साकार किया है। देश की सुरक्षा से अब कोई समझौता नहीं होगा।

चुनावी सभा को संबोधित करते योगी आदित्यनाथ। जागरण

ऐश्वर्या को कितना मिलेगा गुजारा भत्ता, आज तय करेगा कोर्ट

जागरण संवाददाता, पटना

तेजप्रताप यादव फाइल

ऐश्वर्या फाइल

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या को प्रति महीने कितना गुजारा भत्ता मिलेगा, बुधवार को कोर्ट सुनवाई के दौरान यह तय कर सकता है। पटना के परिवार न्यायालय में तेजप्रताप यादव की ओर से पत्नी ऐश्वर्या से तलाक लेने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। सूत्रों की मानें तो मेंटेनेंस की मांग को लेकर ऐश्वर्या ने कोर्ट में पहल आवेदन दिया था। इस पर लंबी सुनवाई चली। तेजप्रताप की ओर से आय से संबंधित वित्तीय वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न की प्रति मंगलवार को उनके वकील की ओर से अदालत में शपथ पत्र के साथ दी गई है। आयकर रिटर्न में तेजप्रताप की आय सालाना करीब 10 लाख रुपये बताई गई है। मामले में मंगलवार को पारिवारिक न्यायालय में ऐश्वर्या और तेजप्रताप उपस्थित नहीं हुए। ऐश्वर्या की ओर से उनके पिता पूर्व मंत्री चंद्रिका राय अदालत में उपस्थित हुए। तेज प्रताप की ओर से उनके कुछ स्वजन सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे।

इस मामले में महिला आयोग की जांच रिपोर्ट भी अदालत को सौंप दी गई है। सूत्र बताते हैं कि राबड़ी देवी और बहू ऐश्वर्या के बीच ससुराल में क्या-क्या विवाद हुआ, उसका रिपोर्ट में विस्तृत ढंग से जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, मामला घरेलू हिंसा का है। अदालत में पेन ड्राइव भी दी गई है जिसमें ऐश्वर्या की ससुराल के कुछ फोटो हैं। पेन ड्राइव का प्रिंट निकालकर अदालत में पेश करने को कहा गया है।

शिकंजा

जन्म प्रमाणपत्र, दो-दो पासपोर्ट व पैन कार्ड बनवाने के मामलों में भी हाई कोर्ट के आदेश का पड़ेगा असर

अभी और भी हैं सांसद आजम खां की मुश्किलें

मुस्लेमीन, रामपुर

आजम खां फाइल

अब्दुल्ला आजम फाइल

सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दरअसल, दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में अब्दुल्ला के साथ ही आजम और उनकी विधायक पत्नी तजीन फात्मा के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, जिसका मुकदमा अदालत में विचराधीन है।

अब्दुल्ला ने जन्मतिथि सही ठहराने के चक्कर में दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड भी बनवाए। इन दोनों मामले में भी उनके खिलाफ थानों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इस तरह इन मुकदमों पर हाई कोर्ट के फैसले का भी असर पड़ सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट अब्दुल्ला की उम्र के विवाद को सही ठहरा चुका है।

अब्दुल्ला की उम्र का विवाद उस समय सामने आया था, जब वह 2017 में विधानसभा चुनाव लड़े। नामांकन प्रक्रिया के दौरान ही बसपा प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने आपत्ति दाखिल की थी। उनकी ओर से आपत्ति दाखिल कराने में शामिल रहे बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मुस्तफा अहमद का कहना है कि निर्वाचन अधिकारी अगर ईमानदारी से फैसला लेते तो नामांकन पत्र चुनाव के दौरान निरस्त हो जाता। चुनाव के बाद नवेद मियां ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अब कोर्ट ने सही फैसला दिया है।

फर्जीवाड़े के चार मुकदमे : अब्दुल्ला के खिलाफ दो-दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने, दो-दो पासपोर्ट बनवाने और दो-दो पैन कार्ड बनवाने के चार मुकदमे लंबित हैं। इनमें तीन मुकदमे भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराए हैं। उनका आरोप है कि अब्दुल्ला ने दो जन्म प्रमाणपत्र बनवा रखे हैं। एक जन्म प्रमाणपत्र उन्होंने रामपुर नगर पालिका से बनवाया है, जिसमें उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्शाई गई है। वहीं, लखनऊ के अस्पताल से भी एक जन्म प्रमाणपत्र बनवा लिया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 है। बाद में पासपोर्ट और पैन कार्ड में उम्र ठीक कराने के लिए भी दूसरा पासपोर्ट और दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया, जिसमें दूसरी जन्मतिथि है। आकाश ने एक मुकदमा दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने का दर्ज कराया है। उसमें अब्दुल्ला के साथ ही आजम और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को भी नामजद किया है। आरोप लगाया है कि अब्दुल्ला का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आजम और उनकी पत्नी ने जो शपथ पत्र दिया है उसमें झूठ बोला है।

वरिष्ठ अधिवक्ता शौकत अली खान का कहना है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसका असर इन सभी मामलों पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये भी उम्र के विवाद से जुड़े हैं। हाई कोर्ट अब्दुल्ला की उम्र के मामले को फर्जी मान चुका है। स्थानीय अदालतों में चल रहे मुकदमे भी धोखाधड़ी से ही संबंधित हैं। उनका कहना है कि दस्तावेजी सुबूत मजबूत हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलने की उम्मीद कम ही है।

चुनाव आयोग अब्दुल्ला पर 10 साल के लिए लगाए प्रतिबंध : नवेद

हाई कोर्ट के फैसले के बाद मंगलवार को पूर्व मंत्री (बसपा सरकार) नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजकर अब्दुल्ला आजम पर 10 साल के लिए प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल

बसपा सरकार में मंत्री रहे नवाब काजिम अली खां की ओर से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल कर दी गई। उनके बेटे नवाबजादा हैदर अली खां उर्फ हमजा मियां ने बताया कि हाई कोर्ट के अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद करने के फैसले का पालन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी की जाएगी। इसके लिए याचिकाकर्ता नवेद मियां की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केविएट लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में यह साबित हो चुका है कि अब्दुल्ला ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ा था।

विधायकी रद होने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अब्दुल्ला आजम

नई दिल्ली, प्रेट्र : समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां ने विधायकी रद किए जाने संबंधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला की विधायकी रद कर दी थी कि वर्ष 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी। वह 11 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित स्वार से सपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे।

हाई कोर्ट ने सोमवार को स्वार विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खां की याचिका पर सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला के चयन को रद कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब अब्दुल्ला ने नामांकन पत्र दाखिल किया था तब वह 25 साल के नहीं थे।

2 लाख शरणार्थियों के भारत में होने की बात संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की वर्ष 2017 की रिपोर्ट में कही गई थी। इस तरह भारत शरणार्थियों को शरण देने वाला 25वां बड़ा देश बना।

सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं करता कोई भुगतान

देश भर में आए दिन कई प्रदर्शन होते हैं, जिनमें से बहुत से उग्र हो उठते हैं। इसका परिणाम हमारे सामने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के रूप में सामने आता है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में देश के विभिन्न इलाकों में उग्र प्रदर्शन हुए हैं। कई जगहों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। हालांकि

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को किसी बात का डर नहीं होता है। इसका कारण ज्यादातर मामलों में दोषी को सजा नहीं मिल पाना है।

बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने फूंकी रेल और हावड़ा में जलाई सरकारी बसें। ● प्रेट्र

बंगाल और दिल्ली में नहीं छोड़ी कोई कोर कसर

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के हालिया मामले सीएए के बाद सामने आए हैं। ताजा उदाहरण दिल्ली का है। जहां पर रविवार को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पुलिस-जनता आमने-सामने हो गए। इस दौरान डीटीसी की बसों, निजी वाहनों और पुलिस की मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया या उनमें जमकर तोड़फोड़ की गई। वहीं बंगाल में भी प्रदर्शनकारियों ने इस कानून के विरोध में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो आसाम भी अछूता नहीं रहा। यहां तीन रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनल, एक पोस्ट ऑफिस और एक बैंक के साथ वाहनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया।

अपनी संपत्ति, अपना नुकसान

सार्वजनिक संपत्ति को लेकर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो लोग अपने खून-पसीने की कमाई से सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण में अहम योगदान देते हैं, वही इसे नुकसान भी पहुंचाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति और वाहनों के विनाश के लिए कोई भी भुगतान नहीं करता है।

सर्वाधिक नुकसान उठाने वाले राज्य

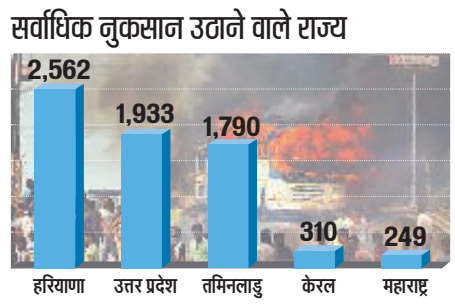

दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने कैब के विरोध में की आगजनी। ● प्रेट्र

दोषसिद्धि की कम दर

सार्वजनिक संपत्ति तोड़फोड़ के मामलों में दोषसिद्धि की दर 29 .8 फीसद है। यह बताता है कि आखिर क्यों सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले नुकसान के लिए कोई भी भुगतान नहीं करता है। 2017 के आखिर तक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 14 हजार से ज्यादा मामले विभिन्न अदालतों में लंबित थे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिनलाडु ऐसे राज्य हैं, जहां पर इस तरह के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इन तीनों राज्यों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कुल 6 हजार मामले सामने आए हैं, जो चिंताजनक हैं।

यह कहता है कानून

सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून 1984 के अनुसार, जो कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को अपने किसी भी कृत्य द्वारा नुकसान पहुंचाता है, उसे पांच साल तक की सजा और जुर्माने देना पड़ सकता है। सार्वजनिक संपत्ति के रूप में ऐसे भवन, प्रतिष्ठान अथवा अन्य संपत्ति को माना गया है जिसका उपयोग जल, प्रकाश, शक्ति या ऊर्जा उत्पादन या वितरण में किया जाता है। इसके साथ ही कोई तेल प्रतिष्ठान, सीवेरज, खान या कारखाना या फिर कोई लोक परिवहन या दूरसंचार साधन या उसके उपयोग के लिए कोई भवन, प्रतिष्ठान या संपत्ति भी सार्वजनिक संपत्ति में आते हैं। वहीं अग्नि अथवा किसी विस्फोटक पदार्थ से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को दस वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

जितना चाहें कर लें नागरिकता संशोधन कानून का विरोध : शाह

किया आश्वस्त ▶ केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, कोई भी भारतीय अपनी नागरिकता नहीं खोएगा

विरोध के बावजूद उत्पीड़ित लोगों की नागरिकता सुनिश्चित करेगी सरकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विरोधी जितना चाहें कानून का विरोध कर सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता हासिल हो और वे देश में सम्मान के साथ जी सकें।

अमित शाह ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर किसी को भी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट पर सारी जानकारी उपलब्ध है। देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून नेहरू-लियाकत समझौते का हिस्सा है, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू किया है और शरणार्थियों को देश की नागरिकता देने का काम किया है। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अपील की कि वे पहले कानून के बारे में अध्ययन करें फिर अपनी राय बनाएं। कानून में नागरिकता देने की बात कही गई है। यह कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं बना है। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों से अन्य देशों से आए हिंदू, सिख और अन्य बिना किसी नौकरी और जमीन के रह रहे हैं। मैं राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि उनकी स्थिति देखें कि वे किस तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि मुस्लिम भाइयों-बहनों को डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी भारतीय नागरिकता खोने नहीं जा रहा है।

नई दिल्ली में मंगलवार को भारत वंदना पार्क के विकास कार्य के शिलान्यास अवसर पर संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

सिर्फ तोड़फोड़-आगजनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

मुंबई, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री ने इंडिया इकोनॉमिक कांक्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई सिर्फ उन लोगों के खिलाफ की जा रही है जो विरोध प्रदर्शनों के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल थे।

पंजाब में नागरिकता कानून के समर्थन में भाजपा का प्रदर्शन

- पंजाब में कानून लागू न करने के एलान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला
- अमृतसर में पुतले की भड़की आग से बाल-बाल बचे भाजपा नेता और मीडियाकर्मी

जेएनएन, जालंधर

भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका और नारेबाजी की। उल्लेखनीय है कि कैप्टन ने बीते सप्ताह घोषणा की थी कि पंजाब में वह इस कानून को लागू नहीं करेंगे।

अमृतसर में प्रदर्शन में शामिल पूर्व सेहत मंत्री डॉ. बलदेव राज चावला ने कहा कि अगर कैप्टन सरकार ने इस कानून को पंजाब में लागू नहीं किया तो शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं कि आने वाले समय में इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। भाजपा हमेशा जनता के हकों की लड़ाई लड़ती आई है। अब भी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। दूसरी तरफ भाजपा नेताओं द्वारा फूंके जाने वाले पुतले पर डाले गए पेट्रोल ने इतनी तेज आग पकड़ी कि मीडियाकर्मियों और नेताओं ने भागकर खुद को बचाया।

जालंधर में भाजपा नेताओं ने पटेल चौक में पंजाब सरकार का पुतला फूंका। जिला प्रधान रमन पब्बी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार पर देश हित की अनदेखी करके राजनीति करने का आरोप लगाया और इसकी निंदा की। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वह कांग्रेस के बहकावे में न आए। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक केडी भंडारी व उनके समर्थक नहीं पहुंचे।

हिंदू न्याय पीठ ने निकाली धन्यवाद रैली

श्री हिंदू न्याय पीठ ने नागरिकता संशोधन कानून को ऐतिहासिक बताते हुए इसका समर्थन किया है। लुधियाना में पीठ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को धन्यवाद रैली निकाली। प्रवक्ता प्रवीण डंग ने कहा कि इस कानून के माध्यम से भारत सरकार ने नागरिकता दी है, किसी की छीनी नहीं है। लेकिन कुछ असामाजिक लोग देश में अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए बिना सोचे-समझे इस कानून का विरोध कर रहे हैं।

'भोजन और पोशाक निजी मर्जी, नहीं हो सकती प्रदर्शनकारियों की पहचान'

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मंगलवार को कोलकाता में मार्च के दौरान समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करतीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। साथ में उन्हें भीड़ की तरफ बढ़ने से रोकतीं तृणमूल सांसद मिमी चक्रवर्ती। प्रेट्र

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार कहा-आग लगाएंगे तो सभी जलेंगे

झारखंड के दुमका में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान की पृष्ठभूमि में मंगलवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन पर निशाना साधा। कहा कि कपड़े प्रदर्शनकारियों की पहचान को उजागर नहीं करते क्योंकि लोग अपने मन मुताबिक भोजन करते हैं और पोशाक पहनते हैं।

नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ सोमवार के बाद मंगलवार को भी तृणमूल प्रमुख सड़क पर उतरीं। विरोध जुलूस की शुरुआत जादवपुर 8 बी बस स्टैंड से हुई। पीएम मोदी का नाम लिए बगैर ममता ने कहा, पोशाक देखकर क्या आंदोलनकारियों की पहचान की जा सकती है। टोपी पहनने का मतलब यह नहीं है कि आप मुस्लिम हैं। क्या आप मुझे और मेरे कपड़े देखकर बता सकते हैं कि मैं कौन हूं। आग लगाएंगे तो राम, रहीम सभी जलेंगे। देश, बंगाल सब जगह विभाजन की राजनीति लेकिन मैं देश को विभाजित नहीं होने दूंगी।

केंद्र पर लगाया राज्य में रेल सेवा बंद करने का आरोप : ममता ने कहा कि केंद्र ने राज्य में हिंसा की एक या दो छोटी घटनाओं पर रेलवे सेवाएं बंद कर दी हैं। हमने बवाल में शामिल 600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। लोगों से अपील है कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए।

हमारा स्लोगन 'नो सीएबी, नो एनआरसी'

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा स्लोगन है नो सीएबी, नो एनआरसी। कार्यकर्ता इसी नारे के साथ तख्तियां लेकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक इस असंवैधाकि कानून को वापस नहीं लिया जाता, हमारा विरोध जारी रहेगा। कहा कि बंगाल में एनआरसी के आतंक से 30 लोगों ने खुदकशी कर ली है। असम में एनआरसी सूची से करीब 13 लाख लोगों को बाहर रखा गया है, 100 लोगों ने खुदकशी की है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।

नागरिकता कानून में संशोधन का एनआरसी से कोई लेना-देना नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून का देश में प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की कवायद से कोई लेना-देना नहीं है। प्रसाद ने यह भी कहा कि कानून किसी धर्म के भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। उन्होंने एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का एनआरसी से कोई लेना-देना नहीं है।' प्रसाद ने कहा कि एनआरसी को देशभर में लागू करने के संबंध में प्रस्तावित कानून का मसौदा जब तैयार हो जाएगा, तब इस पर विचार-विमर्श किया जाएगा और यह जनता के सामने आएगा। उन्होंने कहा कि एनआरसी को संशोधित नागरिकता कानून से जोड़ने का कोई सवाल नहीं है। प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि लोकतंत्र में बातचीत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे शांति की अपील करता हूं। लेकिन हम उन लोगों को नहीं समझा सकते जो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए हर मुद्दे में कूद जाते हैं। वामपंथियों और माओवादियों को तो मोदी की आलोचना करनी ही है, चाहे जो हो।

जेएनयू, एएमयू में तैयार हो रहे जिहादी : प्राची

जासं, बरेली : साध्वी प्राची ने आरोप लगाया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं दी जा रही बल्कि जिहादी तैयार किए जा रहे हैं। मांग उठाई कि इन संस्थानों को बंद कर दिया जाना चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे विरोध पर सर्किट हाउस में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि सरकार के अच्छे काम को गलत ठहराना किसी सूरत में उचित नहीं है। कहा कि नेहरू खानदान की तो विरोध करने की आदत हो गई है।

उद्धव ने जलियांवाला बाग नरसंहार से की जामिया कार्रवाई की तुलना

नागपुर, प्रेट्र : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की तुलना जलियांवाला बाग नरसंहार से की। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उद्धव ने कहा, 'जानबूझकर समाज में अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने जिस तरह परिसर में जबरन घुसकर छात्रों पर फायरिंग की, यह जलियांवाला बाग नरसंहार जैसा लगता है।' उन्होंने आगे कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से देश के युवाओं के दिमाग में खौफ पैदा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, 'मुझे लगता है कि किसी देश का युवा अगर अशांत है तो वह देश स्थिर नहीं रह सकता। मैं केंद्र से कहना चाहूंगा कि इस देश के युवाओं को अस्थिर न करें।' उद्धव ने कहा, 'युवा देश का भविष्य हैं और उनमें काफी क्षमताएं हैं। युवा बम की तरह होते हैं जिन्हें भड़काया नहीं जाना चाहिए। यह मेरा प्रधानमंत्री से विनम्र अनुरोध है।' नागरिकता संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शनों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में अभी तक शांति है।

राष्ट्रपति से मिले विपक्षी दल, नागरिकता कानून निरस्त करने की मांग

- सोनिया बोलीं, मोदी सरकार दबा रही जनता की आवाज
- 14 राजनीतिक दलों में बसपा-शिवसेना शामिल नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच 14 विपक्षी दलों ने मंगलवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोनिया गांधी की अगुआई में राजनीतिक दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मांग की कि वह सरकार से इस कानून को वापस लेने के लिए कहें। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को संसद से विधेयक पारित होने के बाद से देशभर में तनावपूर्ण हालात से भी अवगत कराया। खासकर पूर्वोत्तर और जामिया विश्वविद्यालय की घटनाओं को सामने रखते हुए पूरे मामले में दखल देने की मांग की।

खास बात यह रही कि बसपा विपक्ष की इस पूरी गोलबंदी से अलग रही। बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने संसद भवन परिसर के बाहर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने के लिए अलग से समय मांगा है। वहीं शिवसेना भी इस पूरे परिदृश्य में कहीं भी नजर नहीं आई।

कड़ाके की ठंड में राष्ट्रपति से मिलकर निकलीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जनता की आवाज दबाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जामिया विश्वविद्यालय की घटना इसका एक उदाहरण है जहां शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर पीटा। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि राष्ट्रपति के सामने सारी बात रखी गई है। उनसे मांग की गई है कि वह सरकार से इस असंवैधानिक कानून को वापस लेने के लिए कहें। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा, हमने राष्ट्रपति को बताया है कि हमने संसद के भीतर चर्चा के दौरान जो आशंका जाहिर की थी, वह अब सच साबित हो रही है।

पूर्वोत्तर पूरे देश से कट गया है। वैसे भी पाकिस्तान यही चाहता था। वह चाहता था, जैसे उसके टुकड़े किए गए वैसे ही भारत के टुकड़े हों जो अब यह सरकार मौका दे रही है। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह कानून बांटने वाला है। सरकार को देश और अपने नागरिकों की कोई चिंता नहीं है। हमने सरकार को आगाह किया था कि यह देश इस कानून को खारिज कर देगा और वहीं हुआ। देश के सभी शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में इसे लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने सरकार को पुलिसिया सरकार की संज्ञा दी। राष्ट्रपति से मुलाकात करने वालों में राजद, भाकपा, माकपा, नेशनल कांफ्रेस और कई अन्य छोटे-छोटे दलों के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

पाक से हमदर्दी खुद दिखाते हैं और आरोप हम पर लगाते हैं : सिब्बल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनौती का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मैं चुनौती देता हूं, मेरे साथ आएं और डिबेट करें। हम बताएंगे कि नवाज शरीफ को गले किसने लगाया था और हमने क्या किया था। हम बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने आतंकियों को रिहा किया था और किस तरह से ये पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते थे। पाकिस्तान से हमदर्दी ये लोग करते हैं और आरोप हम पर लगाते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था, कांग्रेस में हिम्मत है तो वह घोषणा करें कि पाक के हर नागरिक को नागरिकता देंगे।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद बाहर आते, दाएं से, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, माकपा नेता सीताराम येचुरी, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, द्रमुक नेता टीआर बालू, भाकपा नेता ए. राजा और कांग्रेस नेता एके एंटनी। प्रेट्र

राजद ने सुप्रीम कोर्ट में सीएए की वैधता को चुनौती दी

नई दिल्ली, प्रेट्र : राजद नेता मनोज झा ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ है। झा ने अपनी याचिका में कहा कि यह कानून धर्मनिरपेक्षतावाद का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें धार्मिक समूहों के खिलाफ 'भेदभाव की दुर्भावना' के साथ नागरिकता मुहैया कराने में कुछ लोगों को बाहर रखा गया है। झा ने वकील फौजिया शकील के जरिये दायर याचिका में कहा है, 'भारतीय नागरिकता का चरित्र धर्मनिरपेक्ष है। धर्म के आधार पर नागरिकता देते हुए लोगों के बीच भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। यह संविधान के मूल सिद्धांत और संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा की घोर उपेक्षा है।' मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की है। उसने कहा है कि यह कानून संविधान के बुनियादी मूल्यों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।

नसीहत

सीएए पर झूठ फैलाने में जुटे पाक पीएम इमरान व पाक संसद को भारत की नसीहत, सोमवार को पाकिस्तानी नेशनल एसेंबली में पास हुआ था नागरिकता संशोधन कानून पर निंदा प्रस्ताव

हमारे जैसे अधिकार अपने अल्पसंख्यकों को दे पाकिस्तान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून पर कभी अपने संसद में प्रस्ताव पारित करके तो कभी अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसे उठाने की कोशिश में जुटे पड़ोसी देश पाकिस्तान को भारत ने एक भली सलाह दी है। भारत ने कहा है कि उसे अपने यहां के अल्पसंख्यकों को भी जो अधिकार भारत के अल्पसंख्यकों को मिले हैं, वैसे ही अधिकार देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस सलाह के साथ भारत ने पाकिस्तान को इस बात के लिए लताड़ भी लगाई है कि उसके जिस संसद में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव वाला विधेयक पारित होता है वहां दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों के हालात पर झूठ फैलाया जा रहा है।

सोमवार को पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। जबकि जेनेवा में फर्स्ट ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और

रवीश कुमार। फाइल

सीएए के संदर्भ में कहा कि दक्षिण एशिया में एक बड़े शरणार्थी संकट पैदा होने की स्थिति बन रही है। खान ने कहा कि अगर भारत में दो-तीन फीसद मुस्लिम आबादी भी अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाती है तो पाकिस्तान और शरणार्थियों को पनाह देने में सक्षम नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो यह न केवल शरणार्थी संकट होगा बल्कि दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच संघर्ष का कारण भी बन सकता है। उन्होंने विश्व बिरादरी से भारत पर दबाव बनाने की अपील करते हुए कहा है कि अगर भारत को ऐसे कदम उठाने से नहीं रोका गया तो यह आने वाले दिनों में कई दूसरी तरह की कठिनाइयों को पैदा कर सकता है।

भारत ने पाक पीएम इमरान खान और वहां के संसद में पारित प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'पीएम इमरान खान ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर झूठा राग अलापा है। पिछले 72 वर्षों में पाकिस्तान ने बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से अपने यहां के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया। उन्हें भारत भागने के लिए मजबूर किया है। पाकिस्तान को इन अल्पसंख्यकों व मुस्लिम समुदाय के दूसरे वर्गों को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।'

इस बयान के अलावा विदेश मंत्रालय ने एक दूसरी विस्तृत विज्ञप्ति जारी की है जिसमें पाकिस्तान के संसद में पारित प्रस्ताव पर भारत ने इसे सीधे तौर पर अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का दुष्प्रयास करार दिया है। साथ ही कहा कि भारत के सभी नागरिकों को उनकी आस्था के निरपेक्ष भारतीय संविधान के तहत समान अधिकार प्राप्त हैं। साथ ही पाकिस्तान से आग्रह किया कि वे भी इसी प्रकार के आदर्शों को आत्मसात करे।

इसमें आगे कहा गया कि यह प्रस्ताव जम्मू व कश्मीर व लद्दाख के मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ से चलाये जा रहे भ्रामक अभियान का ही हिस्सा है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत में चलाई जा रही सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान के सतत समर्थन व सहयोग को न्यायोचित ठहराना है। हमें विश्वास है कि पाकिस्तान अपने ऐसे दुष्प्रयासों में विफल होगा।' भारत ने यह भी कहा है कि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति किए जा रहे दुर्भावनापूर्ण व्यवहार व उत्पीड़न से ध्यान हटाने के लिए एक निष्फल प्रयास किया गया है। पाकिस्तान में इन अल्पसंख्यकों चाहे वे हिंदू हों या ईसाई या सिख या कोई अन्य समुदाय की मौजूदा जनसंख्या ही उनकी वास्तविक स्थिति को बयान कर रही है। इस प्रस्ताव में नागरिकता संशोधन कानून, 2019 के उद्देश्यों के प्रति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है।

मतभेद भूलकर साथ काम करने का है समय : जगदीप धनखड़

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- बंगाल के राज्यपाल ने कहा, राजभवन और सरकार लोकतंत्र की सफलता के लिए करे काम

दो सप्ताह में दूसरी बार बंगाल विधानसभा पहुंचे राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि लोकतंत्र को सफल बनाने के उद्देश्य से राजभवन और राज्य सरकार के लिए अपने मतभेद दरकिनार कर साथ काम करने का समय आ गया है। विधानसभा का भ्रमण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार और राज्यपाल कार्यालय को राज्य के कल्याण के लिए एक साथ काम करने की जरूरत है। कहा कि लोकतंत्र को सफल बनाने में बंगाल का अहम योगदान रहा है। नागरिकता संशोधन कानून पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि अब यह कानून है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि उनके बुलावे पर मुख्यमंत्री उनसे मिलने जरूर आएंगी।

गौरतलब है कि इससे पहले जब राज्यपाल पांच दिसंबर को विधानसभा पहुंचे थे तो गेट नंबर तीन पर ताला लटका हुआ था और उन्हें काफी देर बाद दो नंबर गेट से अंदर जाना पड़ा। दरअसल, तब बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था लेकिन विधानसभा स्पीकर ने यह कहते हुए सदन की कार्यवाही दो दिनों के लिए स्थगित कर दी थी कि राज्यपाल ने विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया है और सदन में चर्चा का कोई मुद्दा ही नहीं बचा है।

हालांकि मंगलवार को जब राज्यपाल विधानसभा पहुंचे तो शहर से बाहर रहने के कारण विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी तो मौजूद नहीं थे लेकिन विस संयुक्त सचिव पार्थ विश्वास ने उनका स्वागत किया और उन्होंने गेट नंबर तीन से विस में प्रवेश किया।

42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हालात शांतिपूर्ण हैं और परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ली जा रही हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थिति बिगड़ी है। सरकार के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 18 दिसंबर 2019

हम क्यों सुनें, याचिकाएं लेकर हाई कोर्ट जाएं

दखल से इन्कार ▸ सीएए विरोध– प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया कोई आदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शनों, हिंसा और फिर पुलिस कार्रवाई के मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह कहते हुए इन्कार कर दिया, 'हम इन याचिकाओं को क्यों सुनें। आप लोग हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते?' इतना ही नहीं कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने का भी कोई आदेश नहीं दिया और न ही मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटनाएं अलग अलग जगहों की हैं ऐसे में एक जांच कमेटी गठित करना ठीक नहीं रहेगा। याचिकाकर्ता संबंधित हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट पक्षकारों और सरकार को सुनकर जांच कमेटी गठित करने के बारे में उचित आदेश दे सकते हैं।

ये आदेश प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में हुए प्रदर्शन और हिंसा का मामला उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए।

इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंद्रा जयसिंह और कोलिन गोंसाल्विस ने कोर्ट से कहा कि इस मामले के दो मुख्य बिंदु हैं। पहला यह की पुलिस विश्वविद्यालय अथॉरिटी की इजाजत के बगैर विश्वविद्यालय में घुसी और फिर उसने छात्रों पर हिंसक कार्रवाई की। छात्रों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात कि घायल छात्रों को चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जयसिंह ने कहा कि नियम के मुताबिक, विश्वविद्यालय प्रशासन की इजाजत के बगैर पुलिस अंदर नहीं घुस सकती।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

सख्त रुख

- कोई पुलिस पर पत्थरबाजी करेगा तो क्या वह केस दर्ज नहीं करेगी : कोर्ट
- सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कमेटी भी गठित नहीं की

'यहां कोई शोर मचाने का मैच नहीं चल रहा'
सुनवाई के दौरान जब कुछ वकील तेज आवाज में बोलने लगे तो कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यहां चिल्लाइए मत, यहां कोई शोर मचाने का मैच नहीं चल रहा है।

सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों का खंडन किया। मेहता ने कहा कि किसी भी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया है। एएमयू के दो छात्र घायल हुए हैं जिनका वहीं के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो छात्र घायल हुए हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेहता ने यह भी कहा कि एएमयू के रजिस्ट्रार ने पुलिस को बुलाया था क्योंकि अफवाह के कारण वहां की स्थिति खराब हो रही थी। पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं हैं। कोर्ट में दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, कोर्ट उनसे पूछ सकता है।

इंद्रा जयसिंह ने कहा कि कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि शांति कायम रहनी चाहिए। अगर शांति बनी रहती है तो छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। पुलिस को केस दर्ज करने से रोका जाए। इन दलीलों पर पीठ ने कहा कि अगर कोई पुलिस पर पत्थरबाजी करेगा तो क्या होगा। क्या पुलिस केस दर्ज नहीं करेगी। कोलिन गोंसाल्विस ने कहा कि जिन छात्रों को चोट लगी है उन्हें उचित इलाज मुहैया नहीं हो रहा है। उन्होंने मांग की कि कोर्ट एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाए जो एएमयू जाकर स्थिति देखे और जांच करे। इस पर पीठ ने कहा, केस देखते हुए उन्हें लगता है कि यह बहुत व्यापक मामला है। अलग-अलग जगह का मामला है, एक जांच कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा। इंद्रा जयसिंह ने कहा कि कोर्ट ने पहले भी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जांच कमेटी बनाई है, जैसे हैदराबाद मुठभेड़ मामले में बनाई गई है वैसी ही यहां बनाई जाए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वहां सिर्फ एक राज्य का मुद्दा था, लेकिन यहां घटनाएं अलग-अलग राज्यों की हैं। सभी राज्यों में हाई कोर्ट हैं। उन्हें भरोसा है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मामले की जांच के लिए जांच कमेटी बनाएंगे।

हाई कोर्ट मामले की जांच करने के बाद गिरफ्तारी और इलाज के बारे में भी उचित आदेश देंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे संबंधित हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट याचिकाकर्ताओं और राज्य व केंद्र सरकार को सुनने के बाद उचित आदेश पारित करेंगे। हाई कोर्ट जांच कमेटी भी गठित कर सकते हैं और उसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शामिल कर सकते हैं।

इंद्रा जयसिंह ने कोर्ट से कहा कि फिलहाल वह पुलिस कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दे, लेकिन कोर्ट ने उस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया। पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए, अखबारों में छपी खबरों पर विचार करने से भी इन्कार कर दिया। पीठ ने कहा, 'हम अखबार पढ़ने नहीं जा रहे। न्यायिक फैसलों के लिए हम अखबार की खबरों पर भरोसा नहीं करेंगे।'

उपराष्ट्रपति ने कहा, भारतीयों की नागरिकता नहीं छीनेगा सीएए

नई दिल्ली, प्रेट्र : संशोधित नागरिकता कानून धार्मिक रूप से पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है। यह किसी भी धर्म के भारतीय से उसकी नागरिकता नहीं छीनेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को बांग्लादेश के प्रशिक्षु राजनयिकों से यह कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत, बांग्लादेश पर म्यांमार के रखाइन प्रांत से लाखों की संख्या में आए शरणार्थियों के कारण पड़े बोझ से अवगत है। उन्होंने इन विस्थापितों के प्रति मानवीय भाव प्रदर्शित करने के लिए ढाका की सराहना भी की।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि विस्थापित रोहिंग्या को वापस म्यांमार भेजने में अपने द्विपक्षीय प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन को बांग्लादेश देख सकता है। नागरिकता (संशोधन) कानून पर उनकी यह टिप्पणी बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन और गृह मंत्री असदुज्जमा खान की भारत यात्रा स्थगित करने के बाद आई है। नायडू ने कहा कि भारत पड़ोस में शांति और स्थिरता के साथ ही सभी पड़ोसियों के साथ दोस्ताना रिश्ते की इच्छा रखता है।

अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं : गडकरी : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों को सीएए से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां वोट बैंक की राजनीति करने के लिए भय और असुरक्षा का वातावरण तैयार करने में जुटी हैं। एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कुछ तत्व कानून के बारे में भ्रम पैदा कर रहे हैं।

किसी भी भारतीय को प्रभावित नहीं करेगा नागरिकता कानून

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की एडवायजरी
- कहा–किसी विदेशी के भारत में निर्वासन से कोई लेना नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून मुसलमानों सहित किसी भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करेगा और संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का लाभ उन्हें मिलता रहेगा। मंत्रालय ने इस मुद्दे पर गलत सूचना फैलाए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान को रोकने की कोशिश के तहत यह कहा है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस कानून का किसी विदेशी के भारत में निर्वासन से कोई लेना-देना नहीं है। इस बीच, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भारतीय के खिलाफ नहीं है और इस कानून को समझना तथा इस बारे में फैलाई जा रही गलत सूचना के खिलाफ जागरूक होना जरूरी है। वहीं, इस विवादित कानून पर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा, 'गलत सूचना फैलाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। नागरिकता (संशोधन) कानून मुसलमान नागरिकों सहित किसी भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करता है।'

दरअसल, इस नए कानून के विरोध में पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सहित देश के कुछ हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। एफएक्यू के जवाब गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि नया कानून सिर्फ हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्मावलंबी विदेशियों के लिए हैं, जो अपने धर्म को लेकर प्रताड़ना का सामना करने के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हैं। मंत्रालय ने कहा कि यह कानून इन तीन देशों सहित किसी अन्य देश से भारत आए मुसलमानों सहित अन्य विदेशियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया कि इस नए कानून का किसी विदेशी के भारत में निर्वासन से कोई लेना-देना नहीं है। गृह मंत्रालय ने कहा कि किसी विदेशी के निर्वासन की प्रक्रिया, चाहे उसका धर्म या देश कुछ भी हो, विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 के मुताबिक क्रियान्वित की जाती है। मंत्रालय ने कहा, 'ये दोनों कानून सभी विदेशियों के भारत में प्रवेश एवं निकास, यहां ठहरने, देश में यहां-वहां आने-जाने को शासित करते हैं, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो। इसलिए, सामान्य निर्वासन प्रक्रिया भारत में रह रहे किसी अवैध विदेशी पर लागू होगी।' यह जवाब इस सवाल पर दिया कि क्या इन देशों से आए मुसलमान आव्रजकों को नए कानून के तहत वापस भेजा जाएगा।

मंत्रालय ने कहा कि किसी विदेशी नागरिक का निर्वासन एक बखूबी विचारित न्यायिक प्रक्रिया है जो स्थानीय पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों की एक उचित जांच पर आधारित है। इसके तहत इस तरह के अवैध विदेशियों का पता लगाया जाता है। मंत्रालय ने कहा, 'यह सुनिश्चित किया गया है कि इस तरह के अवैध विदेशी को उसके देश के दूतावास की ओर से उचित यात्रा दस्तावेज जारी किए गए हों ताकि जब उसे निर्वासित किया जाए तब उसके देश के अधिकारी उपयुक्त रूप से उसकी अगवानी कर सकें।'

गृह मंत्रालय ने कहा कि असम में निर्वासन की प्रक्रिया विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 के तहत ऐसे किसी व्यक्ति के 'विदेशी' निर्धारित होने पर ही होती है। मंत्रालय ने कहा, 'इसके बाद वह निर्वासित किए जाने लायक हो जाता है। इसलिए, इस प्रक्रिया में कुछ भी अपने-आप, मशीनी या भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं होता। राज्य सरकारों और उनके जिला स्तर के अधिकारियों के पास विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा तीन और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 की धारा पांच के तहत केंद्र सरकार की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके तहत वे किसी अवैध विदेशी का पता लगा सकते हैं, उसे हिरासत में ले सकते हैं और उसे निर्वासित कर सकते हैं।'यह सवाल कि क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमान भारतीय नागरिकता कभी नहीं प्राप्त कर सकते, मंत्रालय ने जवाब दिया- 'नहीं'। मंत्रालय ने कहा, 'किसी भी श्रेणी के किसी विदेशी के एक निर्धारित अवधि तक भारत में रहने से उसके भारत की नागरिकता हासिल करने की मौजूदा कानूनी प्रक्रिया (नागरिकता कानून की धारा छह) या पंजीकरण के जरिए (इस कानून की धारा पांच) नागरिकता हासिल करना जारी रहेगा। संशोधित नागरिकता कानून इसमें किसी तरह का संशोधन या बदलाव नहीं करता है।' गृह मंत्रालय ने कहा कि इन तीनों देशों से आए सैकड़ों मुसलमानों को पिछले कुछ बरसों में भारतीय नागरिकता दी गई है। मंत्रालय ने कहा, 'योग्य पाए जाने पर, भविष्य में आने वाले ऐसे सभी प्रवासियों को भी भारतीय नागरिकता मिलेगी, चाहे उनकी संख्या या धर्म कुछ भी क्यों न हो।'मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत-बांग्लादेश सीमा मुद्दे के समाधान के बाद 14,864 बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। उनके 'एनक्लेव' को भारतीय भूक्षेत्र में शामिल किए जाने के बाद ऐसा किया गया था। गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को छोड़ कर किसी अन्य देश में धर्म के आधार पर प्रताड़ित होने वाले हिंदू नये कानून का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे।

भारत सुबूत पेश करे तो हम अपने नागरिकों को लेंगे वापस

जागरण संवाददाता, कोलकाता : राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देश में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के सलाहकार (अंतरराष्ट्रीय मामले) गौहर रिजवी ने कहा कि भारत अगर सुबूत पेश करेगा तो बांग्लादेश वहां गैरकानूनी तरीके से रह रहे अपने किसी भी नागरिक को वापस ले लेगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने भी पिछले रविवार को कहा था कि उनके देश ने भारत को अपने उन नागरिकों की सूची देने का अनुरोध किया है, जो उनके यहां गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं। बांग्लादेश उन्हें वापस लौटने की अनुमति देगा।

सेना के पूर्वी कमान की ओर से आयोजित किए गए विजय दिवस समारोह में शिरकत करने कोलकाता आए रिजवी ने कहा-'मानक पद्धति यह है कि भारत को इस बाबत सुबूत पेश करना होगा। इसे मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध शांतिपूर्ण तरीके से साथ मिलकर रहते हैं। बांग्लादेश ने बहुलवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज के तौर पर नजीर पेश की है। हम अपनी प्रतिबद्धता से कभी नहीं भटके।'

एनआरसी पर रिजवी ने कहा, 'भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें इस मसले पर चिंता नहीं करने को कहा है। भारत के साथ हमारी दोस्ती पिछले 50 वर्षों से है।'

पत्थरों की बारिश के बीच गूंजा 'पूरा हुआ जामिया का बदला'

शुजाउद्दीन, नई दिल्ली

सीएए के विरोध में मंगलवार को नई दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हिंसक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों पर पथराव करते प्रदर्शनकारी। रायटर

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जिस दिन बवाल हुआ था, उसी दिन से जाफराबाद और सीलमपुर में विरोध की आग सुलग रही थी। यही वजह रही कि मंगलवार को प्रदर्शन के हिंसक होते ही लोगों ने छतों से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। साथ ही पुलिसकर्मियों के चोटिल होने पर नारे लगाए और कहा पूरा हो गया जामिया का बदला। पत्थरबाजों ने पहले ही पूरी योजना बना रखी थी। इसके तहत सुबह ही दुकानें भी बंद करा दी थीं। यह अलग बात है कि पुलिस उनके मंसूबों को भांप नहीं सकी।

बच्चों के लिए पुलिसकर्मी बने मसीहा : स्कूल की छुट्टी का समय था, अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई। कई स्कूली बच्चे बुरी तरह से वहां फंस गए, उनके लिए पुलिसकर्मी मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने बच्चों को किसी तरह से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने चार विद्यार्थियों को पत्थरबाजों से बचाया और उन्हें डीसीपी कार्यालय पहुंचाया। बाद में फोन करके बच्चों के अभिभावकों को जानकारी दी। इसके बाद वे अपने बच्चों को ले गए।

आग तक बुझाने नहीं दी: मोटरसाइकिल और मोबाइल शौचालय में पत्थरबाजों ने आग लगा दी। उसे बुझाने के लिए पुलिस ने दमकल की गाड़ी बुलाई, दमकल की गाड़ी मौके तक पहुंची भी। लेकिन पत्थरबाजों ने ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इससे दमकल चालक करीब 500 मीटर तक वापस जाना पड़ा। इसके बाद आग को दमकल से नहीं मिट्टी और दूसरी चीजों से बुझाई गईं।

अफसरों की भी सुनने को तैयार नहीं थे उपद्रवी: गत 15 दिसंबर की शाम जामिया इलाके में जब हिंसक प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ तब संयुक्त आयुक्त दक्षिणी रेंज देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लाउडस्पीकर से बार-बार अपील की थी कि कोई पुलिसकर्मियों पर पत्थर, बोतलें व ट्यूब लाइट न फेंके। लेकिन, उपद्रवी उनकी अपील सुनने को तैयार नहीं थे। अपील के दौरान भी पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। संयुक्त आयुक्त का दो वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने भावुक अपील की थी कि लोग शांति बनाए रखें।

इस तरह की गई थी अपील: मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग बिल्कुल पत्थर न चलाएं। लगातार ये पत्थर हमलोगों पर आ रहे हैं। हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं। आपके बीच जो ये गलत लड़के पहुंचे हुए हैं।

ये लोग जो पत्थर, बम व ट्यूब लाइट फेंक रहे हैं। गाड़ियों को तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि आप लोग बाहर निकलें, आपके नुमाइंदे बाहर आएं और हमसे बात करें। कोई भी ऐसी चीज नहीं करें जिससे इस यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम हो, इस इलाके का नाम खराब हो।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता : मखीजा

नईदुनिया, इंदौर : बलूचिस्तान विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर एडी मखीजा ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उन पर अत्याचार होते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भी भारत के नागरिक थे, लेकिन बंटवारे के बाद वे वहां अल्पसंख्यक हो गए। पाकिस्तान छोड़कर भारत आने के फैसले पर उन्होंने कहा कि सभी अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं। हमारे लिए भारत सुरक्षित था, इसलिए हमने यहां की नागरिकता ली थी।

कानून का विरोध करने वाले सुशांत सिंह 'सावधान इंडिया' से बाहर

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

अभिनेता सुशांत सिंह 'सावधान इंडिया' सीरियल से बाहर हो गए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। टीवी शो से बाहर होने की वजह नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में किए गए उनके ट्वीट् को बताया जा रहा है।

शो से बाहर होने संबंधी सुशांत सिंह के ट्वीट पर एक यूजर ने पूछा कि क्या यह सच बोलने की कीमत है? जवाब में उन्होंने लिखा, 'यह बहुत छोटी कीमत है मेरे दोस्त। हम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जवाब कैसे देंगे।' जब सुशांत से पूछा गया कि क्या इसी वजह से उन्हें शो से बाहर किया गया? उन्होंने कहा कि यह चैनल का शो हैं। वह जब चाहे मेरा कांट्रैक्ट खत्म कर सकता है। किसी ने मुझसे बस यह पूछा था कि क्या यह सच कहने की कीमत है। तो मैंने कहा कि यह बहुत छोटी कीमत है। मैं यह नहीं कहना चाह रहा था कि इस वजह से मुझे निकाला गया है। हो सकता है चैनल की बजट की समस्या हो। हालांकि, वे मुझसे कहते तो मैं अपना बजट कम कर देता।

फिर कभी नहीं करूंगा शो होस्ट: सुशांत ने कहा कि यह दूसरी बार है जब उन्हें शो से निकाला गया है। उनका दिल टूटा है। अब बात आत्मसम्मान की है। वह यह शो अब कभी होस्ट नहीं करेंगे। सुशांत ने कहा कि 'सावधान इंडिया' से उन्हें बहुत प्यार रहा है। वह पैसा कमाने का जरिया नहीं था। शो के जरिये उन मुद्दों पर आवाज उठाने का मौका मिलता था, जिनसे उनके व्यक्तिगत जीवन में फर्क पड़ता है।

सुशांत सिंह। फाइल

सुशांत ने कहा कि शो आते-जाते रहेंगे, लेकिन वह देश के हालात से दुखी हैं। नागरिकता संशोधन कानून में धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है। जो विरोध कर रहे थे, वे छात्र हैं। देश का भविष्य हैं। अगर वे सवाल उठा रहे हैं, तो उनसे बात करनी चाहिए।

जामिया को लेकर देश–विदेश के विवि में प्रदर्शन

नई दिल्ली, एजेंसियां : देश-विदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों ने दिल्ली और अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे अलोकतांत्रिक बताया है।

पुणे में मंगलवार को सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय परिसर में कुछ छात्र संगठनों ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। इन छात्रों ने जामिया मिल्लिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन और नारेबाजी की। वहीं, ऑक्सफोर्ड, हारवर्ड, येल, स्टैनफोर्ड, कोलंबिया, टफ्ट्स और एमआइटी के छात्रों और विद्वानों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई का विरोध किया। विभिन्न अमेरिकी विश्वविद्यालयों के 400 से अधिक छात्रों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके जामिया और एएमयू के छात्रों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लंदन में इंडिया हाउस तक मार्च किया। विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर भारतीय छात्र ही हैं, जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं।

रेलवे को नुकसान पहुंचाने वालों को देखते ही गोली मार दो : अंगड़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र : नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ देशभर में चल रहे प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगड़ी ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने वालों को देखते ही गोली मार देने को कहा है।

हुबली में उन्होंने कहा, 'यदि कोई भी रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो मैंने संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सरदार वल्लभभाई पटेल की तरह कठोर कार्रवाई शुरू करने को कहा है।'

केंद्रीय मंत्री ने सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान रेलवे की संपत्ति को पहुंच रहे नुकसान को रोकने के लिए उठाए गए कदम के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में यह कहा। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने हैदराबाद को भारत में विलय कराया था। पुलिस कार्रवाई की गई थी जिससे निजाम ओर उसकी सेना को समर्पण करना पड़ा था। बंगाल में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों ने रेल लाइन को बाधित कर दिया था जिससे रेल सेवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा था। जब यह पूछा गया कि कड़ी कार्रवाई से उनका आशय क्या है तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'कड़ी कार्रवाई का मतलब देखते ही गोली मार दो।'उन्होंने जोर देकर कहा कि सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक को संकट नहीं पैदा होने जा रहा। उन्होंने कहा कि सीएए से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह में कितना साहस है। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन के हिंसक होने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष संकट को हवा देने में जुटा है। उन्होंने कहा कि अधिनियम का विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों को अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। वे लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टियां सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही हैं। मैं राज्यों से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध कर रहा हूं।

सुरेश अंगड़ी। फाइल

हिंसा के लिए रविवार को पूरी तैयारी से आए थे उपद्रवी

विवेक त्यागी, नई दिल्ली: दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी (एनएफसी) में हिंसा के लिए रविवार को उपद्रवी पूरी तैयारी करके आए थे। जांच के दौरान पुलिस को एनएफसी स्थित माता मंदिर मार्ग से पत्थर भरे दो बोरे बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मौके से कोल्ड ड्रिंक की छोटी-छोटी कई बोतलों में पेट्रोल भी बरामद हुआ। इससे साफ है कि उपद्रवियों की योजना यहां और बड़ी हिंसा करने की थी, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए आंसू गैस के गोले छोड़कर दंगाइयों को मौके से हटाया। डीसीपी दक्षिणी-पूर्वी चिन्मय बिश्वाल ने बोरे से पत्थर बरामद होने की पुष्टि करते हुए कहा कि हिंसक भीड़ के पास अवैध हथियार होने की बात से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता। इससे पहले 13 दिसंबर को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान भी जामिया मिलिया इस्लामिया परिसर से पुलिस पर पथराव हुआ था। उन्होंने बताया कि पुलिस की तरफ कोई फायरिंग नहीं की गई। फायरिंग के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उपद्रवियों की शिनाख्त कर उन पर शिकंजा कसने के लिए 10 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं। सैकड़ों वीडियो क्लिप व सीसीटीवी फुटेज जब्त किया गया है।

तैयारी

मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर व कोलकता में पर्यटन विभाग करेगा रोड शो, थाईलैंड, दुबई और सऊदी अरब के पर्यटकों को भी किया जाएगा आकर्षित

देश–विदेश में होगा कश्मीर के पर्यटन स्थलों का प्रचार

राज्य ब्यूरो, जम्मू

नये जम्मू कश्मीर राज्य में पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के लिए पर्यटन विभाग देश-विदेश में पर्यटकों को रिझाने के लिए पर्यटन प्रचार-प्रोत्साहन अभियान शुरु कर रहा है। 20 दिसंबर के बाद शुरू होने वाले इस अभियान के तहत विदेश में मलेशिया को छोड़कर दुबई, शारजाह और सऊदी अरब के पर्यटकों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

पर्यटन विभाग देश-विदेश में यह अभियान करीब सात सप्ताह तक यानी फरवरी के दूसरे सप्ताह तक चलाएगा। इस दौरान मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, नागपुर, इंदौर, भोपाल, बेंगलुरु, मैसूर, कोलकता, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोच्ची, रांची और वाराणसी में जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग रोड शो व पर्यटन मेलों का आयोजन करेगा। इनमें जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों, पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी, ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। विदेशी पर्यटकों को जम्मू कश्मीर में सैर के लिए आकर्षित करने के इरादे से थाईलैंड, शारजाह, दुबई और सऊदी अरब में भी रोड शो व पर्यटन मेले और ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। इनमें जम्मू कश्मीर की हरी भरी वादियों, एडवेंचर टूरिज्म के साथ साथ धार्मिक पर्यटन के क्षेत्रों का प्रचार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आस्था के प्रसिद्ध स्थलों के अलावा बौद्ध और हिंदू धर्म से जुड़े स्थानों पर आधारित डाक्यूमेंट्री फिल्में भी दिखायी जाएंगी। विदेश में यह अभियान जनवरी 2020 में चलाया जाएगा।

प्रतीकात्मक

दक्षिण भारत है स्थानीय टूर ऑप्रेटरों का लक्ष्य: राज्य में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग चाहते हैं कि दक्षिण भारत के पर्यटकों को जम्मू कश्मीर के लिए आकर्षित करने को व्यापक कार्य योजना होनी चाहिए। उनके मुताबिक, मुंबई और गुजरात या फिर कोलकता के पर्यटक ही मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर में आते हैं। इंडिया प्राइड टूर एंड ट्रैवल के संचालक रमण कुमार के मुताबिक दक्षिण भारतीय पर्यटकों में जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत दिलचस्पी है। दक्षिण भारत की कई फिल्मों की यहां शूटिंग भी हुई है। वहां के लोग इस तरफ आना चाहते हैं, बस उनमें विश्वास बहाल करने की जरुरत है।

इस बार मलेशिया को प्राथमिकता नहीं

जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग जिन मुल्कों में पर्यटन प्रचार का अभियान चलाने जा रहा है, उनमें इस बार मलेशिया शामिल नहीं है। हालांकि विभाग ने इसपर किसी तरह की स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि जम्मू कश्मीर मुद्दे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री द्वारा भारत विरोधी रवैया अपनाने के बाद ही उसे प्राथमिकता से बाहर किया गया है। पर्यटन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, मलेशिया में जम्मू कश्मीर के कई टूर आप्रेटरों का अपना मजबूत नेटवर्क है। इसलिए वह अपने स्तर पर वहां के पर्यटकों को जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए तैयार कर लेते हैं। विभाग का मकसद उन मुल्कों के पर्यटकों को जम्मू कश्मीर की तरफ आकर्षित करना है, जहां के लोग पर्यटन के लिए विभिन्न मुल्कों में तो जाते हैं, लेकिन यहां का रुख कम ही करते हैं।

लोकतंत्र, समानता व स्वतंत्रता के हिमायती थे गांधी : राजमोहन

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

भारत के स्वाधीनता आंदोलन के अगुआ महात्मा गांधी लोकतंत्र, समानता व स्वतंत्रता के हिमायती थे। गांधी ने लोगों को डर से मुक्त रहने की बात समझाई, लेकिन नफरत नहीं करना सिखाने में विफल रहे। गांधीजी के प्रपौत्र राजमोहन गांधी ने गांधीनगर में यह बात कही। आइआइटी गांधीनगर में भारत की खोज कार्यक्रम में राजमोहन गांधी ने कहा कि गांधीजी ने हिंदू धर्म आधारित भारत की पहचान को कभी भी स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजों के भारत छोड़ने में गांधीजी का योगदान कितना था, इस बात का कोई महत्व नहीं है। भारत में संसाधनों की कमी के चलते अंग्रेज वैसे भी भारत छोड़कर चले ही जाते। गांधीजी ने भारत में आजादी का आंदोलन लड़ रहे नेताओं को एक किया, उन्हें एकमत होने के लिए राजी किया यह बात सबसे अहम थी। उन्होंने लोगों को जाति, धर्म तथा किसी भी तरह के भेदभाव के बिना भारत की एक परिकल्पना व विचार को समझाया। गांधीजी लोकतंत्र, समानता व स्वतंत्रता के हिमायती थे, उनके इन्हीं विचारों को संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया तथा संविधान में जगह दी। इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान के जन्म के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संविधान निर्माताओं पर भारी दबाव था, लेकिन भारत के लोगों ने हिंदू राष्ट्र के विचार को ठुकरा दिया था। राजमोहन गांधी ने कहा कि भारत में आज भी कई लोगों व एक वर्ग का मानना है कि भारत की पहचान हिंदू धर्म के आधार पर होनी चाहिए। गांधीजी ने 1906 में अपनी पुस्तक में हिंदू राष्ट्र के विचार को नकार दिया था। उन्होंने माना कि गांधीजी भारतीयों को डरो मत यह बात समझाने में सफल रहे, लेकिन नफरत मत करो यह बात समझाने में विफल रहे।

नहीं रहे प्रख्यात अभिनेता डॉ. श्रीराम लागू

डॉ. श्रीराम लागू। फाइल

पुणे, एजेंसियां : विख्यात थिएटर व फिल्म अभिनेता डॉ. श्रीराम लागू का मंगलवार को पुणे स्थित आवास पर निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। उन्होंने दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

नाटककार सतीश अलेकर ने बताया, 'मैंने उनके दामाद से बात की। उनकी मौत उम्र संबंधी परेशानियों के कारण हुई है।' लागू प्रशिक्षित ईएनटी सर्जन थे। उन्होंने आजादी के बाद विजय तेंदुलकर, विजय मेहता और अरविंद देशपांडे के साथ मिलकर महाराष्ट्र में थिएटर आंदोलन को काफी बल दिया। मराठी नाटक 'नटसम्राट' व 'हिमाल्याची साओली' और फिल्म 'पिंजरा' में यादगार अभिनय ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई।

हिंदी फिल्म 'एक दिन अचानक', 'घरौंदा' व 'लावारिस' आदि में उन्होंने यादगार भूमिका निभाई। लागू अपने लोगों के बीच डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हें ऐसे प्रगतिशील व तर्कवादी के रूप में जाना जाता था जो निर्भीकता के साथ अपनी बात रखते थे। उनके निधन पर फिल्मी तथा राजनीतिक जगत की कई हस्तियों ने दुख प्रकट किया है।

दिल्ली में ठंड ने तोड़ दिया 22 साल का रिकॉर्ड

कांपा उत्तर भारत ▶ दिल्ली में 12 .2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया अधिकतम तापमान, राजस्थान के माउंट आबू में गिरी बर्फ

जेएनएन, नई दिल्ली

उत्तर भारत के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और बारिश के बाद पूरा उत्तर भारत बर्फीली हवाओं की चपेट में है। दिल्ली में मंगलवार को ठंड ने 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री कम 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पूर्व 28 दिसंबर, 1997 को अधिकतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में ही नहीं कई और राज्यों में भी बर्फ गिरी है। इनमें राजस्थान के माउंट आबू में मंगलवार को बर्फ की परत बिछ गई।

पहाड़ी राज्यों में बढ़ी परेशानी : उत्तराखंड के चार शहरों में न्यूनतम एक डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। प्रदेश में नैनीताल जिले का मुक्तेश्वर सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान .8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में आने वाले दिनों में भी शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। वहीं, बर्फबारी के चलते सैलानियों के लिए औली तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। वहीं, दूसरी ओर हिमाचल के कुल्लू, लाहुल और किन्नौर में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान बर्फ के कारण दो लोगों की मौत हो गई। जबकि एक व्यक्ति ग्लेशियर की चपेट में आने से घायल हो गया। इसके अलावा कश्मीर में रात के तापमान में गिरावट जारी है। गुलमर्ग का तापमान माइनस 11 डिग्री रहा। वहीं, श्रीनगर का तापमान भी माइनस 3.7 डिग्री तक पहुंच गया है।

मैदानी इलाके भी ठिठुरे : पश्चिमी विक्षोभ के बाद हुई बारिश और भारी बर्फबारी के बाद राजस्थान में शीतलहर का असर बढ़ गया है। सोमवार रात से शुरू होने वाली शीतलहर का असर अगले दिन तक बना हुआ है। वहीं, माउंट आबू में भी सर्दी का सितम देखने को मिला और न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच गया। इससे शहर के मैदानी इलाकों एवं कारों की छतों पर बर्फ की परत देखने को मिली। वहीं, मध्य प्रदेश के भी मंगलवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से. तक पहुंच गया। यह रतलाम और श्योपुरकला में दर्ज किया गया। वहीं, पंजाब में अमृतसर सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 7.2 डिग्री दर्ज किया गया।

बर्फबारी से परेशान बेजुबान...: हिमाचल प्रदेश स्थित कुफरी चिड़ियाघर में बर्फबारी के बाद जानवरों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही खाने की परेशानी भी सामने आ रही है। बर्फ बिछने से पहले यहां घूमते हुए इन्हें खाने को कुछ न कुछ मिल जाता था। लेकिन अब यह पूरी तरह चिड़िया घर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले खाने पर निर्भर हो गए हैं, जो समयानुसार ही मिलता है। महेंद्र ठाकुर

- पहाड़ी राज्यों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी, पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ीं
- हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण दो लोगों की जान गई

विभिन्न शहरों में तापमान

शहर	अधि.	न्यून.
मसूरी	11.8	01.1
जोशीमठ	10.1	01.6
पिथौरागढ़	14.8	01.2
मुक्तेश्वर	10.0	0.8

दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण नियंत्रण में

मौसमी परिस्थितियों के चलते मंगलवार को भी दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर नियंत्रण में ही रहा। सीपीसीबी द्वारा जारी एयर बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली का एयर इंडेक्स महज 168 दर्ज किया। इस श्रेणी की हवा को मध्यम श्रेणी में ही रखा जाता है। एनसीआर के शहरों में गाजियाबाद का एयर इंडेक्स 238, ग्रेटर नोएडा का 228 और नोएडा का 211 यानि खराब श्रेणी में जबकि गुरुग्राम का 106 और फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 165 यानि मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया।

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी भंग, नई टीम के गठन का रास्ता साफ

राज्य ब्यूरो, देहरादून : आखिरकार उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की मौजूदा तकरीबन 430 सदस्यीय जंबो कार्यकारिणी भंग हो गई। ढाई साल से ज्यादा अरसे बाद प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की नई कार्यकारिणी के गठन का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को बदलने की चर्चाओं पर भी विराम लग जाएगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह को अपनी नई टीम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इस चुनाव के दो माह बाद ही पार्टी हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व को बदलकर प्रीतम सिंह के हाथों में बागडोर सौंप दी। सबको साधने की कवायद में प्रीतम ने अपनी नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर जल्दबाजी से गुरेज किया। नतीजतन पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की टीम अब तक काम करती रही। शुरुआती दौर में टीम किशोर का आंकड़ा 165 रहा, लेकिन बाद में यह आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा हो गया था। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। हाईकमान से हरी झंडी मिलने पर मंगलवार को प्रीतम ने पुरानी प्रदेश कार्यकारिणी भंग करने की घोषणा कर दी। नई कार्यकारिणी का आकार भी जंबो रहने के संकेत हैं। सूत्रों की मानें तो 142 सदस्यीय नई कार्यकारिणी इसी हफ्ते आ जाएगी।

कुलदीप सेंगर को अब 20 को सुनाई जाएगी सजा

उन्नाव कांड

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- पीड़ित पक्ष ने की उम्रकैद के साथ अधिकतम मुआवजा दिलाने की मांग
- बचाव पक्ष ने दी दलील, सेंगर का जीवन सामाजिक कार्य में गुजरा-दया दिखाई जाए

दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए विधायक कुलदीप सेंगर को सजा सुनाने के लिए तीस हजारी अदालत में मंगलवार को दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने सेंगर को उम्रकैद देने और पीड़िता को अधिकतम मुआवजा दिलाने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष ने सेंगर के सामाजिक कार्य गिनाकर और विवाह योग्य दो बेटियों का हवाला देकर दया करने की अपील की। सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला 20 दिसंबर के लिए टाल दिया। उस दिन सेंगर के अधिवक्ता को उसके द्वारा 2017 के चुनाव में दायर किया गया संपत्ति का विवरण भी अदालत में दाखिल करना होगा।

सीबीआइ ने सजा पर बहस करते हुए अदालत में कई दलीलें दीं। जांच एजेंसी ने कहा कि इस मामले में सहानुभूति समाज को अधिक नुकसान पहुंचाएगी। इस मामले में किसी भी तरह का उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले इस तरह के अपराधों का समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सीबीआइ ने कुलदीप सेंगर को अदालत ने सोमवार को पॉक्सो एक्ट की धारा 5-सी और 6 में दोषी करार दिया था। इन धाराओं के तहत यदि कोई लोकसेवक नाबालिग पर भयावह अपराध करता है तो उसे न्यूनतम दस साल और अधिकतम उम्रकैद का प्रावधान है। साथ ही मुआवजा अदा करने की भी बाध्यता है। अदालत से दरख्वास्त की गई है कि दोषी को अधिकतम सजा दी जाए।

-धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, अधिवक्ता पीड़ित पक्ष

पीड़िता को उचित मुआवजा देने की भी मांग की। वहीं, पीड़िता के वकील धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि पीड़िता बेघर हो गई है। उसके पिता की मौत हो चुकी है और परिवार के बचे लोगों के साथ उसे दिल्ली में रहना पड़ रहा है। मिश्रा ने अदालत में कहा कि दोषी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पीड़िता को अधिक से अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। अदालत यह भी तय करे कि मुआवजा सभी मामलों को जोड़ते हुए नहीं, बल्कि सिर्फ इस केस के लिए मिलना चाहिए। पीड़िता के साथ जिस समय दुष्कर्म हुआ, वह नाबालिग थी और इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पूरी बहस में आंखें मूंदे बैठा रहा सेंगर: सजा पर बहस के बीच कुलदीप सेंगर पूरे समय अदालत में कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठा रहा। बीच में कुछ समय के लिए सेंगर ने अपने पक्ष के लोगों से बातचीत करने के लिए आंखें खोलीं तो उनमें नमी और थकान साफ दिखाई दे रही थी। मंगलवार को भी सेंगर के परिजन और समर्थक बड़ी संख्या में अदालत में मौजूद रहे।

बचाव पक्ष ने मांगी दया

बचाव पक्ष के अधिवक्ता, तनवीर अहमद मीर ने कुलदीप सेंगर के लिए दया की मांग की। उन्होंने अदालत को बताया कि सेंगर का जीवन सामाजिक कार्यों में गुजरा है। सेंगर ने नदियों पर बांध बनवाए, आइटीआइ बनवाई, हेल्थ सेंटर बनवाने सहित कई विकास कार्य किए। सेंगर की पृष्ठभूमि आपराधिक नहीं है। सेंगर की दो बेटियां हैं और उनकी उम्र शादी की हो चुकी है। ऐसे में उसे सजा सुनाते समय दया दिखाई जाए। सेंगर के अधिवक्ता ने मुआवजे पर भी सवाल उठाए। इस पर अदालत ने कहा कि सेंगर ने 2017 में जब विधानसभा चुनाव के वक्त शपथपत्र दायर किया था, उसे अदालत में जमा किया जाए।

गोली चलते ही इधर-उधर भागने लगे लोग

प्रथम पृष्ठ से आगे

लोग इधर-उधर भागने लगे। हालांकि, कोर्ट में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों और स्टाफ ने हिम्मत दिखाते हुए तीनों हमलावरों को पकड़ लिया। इस दौरान जब्बार मौके से फरार हो गया। पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट में ही पकड़े गए हमलावर साहिल, उसके साथी सुमित और अफराज से पूछताछ की। कुख्यात शाहनवाज पर लूट, हत्या, रंगदारी सहित डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। वह पूर्वांचल के चर्चित मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा था। साहिल किरतपुर चेयरमैन अब्दुल मन्नान का भांजा भी है। हमलावरों के पास से तीन पिस्टल बरामद हुई है। गंभीर हालत में कोर्ट मोहर्रिर मनीष को मेरठ रेफर कर दिया गया है। बिजनौर के पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने बताया कि तीनों हत्यारोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्याकांड को बसपा नेता एहसान के बेटे ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ अंजाम दिया है। पेशी पर आया एक बदमाश लापता है। उसकी तलाश की जा रही है।

70 फर्मों से होगी 220 करोड़ की रिकवरी

जीएसटी फर्जीवाड़ा

सुमन सेमवाल, देहरादून

- फर्जी फर्मों ने राज्य से बाहर भेजे गए माल पर दिखाया 220 करोड़ रुपये का आइजीएसटी
- इस राशि की रिकवरी के लिए संबंधित राज्यों को भेजा गया पत्र

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में फर्जी तरीके से ई-वे बिल बनाकर 8500 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने वाली 70 फर्मों से 220 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी। इस राशि का भुगतान इन फर्मों ने आइजीएसटी (इंटीग्रेटेड जीएसटी) में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में किया जाना दिखाया है।

रिकवरी के लिए केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के अधिकारियों ने संबंधित राज्यों को पत्र भेज दिए हैं। ताकि, यह फर्में कहीं पर भी इनपुट ट्रैक्स क्रेडिट (आइटीसी) व रिफंड का लाभ भी न प्राप्त कर सकें। अब तक की जांच में यह भी पता चला है कि 1200 करोड़ रुपये के ई-वे बिल के जरिये 8500 करोड़ रुपये का कारोबार दिखाने वाली फर्मों ने उत्तराखंड में करीब 194 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी आइटीसी क्लेम प्राप्त करने की तैयारी भी कर ली थी। हालांकि, समय रहते मामला प्रकाश में आ जाने और अधिकारियों की सक्रियता से टैक्स चोरों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। इनमें दो फर्म देहरादून की भी हैं, जिन्होंने 191 करोड़ रुपये के ई-वे बिल बनाए हैं।

इस तरह किया फर्जीवाड़ा: 70 फर्मों ने 1200 करोड़ रुपये के ई-वे बिल बनवाए। इसके बाद उसी माल को फर्जी ढंग से आपस में ही खरीदा व बेचा गया। जितनी बार फर्जी बिलों से माल खरीदा व बेचा जाना दिखाया गया, उसी अनुपात में माल की कीमत भी बढ़ती चली गई। क्योंकि हर नया खरीदार उसमें अपना मुनाफा भी जोड़ देता है। इससे फर्जी माल की कुल कीमत को 8500 करोड़ रुपये दिखा दिया गया। यह सब इसलिए किया गया, ताकि उन्हें यदि आइटीसी का लाभ प्राप्त करने का मौका मिलता तो वह सरकार को फर्जी खरीद-बिक्री पर बिना टैक्स चुकाए ही 194 करोड़ रुपये का चूना लगा देते।

हल्द्वानी की फर्म का बैंक खाता अटैच : केंद्रीय जीएसटी विभाग ने फर्जी कारोबार पर हल्द्वानी की फर्म बीएन एक्सिन के बैंक खाते को अटैच कर दिया है। यह खाता नई दिल्ली में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अशोक विहार स्थित शाखा का है। इसी फर्म ने 6.62 करोड़ रुपये का फर्जी रिफंड प्राप्त करने का प्रयास भी किया था।

दून की दो फर्मों के पते भी निकले फर्जी : स्टेट जीएसटी के उपायुक्त एसएस तिरुवा ने बताया कि दून में सहसपुर स्थित गुनाश्री ट्रेडर्स व विकासनगर के ग्राम बोहा स्थित गौरा इंडस्ट्रीज भी फर्जी ढंग से ई-वे बिल बनाकर आइटीसी का लाभ लेने की तैयारी में थी। हालांकि, छापेमारी के दौरान कंपनियों के पते ही फर्जी पाए गए। इनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

केंद्रीय जीएसटी से हुई शुरुआत : करीब एक माह पहले केंद्रीय जीएसटी कार्यालय में हल्द्वानी स्थित बीएन एक्सिन फर्म ने माल के निर्माण व उसकी बिक्री के दौरान लगने वाले टैक्स में अंतर पर 6.62 करोड़ रुपये का रिफंड प्राप्त करने का प्रयास किया था। केंद्रीय जीएसटी की टीम ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि फर्म ने पूरा फर्जीवाड़ा किया है।

कुछ और फर्म में भी इस तरह के मामले पकड़ में आए। इसके बाद जब फर्जी आइटीसी व रिफंड को लेकर प्रकरण राज्य जीएसटी विभाग को भेजा गया तो अधिकारियों ने अब तक के सबसे बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया था।

छग में जंगल सफारी में संक्रमण से दो शेरों की मौत

नईदुनिया, रायपुर: एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी रायपुर में संक्रमण और दस्त से सप्ताह भीतर दो शेरों की मौत हो गई। इससे वन विभाग सकते में है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सफारी के सभी वन्यजीवों के रक्त की जांच कराने का निर्देश दिया है। मंगलवार को सफारी के नौ बाघों और छह शेरों के रक्त के नमूने (ब्लड सेंपल) लिए गए। जंगल सफारी के निदेशक एम. मर्शीवेला ने बताया कि रक्त का नमूना लेने के लिए शेर व बाघों को मटन दिखाया गया, जिसके लालच में वे पिंजरे में आ गए और आसानी से डॉक्टरों की टीम ने उनके सैंपल ले लिए। बुधवार को पांच भालू और पांच तेंदुओं का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। सैंपल को जांच के लिए दुर्ग जिले में अंजोरा स्थित वेटनरी कॉलेज भेजा जाएगा। सफारी प्रबंधन का कहना है कि इंफेक्शन की वजह से शेरों की मौत हो हुई है।

बरेली भेजा गया बिसरा: दस साल के शेर निर्भय की मौत के बाद उसके बिसरे को मंगलवार को वन विभाग की टीम ने बरेली स्थित इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भेज दिया।

290 किमी की मारक क्षमता और 300 किलो विस्फोटक ले जाने वाली ब्रह्मोस का परीक्षण

लावा पांडे, बालासोर

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा रूस के वैज्ञानिकों के मिश्रित प्रयास से निर्मित जमीन से जमीन पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का मंगलवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित अंतरिम परीक्षण परिषद के लांचिंग सेंटर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। प्रक्षेपास्त्र का वजन तीन टन है। यह प्रक्षेपास्त्र 300 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक ढोने तथा 290 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। यह सुपर सोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र आवाज की गति से भी 2.8 गुना (3485 किमी प्रतिघंटा) अधिक गति से जाने की क्षमता रखता है। इस प्रक्षेपास्त्र को जल, थल और नभ सहित मोबाइल लांचर से भी छोड़ा जा सकता है। इस प्रक्षेपास्त्र को किसी भी दिशा एवं लक्ष्य की ओर मनचाहे तरीके से छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका प्रक्षेपण पनडुब्बी पोत विमान या जमीन आधारित मोबाइल ऑटोनॉमस लांचर से भी किया जा सकता है। यह शहरी आबादी में छोटे लक्ष्य पर भी सटीक प्रहार करने में सक्षम है। इसमें ठोस प्रॉपर लेट बूस्टर तथा एक तरल पापुलेट इंजन सिस्टम है। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। मंगलवार को इसके परीक्षण के मौके पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ तथा अंतरिम परीक्षण परिषद आइटीआर से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों और वैज्ञानिकों का दल मौजूद था। सूत्रों की माने तो चंद दिनों में रात के समय भी और कई मिसाइलों का परीक्षण किए जाने की संभावना है।

ओडिशा के चांदीपुर में मंगलवार को जमीन से जमीन पर मार करने वाले सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एएनआइ

थाने से अपहरण व दुष्कर्म का आरोपित फरार, छह पुलिसकर्मी निलंबित

नईदुनिया, अंबिकापुर : छत्तीसगढ़ के सूरजपुर थाने से मंगलवार तड़के अपहरण व दुष्कर्म का आरोपित हथकड़ी समेत भाग निकला। उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी कर्मचारी सोते रह गए। आरोपित के फरार होने की घटना थाने के सीसीटीवी में कैद हुई है। प्रथम दृष्टया लापरवाही उजागर होने पर सूरजपुर एसपी राजेश कुकरेजा ने एक एएसआइ, एक प्रधान आरक्षक और चार आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फरार आरोपित की खोजबीन के लिए अलग-अलग टीमों को लगाया गया है। एक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और अनाचार के आरोपित को सूरजपुर कोतवाली में सोमवार देर शाम लाया गया था। आरोपित सूरज विश्वकर्मा को मंगलवार को न्यायालय में पेश करने की तैयारी थी। उसे लॉकअप में नहीं रखा गया था। हथकड़ी पहनाकर पुलिसकर्मियों की निगरानी में उसे थाना दफ्तर में रखा गया था। उसकी निगरानी में तैनात पुलिस अधिकारी कर्मचारी सोते रह गए और वह भाग निकला। सूरजपुर एसपी राजेश कुकरेजा ने एएसआइ शोभित पैकरा, प्रधान आरक्षक विष्णु देव, आरक्षक भीमेश आर्मो, अनीश तिवारी, बृजलाल सिंह, मदन भगत को निलंबित कर दिया।

जिंदा जलाई गई युवती की मौत पर मुजफ्फरपुर और पटना में बवाल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर

- मुजफ्फरपुर के खबड़ा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव
- अनियंत्रित भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंदोलनकारियों को खदेड़ा

अहियापुर में जिंदा जलाई गई युवती की पटना के अपोलो बर्न हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत के बाद मंगलवार को मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक लोगों में उबाल दिखा। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा, अहियापुर स्थित जीरो माइल गोलंबर, छाता चौक, खबड़ा सहित अन्य इलाकों में सुबह से ही लोग सड़कों पर उतर आए। जगह-जगह टायर जलाकर प्रदर्शन किया। दिनभर जगह-जगह आगजनी कर सड़क जाम व विरोध प्रदर्शन होता रहा। खबड़ा में सड़क जाम कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। इसमें नगर डीएसपी के बॉडीगार्ड पुलिन कुमार सहित आधा दर्जन जवान चोटिल हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दो उप्रद्रवियों को हिरासत में लिया गया है।

उधर, पटना में आक्रोशितों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। ट्रेनें रोक दीं। बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। पीड़िता की मौत से नाराज लोग आरोपितों को अविलंब सजा देने की मांग कर रहे थे। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

सुबह नौ बजे से पटना में कर दिया जाम: राजधानी में हॉस्पिटल के सामने युवती के स्वजन व अन्य लोगों ने सुबह करीब नौ बजे से ही रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। अप लाइन पर राजगनी एक्सप्रेस व डाउन लाइन पर पटना-झाझा पैसेंजर ट्रेन को रोक दी। समझाने गए आरपीएफ इंस्पेक्टर आरआर कश्यप के साथ लोगों की नोकझोंक हुई। अस्पताल के सामने कंकड़बाग पुरानी बाइपास स्थित बीच सड़क पर धरने पर सभी बैठ गए।

पटना में आक्रोशित लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाने की मांग पर अड़े थे। वे लोग 24 घंटे के भीतर आरोपितों को सजा दिलाने व मृतक के परिजनों की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर रहे थे। पटना डीएम के आश्वासन के बाद दोपहर सवा एक बजे पोस्टमार्टम के लिए शव को एनएमसीएच भेजा गया। मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी पीके मंडल ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रित है।

महिलाओं को निगम अधिकारी बताकर होटलों में ठहराता था हरभजन सिंह

नईदुनिया, इंदौर

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में जिला कोर्ट में चालान पेश होने के बाद नए राज उजागर होने लगे हैं। मामले में फरियादी इंदौर नगर निगम के तत्कालीन इंजीनियर हरभजन सिंह (अब निलंबित) अपने रसूख का फायदा उठाकर आरोपित महिलाओं को आलीशान होटलों में निगम अधिकारी बताकर ठहराता था।

वह फोन पर यह कहकर कमरे बुक कराता था कि दूसरे शहर के निगमों से बड़ी अधिकारी आ रहीं हैं। उनके ठहरने और घूमने का इंतजाम करना है। हरभजन इंदौर नगर निगम के अधिकारी के बतौर इन महिलाओं से होटलों में मिलने भी पहुंचता था।

सोमवार को कोर्ट में पेश 390 पेज के चालान के पेज नंबर 150 पर होटल के रिसेप्शनिस्ट ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस को दिए बयान में उसने स्वीकारा है कि हरभजन पहले भी होटल में लोगों को रुकवा चुका है। 10 पेज में पुलिस ने हरभजन सिंह और आरोपित आरती के बीच हुई बातचीत का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया है। इसमें हरभजन सिंह ने आरोपितों को नकद रकम के बजाय प्रॉपर्टी देने की पेशकश भी की थी। उसने आरती से पूछा था कि वह दो करोड़ नकद के बदले कोई प्रॉपर्टी दे सकता है क्या। बातचीत में उसने बार-बार ब्लैकमेलिंग की रकम कम करने की गुजारिश की। उसने आरती से यह भी पूछा था कि बाकी लोगों से नकदी ही लिया है या कुछ प्रॉपर्टी ली।

मप्र का हनी ट्रैप मामला

- कोर्ट में चालान पेश होने के बाद उजागर होने लगे राज
- मामले में फरियादी नगर निगम इंजीनियर हरभजन नकदी के बजाय प्रॉपर्टी देने को था तैयार

विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने उठाया हनी ट्रैप मामला

मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक केपी सिंह ने हनी ट्रैप मामले को लिखित प्रश्न के माध्यम से उठाया। कार्रवाई के बारे में जानना चाहा तो सरकार ने जवाब में कहा कि मामले की अभी जांच चल रही है और विवेचना कब पूरी होगी, इसकी समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

सामूहिक दुष्कर्म में एक नाबालिग पर वयस्क की तरह चलेगा केस

नईदुनिया, रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेल कर धमकाने के बहुचर्चित मामले में आरोपित दो नाबालिगों में से एक पर वयस्क की तरह बालक न्यायालय में प्रकरण चलेगा। किशोर न्याय बोर्ड ने इस 16 वर्षीय किशोर के खिलाफ विचारण (विचार) वयस्क की तरह बालक न्यायालय में करने का आदेश देते हुए 23 दिसंबर की पेशी नियत की है।

किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 15 के तहत आदेश दिया कि वारदात के समय यह नाबालिग (विधि विरुद्ध बालक) 16 वर्ष का था। नाबालिग का इंस्टाग्राम अकाउंट था, जिससे वह छात्रा से चेटिंग करता था। इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए 18 वर्ष की आयु आवश्यक है। उसने स्वयं को वयस्क बताते हुए अकाउंट बनाया था। इससे पता चलता है कि वह उन अपराधों की प्रकृति समझने में मानसिक रूप से सक्षम है।

विवादित ढांचा विध्वंस की नाटकीय प्रस्तुति पर पांच के खिलाफ केस दर्ज

बेंगलुरु, प्रेट्र : स्कूल के वार्षिकोत्सव में छात्रों द्वारा अयोध्या के विवादित ढांचा ढहाए जाने की नाटकीय प्रस्तुति करने को लेकर स्कूल प्रबंधन के पांच सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बंटवाल के समीप स्थित स्कूल में छात्रों ने रविवार को नाटकीय प्रस्तुति की थी। पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काल्लाडका पदाधिकारी प्रभाकर भट्ट और श्री राम विद्या केंद्र संचालित करने वाले चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। मंगलुरु से करीब 30 किलोमीटर दूर काल्लाडका गांव में यह स्कूल है। सभी के खिलाफ आइपीसी की धारा 295 (ए) और 298 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। उसी क्षेत्र में रहने वाले पापुलर फ्रंट (पीएफआइ) के नेता अबूबकर सिद्दीकी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है।

- पीएफआइ नेता की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

दक्षिण कन्नड़ जिले के पुलिस अधीक्षक बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने कहा, 'पीएफआइ कार्यकर्ता की शिकायत पर हमने स्कूल प्रबंधन के पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच जारी रहने के कारण हमने अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। यह शिकायत आधे मिनट के वीडियो पर आधारित है। हम सुबूत जुटा रहे हैं।' किरण बेदी ने इस नाटक का वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले 3800 से अधिक छात्रों ने अयोध्या में राम मंदिर का प्रारूप भी बनाया था। भट्ट ने कहा है कि यह हमारे इतिहास के घटनाक्रम पर जागरूकता पैदा करने और देश भक्ति की भावना जाग्रत करने का प्रयास था। हर साल छात्र अपना कार्यक्रम चुनते हैं।

तिहरे हत्याकांड में मुकुल राय की गिरफ्तारी पर रोक

जागरण संवाददाता, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य के चर्चित तिहरे हत्याकांड में भाजपा नेता मुकुल राय को बड़ी राहत देते हुए पांच सप्ताह तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस दौरान पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।

इससे पहले मुकुल ने उक्त मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में शरण ली थी। गौरतलब है कि बोलपुर कोर्ट ने लाभपुर में तीन भाइयों की हत्या के मामले में भाजपा नेता मुकुल राय और मनिरुल इस्लाम के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बीरभूम जिला पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश की गई अतिरिक्त चार्जशीट में दोनों नेताओं के नाम शामिल किए जाने के बाद वारंट जारी हुआ था। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की पूर्ण जांच कर तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। पुलिस ने 16 नवंबर 2019 को जांच पूर कर बोलपुर कोर्ट में अतिरिक्त आरोप पत्र पेश किया था, जिसमें भाजपा के दोनों नेताओं के साथ ही अन्य आरोपितों के नाम शामिल हैं।

दैनिक जागरण

आत्मविश्लेषण से ही स्वयं में सुधार संभव हो सकता है

शरारत भरी राजनीति

कांग्रेस की अगुआई में 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलकर नागरिकता कानून वापस लेने की मांग करके यही प्रकट किया कि वे इस मसले पर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आखिर किस नियम-कानून के तहत संसद से पारित किसी कानून की वापसी हो सकती है? जो काम संभव ही नहीं उसकी मांग करना राजनीति चमकाने के अलावा और कुछ नहीं। विपक्षी दल यह सब इसीलिए कर रहे हैं, ताकि उन तत्वों को उकसाने में आसानी हो जो इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतरकर आगजनी एवं तोड़फोड़ कर रहे हैं। विपक्ष की भड़काऊ राजनीति का पता इससे भी चलता है कि उसकी ओर से दिल्ली से लेकर बंगाल तक फैलाई जा रही अराजकता के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। यह अराजकता शरारत भरी राजनीति, अज्ञानता और कुप्रचार की उपज ही है, क्योंकि सच यही है कि नागरिकता कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई वास्ता नहीं। यह कानून तो असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए है और वह भी उन्हें जो 2014 के पहले आ चुके हैं। हालांकि असम, त्रिपुरा आदि के लोग यह नहीं चाह रहे कि बाहर से आया कोई भी विदेशी उनकी धरती पर बसे। इसीलिए वहां इस कानून का विरोध तेज हुआ। यह बात और है कि उन्हें भी यह नहीं पता कि वास्तव में कितने बाहरी लोग इस कानून से लाभान्वित होंगे और उनके यहां के नागरिक बन जाएंगे।

यह विडंबना ही है कि पूर्वोत्तर के जो लोग इस कानून से किसी न किसी रूप में प्रभावित हो सकते हैं उन्होंने तो अपना उग्र विरोध त्याग दिया, लेकिन शेष देश में इस झूठी अफवाह के सहारे हिंसा की जा रही है कि इससे उनके हित प्रभावित होंगे। यह तो संभव ही नहीं, क्योंकि यह कानून नागरिकता देने का है, न कि लेने का। अगर लोगों को यह साधारण सी बात समझ नहीं आ रही तो इसका यही मतलब है कि वे न समझने का बहाना कर रहे हैं। यह हास्यास्पद ही है कि नागरिकता कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले विपक्षी नेता भी राष्ट्रपति के पास यह गुहार लगाने चले गए कि इस कानून को वापस ले लिया जाए। क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा या फिर वे यह जान रहे हैं कि वहां उनकी दलीलें कमजोर साबित होने वाली हैं? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वे यह खुली मांग क्यों नहीं करते कि बांग्लादेश, पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता प्रदान करने वाला कानून बनाया जाए?

बंगाल में एनपीआर बंद

पश्चिम बंगाल की ममता सरकार का केंद्र के साथ रार लगातार बढ़ता जा रहा है। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर जिस तरह से तृणमूल प्रमुख एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है उससे ऐसा लग रहा है कि स्थिति और बदतर हो सकती है। क्योंकि सीएए ही नहीं, बल्कि ममता सरकार ने अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का कार्य भी बंद करने की घोषणा कर दी है। लगातार दूसरे दिन सड़क पर उतरकर तृणमूल प्रमुख ने सीएए के खिलाफ जमकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने विपक्षी दलों को संशोधित नागरिकता कानून पर विचार-विमर्श करने का वक्त ही नहीं दिया, इसे जल्दबाजी में पारित करवाया। यही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को कपड़ों से नहीं पहचाना जा सकता। तीन दिन पहले झारखंड की एक रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि ये कांग्रेस और उसके साथी हो-हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं। उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पर जो उनके दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं, उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इसे लेकर ममता ने कहा कि संसद में भाजपा के पास संख्या बल है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह राज्यों पर कानून लागू करने का दबाव बनाएगी। महज एक या दो छोटी घटनाएं होने पर केंद्र ने बंगाल में रेल सेवा बंद कर दी। रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों का काम है, फिर भी उन्हें हमने मदद दी। हमने (परेशानी खड़ी करने वाले) 600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। हम रेलवे और केंद्र सरकार से सेवाएं बहाल करने का अनुरोध करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों का जो उत्पीड़न किया गया हम उसकी निंदा करते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने भाजपा पर देश में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, परंतु यहां एक सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आंदोलन और जुलूस निकालने से स्थिति बदल जाएगी और जो कानून बन चुका है उसे वापस लिया जाएगा? क्या यह सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं हो रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो लोग उठा रहे हैं। एनपीआर को बंगाल में बंद कर ममता सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती हैं? इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सभी विपक्षी नेताओं को मिलकर एक साथ हिंसा रोकने का प्रयास करना चाहिए।

सीएए ही नहीं, बल्कि ममता सरकार ने अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का कार्य भी बंद करने की घोषणा कर दी है

निहित स्वार्थों वाला बेजा विरोध

ए. सूर्यप्रकाश

नागरिकता कानून का किसी भी धर्म से जुड़े भारतीय नागरिक से कोई लेनादेना नहीं है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे भी इससे भलीभांति परिचित हैं

कम से कम छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एलान किया है कि वे संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन कानून को अपने यहां लागू नहीं होने देंगे। गैर भाजपा शासित राज्यों के इन मुख्यमंत्रियों ने इस घोषणा से भारत के संविधान और देश की एकता-अखंडता को खुली चुनौती दी है। नागरिकता कानून के खिलाफ ऐसे विरोध की शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी इस मुहिम में शामिल हो गए। फिर केरल के मुख्यमंत्री पी.विजयन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस धड़े से जुड़ गए। इन सभी ने एक सुर में कहा कि वे अपने राज्यों में इस संशोधित कानून को लागू नहीं करेंगे। ऐसे बयानों से उनका दुस्साहस ही झलकता है। ये सुर किसी भी सूरत में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए उचित नहीं कहे जा सकते।

असल में नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित छह अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इन इस्लामिक देशों में उत्पीड़ित ऐसे समुदायों के रूप में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों को चिन्हित किया गया है। इस कानून के तहत इन तबकों के उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने की गुंजाइश रखी गई जो उत्पीड़न से त्रस्त होकर 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आ गए। संशोधन यही कहता है कि ऐसे लोगों को अब 'अवैध आव्रजक' नहीं माना जाएगा।

संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों की विधायी शक्तियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। संघ सूची की प्रविष्टि 17 के अनुसार 'नागरिकता' से जुड़े सभी मसलों पर कानून बनाना पूरी तरह संघीय सरकार के अधिकार में आता है। संविधान के अनुसार किसी भी राज्य के पास संघ द्वारा प्रवर्तित उस कानून को खारिज करने का अधिकार नहीं जो विषय विशुद्ध रूप से संघ के अधिकार की परिधि में आता है। संविधान सभा में संघ-राज्य संबंधों पर डॉ. आंबेडकर ने 4 नवंबर, 1948 को कहा था, 'संघवाद का मूल सिद्धांत यही है कि संघ-राज्यों के बीच विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों के पृथक्करण में कोई विधि संघ द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं संविधान द्वारा बनाई जाए।'

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों की दलील है कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण प्रदान करता है। उनका कहना है कि संबंधित देशों के मुस्लिमों को इस कानून के दायरे से बाहर रखना इस अनुच्छेद का उल्लंघन है। इस पर सवाल उठाने वाले कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की देहरी तक पहुंच भी गए हैं। ऐसे में इस पर शीर्ष अदालत की राय के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। इस कानून का किसी भी धर्म से जुड़े भारतीय नागरिक से कोई लेनादेना नहीं है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे भी इससे भलीभांति परिचित हैं। यह किसी भी भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 14 के अधिकार से वंचित नहीं करता। ऐसा प्रतीत होता है कि विरोध करने वाले इस बात से कुपित हैं कि यह कानून पाक, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम नागरिकों का निषेध करता है। क्या कोई भी राष्ट्र दूसरे देशों के नागरिकों को संवैधानिक गारंटी सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है?

अवधेश राजपूत

भले ही नागरिकता कानून का संशोधन छह समुदायों की बात करता हो, लेकिन असल में ये किसी धर्म विशेष के अनुयायियों से अधिक सताए गए लोगों के समूह हैं। सुप्रीम कोर्ट के और भी ऐसे निर्णय हैं जिनके अनुसार अनुच्छेद 14 युक्तियुक्त वर्गीकरण के लिए भी आधार प्रदान करता है। इन समुदायों को राहत पहुंचाने के केंद्र के निर्णय का दो कारणों से स्वागत किया जाना चाहिए। पहला तो यह कि भारत सदियों से ही सताए हुए वर्गों की शरणगाह रहा है। 12वीं शताब्दी में पारसियों का आगमन इस परंपरा की उम्दा मिसाल है। वहीं चीन के हमले के बाद 1959-60 के दौरान तिब्बत से तकरीबन 80,000 से अधिक शरणार्थियों का रेला भारत आया। उसके बाद से भारत में तिब्बती शरणार्थी लगातार आते रहे। धर्मशाला और कर्नाटक सहित देश के कई हिस्सों में उनकी बसावट के लिए केंद्र सरकार ने विशेष प्रावधान किए। भारत ने तिब्बती शरणार्थियों के मामले में जो किया उससे यही आभास हुआ कि इस्लामिक देशों से आने वालों को लेकर भी यही दस्तूर कायम रहेगा। यानी उन्हें भी देश के विभिन्न हिस्सों में बसाया जाएगा।

चूंकि इस संशोधन में 31 दिसंबर, 2014 की तारीख के रूप में एक मियाद तय कर दी गई है तो नए आव्रजकों को लेकर जताई जा रही चिंता पूरी तरह आधारहीन है। भविष्य में भारत आने वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस तथ्य को भी अनदेखा किया जा रहा है कि यह संशोधन वर्ष 2015 और 2016 में आई केंद्र सरकार की कुछ अधिसूचनाओं का अनुवर्ती भी है। पहली अधिसूचना के अनुसार 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए इन छह समुदायों के लोगों पर पासपोर्ट अधिनियम एवं विदेशी अधिनियम के दंडनीय प्रावधानों से राहत मिलेगी। यानी अगर उनके पास पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज नहीं हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनका प्रवेश एवं प्रवास नियमित माना जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने इन लोगों को दीर्घावधिक वीजा की सुविधा उपलब्ध कराई। इस लिहाज से नागरिकता कानून में संशोधन अनिवार्य हो गया था, क्योंकि इन अधिसूचनाओं के बावजूद नागरिकता कानून के तहत ये लोग अभी भी 'अवैध आव्रजक' बने हुए थे। जब तक यह संशोधन नहीं होता तब तक ये लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे।

असल मुद्दा यह नहीं कि ऐसा कानून अब क्यों लाया गया है, बल्कि सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि यह काम पहले क्यों नहीं किया गया? आखिर कांग्रेस के लंबे शासनकाल में इन इस्लामिक देशों में इंडिक धर्मों के मतावलंबियों और ईसाइयों की दुर्दशा की ऐसी अनदेखी क्यों की गई? वहीं इतने वर्षों तक बांग्लादेशी मुस्लिम विस्थापितों को बढ़ावा देकर उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस अब इस कानून का विरोध क्यों कर रही है? कांग्रेस का रुख-रवैया मुस्लिम तुष्टीकरण से ही प्रेरित है जबकि इसका उसे भारी खामियाजा ही भुगतना होगा। इतने लंबे अरसे तक देश की सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी खुद के हाशिये पर चले जाने की हकीकत को पचा नहीं पा रही है। इस कानून के विरोधियों के लिए एकमात्र संवैधानिक विकल्प सुप्रीम कोर्ट है जहां वे इसे चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने मुख्यमंत्रियों को इस कानून को लागू न करने को लेकर जिस तरह उकसा रही है वह आग से खेलने जैसा ही है। इसके परिणाम भुगतने की जिम्मेदारी उसी की होगी।

(लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

अर्थव्यवस्था में बाधक सुस्त न्याय व्यवस्था

डॉ. भरत झुनझुनवाला

इसमें दोराय नहीं कि जिन देशों में न्याय शीघ्र और आसानी से उपलब्ध होता है वहां अर्थव्यवस्था को गति मिलती है

किसी फैक्ट्री की भूमि को लेकर दो लोगों में विवाद हो गया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। करीब 25 वर्षों बाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया। इतने वर्षों तक वह भूमि बिना किसी उपयोग के पड़ी रही। इसी प्रकार तमाम संपत्तियां उपयोग में नहीं आ रही हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए न्याय शीघ्र उपलब्ध कराने की जरूरत है। जिन देशों में न्यायतंत्र सुदृढ़ है, सामान्य रूप से उनकी आय भी अधिक है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की 2019 की रपट के अनुसार कानून व्यवस्था में इंग्लैंड की रैंक 12, सिंगापुर की 13, अमेरिका की 20 और भारत की 68 पाई गई है, जबकि पाकिस्तान की 117 है। पहले तीनों देशों की रैंक ऊंची है और वे विकसित भी हैं। भारत की रैंक 2018 में 65 से घटकर 2019 में तीन पायदान नीचे 68 पर आ टिकी है। हमारी आर्थिक विकास दर में भी गिरावट आ रही है। इन दोनों बातों के आपसी संबंध को नकारा नहीं जा सकता।

न्यायपालिका पर खर्च के दो पक्ष हैं। सरकार न्यायपालिका पर आधिक खर्च करती है तो न्याय शीघ्र मिलता है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। दूसरी तरफ न्यायपालिका पर अधिक खर्च करने से सीधे सरकारी बजट पर भार पड़ता है और दूसरे आवश्यक निवेश प्रभावित होते हैं, लेकिन जैसा कहा कि जिन देशों ने न्याय व्यवस्था सुदृढ़ बनाई है वे आज विकसित हैं। न्यायपालिका पर बढ़े हुए खर्च का सकारात्मक प्रभाव अधिक होता है। तुलना में न्यायपालिका पर खर्च के बोझ का नकारात्मक प्रभाव कम पड़ता है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार कानूनी विलंब के कारण भारत की विकास दर में 0.5 प्रतिशत की कमी आई है। ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के अनुसार आपराधिक मामलों में न्याय में देरी होने के कारण भारत में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं। इसके कारण हमारी जीडीपी में गिरावट आई है।

यह विवाद का विषय हो सकता है कि न्यायपालिका में विलंब से आर्थिक विकास पर कितना प्रभाव पड़ता है, पर इसका एक हद तक नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट है। न्यायपालिका में सुधार करना दुष्कर नहीं है। सिंगापुर में 1990 में एक विवाद को निपटाने में औसत छह वर्ष का समय लगता था। 1990 के दशक में वहां कानूनी सुधार लागू किए गए। वर्ष 1999 में यह अवधि घटकर मात्र एक वर्ष तीन माह की रह गई। हम भी अपनी जनता को न्याय शीघ्र उपलब्ध करा सकते हैं। अब सुधार के रास्ते पर चर्चा करते हैं। पहला विषय रिक्त पदों का है। हमारी न्यायपालिका में 2006 में 15 प्रतिशत पद रिक्त थे जो 2015 में 37 प्रतिशत हो गए और 2019 में भी 37 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त 2018-19 में न्यायपालिका को 4386 करोड़ रुपये का बजट दिया गया, जो 2019-20 में घटाकर 3055 करोड़ रुपये कर दिया गया। सरकार को चाहिए कि रिक्त पदों को भरे और न्यायपालिका पर खर्च बढ़ाए, जिससे जनता को त्वरित न्याय मिले, विवादों का शीघ्र निपटारा हो और आर्थिक विकास को गति मिले।

दूसरा विषय कार्य दिवसों का है। एक अध्ययन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में वर्ष में करीब 190 दिन काम होता है। हाईकोर्ट में 232 दिन और निचली अदालतों में 244 दिन। गर्मी के दिनों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट लगभग दो माह के लिए बंद रहते हैं। इसका कोई औचित्य नही। इसके अलावा दशहरा, नववर्ष इत्यादि के समय भी एक या दो सप्ताह का अवकाश होना आम है। न्यायपालिका के सभी स्तरों पर कार्यदिवस बढ़ाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। मेरा अनुभव है कि अक्सर अदालत जाने पर पता लगता है कि जज साहब आज नहीं बैठ रहें हैं। ऐसा होने पर विवाद के निपटारे पर विलंब होता ही है। जनता को अनावश्यक खर्च वहन करना पड़ता है जिससे आर्थिक विकास धीमा पड़ता है।

तीसरा विषय वकीलों और जजों के तालमेल का है। चूंकि कई वकील प्रति सुनवाई के हिसाब से फीस लेते हैं इसलिए मामला जितनी देर तक चले, जितनी अधिक तारीखों पर सुना जाए उन्हें उतनी ही अधिक फीस मिलती है। जजों और वकीलों को यह देखना होगा कि मामलों का निपटारा जल्द कैसे हो? किरायेदारी के एक विवाद में जज साहब ने तीन बार पंजीकृत डाक से नोटिस भेजने के बाद ही प्रकाशन का आदेश दिया। आग्रह करने पर भी पहली बार पंजीकृत नोटिस के वापस आने पर प्रकाशन का आदेश नहीं दिया। यह स्वीकार करना होगा कि मामले के लंबा खिंचने में कुछ लोगों के निहित स्वार्थ होते हैं।

चौथा विषय तकनीक के उपयोग का है। आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वादों की स्थिति को ऑनलाइन देखा जा सकता है, लेकिन जो वाद दायर किया गया उसकी प्रतिलिपि ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होती। आपको निर्णय और उसका मसौदा भी मिल जाएगा, लेकिन उस निर्णय के संबंध में जो दायर दस्तावेजों की प्रतिलिपि ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होगी। न्यायपालिका व्यवस्था कर सकती है कि जितने कागज पेश किए जाएं उन सभी को ऑनलाइन अपलोड करके जनता को उपलब्ध कराया जाए।

पांचवां विषय जजों की जवाबदेही का है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कानून में व्यवस्था है कि निर्णय छह माह में दिया जाएगा, लेकिन ट्रिब्यूनल से निर्णय मिलने में चार साल तक लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जजों का मूल्यांकन कराए और जो जज समयबद्ध तरीके से कार्य नहीं करते उनकी पदोन्नति रोकी जाए अथवा उन्हें सेवा से विरत किया जाए। जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था तो मेरा मकान मालिक से विवाद हो गया। फैसला मात्र 20 दिन में हो गया। इस प्रकार त्वरित निर्णय से मन में भय रहता है और लोग कानून का उल्लंघन नहीं करते। निर्णय में देरी गलत कार्य करने वालों का मन बढ़ाती है। उन्हें पता होता है कि मामला अदालत में पहुंचेगा तो लंबा खिंचेगा। पीड़ित पक्ष भी अदालत में उनके गलत कार्यों को चुनौती नहीं देता, क्योंकि उसे मालूम है कि न्यायपालिका में बहुत समय लगता है। इस तरह समाज में गलत काम का प्रतिरोध न करने को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि न्यायपालिका पर खर्च बढ़ाए और रिक्त पदों पर नियुक्तियां करे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अवकाश की संख्या घटाए और जजों की जवाबदेही सुनिश्चित करे।

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

निष्ठुरता

आध्यात्मिक कार्यक्रमों में कर्मकांड को लेकर लोगों के अलग-अलग मत होते हैं। कर्मकांड में किसी पूजा-पाठ, यज्ञ-अनुष्ठान में पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन-प्रक्रिया को भी माना जाता है। इसी कर्मकांड के तहत संकल्प, दान-दक्षिणा, मांगलिक कार्यक्रमों के अलावा निधनोपरांत पिंडदान आदि को लेकर तर्क-वितर्क भी होते हैं। कुछ लोग इसे पाखंड की संज्ञा देते हैं, जबकि कर्मकांडी इसको आस्था से जोड़ते हैं और बिना विधिक कर्मकांड के आध्यात्मिक अनुष्ठान निष्फल मानते हैं। आध्यात्मिक कार्यक्रमों के पूर्ण होने तक कतिपय निषेध को जीवन में निषेध का भाव जागृत करने का सहायक तरीका मानना चाहिए और कर्मकांड को जीवन के किसी क्षेत्र में किसी तरह के कार्य के लिए मन केंद्रित करने का पूर्वाभ्यास मानना चाहिए। एक छोटे से मंत्र के जप के पूर्व अनेकानेक किए जाने वाले कार्य तथा मुद्राएं मन को एकाग्र करने के लिए ही तो हैं। कर्मकांड की प्रक्रिया के दौरान बेलगाम मन पूजा-उपासना या अनुष्ठान के लिए तैयार होने लगता है और जब मन पूरी तरह तैयार हो जाता है तो पूजा-उपासना के दौरान आसपास अनुकूल तरंगों का अहसास होने लगता है, जबकि भटकाव की स्थिति में कब पूजा शुरू हुई, कब खत्म हो गई कुछ पता नहीं चलता।

आध्यात्मिक अनुष्ठानों में संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय मन को शुभ कार्य के लिए तैयार किया जाता है। किसी भी काम में मन ही भटके तो काम में गुणवत्ता नहीं आएगी। कर्मकांड के नाम पर भयादोहन गलत है। यह काम कुछ स्वार्थीतत्व करते हैं। जबकि उपासक या धर्मनिष्ठ व्यक्ति पैसा चढ़ाता या दक्षिणा देता है तो उतने धन से मोह खत्म करने का भाव उत्पन्न होता है। अन्यथा धन के प्रति अधिक लगाव से कभी-कभी पैसा रहते घर के सदस्यों की अति आवश्यकताओं को व्यक्ति पूरा नहीं करता है। माता-पिता तक की सेवा में पैसा खर्च करने से कभी-कभी कतराने की स्थिति देखी जाती है। धन का मोह व्यक्ति को निष्ठुर बनाता है। निष्ठुरता घर-परिवार और समाज के लिए घातक है।

सलिल पांडेय

कब मिलेगा सुरक्षित मातृत्व का हक

डॉ. मोनिका शर्मा

मां के रूप में महिलाएं न केवल पारिवारिक-सामाजिक मूल्यों और रिश्तों की पोषक होती हैं, बल्कि देश के भावी नागरिक भी गढ़ती हैं

'जच्चा-बच्चा' सर्वेक्षण-2019 की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लगभग आधी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जरूरी पोषण नहीं मिल पाता है। गर्भावस्था और मां बनने वाली महिलाओं की समस्याओं को समझने के लिए देश के छह राज्यों में यह सर्वेक्षण किया गया था। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में किया गए इस अध्ययन के स्पष्ट होता है कि देश के दूर-दराज के इलाकों में आज भी गर्भवती स्त्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सही पोषण न मिल पाने के कारण गर्भावस्था के दौरान उनका वजन तय मानक के अनुरूप नहीं बढ़ता। यह बताता है कि महिलाओं को गर्भावस्था और उसके बाद की सावधानियों के बारे में भी बहुत कम जानकारी है। उत्तर प्रदेश में 48 फीसद गर्भवती महिलाओं को पता ही नहीं था कि गर्भावस्था के दौरान उनका वजन बढ़ना भी जरूरी है। चिंतनीय है कि सर्वेक्षण में सिर्फ 31 प्रतिशत महिलाएं ही ऐसी पाई गईं, जो गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन कर रही थीं। प्रसव के समय तक कुछ महिलाओं का वजन 40 किलो से कम था। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं को अतिरिक्त आराम नहीं मिला। घरेलू जिम्मेदारियों के चलते वे उसी तरह नियमित काम करती रहती थीं। 63 फीसद महिलाएं तो ऐसी थीं, जिन्होंने डिलीवरी के दिन तक काम किया था। जिसका सीधा-सा अर्थ है कि अधिकतर घरों में मां बनने जा रही या हाल ही में मां बनीं स्त्रियों के भोजन, आराम, स्वास्थ्य की देखभाल और विशेष जरूरतों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था।

मां के रूप में महिलाएं न केवल पारिवारिक-सामाजिक मूल्यों और रिश्तों की पोषक होती हैं, बल्कि देश के भावी नागरिक भी गढ़ती हैं। ऐसे में देश के हर हिस्से, हर तबके की महिलाओं के लिए सुरक्षित मातृत्व पाना एक बुनियादी अधिकार है। इतना ही नहीं यह सीधे-सीधे उनकी सेहत से जुड़ा मसला भी है जो महिलाओं के सबलीकरण से जुड़ा सबसे अहम पक्ष है। बावजूद इसके सामाजिक-पारिवारिक हालातों के अधिकतर पहलुओं पर आए बदलावों के बावजूद मां बनने जा रही स्त्रियां आज भी उचित पोषण और देखभाल से वंचित रहती हैं। परिवार के सदस्य हों या खुद महिलाएं, यह सजगता ही नहीं है कि भावी मांओं को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है।

विचारणीय है कि गर्भवती महिलाओं के खान-पान और सेहत की खैरियत से जुड़े ऐसे सभी कारक मां ही नहीं बच्चे की सेहत पर भी असर डालते हैं। बीते दिनों समग्र राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण में भी मां और बच्चे दोनों की पोषण की चिंतनीय तस्वीर आई है। इस सर्वे के मुताबिक पांच वर्ष तक के 35 फीसद बच्चे नाटे कद के हैं, 17 फीसद कमजोर हैं, 33 फीसद का वजन कम है और 11 फीसद भयंकर कुपोषित हैं। राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के सर्वे बताता है कि बच्चे की पोषणता की स्थिति का मां की पोषणता और शैक्षणिक स्तर के बीच गहरा संबंध है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

अब पाठ्यक्रमों में सुधार की जरूरत

भारतीय हितों की जानबूझकर अनदेखी शीर्षक से लिखा गया शंकर शरण का आलेख गागर में सागर के समान है, जिसमें उन्होंने एक ही जगह पर हिंदू हितों या यूं कहें कि देश के हितों से जुड़े तमाम मुद्दों की गहरी पड़ताल की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश का सेक्युलर-वामपंथी बौद्धिक धड़ा सदैव से हिंदू हितों के प्रति घोर असंवेदनशील रहा रहा है। उसे हिंदू विश्वासों और प्रतीकों में तो अंधविश्वास और क्रूरता दिखती है, लेकिन वहीं वे हिंसा और अंधविश्वास से भरी सामग्री और सिद्धांतों के प्रति समर्थन और बचाव में खड़े रहते हैं। अभी पिछले दिनों ही संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (सीएसडब्ल्यू) ने पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता की बदतर होती स्थिति पर एक लंबी-चौड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है, लेकिन इस पर भी बुद्धिजीवियों की इस जमात ने चुप्पी साध ली। कोई चर्चा तक नहीं। लेखक की यह बात भी सही है कि इन बुद्धिजीवियों ने देश की औपचारिक शिक्षा तक को अपना बंधक बना लिया है। पाठ्य पुस्तकों में महान हिंदू धर्मग्रंथों के प्रति तिरस्कार साफ-साफ दिखता है, एक शिक्षक के रूप में मुझे भी अपने छात्रों को कई बार वह सब पढ़ाना पड़ता है, जिस पर मुझे स्वयं विश्वास नहीं। यह कैसा दुर्भाग्य है? यहां यह मानने में कोई हर्ज नहीं कि जहां कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए सार्थक कदम उठाया है, वहीं शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में सुधार लाकर उसे वामपंथी चंगुल से बाहर निकालने को लेकर अभी तक कुछ खास नहीं कर पाई है। सरकार को चाहिए कि देश हित में वह इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकता सूची में शामिल करे और चीजों को दुरुस्त करे। आखिर किसी इंसान के चरित्र निर्माण का मुख्य आधार उसकी शिक्षा ही तो है। इसके व्यापक पहलुओं पर समग्र विचार बहुत आवश्यक हो गया है।

चंदन कर्ण, देवघर

मेलबाक्स

खतरनाक खेल

संपादकीय पेज पर प्रकाशित 'खतरनाक राजनीति' लेख पढ़ा। नागरिक संशोधन कानून को लेकर देश भर में अराजकता का माहौल है। पूर्वोत्तर से फैली हिंसा की आग देश के अन्य भागों के साथ राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देश के कई विश्वविद्यालयों के छात्र इस हिंसा में कूद पड़े हैं। देश का युवा जिसे अपनी ऊर्जा पढ़ाई लिखाई में खर्च करनी चाहिए, बहकावे में आकर हिंसा पर उतारू हैं। जिन लोगों को नागरिकता बिल के बारे में पूरी जानकारी तक नहीं है, वे भी राजनितिक दलों के बहकावे में अराजकता फैला रहे हैं। विपक्षी दल लोगों को उकसा कर हिंसा का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। समाज में नागरिकता बिल को लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार बार-बार सफाई दे रही है कि इस कानून से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन विपक्षी दल राजनितिक लाभ के लिए लोगो को उकसा रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसे अराजक तत्वों से सबसे पहले शांति की अपील करनी चाहिए, ताकि बातचीत के जरिये मसले को हल किया जा सके।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग, दिल्ली

छात्रों का राजनीतिक दोहन

भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने और रखने का अधिकार देता है, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय परिसर और परिसर के बाहर छात्रों का नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन जेएनयू स्टाइल में नारेबाजी लेकर रहेंगे आजादी के नारे बिल्कुल असंवैधानिक है। आखिर आजादी किससे? भारत से, भारतीय संविधान से, भारतीय संसद से या फिर भारत सरकार से? दूसरा छात्रों द्वारा सरेआम सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कहां तक उचित है? छात्र मृत्यु की अफवाहें फैलाना, ताकि छात्र प्रदर्शन और उग्र हो सके, इससे राजनीति की बू आती है। क्या ये निर्दोष छात्रों का राजनीतिक दोहन नहीं? बड़े पैमाने पर 750 नकली छात्र पहचान पत्रों का मिलना पूर्व नियोजित और बाहरी हस्तक्षेप की ओर इशारा करता है।

दीपक गौतम, सोनीपत

स्पष्टीकरण : कल के अंक में सुधार मांगती आपराधिक न्याय प्रणाली वाले लेख में लेखक वैभव कृष्ण की बाराबंकी में तैनाती का वर्ष भूल से 2007 छप गया है। तैनाती का सही वर्ष 2017 है।

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

18 करोड़ भारतीय नागरिकों को रात को भर पेट खाना नसीब नहीं हो पाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार। वहीं संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक भूखे लोग भारत में रहते हैं।

आजकल

नागरिकता कानून के विरोध का औचित्य

अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

आखिर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों का औचित्य क्या है? इस कानून में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे भारत के किसी समुदाय के नागरिक को किसी तरह का भय होना चाहिए। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने के लिए भर है। इसमें मुसलमानों का विरोध कहां है?

प्रतीकात्मक

राजधानी दिल्ली में हिंसा और आगजनी तथा उस पर हो रही राजनीति हर विवेकशील व्यक्ति को आतंकित करने वाला है। जिन लोगों ने आगजनी और हिंसा की वे कहां हैं यह बताना कठिन है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि नागरिकता कानून के विरोधी नेताओं में से किसी ने हिंसा की अभी तक निंदा नहीं की है। हां, जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ छात्रों की पुलिस द्वारा पिटाई के खिलाफ माहौल बनाने में अधिकांश नेता आगे हैं।

पुलिस पर आरोप : जामिया के छात्रों का आरोप है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, जबकि पुलिस ने परिसर में घुसकर पुस्तकालय में पढ़ रहे छात्रों तक को पीटा। पुलिस पर आंसू गैस के गोले छोड़ने का भी आरोप है। पुलिस कभी खाली जगह पर आंसू गैस के गोले छोड़े यह न देखा गया, न सुना गया। आंसू गैस के गोले प्रायः भीड़ को तितर-बितर करने के लिए छोड़े जाते हैं। दरअसल प्रदर्शन के दौरान काफी लोग पुलिस पर पत्थरें फेंक रहे थे तथा भागकर जामिया परिसर में चले जा रहे थे। परिसर के अंदर से भी पत्थर फेंके जाने के वीडियो सामने आ गए हैं। उसमें पुलिस लाउडस्पीकर से बार-बार पत्थर, कांच आदि नहीं फेंकने की अपील कर रही है। यह जांच का विषय है कि उनमें जामिया के छात्र थे या नहीं, किंतु अगर परिसर के अंदर से हमला हो रहा हो तो उस समय कोई पुलिस समूह विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति मांगने नहीं जाएगा। वह भी उस परिस्थिति में जब एक ओर आगजनी और तोड़फोड़ हो रही हो।

विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस का प्रवेश दुखद है और यह प्रवृत्ति रुकनी चाहिए, लेकिन यह एकपक्षीय नहीं हो सकता। यदि विश्वविद्यालय हिंसा और अवैध गतिविधियों के केंद्र बनेंगे तो पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। कोई हिंसा फैलाते हुए परिसर में घुस जाए और हम सोचे कि शिक्षा के मंदिर का ध्यान रखते हुए पुलिस अंदर न जाए यह संभव नहीं। राजधानी में जामिया के आसपास दो दिनों से वातावरण विषाक्त करने की कोशिश हो रही थी। लोगों को घर से निकलकर सड़क पर आने के लिए उकसाया जा रहा था। जिस तरह भीड़ निकली और उसने तोड़फोड़ आरंभ किया उससे चारों ओर आतंक का वातावरण बना। लोगों के घरों तक पर पत्थर मारे गए। उसके बाद बसों को आग के हवाले किया गया। पुलिस की मोटरसाइकिल भी जली। इतना कुछ होने के बावजूद यदि भीड़ पर गोली नहीं चली तो इसे पुलिस का संयम नहीं तो और क्या कहेंगे। पुलिस और अग्निशमन के अनेक कर्मचारी दूसरी ओर से हमलों से घायल हुए हैं। कई अस्पतालों में पड़े हैं। पांच आइपीएस अधिकारी घायल हुए। इसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी हिंसा हुई है।

बेजा डर : एक दूसरा पक्ष है जिसकी चर्चा न विरोधी नेता कर रहे हैं और न इन शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन। अब यहां मूल सवाल पर आएं। आखिर इन विरोध प्रदर्शनों का औचित्य क्या है? जो नागरिकता विधेयक संसद से पारित हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन गया उसमें ऐसा कोई पहलू नहीं है जिससे भारत के किसी समुदाय के नागरिक को किसी तरह का भय होना चाहिए। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने के लिए है। इसमें मुलसमानों का विरोध कहां है? संसद के दोनों सदनों में गृहमंत्री अमित शाह ने साफ-साफ और कई बार कहा कि यह विधेयक किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं देने के लिए है। इससे किसी भी भारतीय मुसलमान को भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। मुसलमान भारतीय नागरिक हैं और रहेंगे। बावजूद यदि यह बात फैली कि नागरिकता कानून मुसलमानों के खिलाफ है तो जाहिर है, कुछ अवांछित तत्व इसके पीछे हैं। पूर्वोत्तर का विरोध तो एक हद तक समझ में भी आता हैं। हालांकि उनकी आशंकाओं के निवारण की कोशिश भी पूरी की गई है। बावजूद अपने जातीय, नस्ली परंपराओं, संस्कृति, संसाधनों को लेकर असम की चिंता का और निवारण करने की आवश्यकता है। हालांकि वहां भी अब यह भयावह सच सामने आ रहा है कि नागरिकता कानून के नाम पर मुसलमानों को भड़काया गया था।

अशांति फैलाने की साजिश : मुसलमानों का इसके विरोध में जाने का कोई तार्किक आधार नहीं है। किसी मुसलमान की नागरिकता न छीनी जा रही है और न छीनी जा सकती है। वे सब भारतीय हैं। इस कानून में ऐसा एक शब्द नहीं है जिससे कोई आशंका पैदा हो। तो जिन लोगों ने यह गलतफहमी फैलाकर आम लोगों को भड़काया वे निश्चय ही भारत में सांप्रदायिक हिंसा की भयावह आग लगाना चाहते हैं। इस देश में एक वर्ग है, जिसके अंदर यह छटपटाहट थी कि एक साथ तीन तलाक के विरुद्ध कानून बन गया और कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ, उसके बाद अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया और देश में शांति बनी रही, अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आ गया और कहीं कोई विरोधी स्वर नहीं। ऐसा लगता है कि इस वर्ग ने नागरिकता कानून पर भ्रम और डर पैदा कर पूरे भारत में आग लगाने की रणनीति बनाई और उसे अंजाम देने की कोशिश की है। यह अफवाह फैला दी गई कि जामिया के छात्र मारे गए हैं। जामिया की उप कुलपति नजमा अख्तर ने पुलिस के अंदर प्रवेश करने का तो तीखा विरोध किया, लेकिन यह साफ किया कि हमारा कोई छात्र नहीं मारा गया है।

विरोध का अधिकार : हालांकि सबके बावजूद लोकतंत्र में विरोध का अधिकार संविधान देता है। जिसे नागरिकता कानून से असहमति है उसे विरोध करने का पूरा अधिकार है। यहां तक कि अनावश्यक एवं निराधार विरोध प्रदर्शन की भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुमति है तो जो विरोध करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। पर हिंसा, तोड़फोड़ और देश विरोधी नारे तथा किसी समुदाय को भड़काने वाले नारे अपराध की श्रेणी में आएंगे। इसका अधिकार संविधान और कानून किसी को नहीं देता। सच कहें तो किसी तरह इन विरोधों को सामान्य विरोध नहीं माना जा सकता है। इसके पीछे एक समुदाय को भड़काने की गहरी साजिश है। यह जांच एजेंसियों का दायित्व है कि ऐसे चेहरों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आखिर देश में आग लगाने की चाहत रखने वाले ये कौन लोग हैं? और राजनीति देखिए, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया कि पुलिस ने स्वयं बसों में आग लगाई है और एक वीडियो भी जारी किया। अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि पुलिस वाले दरअसल आग बुझा रहे थे।

इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा कोई व्यक्ति यदि ऐसे संवेदनशील मामले पर इस तरह गैर जिम्मेदार टिप्पणियां करे तो फिर आग बुझाएगा कौन? यह नेताओं के गैर जिम्मेदार रवैये का केवल एक उदाहरण है। बहरहाल यह कैसा राजनीतिक समुदाय है जो हिंसा और आगजनी तक का भी खुलकर विरोध नहीं कर सकता! क्यों? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश में शांति तथा कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए तो एक स्वर में बोलना चाहिए। अगर अपनी इतनी छोटी जिम्मेदारी का भी अहसास हमारे नेताओं को नहीं है तो फिर इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। किंतु नागरिक समाज के नाते हम सबका दायित्व है कि सजग और सतर्क रहें तथा जितना बन पड़े शांति के लिए काम करें।

विरोध के लोकतांत्रिक तरीके की अनदेखी

आदर्श तिवारी

जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह कानून तीन देशों से आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देगा, इसमें किसी के नागरिकता को खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही देश के मुसलमानों का इससे कोई संबंध है फिर इस विरोध का आधार क्या है? शंकाओं के आधार पर यह आराजकता कहां तक जायज है? प्रदर्शनकारी गांधी, आंबेडकर, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य से उनके विचारों को सुनने, समझने की शक्ति उनमें नहीं है। गांधी की दुहाई देकर प्रदर्शन करने वाले लोग अहिंसा से परहेज कर रहे हैं और आंबेडकर की दुहाई देने वाले कानून को अपने हाथ में लेकर संविधान का धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रदर्शन, विरोध जब हिंसा की राह पकड़ता हुआ पत्थरबाजी पर आकर रुकता है, तब पुलिस मूकदर्शक बने तमाशा नहीं देख सकती। उसका काम है माहौल पर काबू पाना।

जामिया हिंसा को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी अहम हो जाती है। 16 दिसंबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जामिया और अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हुई हिंसा पर सुनवाई को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि 'आप छात्र हैं इसलिए आपको हिंसा करने का अधिकार नहीं मिल जाता। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि अगर प्रदर्शन और हिंसा में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो हम सुनवाई नहीं करेंगे'। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने तल्ख लहजे में कहा कि हम दखल नहीं देंगे। यह कानून व्यवस्था का मामला है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि बसें कैसे जलीं? जब कोई कानून तोड़ता है तो पुलिस क्या करेगी? कोई पत्थर मार रहा है। कोई बस जला रहा है। हम पुलिस को एफआइआर करने से कैसे रोक सकते हैं?

बहरहाल यह विरोध तब जायज रहता जब केवल किसी एक धर्म विशेष को सरकार नागरिकता देने का प्रावधान लाती, लेकिन इस विधेयक में तीनों मुस्लिम बहुसंख्यक देशों से अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जा रही है। अगर किसी को इस कानून से दिक्कत है तो इसके विरोध के और भी कई संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके हैं, जिसको प्राथमिकता देनी चाहिए। गौरतलब है कि संसद में पारित इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एक दर्जन से अधिक याचिकाएं इस विधेयक की संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़े करते हुए दाखिल की गई हैं। यह तो भविष्य के गर्भ में है कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर क्या निर्णय लेता है। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है, सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इसकी व्याख्या कैसे करता है? प्रदर्शन में उतरे लोगों को सब्र के साथ सच्चाई की तह तक जाने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। कुछ लोगों ने सच जानकर भी अफवाह फैलाना जारी रखा। बहरहाल प्रदर्शनकारियों को संविधान के अनुरूप और गांधी के बताए मार्ग पर चलते हुए अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, जिसकी दुहाई वे स्वयं दे रहे हैं।

खरी-खरी

मोहतरम का माफीनामा!

आशीष दशोत्तर

मोहतरम जनाब खयालीराम को आप अगर नहीं जानते तो आपको इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। आपका ज्ञान और अनुभव इस जानकारी के बिना अधूरा है कि खयालीरामजी किस चीज का नाम है। लोग उत्सुक थे कि मोहतरम जनाब के माफीनामे के बारे में जानें। कहा गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। इस बात के निहितार्थ किसी ने कुछ भी निकाले हों, मगर खयालीरामजी ने इसका यह मतलब निकाल लिया कि माफी मांगना अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं, क्योंकि इसमें मांगने का भाव छिपा है। मांगने की क्रिया से उनकी पिछली पुश्तों का भी वास्ता नहीं रहा। हालांकि उनके सलाहकारों ने कई बार समझाया भी कि माफी मांगना वैसा मांगना नहीं है, मगर वे नहीं समझे। वैसे भी वे अच्छी सलाह को समझते ही कहां हैं!

वे अपनी बात पर अड़े रहे। कहते रहे माफी नहीं मांगूंगा। माफी मांगना कायरों का काम है। अब मोहतरम जनाब को कौन समझा सकता था, सिवाय रामदीन के। रामदीन को काफी अरसा हो गया था जनाब की खिदमत करते हुए। रामदीन ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम की तरह उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे इस तरकीब से काम लें कि लाठी भी टूट जाए और सांप भी न मरे। हालांकि यह कहावत को उल्टे नजरिये से देखने जैसा था। खयालीरामजी को यह तरकीब पसंद आई।

रामदीन ने उन्हें समझाया कि आप माफी मांगने के बजाय ऐसा कुछ किया करें, जिससे आपसे माफी मांगने वाले खुद ही उलझ जाएं और वे थक-हार कर खुद ही आपको माफ कर दें। रामदीन ने समझाया कि आपसे गलती तो लगभग हर दिन हो जाती है। आपकी गलती पर आपसे माफी मांगने को कहा जाता है। इसलिए किसी गलती की आयु को बड़ा होने ही न दें। खयालीरामजी ने पूछा, वह कैसे? रामदीन ने समझाया कि एक गलती पर माफी मांगने को कहे, उससे पहले दूसरी गलती कर दीजिए। सामने वाला तय करे कि किस गलती पर माफी मांगी जाए, उससे पहले तीसरी गलती कर दीजिए। रामदीन की यह बात जनाबेआली ने गांठ बांध ली। वे अब गलती पे गलती करने लगे। माफी की मांग करने वाले धीरे-धीरे 'क्षमा वीरस्य भूषणम्' के सूत्रवाक्य का स्मरण करते हुए उन्हें हर बार माफ कर स्वयं को वीर मानने लगे।

ट्वीट-ट्वीट

पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि सरेआम गुंडागर्दी है। कानून हाथ में लेकर कोई प्रदर्शन नहीं होता। देश का लोकतंत्र आपको चुनी हुई सरकार से सवाल पूछने का हक देता है। हिंसा का नहीं..हिंसा होगी..पुलिस वालों पर हमला होगा तो फिर पुलिस की लाठियां खाने को तैयार रहो।

समीर अब्बास@TheSamirAbbas

दिल्ली में हुई हिंसा में कथित तौर पर शामिल लोगों पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है और यह होना भी चाहिए, परंतु जो हिंसा पुलिस ने जामिया परिसर के भीतर छात्रों पर की उसके लिए उन पर कार्रवाई कौन करेगा?

प्रशांत किशोर@PrashantKishor

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे रविवार को जामिया मिलिया परिसर में हुए घटनाक्रम की तुलना जलियांवाला बाग से कर रहे हैं। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह से मेरी गुजारिश है कि वह उन्हें जलियांवाला बाग का दौरा कराने के साथ ही इतिहास का जरूरी सबक सिखाएं। स्मिता प्रकाश@smitaprakash

खेल के साथ सियासत में भी बढ़ रही हलचल

जम्मू-कश्मीर डायरी

अभिमन्यु शर्मा
संपादक, जम्मू-कश्मीर

ठंड ने जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह पांव पसार लिए हैं। अमूमन सर्दियों में खासकर दिसंबर माह के दौरान जम्मू-कश्मीर में सियासत और खेल, दोनों संबंधित गतिविधियां लगभग ठंडी रहती हैं, खैर इस बार ऐसा नहीं है। गर्मियों में अलगाववादियों की सियासत और हिंसक प्रदर्शनों से गर्म रहने वाले जम्मू-कश्मीर में बीते पांच माह के दौरान ब हुत कुछ बदला है। प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के बदलाव के बीच सियासत भी बदली है।

पांच अगस्त के बाद से जिस तरह से जम्मू-कश्मीर के हालात ने करवट बदली, जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित राज्यों में पुनर्गठित हुआ, उसके बाद तो कई राजनीतिक पंडित कहने लगे थे कि गर्मियां तो गर्मियां इस बार सर्दियां भी खूब गर्म रहेंगी। हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाएंगे। कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपुल्स कांफ्रेंस जैसे संगठन जो अलगाववादियों और मुख्यधारा की सियासत के बीच भारत का झंडा थामकर एक बफर जोन प्रदान करते हैं, वे पूरी तरह गायब हो जाएंगे। मुख्यधारा की सियासत पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, स्थानीय युवकों के हाथ में सिर्फ क्लाशनिकोव राइफल और पत्थर नजर आएंगे। शुरू में कुछ समय तक ये सभी आशंकाएं सही साबित होती नजर आने लगी थीं, लेकिन दिन बीतने के साथ ये आशंकाएं धीरे-धीरे मिटने लगीं। स्थानीय युवाओं के हाथ में क्लाशनिकोव और पत्थर नहीं रहे, वे खेल के मैदान और स्कूलों में नजर आ रहे हैं। आइलीग फुटबॉल प्रतियोगिता जिसके पहले दो मैच रद हो चुके हैं, के 26 दिसंबर को होने वाले मुकाबले का युवा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। स्थानीय प्रशासन और सेना तथा पुलिस द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में ठंड के बावजूद युवा हिस्सा ले रहे हैं।

श्रीनगर के टीआरसी मैदान में बिछी बर्फ की मोटी चादर के बीच फुटबॉल खेलते रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी। सौजन्य-रियल कश्मीर

स्थानीय युवाओं का अलगाववाद और आतंकवाद से पूरी तरह उदासीन रवैया अपनाया जाना जम्मू-कश्मीर में बदलाव का प्रतीक है और शायद यही कारण है कि कल तक अनुच्छेद 370 की बहाली तक किसी भी तरह की सियासी गतिविधि से दूर रहने का दावा करने वाली नेशनल कांफ्रेंस ने भी धीरे-धीरे अपनी सियासी गतिविधियां बढ़नी शुरू कर दी है। दो दिन पहले नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी देवेंद्र राणा द्वारा जारी यह बयान कि सभी वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को रिहा किया जाए ताकि जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हों। साथ ही उनकी ही पार्टी के सांसद हसनैन मसूदी का यह कहना कि सभी राजनीतिक दल अपने नेताओं की रिहाई के लिए एकजुट होकर न्यायालय जाने पर विचार कर रहे हैं, बताता है कि जिस बफर जोन के पूरी तरह समाप्त होने की बात की जा रही थी, वह समाप्त तो हुआ है, पर उसने अपनी सियासत का रुख पूरी तरह मुख्यधारा की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है।

गत पांच अगस्त से श्रीनगर नगर निगम की गतिविधियों से पूरी तरह दूर रहने वाले श्रीनगर के मेयर और पीपुल्स कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता जुनैद अजीम मट्टू भी अपनी कुर्सी हिलते देख फिर सक्रिय हुए हैं। इन सबके बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से निष्कासित दो पूर्व मंत्रियों अल्ताफ बुखारी और डॉ. हसीब द्राबू ने पहले जम्मू में और उसके बाद श्रीनगर में कांग्रेस, नेकां एवं पीडीपी के अलावा कुछ अन्य दलों के नेताओं के साथ संपर्क साध बदले हालात में जम्मू-कश्मीर की सियासत में गर्मी पैदा करने का प्रयास करते हुए नए नारों के आधार पर सियासी मोर्चा बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या नागरिकता कानून पर सरकार अपना पक्ष सही तरह से पेश नहीं कर पाई है?

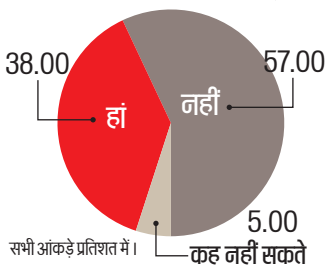

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या संसद के दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

चुनना होगा एक को–सत्ता या सिद्धांत,
उद्धव जी अब सोचिए बैठ जरा एकांत।
बैठ जरा एकांत कि क्या है अधिक जरूरी,
अब ढोना सिद्धांत नहीं बिल्कुल मजबूरी!
राहुल का आदेश पड़ेगा अब तो सुनना,
सावरकर–कांग्रेस बीच है तुमको चुनना।

– ओमप्रकाश तिवारी

दो टूक

अश्लीलता पर लगे अंकुश

सिनेमा निर्माण एक सामाजिक एवं नैतिक दायित्व से पूर्ण कर्म है जिसका ध्यान इससे जुड़े लोगों को रखना चाहिए

पीयूष द्विवेदी
कला–संस्कृति मामलों के जानकार

देश में दुष्कर्म के मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। प्रश्न यह है कि इस समस्या का मूल कारण क्या है और किस तरह इसे रोका जा सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि कड़ा कानून बनाकर दुष्कर्म पर अंकुश लगाया जा सकता है तो कुछ का मानना है कि दुष्कर्मियों को गोली मार देना इसका उपाय है, लेकिन विचार करें तो वास्तव में इन सब बातों में अज्ञान आधारित भावुकता ही अधिक है, ठोस समाधान नहीं। देश में दुष्कर्म को लेकर पहले से ही बहुत सख्त कानून मौजूद है, उसे और कितना भी सख्त कर लिया जाए, वह दुष्कर्म को रोकने में बहुत अधिक कारगर नहीं हो सकता। कारण यह कि दुष्कर्म चोरी-तस्करी जैसा कोई पेशेवर अपराध नहीं है, बल्कि यौन कुंठाओं और मानसिक विकृति से अभिप्रेरित एक बर्बर आपराधिक कृत्य है।

अब प्रश्न यह उठता है कि फिर दुष्कर्म को रोकने का उपाय क्या है? इस पर अंकुश के लिए आवश्यक है कि लोगों में यौन कुंठा और विकृति पैदा करने वाले कारकों पर लगाम लगाई जाए जिनमें एक प्रमुख कारक है-पॉर्न। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से सभी पॉर्न वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हालांकि बीते दिनों केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि सरकार ने तीन सौ के करीब चाइल्ड पॉर्न की वेबसाइटों को प्रतिबंधित किया है। यह अच्छा है कि अब दुष्कर्म के पीछे पॉर्न को जिम्मेदार मानकर बहस होने लगी है, लेकिन यह समस्या सिर्फ इसकी वेबसाइटों तक सीमित नहीं है, बल्कि टीवी, सिनेमा जैसे मनोरंजन के क्षेत्रों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया है।

आजकल तमाम फिल्मों में रोमांस के नामपर जिस प्रकार नायक-नायिका के अंतरंग दृश्यों का एकदम नग्न और खुला प्रदर्शन होने लगा है, उसे पॉर्न तो नहीं, लेकिन 'सॉफ्ट पॉर्न' अवश्य कहा जा सकता है। ऐसे अंतरंग दृश्य हेट स्टोरी, जिस्म, मर्डर, रागिनी एमएमएस जैसी कितनी ही फिल्मों की पहचान हैं। इन फिल्मों का हर भाग इसी दावे के साथ आता है कि उसमें पिछले भाग की तुलना में अधिक अंतरंग दृश्य हैं। हालांकि मुख्यधारा की सिनेमा में तो फिर भी सेंसर बोर्ड के कारण थोड़ी मर्यादा रहती है, लेकिन इससे अलग आजकल ओटीटी माध्यमों पर प्रसारित वेब सीरीजों में तो जैसे होड़ मची है कि कौन सेक्स दृश्यों को कितनी अधिक नग्नता और मर्यादाहीनता के साथ दिखा सकता है।

आज अश्लीलता की सब सीमाएं पार करतीं वेब सीरीजें देश के कई प्रमुख ओटीटी माध्यमों पर प्रसारित हो रही हैं। इन वेब सीरीजों में न तो संबंधों की मर्यादा का ध्यान रखा जाता है और न ही लोकलाज की भावना का। इनके अलावा कितने ही छोटे-छोटे ओटीटी माध्यम भी हैं, जिनका निर्माण ही शायद वेब सीरीज के नाम पर 'सॉफ्ट पॉर्न' दिखाने के लिए हुआ है। उन पर मौजूद सामग्रियों में और कुछ होता हो नहीं है। साथ ही वीडियो के सबसे सहज और लोकप्रिय माध्यम यूट्यूब पर भी इस तरह की सामग्री की भरमार है, लेकिन समस्या यह है कि इन माध्यमों के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है, इस कारण 'कलात्मक आजादी' के नामपर इन्हें मनमानी चीजें प्रस्तुत करने में कोई बाधा नहीं होती। दुखद किंतु सत्य है कि इस प्रकार की कथित मनोरंजन सामग्री के समर्थक भी हैं। उनका तर्क होता है कि जो समाज में हो रहा है, उसी को दिखाया जा रहा है। यहां सवाल है कि क्या सिनेमा समाज की कोरी नकल होती है? क्या उसकी अपनी कोई मौलिकता और अंतर्दृष्टि नहीं होती? क्या वह सबकुछ वैसे ही प्रस्तुत करती है जैसे समाज में हो रहा होता है? इन सवालों का कोई संतोषप्रद जवाब इन कथित मनोरंजन सामग्रियों के समर्थकों के पास शायद ही हो।

एक तर्क यह भी दिया जाता है कि अगर ये चीजें दर्शकों को पसंद आईं तो वे देखेंगे वर्ना नहीं देखेंगे। अब अगर दर्शकों की इच्छाओं को आधार बनाकर ही चला जाए तब तो दर्शक और भी बहुत कुछ देखना एवं करना चाहते हैं तो क्या उन्हें उसकी आजादी दे दी जाएगी। ऐसा नहीं होता। सिनेमा निर्माण एक सामाजिक एवं नैतिक दायित्व से पूर्ण कर्म है जिसका ध्यान इससे जुड़े लोगों को रखना चाहिए। रही बात कलात्मक आजादी की तो कलात्मकता तो इस बात में है जब आप किसी अश्लील लगने वाले दृश्य को भी ऐसे फिल्मा लें कि बात संप्रेषित भी हो जाए और अश्लीलता का प्रदर्शन भी न हो। पुरानी फिल्मों में फिल्माए जाने वाले अंतरंग रुमानी दृश्य या दुष्कर्म के दृश्य इसका उदाहरण हैं, जिनमें संबंधित व्यक्तियों की एक झलक देने के बाद कैमरा बंद दरवाजे, दीये, चलते पंखे, खुली खिड़की या किसी अन्य वस्तु की तरफ घूम जाता था और संगीत के माध्यम से पार्श्व में हो रही क्रिया का आभास दर्शक को दिया जाता था। वास्तव में इसे ही कला कहते हैं। फिर आज के इस तकनीक संपन्न समय में अंतरंग दृश्यों को फिल्माने के लिए ऐसे कुछ नए सांकेतिक तरीके क्यों नहीं ईजाद किए और अपनाए जा सकते?

प्रतीकात्मक

निःसंदेह सेक्स कोई वर्जित या दूषित चीज नहीं है, लेकिन समाज में उसको लेकर कुछ मर्यादाएं निश्चित की गई हैं, ताकि समाज व्यभिचार के मार्ग पर न बढ़े। आज मनोरंजन के नाम पर उक्त प्रकार की सामग्रियों द्वारा उन मर्यादाओं को नष्ट करने का तो प्रयास किया ही जा रहा है, यहीं से लोगों के मन-मस्तिष्क में यौन विकृति भी पनप रही है, जो कि दुष्कर्म जैसी घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। अतः सरकार को न केवल पॉर्न वेबसाइटों पर प्रतिबंध की दिशा में काम करना चाहिए, बल्कि मनोरंजन की आड़ में परोसे जा रहे इस सिनेमाई 'मिनी पोर्न' पर अंकुश लगाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। अगर पॉर्न और सॉफ्ट पॉर्न दोनों को पूरी तरह से रोका जा सके तो निःसंदेह दुष्कर्म के मामलों में बड़ी मात्रा में कमी आ सकती है।

1 जनवरी 2020 से ग्राहकों को बैंक से एनईएफटी के जरिये किए जाने वाले लेन-देन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 18 दिसंबर 2019

डाटागीरी

बीते साल वन्यजीव अपराध के 388 मामले हुए दर्ज

देश में तेंदुओं और इंसानों के बीच संघर्ष के मामले पिछले कुछ सालों में बढ़ गए हैं। वर्ष 2018 में वन्यजीव अपराध के सबसे ज्यादा मामले भी तेंदुओं से ही संबंधित थे। कुल 388 मामलों में तेंदुओं के 81 और बाघ से संबंधित 42 मामले सामने आए। दोनों के मामलों को मिलाकर देखें तो प्रत्येक तीन में से एक मामला इन्हीं दो जानवरों से संबंधित था।

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

वर्ष 2018 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव संबंधी अपराधों के 388 मामले दर्ज किए गए। यह जानकारी बीते दिनों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संसद में दिए गए एक जवाब से सामने आई है।

388 में 123 मामले यानी दर्ज किए गए प्रत्येक तीन में से एक मामला तेंदुए या बाघ से संबंधित था। इनमें 81 मामले यानी प्रत्येक पांच में से एक मामला तेंदुए से संबंधित तो 42 मामले बाघ से संबंधित थे। इन सबके बीच प्रवासी पक्षियों से संबंधित 61 मामले दर्ज किए गए। 388 में से 259 मामले यानी हर तीन में से दो मामले केवल पांच प्रजातियों से ही संबंधित थे। इसमें तेंदुए (21 प्रतिशत), संरक्षित पक्षी (16 प्रतिशत), बाघ (11 प्रतिशत) के साथ तारा कछुआ या समुद्री कछुए (10 प्रतिशत) और हिरण (नौ प्रतिशत) थे।

अगर बड़े स्तर पर बात की जाए तो 90 फीसद मामले 10 प्रजातियों के वन्य जीवों से ही जुड़े हैं। हाथी से जुड़े मामले सात प्रतिशत, सांप से जुड़े पांच प्रतिशत, गैंडे के चार प्रतिशत, नेवले के चार प्रतिशत और पैंगोलिन के चार प्रतिशत से थोड़ा कम मामले सामने आए हैं।

शेष दस प्रतिशत मामले दस अन्य प्रजातियों से संबंधित हैं, जिनमें टोके गेको (छिपकली की एक प्रजाति) और बंदर शामिल थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2016 के बाद से वन्यजीव अपराध के मामलों की संख्या में कमी आई है, लेकिन 2017 की तुलना में 2018 में थोड़े मामले बढ़ गए। 2016 में 565 मामले पंजीकृत किए गए थे और 2017 में 342 केस दर्ज किए गए थे।

2018 में देश में वन्यजीव अपराध

प्रजाति	दर्ज मामले	हिस्सा (% में)
तेंदुए	81	20.9
संरक्षित पक्षी	61	15.7
बाघ	42	10.8
तारा कछुआ और समुद्री कछुआ	39	10.1
हिरण	36	9.3
हाथी	27	7.0
सांप	19	4.9
गैंडा	16	4.1
नेवला	15	3.9
पैंगोलिन	14	3.6
अन्य	38	9.8
कुल	388	100

किए जा रहे हैं प्रयास : मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जानवरों के अवैध व्यापार और शिकार के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई है। केंद्र संचालित योजनाओं जैसे, 'प्रोजेक्ट टाइगर', 'प्रोजेक्ट एलीफेंट 'वन्यजीव के आवासों का विकास' तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र की ओर से धनराशि प्रदान की जाती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, वन्यजीव अपराध के सबसे ज्यादा तेंदुओं से संबंधित थे। फाइल

-15 डिग्री तापमान में भी संवर रही केदारपुरी

जागरण विशेष ▶ बर्फबारी के बीच स्वयं को स्वस्थ और सुरक्षित रखना भी है श्रमिकों के समक्ष बड़ी चुनौती

अप्रैल से शुरू होने वाले यात्रा सीजन से पहले निर्माण कार्यों को पूरा करने का है लक्ष्य

बृजेश भट्ट, रुद्रप्रयाग

केदारपुरी में छह फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। तापमान माइनस 15 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, लेकिन बर्फ के टीलों और हाड़ कंपा देने वाली तीखी ठंड के बीच भी केदारपुरी को संवारने का कार्य रुका नहीं है। प्रयास है कि अप्रैल से शुरू होने वाले यात्रा सीजन की शुरुआत से पहले इसे पूर्ण कर दिखाया जाए।

वुड स्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी और प्रशासन के सदस्यों-श्रमिकों के सामने चुनौती कम नहीं है। पुनर्निर्माण कार्यों की सूची लंबी है। यात्रा सीजन में केदारपुरी में करीब सात हजार लोग स्थायी रूप से बने रहते हैं। इनमें मंदिर समिति के कर्मचारी, व्यापारी, पुलिस-प्रशासन समेत विभिन्न विभागों के कर्मचारी, श्रमिक और तीर्थ पुरोहित सम्मिलित होते हैं। इनके रहने के लिए कुछ पक्के भवन हैं और शेष टेंट कॉलोनी तैयार की जाती है। आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनरुद्धार भी एक बड़ा लक्ष्य है। आस्था पथ और तीर्थ पुरोहितों के लिए 146 मकानों का निर्माण किया जा रहा है। भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए सरस्वती नदी और गरुड़चट्टी जाने के लिए मंदाकिनी नदी पर पुलों का निर्माण भी अहम है। इसके अतिरिक्त यहां एक शॉपिंग मॉल का निर्माण किया जाना है। इन निर्माण कार्यों का दायित्व उठा रही कंपनी के बेड़े में वर्तमान में 50 श्रमिक डटे हुए हैं। बर्फबारी के बीच उनके सामने चुनौती स्वयं को स्वस्थ और सुरक्षित रखने की भी है। बैरकों के ऊपर अधिक बर्फ जमा होने से छत ढहने का खतरा बना रहता है। इसलिए नियमित अंतराल पर बर्फ को हटाना जरूरी है। इसके अलावा मशीनों को बर्फ में दबने से बचाने की चुनौती भी है। ऐसी स्थिति में श्रमिकों को सोने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है।

एक साथ नहीं सोते श्रमिक : यहां काम कर रहे श्रमिक 52 वर्षीय काली प्रसाद बताते हैं कि बर्फबारी से कोई अनहोनी न घटे, इसलिए सभी श्रमिक एक साथ नहीं सोते। वह रात में स्वयं भी साथियों के साथ दो-दो घंटे के अंतराल में ड्यूटी देते हैं। बीच-बीच में उन्हें बैरक की छत और उसके आसपास से बर्फ हटानी पड़ती है। वह बीते पांच वर्षों से शीतकाल के दौरान केदारपुरी में कार्य कर रहे हैं। चमोली निवासी इंद्र सिंह, रुद्रप्रयाग निवासी नवील पुरोहित और प्रमोद बताते हैं कि शीतकाल के छह महीने धाम में आठ-दस फीट तक बर्फ जमी रहती है। फिर भी सभी श्रमिक नियमित टाइम टेबल के हिसाब से ही कार्य करते हैं।

पहले काम फिर खाना : कंपनी के प्रोजेक्ट प्रभारी मनोज सेमवाल ने बताया कि भोर होने पर बैरक की छत, आंगन और रास्ते से बर्फ हटाने के बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसीलिए यह काम करने के बाद ही सभी नाश्ता करते हैं। फिर मशीनों के ऊपर से बर्फ हटाकर उनकी नियमित सर्विसिंग, तीर्थ पुरोहितों के निर्माणाधीन मकानों में लकड़ी, वेल्डिंग, टाइल्स सेटिंग जैसे अन्य काम दोपहर तक चलते हैं। दूसरी शिफ्ट दोपहर के भोजन के बाद एक से चार बजे तक चलती है। शरीर में गर्माहट रहे, इसके लिए वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि की भी व्यवस्था है। साथ ही कमरों में रूम हीटर भी लगाए गए हैं।

रंग ला रही मेहनत : नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (निम) उत्तरकाशी के पूर्व प्रधानाचार्य कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में वर्ष 2014 से केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुए। हालांकि, तब केदारपुरी को नए सिरे से बसाना आसान नहीं था, लेकिन कर्नल कोठियाल ने चुनौतियां स्वीकार करते हुए शीतकाल में भी निर्माण कार्य जारी रखे। इसी का नतीजा है कि अब केदारपुरी नए रूप-रंग में है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में भारी बर्फबारी के चलते कंस्ट्रक्शन कंपनी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 30 श्रमिक सोनप्रयाग वापस लौट गए थे। जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि मौसम खुलने पर इन्हें वापस केदारनाथ भेज दिया जाएगा। ताकि कार्य समय से पूरे हो सकें।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

बर्फ को हटाने का काम करता मजदूर।

केदारपुरी में जेसीबी से बर्फ हटाते निर्माणकर्मी। सभी फोटो साभार : वुड स्टोन कंस्ट्रक्शन

बुलंदी की राह पर बढ़ती 'हिदायत'

राहुल कुमार, बांका

▶ समाज के तानों के बीच लक्ष्य की ओर बढ़ रही बिहार वॉलीबॉल की पहली मुस्लिम महिला खिलाड़ी

▶ दसवीं की छात्रा चार बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में ले चुकी है हिस्सा, अब राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने का लक्ष्य

घर-परिवार साथ दे तो समाज की 'हिदायतें' बुलंदी की राह में बाधक नहीं बन सकती। यह बात बांका जिले (बिहार) के अमरपुर के पुरानी कलाली की तंग गलियों के एक कमरे में परिवार के साथ रहने वाली हिदायत खातून पर लागू होती है। 16 वर्ष की छोटी सी उम्र में राष्ट्रीय वॉलीबॉल में चार बार बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। चांदन नदी किनारे खाने-पीने के सामान की छोटी सी दुकान चला कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले अमरपुर धीमड़ा निवासी रियाज आलम की बेटी हिदायत खातून बिहार की पहली मुस्लिम महिला वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं।

हिदायत जब आठवीं में ही पढ़ रही थीं, तब अंडर-14 बालिका वॉलीबॉल में बिहार टीम का हिस्सा बनीं। अब वह मैट्रिक में हैं और अंडर-17 बिहार बालिका टीम का हिस्सा भी। हिदायत जहां रह रहीं हैं और जिस समाज से हैं, वहां रूढ़िवादिता कूट-कूटकर भरी है। हिदायत कहती हैं, 'हमारे आसपास के इलाके में भी मुस्लिम परिवार की कोई लड़की वॉलीबॉल नहीं खेलती है। ऐसे में हर दिन अभ्यास के लिए खेल वाली पोशाक में निकलना समाज की नजरों को खूब चुभता है। अब्बा और अम्मी को तरह-तरह के ताने सुनने पड़ रहे हैं। लोग कहते हैं-बेटी को बेटा की पोशाक पहनाकर क्या कर लेगा? हमारे परिवार में कौन लड़की खेलती है, जो इसे पूरा देश घुमा रही है? अब्बा-अम्मी इन तानों को तरजीह नहीं देते। मैं उनकी अनुमति व प्रोत्साहन से खेल रही हूं।' यही वजह है कि केवल माता-पिता के साथ के बल पर व न केवल लगातार खेल रही हैं, बल्कि आगे बढ़ते हुए परिवार का नाम भी देश में रोशन कर रही हैं। आज कई ट्रॉफी और मेडल उनके एक कमरे के घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। हिदायत के मुताबिक, अब अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के लिए राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में चयनित होना उनका एकमात्र लक्ष्य है।

प्रदर्शन ने किया है प्रभावित : हिदायत के प्रशिक्षक सह स्टेट रेफरी प्रदीप कुमार बताते हैं कि हिदायत ने पहली बार कर्नाटक की मेजबानी में नेशनल गेम खेला। कर्नाटक के बाद तालपेडीगुड़म, फिर महाराष्ट्र के शिरडी और फिर गुजरात के अहमदाबाद में भी खेल चुकी है। उसके प्रदर्शन ने सबको प्रभावित किया है। उसका कॅरियर लंबा।

पुरस्कारों और प्रमाण पत्रों के साथ हिदायत खातून। जागरण

निशाना लगाने से पहले अंगुली का निशान लेगी पिस्टल

फिंगर प्रिंट गन सेफ्टी डिवाइस तैयार करने वाले युवक (बाएं से) सुमन कुमार, सिद्धार्थ शर्मा, जावेद रजा अंसारी और विवेक कुमार। जागरण

शशि भूषण कुमार, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)

▶ बिहार के चार युवाओं ने ईजाद की सेफ्टी ग्रिप डिवाइस

▶ फिंगर प्रिंट से पिस्टल को कर सकते लॉक या अनलॉक

पिस्टल अब अंगुली का निशान लेगी, फिर निशाना साधा जा सकेगा। यदि कोई छीनने की कोशिश करता है तो पिस्टल स्वतः लॉक हो जाएगी। चोरी होने पर कोई बेजा इस्तेमाल भी नहीं कर सकेगा। यह संभव होगा 'सेफ्टी ग्रिप डिवाइस' की बदौलत। 12वीं पास बिहार के चार युवाओं ने पिस्टल के लिए यह सेफ्टी फीचर ईजाद किया है। हालांकि, अभी इसका ट्रायल चल रहा है।

इस तरह आया विचार : अक्सर जीवन की कोई घटना कोई नया रास्ता दिखा जाती है। इस सेफ्टी फीचर को ईजाद करने के पीछे भी यही कहानी छिपी है। दरअसल, 12वीं की पढ़ाई के बाद दिल्ली में काम कर रहे सहरसा निवासी सिद्धार्थ कुमार के एक परिचित के साथ दो साल पहले बंदूक से गलती से गोली चलने से एक हादसा हो गया था। तब उन्होंने सोचा कि मोबाइल फोन की तरह फिंगर प्रिंट से बंदूक या पिस्टल को क्यों नहीं लॉक या अनलॉक कर सकते? शुरू से रोबोटिक्स और विज्ञान में रुचि रखने वाले सिद्धार्थ ने यह बात अपने मित्र सीतामढ़ी निवासी सुमन कुमार को बताई। फिर दोनों ने इस पर काम शुरू किया। टीम में आगे चलकर पूर्वी चंपारण निवासी विवेक कुमार और सहरसा के जावेद रजा अंसारी जुड़ गए। दो साल की कड़ी मेहनत के बाद इसी साल अप्रैल में सेफ्टी ग्रिप डिवाइस तैयार हुई। चारों इसी साल सितंबर में भारत सरकार के पुलिस आधुनिकीकरण विभाग के संयुक्त सचिव विवेक भारद्वाज से दिल्ली में मिले थे। उनके निर्देश पर इस डिवाइस के ट्रायल के लिए गत 13 सितंबर को उत्तर प्रदेश व हरियाणा के डीजीपी, आइजी असम राइफल, बीएसएफ, सीआइएसएफ, सीआरपीएफ, आइटीबीपी व एसएसबी को पत्र लिखा गया। 12 दिसंबर को दिल्ली के एनएसजी के हेडक्वार्टर में इसका ट्रायल किया गया। उस समय चारों दोस्त मौजूद थे।

फिंगर प्रिंट गन सेफ्टी डिवाइस लगा हथियार। जागरण

इस डिवाइस की खासियत यह है कि इसमें एक साथ 50 लोगों के फिंगर प्रिंट जोड़े जा सकते हैं। चोरी होने पर हथियार में लगे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से उसे ट्रैक किया जा सकता है। वहीं, अगर कोई हथियार छीनने की कोशिश करता है तो पिस्टल तुरंत लॉक हो जाएगी। साथ ही इसमें वॉयस रिकार्डर भी लगाया गया है। जिस तरह बॉयोमीट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाई जाती है, यह तकनीक ठीक उसी तरह है।

कश्मीर के सेब से महंगा है शिवालिक का अमरूद

हरिओम शर्मा, बेहट (सहारनपुर)

▶ शिवालिक की तलहटी में हो रही पैदावार, आकार बड़ा व उम्दा स्वाद

▶ सेब से ढाई-तीन गुना महंगा है अमरूद, बदल रहा किसानों की किस्मत

आम की मिठास के लिए मशहूर शिवालिक की तलहटी में अब अमरूद भी रंग दिखा रहा है। गुणवत्ता और स्वाद के लिहाज से यहां का अमरूद कश्मीर की वादियों से आए सेब को भी मात दे रहा है। कश्मीरी सेब का भाव 40-50 रुपये किलो है, जबकि शिवालिक के अमरूद की कीमत 120 रुपये किलो तक। पिछले दो साल से अमरूद का यह रुतबा कायम है।

शिवालिक की पहाड़ियों में बसे बेहट तहसील क्षेत्र को आम की उत्कृष्ट खेती के लिए जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय आम प्रदर्शनियों में भी यहां का आम छाया रहता है। हर साल यहां से करोड़ों रुपये का आम निर्यात किया जाता है। यह क्षेत्र फल पट्टी घोषित है। बदली स्थितियों में शिवालिक पहाड़ियों के बीच बसे घाड़ क्षेत्र ने अब अमरूद उत्पादन में भी नया कीर्तिमान बनाया है।

सेब से महंगा होने की बड़ी वजह यह है कि यहां का अमरूद सामान्य अमरूद के मुकाबले काफी बड़ा व कई गुना मीठा होता है। मधुमेह रोगियों के लिए इसे काफी फायदेमंद माना जाता है। यही इसका आकर्षण भी है। यही कारण है कि यहां के किसान भी अमरूद को आम से अधिक फायदे का सौदा मानने लगे हैं। कश्मीर से यहां पहुंचने वाले सेब की कीमत 40 से 50 रुपये किलो है, जबकि अमरूद 80 से 120 रुपये प्रति किलो तक बिक जाता है।

शिवालिक का अमरूद सामान्य अमरूद से बड़ा व कई गुना मीठा होता है। फाइल

संयुक्त फसल को देते हैं तवज्जो

पिछले 50 साल से बागवानी कर रहे मु. हाशिम का कहना है कि तीन-चार साल से क्षेत्र में अमरूद की खेती ने बढ़त बना ली है। नारियल, सफेदा, गुलाबिया, बर्फखाना, थाइलैंड व बनारसी प्रजातियों से अमरूद की शुरुआत हुई थी। पिछले दो साल से नई प्रजाति वन केजी को किसान तवज्जो दे रहे हैं। इसका पौधा 80 से 100 रुपये तक मिलता है, जबकि अन्य प्रजातियों के पौधे 30-40 रुपये में मिल जाते हैं। हाशिम बताते हैं कि अमरूद का बाग दो वर्ष में फल देने लगता है, जबकि आम से पांच साल बाद आमदनी मिलनी शुरू हो पाती है। आम और अमरूद का संयुक्त बाग लगाने पर दोनों की रखवाली एक साथ हो जाती है। इसके चलते भी घाड़ क्षेत्र के अधिकतर किसान इसी पद्धति से संयुक्त बाग लगाते हैं।

इस उपकरण से बीज होंगे गायब, तरबूज रहेगा सलामत

मनोज त्रिपाठी, जालंधर

तरबूज के बीज उसको खाने का मजा किरकिरा कर देते हैं। इसका विकल्प तलाशते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआइटी) जालंधर के इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कुलदीप सिंह नागला ने तरबूज से बीज निकालने वाले उपकरण का निर्माण किया है। यह उपकरण बीज निकालते समय तरबूज के मुख्य भाग को बिल्कुल भी बिखरने नहीं देगा।

इलेक्ट्रो मैकेनिकल तकनीक से तैयार उपकरण को बिजली व बैट्री के अलावा हाथ से भी चलाया जा सकेगा। इसकी लागत भी 500 से 2,000 हजार रुपये तक आएगी। एनआइटी ने इस नए अविष्कार को पेटेंट कराने की कवायद शुरू कर दी है।

तरबूज का सबसे बड़ा बाजार चीन में : इस फल की सबसे ज्यादा पैदावार चीन में हो रही है। चीन में 7.92 करोड़ टन, तुर्की में 39 लाख टन, ईरान में 28, ब्राजील में 20 तथा उज्बेकिस्तान में 19 लाख टन तरबूज का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है।

एनआइटी जालंधर में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह नागला अपनी डिवाइस पर काम करते हुए। जागरण

बीज से ऐसे ले सकते हैं लाभ : उपकरण से निकाले बीज का चूरा बनाकर या विभिन्न प्रकार की विधियों से प्रयोग कर औषधीय लाभ ले सकते हैं। बीज में मौजूद मैग्नीशियम दिल की बीमारी, बालों के झड़ने से रोकने, लंबे करने तथा चमक पैदा करने में सहायक है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा संबंधी रोगों और मुहांसों में भी लाभकारी है। डायबिटीज के रोगियों के लिए बीज लाभकारी है।

मोर को संजीवनी दे रहे 'हंस'

बलवान शर्मा, भिवानी

▶ अब तक लगभग 500 घायल मोरों का इलाज करवा चुके हैं हरियाणा के हंसराज

▶ हर बार सीजन में 100 से 150 मोर हो रहे हैं घायल, 70 फीसद की हो जाती है मौत

खेतों में कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से राष्ट्रीय पक्षी मोर के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल, बिजाई के दौरान किसान गेहूं के बीजों को बीमारी आदि से बचाने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें खाकर मोर बेहोश हो जाते हैं और कुत्ते आदि दूसरे जानवरों का शिकार बन जाते हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो बहुत जल्द मनमोहक नृत्य और खूबसूरत पंख के लिए राष्ट्रीय पक्षी बने मोर की पिहू-पिहू शांत हो सकती है। मोरों को इस खतरे से बचाने का संकल्प लिया है रियल सोसाइटी प्रवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल के चेयरमैन हंसराज ने। वह घायल मोरों को बचाने के लिए जी जान से जुटे हैं। वह अब तक लगभग 500 मोरों की जान बचा भी चुके हैं। उन्होंने घायल मोरों का उपचार के लिए एंबुलेंस और दवाओं की व्यवस्था भी की हुई है।

20 साल से जुटे हैं मुहिम में : हरियाणा के भिवानी जिले के गांव ढाणी हरि सिंह गुजरानी निवासी मास्टर हंसराज पिछले 20 साल से पूरे प्रदेश में मोर को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। उनका कहना है कि मोरों के मरने की घटनाएं पिछले सात-आठ साल में बढ़ी हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं, जहां मोर नाममात्र के ही बचे हैं। जीटी रोड बेल्ट में तो पहले से ही मोर बहुत कम हो चुके हैं। दादरी में कपूरी की पहाड़ी में अभी 250 से ज्यादा मोर संरक्षित हैं। हालांकि, किसी जमाने में यहां पर तीन से चार हजार मोर होते थे। हंसराज ने बताया कि लोहारू, डूडीवाला, अटेला, ढिगावा, बाढड़ा, कालूवाला सहित विभिन्न इलाकों से मोरों के घायल होने की शिकायतें आती हैं। गेहूं की बिजाई के सीजन में हर बार 100 से 150 मोर घायल हो जाते हैं, जिनमें से 70 फीसद की समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण मौत हो जाती है।

मोर की गर्दन की होती है तस्करी : हंसराज के अनुसार कुछ, घुमंतू जाति के लोग भी मोरों का शिकार करते हैं। वह इसके पंख बेच देते हैं। इसके अलावा विदेशों में मोर की गर्दन की तस्करी भी की जाती है।

घायल मोर को गोद में उठाए हरियाणा के भिवानी निवासी हंसराज। सौजन्य : हंसराज

जुताई के समय करें दवा का इस्तेमाल

हंसराज ने किसानों से अपील की है कि मोर किसानों की फसलों को दीमक से बचाते हैं और सांपों से भी रक्षा करते हैं। इसलिए किसानों को चाहिए कि वे बिजाई की बजाय खेत की जुताई के समय कीटनाशक का प्रयोग करें। इससे काफी हद तक मोरों को बचाया जा सकता है।

अब पाणिनि पद्धति से पढ़ेंगे बच्चे, तनाव मुक्त होगी शिक्षा

जागरण संवाददाता, रांची

▶ झारखंड में किसलय विद्यालय के पठन-पाठन का प्रशिक्षण लेने पहुंचे 10 सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक

झारखंड के शिक्षा विभाग ने पाणिनि पद्धति से बच्चों को पढ़ाने के किसलय विद्यालय के प्रयोग को अपनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत नवागढ़ पंचायत के 10 प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण शुरू किया गया है। ये शिक्षक प्रशिक्षण के बाद किसलय की पाणिनि पद्धति को अपने-अपने स्कूलों में जाकर उतारेंगे। छह महीने तक इन सभी स्कूलों के बच्चों को निगरानी में रखा जाएगा। यदि बच्चों की सीखने-पढ़ने और समझने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो फिर इस पद्धति को राज्य के सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा।

बीआइटी मेसरा स्थित किसलय विद्यालय में शिक्षकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण गत सोमवार से शुरू हुआ है। पहले चरण के प्रशिक्षण के बाद सभी शिक्षक अपने स्कूलों में जाकर इसी पद्धति से पठन-पाठन शुरू करेंगे। पाणिनि पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हर बच्चे के विकास के लिए उसके गुण-दोष को पहचानना जाता है और उसके बाद उसकी कमजोरियों को दूर किया जाता है। पहले चरण के प्रशिक्षण में शिक्षकों को यही बताया जाएगा कि कैसे वे अपनी-अपनी कक्षा के बच्चों के गुण-दोष को पहचानेंगे। अभी स्कूली शिक्षा में इसी बात का बड़ा अभाव है।

अब व्यवसाय बन गई है शिक्षा : किसलय विद्या मंदिर की प्राचार्या रमा पोपली कहती हैं कि हमारे बच्चे बहुत सारी क्षमताएं लेकर इस दुनिया में आते हैं। उनकी सारी क्षमताएं मुखर हों तथा उनकी समझ बेहतर हो तभी ये बच्चे देश के बेहतर नागरिक बनेंगे और तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले नवागढ़ पंचायत के ही कुछ शिक्षक इस विद्यालय में पठन-पाठन के तरीके जानने आए थे। वे यहां के अध्यापन से बेहद प्रभावित हुए। इसके बाद शिक्षकों ने अपने वरीय अधिकारियों को बताया। शिक्षा अधिकारियों का एक समूह गत 15 नवंबर को विद्यालय पहुंचा था। उन्होंने यहां के छात्रों तथा शिक्षकों से पाठ्य पद्धतियों के संबंध में जाना। शिक्षाधिकारी बच्चों से बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद ही राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

84 वर्षीय रॉय स्वेनिंगसेन अंटार्कटिक आइस मैराथन में भाग लेने वाले सबसे बुजुर्ग धावक बन गए हैं। उन्होंने यह दौड़ 11 घंटे 41 मिनट और 58 सेकंड में पूरी की। वह कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की राजधानी एडमोंटन के रहने वाले हैं।

बांस की तीलियों से खोल रहे समृद्धि के द्वार

तलाशी राह ▶ कोई बना रहा कबाब और अगरबत्ती स्टिक, कोई गढ़ रहा सजावट का सामान तो कोई थैला और कूड़ेदान

जेएनएन, नई दिल्ली

बांस उत्पादन के मामले में देश दूसरे नंबर पर है, लेकिन बांस उत्पादों के स्वदेशी बाजार पर चीन और वियतनाम का कब्जा है। भारत में बांस धीरे-धीरे ही सही, रोजगार के अवसर सृजित कर रहा है। अब नवोन्मेष, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और बेहतर बाजार की दरकार है। भारत ने गैर वन क्षेत्रों में भी बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कानूनी सुधार 2017 में किया, ताकि रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित हो सकें।

जनसंख्या नियोजन

एक अनुमान के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था में बांस का योगदान करीब 851 अरब रुपये है। विकासशील देश ही इसमें अग्रणी भूमिका में हैं। बांस की प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसकी मांग सौंदर्य और डिजाइन की दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के उपयोग को बांस के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का भी प्रयास तेज हुआ है। देश का उत्तरपूर्वी क्षेत्र बांस उत्पादन में समृद्ध है, जहां देश का 65 प्रतिशत और विश्व का 20 प्रतिशत बांस उत्पादित होता है। हालांकि अब देश के अन्य भागों में भी बांस के बूते समृद्धि और संभावनाओं की राह खोजी जा रही है...। जलपाईगुड़ी (बंगाल) से गौरव मिश्र, महासमुंद (छत्तीसगढ़) से राजेश निषाद और उत्तरकाशी (उत्तराखंड) से शैलेंद्र गोदियाल की रिपोर्ट :

स्वनिर्मित मशीन से कर रहे उत्पादन

सुब्रत घराई के जलपाईगुड़ी स्थित कारखाने में स्टिक तैयार करते कर्मचारी। जागरण

जलपाईगुड़ी : उत्तरी बंगाल में बांस के पेड़ बहुतायत हैं। बांस की तीलियां (स्टिक) बनाकर इन्हें देश के विभिन्न बाजारों में पहुंचाने में जलपाईगुड़ी निवासी सुब्रत घराई की सफलता को प्रेरक माना जा सकता है। सुब्रत ने जलपाईगुड़ी में ही बैंबू स्टिक बनाने का कारखाना स्थापित कर अनेक लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। उन्होंने कारखाने में लगाई गई मशीनें भी खुद ही बनाई हैं।

मैकेनिकल इंजीनियर सुब्रत कहते हैं, भारत में प्रतिवर्ष तीन लाख 20 हजार मीट्रिक टन बांस स्टिक की खपत है। इसका 70 प्रतिशत चीन और वियतनाम से आता है। अकेले चीन ही 60 हजार मीट्रिक टन स्टिक की आपूर्ति करता है। वहीं, वियतनाम 800 करोड़ रुपये की तीलियों (अगरबत्ती में इस्तेमाल होने वाली) की आपूर्ति कर रहा है।

सुब्रत की मानें तो बांस की तीलियों पर ही ध्यान केंद्रित कर दिया जाए तो चीन और वियतनाम जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा। लोगों को रोजगार भी मुहैया हो सकेगा। सुब्रत फिलहाल अगरबत्ती में इस्तेमाल होने वाली तीलियों के अलावा कबाब स्टिक और आइसक्रीम स्टिक भी तैयार कर रहे हैं। इनकी देश के विभिन्न हिस्सों में आपूर्ति करते हैं।

बना रहे बंदर, शेर, भालू और मोर

बांस से बनाए मयूर के साथ कलाकार घासीराम। नईदुनिया

महासमुंद : छत्तीसगढ़ के सोनासिल्ली गांव के आदिवासी घासीराम कमार बांस के बूते स्वउद्यम का सफल उदाहरण पेश कर रहे हैं। बांस से वह मोर, बंदर, भालू समेत कई तरह के पशु-पक्षियों की सुंदर आकृति गढ़ देते हैं। उनकी कला को देखने और सीखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। बाजार में बेहतर दाम भी मिल रहे हैं। घासीराम कहते हैं, सबसे पहले मैंने बांस से गेंदा का फूल बनाया था, जिसे काफी सराहना मिली। फिर प्रशासन ने मुझे बांस हस्तकला के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में कई एनजीओ और संस्थाओं से जुड़े लोग मुझसे यह हस्तकला सीख रहे हैं। प्रशिक्षण, संसाधन और बेहतर बाजार मिलने पर यह शिल्प जनजातीय समुदायों को सहज रोजगार मुहैया करा सकता है।

हस्तशिल्पकार विनोद द्वारा तैयार किए गए रिंगाल के उत्पाद। जागरण

रिंगाल हस्तशिल्प से गांव का कायाकल्प

उत्तरकाशी : उत्तराखंड के सीमांत उत्तरकाशी जिले के हलना गांव निवासी विनोद रिंगाल (बौना बांस) के सहारे पूरे गांव को स्वावलंबन की राह दिखाने में सफल हुए हैं। अपने पुश्तैनी व्यवसाय रिंगाल हस्तशिल्प को आगे बढ़ाते हुए अब वह हिमाचल और पंजाब तक भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनके बांस निर्मित कूड़ेदान मॉडल को नमामि गंगे परियोजना ने स्वीकृति दी है और अब बड़ा ऑर्डर मिलने की प्रतीक्षा है। बताते हैं, हर माह 25 हजार रुपये तक घर बैठे कमा लेते हैं। शहरों से ऑर्डर जुटाते हैं और गांव के प्रशिक्षित लोगों से उत्पाद तैयार कराते हैं। गांव के 70 परिवार भी इससे महीने में दस-दस हजार रुपये तक की कमाई कर रहे हैं। बैग, डस्टबिन जैसी वस्तुओं की खासी डिमांड है।

हस्तशिल्पकार विनोद। जागरण

ठंड का दिल-दिमाग पर असर, हार्ट अटैक व ब्रेन स्ट्रोक के मरीज बढ़े

- ठंड से होने वाली बीमारियों के मरीज 30 से 50 फीसद बढ़े
- गले में संक्रमण और निमोनिया के मामलों में भी इजाफा
- डॉक्टरों ने दी सावधानी बरतने की सलाह

सर्दी में बुजुर्गों और बच्चों को ज्यादा सतर्कता बरतने की सलाह देते हैं डॉक्टर। फाइल

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में इसी हफ्ते से शुरू हुई तेज ठंड ने लोगों के दिल और दिमाग पर असर डालना शुरू कर दिया है। अस्पतालों में हार्ट अटैक के मरीज 30 से 50 फीसद तक बढ़ गए हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आइसीसीयू में पहले हार्ट अटैक के रोज एक-दो मरीज आ रहे थे, लेकिन अब चार-पांच मरीज आ रहे हैं। दिमाग की नसों में खून का थक्का जमने से ब्रेन स्ट्रोक (लकवा) के औसतन तीन मरीज रोज पहुंच रहे हैं।

हार्ट की नसें सिकुड़ने का खतरा : हमीदिया अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आरएस मीना ने बताया कि ठंड में अन्य अंगों की तरह हार्ट की नसें सिकुड़ती हैं। खून भी गाढ़ा होता है। ऐसे में जिन मरीजों को दिल की आर्टरी (नसें) में पहले से कुछ ब्लॉकेज रहता है, उन्हें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इन दिनों दिल की अन्य बीमारियों के मरीज कम हुए हैं पर हार्ट अटैक के बढ़ गए हैं।

गले के संक्रमण व निमोनिया के मरीज भी 30 फीसद बढ़े : एलएन मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. विवेक त्रिपाठी ने बताया कि ठंड बढ़ने के साथ ही हार्ट अटैक के 25 फीसद मरीज बढ़े हैं। बच्चों में गले में संक्रमण, निमोनिया के मरीज 30 फीसदी तक बढ़े हैं। हमीदिया अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. आरएस यादव ने बताया कि अस्पताल में लकवा के मरीज बढ़े हैं। रोज दो-तीन मरीज ब्रेन स्ट्रोक के आ रहे हैं।

यह रखें सावधानियां

- सुबह धूप निकलने के पहले न निकलें। गुनगुना पानी पीएं।
- बीपी के मरीज नियमित दवाएं लें।
- बिना फिटनेस टेस्ट के टीएमटी या अन्य व्यायाम न करें।
- किसी अंग में कमजोरी या सुन्नपन आए तो फौरन डॉक्टर के पास पहुंचें।
- ठंड से बचने के लिए शरीर को पूरी तरह से ढंके, खासतौर पर सिर को।
- जिनका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है उन्हें निमोनिया का डर रहता है, इसलिए निमोनिया का टीका लगवाएं।
- डायबिटीज, हाई बीपी, क्रॉनिक किडनी रोगी विशेष ध्यान रखें।

आंखों की रोशनी पर भी असर

ठंड बुजुर्ग मरीजों की आंख पर भी असर डाल रही है। हमीदिया अस्पताल में नेत्र रोग विभाग के सह प्राध्यापक डॉ. एसएस कुबरे ने बताया कि दो दिन के भीतर दो मरीजों की एक-एक आंख की रोशनी सेंट्रल रेटिनल आर्टियरी ऑक्लूजन की वजह से चली गई। इस बीमारी में रेटिना को खून पहुंचाने वाली नस में रुकावट होने की वजह से रोशनी चली जाती है। बुजुर्गों को गुनगुना पानी खूब पीना चाहिए। आंख में अचानक दिखाई देना कम हो जाए तो आइ बॉल की मसाज करना चाहिए। नीचे की तरफ देखते हुए आंख को पांच सेकंड तक दबाकर रखने के बाद छोड़ना चाहिए।

'आयुष्मान भारत' से मध्य प्रदेश के छोटे जिलों में आसान होगा इलाज

नईदुनिया, भोपाल

- अस्पतालों के लिए एनएबीएच की मान्यता की शर्त खत्म होगी
- राज्य के 43 जिलों के और निजी अस्पताल होंगे योजना में शामिल

सरकारी अस्पतालों के लिए रिजर्व पैकेज कम किए जाएंगे। साथ ही छोटे जिलों में एनएबीएच की शर्त भी हटाई जाएगी।

- डॉ. जे विजय कुमार सीईओ, आयुष्मान भारत योजना

प्रतीकात्मक

मध्य प्रदेश के छोटे जिलों में 'आयुष्मान भारत' योजना के मरीजों का इलाज अब और आसान हो जाएगा। इसके लिए योजना में कई बड़े बदलाव करने की तैयारी है। प्रदेश के नौ बड़े जिलों को छोड़ बाकी 43 जिलों में आयुष्मान योजना में शामिल होने के लिए निजी अस्पतालों के लिए एनएबीएच (नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हास्पिटल्स) की मान्यता जरूरी नहीं होगी। एक-दो दिन में स्टेट हेल्थ एजेंसी की बोर्ड मीटिंग में इस पर निर्णय होने की उम्मीद है।

पिछले महीने आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी जिलों में कम से कम दो निजी अस्पतालों को योजना में शामिल करने को कहा था। उन्होंने कुछ और सुझाव दिए थे। इसके बाद आयुष्मान योजना का संचालन करने वाली स्टेट हेल्थ एजेंसी ने कई बड़े बदलाव की तैयारी की है। अभी योजना में निजी अस्पतालों को शामिल करने के लिए एनएबीएच की मान्यता की शर्त अनिवार्य है। अस्पतालों में सेवाओं की अच्छी गुणवत्ता के लिए तय मापदंडों के आधार पर यह सर्टिफिकेट दिया जाता है।

नौ शहरों को छोड़ बाकी पर मान्यता की शर्त नहीं : नई व्यवस्था लागू होने पर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत नौ शहरों को छोड़ बाकी जिलों के लिए एनएबीएच की शर्त अनिवार्य नहीं होगी। आलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, डिंडोरी समेत आठ हाई फोकस जिलों में निजी अस्पतालों के लिए 50 बिस्तर के शर्त भी हटाई जाएगी। वजह, इन जिलों में बड़े अस्पताल ही नहीं है। 10 बिस्तर वाले अस्पताल को भी योजना में शामिल किया जाएगा।

सरकारी अस्पतालों में इलाज की नहीं रहेगी मजबूरी : सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित 473 पैकेज (बीमारियां) को कम कर 219 किया जा रहा है। इस तरह बाकी बीमारियों का इलाज मरीज अपनी मर्जी से निजी या सरकारी अस्पतालों में करा सकेगा। अभी कई बीमारियों के इलाज की सुविधा जिला अस्पतालों तक में नहीं है। ऐसे में मरीजों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। आयुष्मान कार्ड होने पर भी मरीज इलाज के लिए भटकते रहते हैं।

हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्र सीखेंगे तेलुगु

महेंद्र सिंह मेहरा, सिरसा

- एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हरियाणा व तेलंगाना के विद्यार्थी एक-दूसरे की भाषा जानेंगे
- सिरसा जिले के हर ब्लॉक से दो स्कूलों को मिलाकर कुल 14 स्कूलों का किया गया चयन

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत विद्यार्थियों को दक्षिण भारत की भाषा सिखाई जाएगी। इसके लिए सिरसा जिले के 14 स्कूलों का चयन कर लिया है।

- नरेंद्र कुमार, सहायक परियोजना, समग्र शिक्षा अभियान, सिरसा

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान के तहत हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दक्षिण भारतीय भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा। अभियान के तहत हरियाणा व तेलंगाना के विद्यार्थी एक-दूसरे की भाषा जानेंगे। हरियाणा के विद्यार्थियों को तेलुगु भाषा सिखाई जाएगी, जबकि तेलंगाना के विद्यार्थी हरियाणवी बोली का ज्ञान लेंगे। इस कड़ी में सिरसा जिले के 14 स्कूलों (हर ब्लॉक से दो स्कूल) का चयन किया गया है।

जिन स्कूलों में तेलुगु भाषा सिखाई जानी है, उनमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत एबीआरसी (एडिशनल ब्लॉक रिसोर्स कोआर्डिनेटर) व बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद एक अध्यापक को कोआर्डिनेटर बनाकर तेलुगु भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बताया जाएगा तेलंगाना के इतिहास के बारे में : 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान के तहत स्कूल में सबसे पहले तेलंगाना के इतिहास बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके तहत वहां के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिलों व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना अधिकारी पवन सुथार ने स्कूलों में तेलुगु भाषा सिखाने को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में स्कूलों का चयन किया गया। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना के 76 फीसद लोग तेलुगु बोलते हैं।

राम विवाहोत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने की पहल

नवनीत श्रीवास्तव, अयोध्या

- अगले वर्ष प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद की कांफ्रेंस
- शोधपत्रों के जरिये विद्वानों के मध्य इस विरासत को किया जाएगा साझा

'सिय रघुबीर बिबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहिं, तिन्ह कहुं सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु।' अर्थात श्रीसीतारामजी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेमपूर्वक गाएंगे-सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है। रामनगरी की इस सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने की पहल होने जा रही है, जिसके केंद्र में डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विवि के कुलपति प्रो. मनोज दीक्षित होंगे।

माहात्म्य अयोध्या में प्रतिवर्ष अगहन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को प्रकट भी होता है, जब रामनगरी राम विवाहोत्सव के उल्लास में डूबती है। कहीं अवध एवं मिथिला की संस्कृति के अनुरूप विवाह की रस्म निभती है तो कहीं राम विवाह पर केंद्रित लीला की प्रस्तुति से विवाहोत्सव का उल्लास बिखरता है। अगले वर्ष अवध विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद (आइसीओएमओएस) की कांफ्रेंस प्रस्तावित है। इसमें राम विवाहोत्सव से संबंधित शोध पत्रों को रखा जाएगा। कुछ शोधपत्र तैयार भी कर लिए गए हैं। कांफ्रेंस में इन शोधपत्रों के जरिये राम विवाहोत्सव की विरासत को विद्वानों के मध्य साझा किया जाएगा। आइसीओएमओएस की कांफ्रेंस फरवरी माह में हो सकती है। पर्यटन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाले अवध विवि के कुलपति प्रो. मनोज दीक्षित कहते हैं कि बरसाने की होली को देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी जुटते हैं। यदि थोड़ा प्रयास किया जाए तो ऐसा ही मुकाम राम विवाहोत्सव को भी मिल सकता है। इसीलिए यह कोशिश की जा रही है।

हर माह होता है उत्सव

रामनगरी में कुछ एक ऐसे भी मंदिर हैं, जहां हर माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी भगवान के विवाहोत्सव की तरह मनाई जाती है। स्वर्गद्वार मुहल्ला स्थित विअहुतिभवन व गोलाघाट चौराहा के निकट स्थित मिथिलामणि मंडप जैसे मंदिरों में हर माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी भगवान के विवाह को समर्पित रहती है।

शिप्रा को प्रवाहमान व प्रदूषण मुक्त करने की कार्ययोजना तैयार

नईदुनिया, उज्जैन : मध्य प्रदेश की मोक्षदायिनी शिप्रा नदी की शुद्धि के लिए उज्जैन में आयोजित राष्ट्रीय जल सम्मेलन में देशभर से आए विशेषज्ञों ने मंगलवार को श्वेत पत्र जारी किया। इसमें शिप्रा को प्रवाहमान बनाने और प्रदूषण मुक्त करने के लिए 12 बिंदु पर कार्ययोजना बनाई गई। मैग्सेसे अवॉर्ड विजेता 'जल पुरूष' के नाम से ख्यात राजेंद्र सिंह ने कहा कि श्वेत पत्र में समाज और सरकार, दोनों की जिम्मेदारी तय की है। श्वेत पत्र जल्द ही सरकार को सौंपेंगे। अब अगर सरकार नदी साफ नहीं कर सकी तो उसे कुंभ जैसे आयोजन बंद कर देना चाहिए। इतिहास गवाह है कि कुंभ जैसे आयोजन भलाई-बुराई और नदियों को साफ रखने के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए किए जाते थे, लेकिन आधुनिक भारत में नदियों को मात्र उपयोग की वस्तु बना दिया है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह के साथ देशभर से आए 150 से अधिक जल योद्धा और जल सहेलियों ने मंगलवार शाम झालरिया मठ से रामघाट तक शिप्रा की शुद्धि के लिए युद्ध यात्रा निकाली। उन्होंने गोदावरी, कृष्णा, यमुना, बेतवा, चंबल समेत 11 नदियों के जल से शिप्रा का अभिषेक कर शिप्रा की शुद्धि का संकल्प लिया। सम्मेलन का बुधवार को समापन होगा।

नए साल में चिन्यालीसौड़ और गौचर को हेली सेवा

विकास गुसाईं, देहरादून

- सहस्रधारा हेलीपैड से दोनों स्थानों को भरी जाएगी उड़ान
- उड़ान योजना के तहत हेली सेवाओं का होना है संचालन

उत्तराखंड में उड़ान योजना के तहत नए वर्ष की शुरुआत में ही गौचर (चमोली) व चिन्यालीचौड़ (उत्तरकाशी) के लिए हेली सेवा शुरू हो जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सेवा प्रदाता कंपनी ने भी इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब जल्द ही शासन में तैयारियों को गति देने के लिए बैठक प्रस्तावित की गई है।

प्रदेश में उड़ान योजना के तहत तीन चरणों में इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। पहले और दूसरे चरण में वायुयान सेवाओं का संचालित प्रस्तावित है। इस योजना के तीसरे चरण में हेली सेवाओं का संचालन प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत प्रदेश के 16 स्थानों पर हेली सेवाओं का संचालन किया जाना है। अब विभाग की योजना सबसे पहले गौचर और चिन्यालीसौड़ तक हेली सेवा संचालित करने की है। ये दोनों हवाई सेवाएं देहरादून के सहस्रधारा हेलीपैड से संचालित की जाएंगी और हैरीटेज एविएशन इसका संचालन करेगा। गौचर से जोशीमठ और श्रीनगर के लिए भी हवाई सेवाएं प्रस्तावित की गई हैं लेकिन इनका संचालन अन्य कंपनी करेगी। फिलहाल सरकार का फोकस इन दिनों स्थानों से ही हेली सेवा शुरू करने पर है। इसके लिए सचिव नागरिक उड्डयन दिलीप जावलकर की संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। इस क्रम में सहस्रधारा के साथ ही गौचर और चिन्यालीसौड़ हेलीपैड को दुरुस्त करने को कहा गया है। सचिव नागरिक उड्डयन दिलीप जावलकर ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अधिकारियों को इसकी कार्ययोजना तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस वर्ष अंत अथवा नए वर्ष की शुरुआत में इनका संचालन किया जा सके।

खोजा विकल्प

हरिद्वार के भगवानपुर और बहादराबाद ब्लाकों के किसानों ने किया प्रयोग, राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे इन ब्लॉकों के गांवों में खेती चौपट कर रहे थे वन्यजीव, कैप का अगले साल तक 400 और किसानों को सगंध खेती से जोड़ने का है लक्ष्य

फसल पैटर्न बदलकर लिखी तरक्की की इबारत

केदार दत्त, देहरादून

- सगंध खेती के जरिये वर्तमान में वहां167 किसान सालाना कमा रहे करीब छह लाख

परेशानियों से जूझती खेती-किसानी को संबल देने को उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के भगवानपुर और बहादराबाद के किसानों ने रोशनी दिखाई है। राजाजी टाइगर रिजर्व (आरटीआर) से सटे इन ब्लॉकों में किसानों ने वन्यजीवों से पार पाने को फसल पैटर्न बदला और गन्ना, धान व गेहूं को छोड़ सगंध खेती शुरू की। इससे आर्थिकी संवरी तो वन्यजीवों के भय से मुक्ति मिल गई। वर्तमान में इन ब्लॉकों के 167 किसान सगंध खेती से जुड़े हैं। प्रति किसान सालाना करीब छह लाख की आय हो रही है।

खेती में बदलाव कर तरक्की की ये इबारत लिखी गई सगंध पौधा केंद्र (कैप) सेलाकुई के सहयोग से। भगवानपुर व बहादराबाद ब्लॉकों के 40 गांवों की खेती आरटीआर से सटी है। यहां हाथी, सूअर, नील गाय जैसे जानवर खड़ी फसल चौपट कर रहे थे। ऐसे में किसानों के सम्मुख दो ही विकल्प थे। या तो खेती छोड़ दें अथवा ऐसी फसलें लगाएं जो लाभकारी हो और वन्यजीवों से छुटकारा दिलाएं। कैप के जरिये संगध खेती

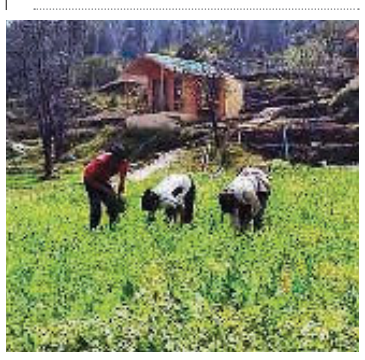

प्रतीकात्मक

का रास्ता उन्हें मिला। फिर दोनों ब्लॉकों के जंगल से लगे खेतों में लैमनग्रास, मिंट, कैमोमाइल जैसी सगंध फसलें लहलहाने लगीं। इनमें लागत कम व श्रम कम लगने के साथ ही अच्छी आय हो रही है। वन्यजीवों के खौफ से निजात मिल गई। वजह, सगंध फसलें जानवर नहीं खाते। सिकरोड़ा (भगवानपुर) के राव फरमूद बताते हैं कि वह 90 बीघे में सगंध खेती कर रहे हैं। लैमनग्रास व मिंट से तेल निकालने को आसवन संयंत्र लगा है। हर चार माह में इन फसलों से मिलने वाले 20 किलो तेल से वह दो लाख तक कमा लेते हैं। यह फायदा अन्य फसलों के मुकाबले कहीं अधिक है।

पीकेवीवाई में 17 एरोमा क्लस्टर : कैप के निदेशक डॉ. नृपेंद्र चौहान के अनुसार परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) में भगवानपुर में 13 व बहादराबाद में चार एरोमा क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। इनमें लगभग 167 किसान जुड़े हैं। अगले साल तक यह संख्या 400 हो जाएगी। यही नहीं, मनरेगा में भी सगंध फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

नजीर पेश कर रहे जगपाल व फारूख : बिशनपुर (बहादराबाद) के जगपाल सिंह की 35 बीघा भूमि बंजर पड़ी थी। गत वर्ष उन्होंने इसमें लैमनग्रास व मिंट की फसल लगाई। सवा साल में उन्हें 4.5 लाख का मुनाफा हुआ। सिकरोड़ा (भगवानपुर) के राव फारूख खां भी अपनी 55 बीघा भूमि में लैमनग्रास, मिंट, कैमोमाइल उगा रहे हैं। उनकी सालाना आय छह लाख रुपये है।

रेलवे स्टेशन होंगे 'दिव्यांग फ्रेंडली'

दीपेंद्र प्रताप सिंह, बरेली

- दक्षिण भारत के कुछ बड़े स्टेशनों पर व्यवस्था शुरू
- उत्तर रेलवे समेत अन्य जोन के ए-वन स्टेशन होंगे अपग्रेड
- दिव्यांगों की सुविधा के लिए फोल्डेबल रैंप तैयार किए जाएंगे

दिव्यांगों की सुविधा के लिए रेलवे विशेष इंतजाम करेगा। प्रतीकात्मक

सफर पर जाना है, साथ में परिचित दिव्यांग हैं। भीड़ की वजह से परेशानी और बढ़ रही कि ट्रेन पर कैसे चढ़ाएंगे? तो अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। रेलवे स्टेशनों को 'दिव्यांग फ्रेंडली' बनाया जाएगा। इस मुहिम के तहत रेलवे स्टेशनों पर ऐसे विशेष इंतजाम होंगे, जिससे दिव्यांगजनों के सफर में कोई बाधा न हो। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनमें आत्मविश्वास भरने के लिए दक्षिण भारत के कुछ बड़े स्टेशनों पर इसकी शुरुआत हो चुकी। जल्द उत्तर रेलवे समेत अन्य ए-वन श्रेणी के स्टेशनों पर भी दिव्यांगजनों को विशेष सुविधा मिलेगी।

दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था तो स्टेशनों पर पहले ही कर दी गई थी, लेकिन पैरों से दिव्यांग मुसाफिरों को ट्रेन में चढ़ाना अब भी परेशानी की वजह है। इसे दूर करने के लिए फोल्डेबल रैंप तैयार किए जाएंगे। इसका शेप कुछ ऐसा होगा कि व्हील चेयर को इसके अंदर रखा जा सकेगा। साथ ही लोहे का एक शेड होगा जो ट्रेन के गेट और प्लेटफार्म के बीच एक रैंप का काम करेगा। इससे दिव्यांग मुसाफिर आराम से ट्रेन से चढ़-उतर सकेंगे। बरेली जंक्शन पर भी यह व्यवस्था लागू किए जाने की तैयारी हो रही है।

अलग टिकट विंडो और विशेष कोच की व्यवस्था : दिव्यांगजनों के लिए हर ए-वन ग्रेड रेलवे स्टेशन पर अलग से टिकट विंडो की व्यवस्था भी होगी। व्हील चेयर पर आने वाले दिव्यांग यात्री काउंटर पर पहुंचें तो आरक्षण या टिकट लिपिक को वे दूर से दिख जाएं, इसलिए काउंटर पारदर्शी होगा। वहीं, इसकी खिड़की भी नीचे की ओर होगी।

मुसाफिरों के सफर में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए भारतीय रेल सुविधाएं मुहैया कराता है। फिर बात चाहे दिव्यांगजनों की ही क्यों न हो। स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए कई व्यवस्थाएं जल्द लागू होंगी।

- तरुण प्रकाश, डीआरएम, मुरादाबाद मंडल, उत्तर रेलवे

महंगाई दर में कमी का लाभ उठाने में हुई चूक

मुंबई : प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने कहा है कि हम कम महंगाई दर का लाभ उठाने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब महंगाई निचले स्तर पर थी, तब आरबीआइ को ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए थी। इससे महंगाई को ज्यादा प्रभावित किए बिना आर्थिक गतिविधियों को बल मिलता। मिश्रा ने कहा कि वर्तमान आर्थिक सुस्ती मौकों का फायदा उठाने में हुई चूक के चलते आई है। (प्रेट्र)

हमारा प्रयास है कि पांच करोड़ नौकरियां पैदा की जाएं। इसके लिए हम इन्फ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर जोर दे रहे हैं।
— नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री

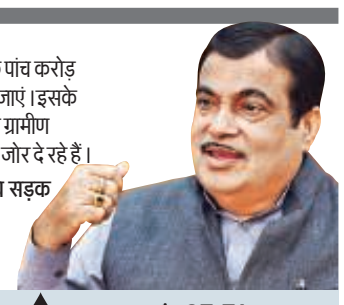

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना	चांदी	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट)
41,352.17 ▲ 413.45	12,165 ▲ 111.05	₹ 38,771 प्रति दस ग्राम ▲ ₹11	₹ 45,610 प्रति किलोग्राम ▲ ₹75	₹ 70.98 ▼ ₹ 0.02	$ 65.51 प्रति बैरल

भारत को बनाएंगे सॉफ्टवेयर उत्पादन का बड़ा केंद्र : रविशंकर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 2022 तक सभी गांवों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान शुरू
- संचार मंत्री ने कहा, डिजिटल इंडिया से ही मिली आधार और यूपीआइ को गति
- आइआइटी से निकले छात्र नौकरी की तलाश के बजाय नौकरी देने की बात करने लगे हैं

केंद्र सरकार का इरादा भारत को सॉफ्टवेयर उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने का है। सभी गांवों में ब्रॉडबैंड की उपलब्धता से कनेक्टिविटी के साथ डाटा स्पीड बढ़ने से यह लक्ष्य पाना आसान होगा। यह बात केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान को लांच करते हुए कही। मिशन का उद्देश्य 2022 तक देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंचाकर मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करना तथा डाटा स्पीड को बढ़ाना है।

प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान यानी नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने भाषण में किया था। इसके जरिये सरकार पूरे देश, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती व सर्वसुलभ ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों के साथ मिलकर सात लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। उन्होंने मिशन को कामयाब बनाने के लिए राज्य सरकारों का सहयोग मांगा और उनसे अपने यहां उचित ऑप्टिकल फाइबर इंडेक्स तैयार करने की अपील की। रविशंकर ने कहा कि ब्रॉडबैंड और डिजिटल इंडिया के महत्व को इससे समझा जा सकता है कि इसी की बदौलत 'आधार' और 'यूपीआइ' का देश में विकास हुआ जिनकी आज दुनियाभर में चर्चा हो रही है। यूपीआइ की तारीफ गूगल के मुखिया सुंदर पिचाई तक ने की है। आज देश में 25 हजार से ज्यादा स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं जिनमें 25 हजार करोड़ रुपये) से ज्यादा है। आइआइटी से निकलने वाले छात्र नौकरी की तलाश करने के बजाय नौकरी देने की बात करने लगे हैं। हमारे नेशनल ज्यूडीशियल डाटाबेस में 10 करोड़ मुकदमों और नौ करोड़ न्यायिक आदेशों का संग्रह है और एक क्लिक में किसी की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने टेलीकॉम अफसरों तथा उद्योग से कहा कि सरकार ने सारी जरूरी नीतियां बना दी हैं। अब आपको काम करना है और अभियान को समयसीमा के भीतर पूरा करके दिखाना है। सरकार देश को सॉफ्टवेयर उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी कर रही है।

एनबीएम की लांचिंग के मौके पर रविशंकर प्रसाद। एएनआइ

टावर घनत्व को दोगुने से ज्यादा करने का है लक्ष्य

इससे पहले संचार राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने कहा कि मंत्रालय ने 2024 तक प्रति हजार की जनसंख्या पर टावर घनत्व को मौजूदा 0.42 से बढ़ाकर 1.0 करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 30 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। मिशन के लिए 10 फीसद राशि का इंतजाम यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) से किया जाएगा। बाकी राशि का निवेश उद्योग तथा अन्य स्टेकहोल्डरों द्वारा किया जाएगा।

गांवों को बनाएंगे डिजिटल विलेज : उन्होंने कहा हमारा इरादा देश में एक लाख गांवों को डिजिटल विलेज में तब्दील करने का है। ताकि गांवों में ई-स्कूल, ई-अस्पताल, ई-पंचायत स्टार्ट-अप आदि का सपना साकार हो सके। बीएसएनएल, एमटीएनएल के अलावा प्राइवेट कंपनियों को भी इसमें भागीदारी निभानी होगी। हमारा लक्ष्य डाटा स्पीड को 50 एमबीपीएस पर पहुंचाना, मोबाइल टावरों की संख्या को 5.6 लाख से बढ़ाकर दस लाख करना तथा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की लंबाई को 22 लाख किमी से बढ़ाकर 50 लाख किमी करना है।

जीएसटी काउंसिल रेवेन्यू बढ़ाने पर करेगी विचार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- काउंसिल की बैठक आज, कुछ राज्यों ने फिलहाल जीएसटी की दरों में वृद्धि से बचने की दी है सलाह

जीएसटी के रेवेन्यू की धीमी रफ्तार से चिंतित जीएसटी काउंसिल की बैठक में बुधवार को इससे निपटने के उपायों पर विचार होगा। बैठक में राज्यों की तरफ से आए सुधारों पर चर्चा होगी। इनमें टैक्स दरों में संशोधन करने के सुझाव भी शामिल हैं। हालांकि कुछ राज्यों ने फिलहाल टैक्स दरों में वृद्धि जैसे किसी भी कदम से परहेज की सलाह भी दी है। गैर भाजपा शासित राज्यों के वित्त मंत्री आइजीएसटी सेटलमेंट का मुद्दा भी काउंसिल की बैठक में उठा सकते हैं।

बीते कई महीनों से जीएसटी के रेवेन्यू की रफ्तार बेहद धीमी बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष में भी जीएसटी रेवेन्यू केवल चार महीने एक लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर पाया है। इसका असर सरकार के कर संग्रह पर भी दिख रहा है। इसे देखते हुए काउंसिल ने राज्यों से रेवेन्यू में वृद्धि करने और इसका दायरा बढ़ाने संबंधी सुझाव मांगे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली काउंसिल की बैठक में इन सभी सुझावों पर चर्चा होने की उम्मीद है। वैसे काउंसिल ने सात राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक मंत्रिसमूह भी गठित किया है जो इन सुझावों पर विचार कर अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को देगा। सूत्र बताते हैं कि काउंसिल को अब तक जो सुझाव में मिले हैं उनमें जीएसटी दरों के पुनर्गठन और उनमें वृद्धि के प्रस्ताव भी शामिल हैं। कुछ राज्यों ने छूट वाले कुछ उत्पादों को भी इनमें शामिल करने का सुझाव दिया है। इनमें अधिकांश वस्तुएं रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली हैं।

जीएसटी दरों में वृद्धि को लेकर कुछ राज्यों की राय है कि यह कदम महंगाई को और बढ़ाएगा। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सीतारमण को पत्र लिखकर कहा है, 'मौजूदा समय में जीएसटी की दरों में किसी भी तरह का बदलाव या कोई नया सेस नहीं लगाना चाहिए। स्टैगफ्लेशन (धीमी विकास दर और ऊंची महंगाई दर) की स्थिति में उद्योग और ग्राहक दोनों के लिए यह खराब हो सकता है। गौरतलब है कि नवंबर में खुदरा महंगाई की दर तीन साल के उच्च स्तर 5.54 परसेंट पर पहुंच गई है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी की दर 4.5 परसेंट रही है।

रूस के सुदूर पूर्व में रॉसनेफ्ट के साथ निवेश की तैयारी

मुंबई, प्रेट्र : केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रूस की तेल कंपनी रॉसनेफ्ट के साथ रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में निवेश को लेकर बातचीत कर रही है। भारत ने पहले ही रूस के एनर्जी सेक्टर में करीब एक हजार करोड़ डॉलर (करीब 70 हजार करोड़ रुपये) का निवेश किया हुआ है। यह निवेश सखालिन-1, तास-यूर्याख और वानकोर जैसे ऑयल फील्ड्स में हिस्सेदारी खरीदने में किया गया है।

प्रधान ने बताया कि हम रूस के पूर्वी क्लस्टर में निवेश के लिए सरकारी कंपनी रॉसनेफ्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं। एनर्जी के लिहाज से रूस का पूर्वी हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। हम भू-राजनैतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में भी निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत विकासशील देश है। यहां ऊर्जा की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। भू-राजनैतिक कारणों से तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव की आशंका बनी रहती है। कीमत के मामले में हमारा देश बहुत संवेदनशील है। वैश्विक स्तर पर कीमतों में उतार-चढ़ाव का यहां व्यापक असर पड़ता है। ऐसे में हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। भारत की 70 से 80 फीसद ऊर्जा जरूरतें आयात से पूरी होती हैं। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने की बात भी कही।

फास्टैग से टोल संग्रह में सालाना 15 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ोतरी की उम्मीद

बेहतर नतीजे ▶ एनएचएआइ का दैनिक टोल संग्रह 66 करोड़ से बढ़कर 86 करोड़ पहुंचा

सिर्फ 50 फीसद वाहनों में फास्टैग लगने से इतना असर, अंडर रिपोर्टिंग भी घटी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

फास्टैग की व्यवस्था सुकून के साथ-साथ टोल संग्रह बढ़ाने में भी सहायक साबित हो रही है। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो सभी टोल प्लाजा के फास्टैग अनुकूल होने तथा हाईवे पर चलने वाले सभी वाहनों में फास्टैग लगने से एनएचएआइ के टोल संग्रह में सालाना 15 हजार करोड़ रुपये तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है।

सड़क मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक पिछले एक महीने में एनएचएआइ ने राष्ट्रीय राजमार्गों के अपने सभी 502 टोल प्लाजाओं में से 90 फीसद टोल प्लाजाओं को फास्टैग के अनुकूल बना दिया है। केवल 50 ऐसे टोल प्लाजा को फास्टैग अनुकूल बनाने का काम बाकी है जो पीडब्ल्यूडी के अधीन आते हैं और जहां इलेक्ट्रॉनिक के बजाय पुरानी तकनीक से मैन्युअल टोल संग्रह हो रहा था। इस बीच 22 नवंबर को सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की फास्टैग अनिवार्यता संबंधी प्रेस कांफ्रेंस के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले तकरीबन पचास फीसद वाहन चालकों ने अपने वाहनों में फास्टैग लगा लिए हैं। इतने से ही एनएचएआइ के दैनिक टोल संग्रह में 20 करोड़ रुपये का इजाफा हो गया है। पहले जहां रोजाना लगभग 66 करोड़ रुपये का टोल संग्रह होता था। वहीं अब हर रोज टोल से 86 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब हर महीने 600 करोड़ और हर साल 7200 करोड़ रुपये का इजाफा। स्पष्ट है कि जब शत-प्रतिशत वाहनों में फास्टैग लग जाएगा तब एनएचएआइ को हर साल टोल संग्रह से 14,400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम हासिल होगी।

केवल 50 टोल प्लाजा को फास्टैग के अनुकूल बनाने का काम बाकी। प्रतीकात्मक फोटो

अभी एनएचएआइ का औसत दैनिक टोल संग्रह लगभग 66 करोड़, मासिक 2200 करोड़ और वार्षिक टोल संग्रह करीब 24 हजार करोड़ रुपये है। सड़क मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार फास्टैग से पहले के टोल संग्रह के आंकड़ों को सही नहीं माना जा सकता क्योंकि कैश भुगतान में बड़े पैमाने पर अंडर रिपोर्टिंग होती थी। अर्थात टोल संग्रहकर्ता कांट्रैक्टर जितना संग्रह करते थे, उतना रिकॉर्ड पर दिखाते नहीं थे। अनुमान है कि लगभग 20 फीसद कम टोल संग्रह दर्शाया जाता था। फास्टैग लागू होने से अंडर रिपोर्टिंग पर पूरी तरह अंकुश लग जाएगा। इसके अलावा 15 जनवरी अथवा उसके बाद जब बिना फास्टैग वाले वाहनों से दोगुना टोल वसूलने का नियम सख्ती से लागू होगा तब राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले सभी वाहनों से टोल कलेक्ट होगा और धौंसपट्टी या रसूख के बल पर टोल न देने वाले भी इससे बच नहीं पाएंगे। इससे टोल संग्रह में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

आ रही हैं कुछ दिक्कतें : इस बीच कुछ टोल प्लाजाओं पर तकनीकी समस्याओं के अलावा कई टोल प्लाजाओं पर फास्टैग लेन में बिना फास्टैग वाहनों के प्रवेश करने और फिर दोगुना टोल देने की नौबत पर बहस और झगड़े-झंझट की घटनाएं देखने-सुनने में आ रही हैं। कुछ जगहों पर कैश के लिए एक चौथाई से कम लेन खोले जाने को लेकर बवाल हो रहा है। एनएचएआइ के अधिकारियों ने इन्हें शुरुआती समस्याएं कहा है, जो धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी।

टैक्स कलेक्शन पर बढ़ी सक्रियता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार ने कर अधिकारियों को आगाह कर दिया है कि वित्त वर्ष के अंत तक टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य को पूरा करने में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। जीएसटी के लिए बाकी बचे चार महीने में 1.10 लाख करोड़ रुपये मासिक संग्रह का लक्ष्य विभाग को सौंपा गया है।

वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने सीबीडीटी और सीबीआइसी के प्रिंसिपल और चीफ कमिश्नरों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये बैठक की। जीएसटी के बाकी बचे चार महीने में से किसी एक महीने में अधिकारियों को 1.25 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त करने का लक्ष्य भी सौंपा गया है। इस वित्त वर्ष में केवल चार बार जीएसटी का मासिक कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपये को पार कर पाया है। सूत्र बताते हैं कि रेवेन्यू सचिव ने सभी कमिश्नरों को स्पष्ट कर दिया है कि कॉरपोरेट टैक्स में 1.45 लाख करोड़ रुपये की छूट चालू वित्त वर्ष में रेवेन्यू कम प्राप्त होने का बहाना नहीं हो सकती। सभी को 13.5 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य पाने के लिए काम करना होगा। इसके लिए दोनों बोर्ड के सदस्यों, प्रिंसिपल कमिश्नरों और सभी चीफ कमिश्नरों को प्रत्येक सप्ताह अपने क्षेत्र का दौरा करने को कहा गया है। राजस्व सचिव भी देशभर का दौरा करेंगे।

अधिकारियों से टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और मामला दर्ज कराने को कहा गया है। यदि किसी टैक्सपेयर ने कोई जानकारी अपने रिटर्न में नहीं दी है तो अधिकारी उसे संशोधित रिटर्न दाखिल करने को कहें। अप्रैल से नवंबर तक की अवधि में सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5.56 लाख करोड़ रहा है। पिछले साल की इसी अवधि में सरकार को 5.47 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इसी तरह जीएसटी कलेक्शन इस अवधि में 3.98 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल समीक्षाधीन अवधि में 5.82 लाख करोड़ रुपये रहा था।

जल्दबाजी में विदेश व्यापार समझौते नहीं करेगी सरकार : पीयूष गोयल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- गैरजरूरी आयात से घरेलू उद्योगों को संरक्षित करने का दिया भरोस
- उद्योग जगत की शिकायतों पर उठाए जाएंगे त्वरित कदम

घरेलू उद्योगों के हितों के विपरीत जाकर विदेश व्यापार समझौते (एफटीए) नहीं किए जाएंगे। सरकार अन्य देशों या देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने की जल्दबाजी में नहीं है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ते आयात से घरेलू उद्योगों को जब भी परेशानी होगी, सरकार उसके लिए तत्काल कदम उठाएगी।

पिछले महीने ही प्रधानमंत्री न रेंद्र मोदी ने बैंकाक में भारत की चिंताओं को नजरअंदाज करने के चलते आरसेप में शामिल होने से इन्कार कर दिया था। सरकार का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में आरसेप भारतीय उद्योग के हितों के पक्ष में नहीं जाता। सीआइआइ की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रहित में यह सख्त फैसला लिया। सरकार के दरवाजे उद्योग के लिए हमेशा खुले हैं और किसी भी तरह की परेशानी महसूस होने पर उद्योग की मदद के लिए हम तैयार हैं। गोयल ने स्पष्ट किया कि आरसेप से बाहर रहने का यह अर्थ नहीं है कि भारत ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन यह वेल्यू चेन केवल चीन में नहीं, पूरी दुनिया में है। हमें घरेलू उद्योगों को सशक्त करना होगा और ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनने की चाहत रखने वालों को प्रोत्साहित करना होगा। उद्योग जगत को यूरोप, अमेरिका, आसियान देश, जापान व कोरिया के वैल्यू चेन का हिस्सा बनने के बारे में सोचना चाहिए। बढ़ते आयात से घरेलू उद्योगों को हो रहे नुकसान पर गोयल ने कहा कि सरकार के पास ऐसे कई उपाय हैं जिनसे गैरजरूरी आयात को सीमित किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पहल उद्योग की तरफ से होनी चाहिए। उद्योग जगत सरकार को बताए कि कहां दिक्कत है, उस पर तत्काल कदम उठाया जाएगा। सरकार और उद्योगों के बीच संवाद लगातार बना रहना चाहिए।

निर्यातकों की मुश्किलें समझ रही सरकार : गोयल ने कहा कि भारतीय निर्यातकों को कई देशों में व्यापार प्रतिबंधों से गुजरना पड़ता है। ऐसा बीते समय में हुए व्यापार समझौतों की वजह से भी हो रहा है। गोयल ने निर्यातकों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में होने वाले किसी भी मुक्त व्यापार समझौते को करने में जल्दबाजी नहीं बरती जाएगी।

विभिन्न कंपनियों से मुलाकात कर रहे गोयल : वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योगों के साथ बातचीत का सिलसिला पिछले कुछ समय से फिर शुरू किया है। वह इस बीच कई कंपनियों से मुलाकात कर चुके हैं। इन बैठकों में देश में मांग की स्थिति में सुधार करने के उपायों पर चर्चा हुई है। बैठकों में अब तक हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेकर मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां हिस्सा ले चुकी हैं। इन कंपनियों ने अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित दिक्कतें मंत्री के समक्ष रखी हैं, जिनका निदान तलाशने का काम किया जा रहा है।

देश में निवेश का माहौल सुधारने की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- वित्त मंत्री सीतारमण के साथ उद्योग जगत की बजट पूर्व बैठक
- घरेलू मांग की कमजोर स्थिति पर सभी पक्षों ने जताई चिंता

देश में निवेश की घटती रफ्तार की गूंज मंगलवार को बजट पूर्व बैठक में भी सुनाई दी। देश के प्रमुख उद्योग चैंबरों के प्रतिनिधियों ने सरकार से कहा कि निवेश के माहौल में बड़े सुधार करने की जरूरत है। चैंबरों की तरफ से निर्यात के लिए सुविधाओं को बढ़ाने और श्रम सुधार जैसी दूसरी पारंपरिक मांगों की फेहरिस्त भी अलग-अलग रखी गई। लेकिन निवेश के माहौल पर चिंता सभी पक्षों जताई। घरेलू मांग की स्थिति पर भी साझा चिंता देखने को मिली। इसके लिए आम आयकर दाता को ज्यादा छूट देने की बात भी कई प्रतिनिधियों ने रखी। इस बैठक में उद्योग, कारोबार व सेवा क्षेत्र के तमाम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

बैठक के बाद सरकार की तरफ से जारी सूचना में भी इस बात के संकेत दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि निजी निवेश को प्रभावित करने वाले नियमन संबंधी माहौल, दुनिया में जिस तरह से संरक्षणवाद बढ़ रहा है उसे देखते हुए निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी भावी कदम, औद्योगिक उत्पादन जैसे मुद्दों पर मुख्य तौर पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सीआइआइ के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने बताया, 'वित्त मंत्री व वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने हमारे सुझावों को बहुत ही गंभीरता से सुना। उन्हें अर्थव्यवस्था के हालात के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। हमारी तरफ से कर संग्रह को बेहतर बनाने के कई सुझाव दिए गए हैं।

हमें उम्मीद है कि घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उन पर भी गौर किया जाएगा।' इसी तरह से फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने कहा कि नियमों व कानूनों के कारण निवेश की राह में आने वाली अड़चनें विमर्श का अहम मुद्दा रहीं। कारोबार के माहौल को मुक्त बनाना अभी एक बड़ी जरूरत है। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि अभी जो माहौल है उसमें मांग को बढ़ाना व सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी सबसे ज्यादा जरूरी है।

पीएचडी चैंबर के अध्यक्ष डीके अग्रवाल ने कहा, 'हमने कई मांगें वित्त मंत्रालय के समक्ष रखी हैं, लेकिन एक मांग जो हमें लगता है बहुत जरूरी है, वह है संकट में फंसी छोटी व मझोली इकाइयों के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के एक विशेष कोष की स्थापना करना। अभी बैंकों व एनबीएफसी की तरफ से इन इकाइयों को फंड नहीं मिल पा रहा है, इसलिए यह कदम जरूरी हो गया है।' फियो के अध्यक्ष अजय सहाय ने कहा कि जीएसटी काउंसिल में पहले ही निर्यातकों के लिए ई-वालेट सुविधा बहाल करने पर चर्चा हुई है। इसे स्वीकृति दिलाने व लागू करने को तत्काल ध्यान देना चाहिए। निर्यात समुदाय को मदद करने के लिए सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाने में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए।

बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (मध्य), वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर (दाएं) एवं आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती। प्रेट्र

शेयर बाजार

फाइनेंशियल, मेटल और आइटी स्टॉक्स में तेज उछाल, ग्लोबल संकेतों के साथ आरबीआइ के बयान का दिखा असर

सेंसेक्स-निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर

मुंबई, प्रेट्र : पिछले सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए प्रमुख भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार को जबर्दस्त तेजी का रुख रहा। इस दौरान मेटल, फाइनेंशियल और आइटी स्टॉक्स में जोरदार खरीदारी हुई। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 413.45 अंक उछलकर 41,352.17 के सार्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में 111.05 अंक की तेजी दर्ज की गई। यह भी 12,165 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील के शेयरों में सबसे ज्यादा 4.38 परसेंट का उछाल देखा गया। इसके साथ ही एयरटेल, वेदांता, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस के शेयरों में 2.39 परसेंट तक की तेजी दर्ज की गई। वहीं सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो और एचयूएल के शेयर 1.37 परसेंट तक की गिरावट के साथ बंद हुए।

जानकारों के मुताबिक घरेलू शेयर बाजारों पर ग्लोबल मार्केट का असर देखने को मिला। अमेरिका-चीन व्यापार समझौते के बाद दुनियाभर के बाजारों में उत्साह देखा गया है। भारतीय बाजार भी इससे अछूते नहीं हैं। इसके अलावा आरबीआइ गवर्नर के बयान से भी बाजारों पर सकारात्मक असर पड़ा है। आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक दिन पहले कहा था कि अभी नीतिगत ब्याज दरों में और कटौती की जा सकती है।

बुधवार को होने जा रही जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर भी निवेशक उत्साहित रहे। कारोबारियों को इस बैठक से सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। एशिया के अन्य बाजारों में भी तेजी देखने को मिली। शंघाई, हांगकांग, सियोल और टोक्यो के बाजार हरे निशान पर बंद हुए। इस बीच डॉलर के मुकाबले रुपये के भाव में दो पैसे की मजबूती दर्ज की गई। एक डॉलर की कीमत 70.98 रुपये रही।

मझगांव डॉक को मिली आइपीओ लाने की मंजूरी : पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सरकारी जलपोत निर्माता कंपनी मझगांव डॉक को आइपीओ लाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने अगस्त में सेबी से मंजूरी मांगी थी। देश की अग्रणी जलपोत निर्माता कंपनी करीब 2.8 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री करने की योजना बना रही है। आइपीओ लाने का यह कदम सरकार की विनिवेश योजना का हिस्सा है।

बीएसई और आइएचएस मार्किट में करार

मुंबई, एएनआइ : बीएसई लिमिटेड ने वैश्विक सूचना सेवा प्रदाता आइएचएस मार्किट के साथ एक एएमयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां फिक्स्ड इनकम सिक्युरिटीज के वैल्यूएशन के लिए एक नई सेवा की शुरुआत करेंगी। इसे अगले वर्ष की पहली छमाही में शुरू करने की योजना है। बीएसई के सीईओ अशीष कुमार चौहान ने बताया कि इससे भारतीय फिक्स्ड इनकम मार्केट के निवेशकों को लाभ मिल सकेगा।

इन शेयरों में रही गहमागहमी

यस बैंक : मंगलवार को यस बैंक के शेयरों में दो परसेंट तक का उछाल दर्ज किया गया। बीएसई में बैंक के शेयर 1.71 परसेंट उछाल के साथ 47.60 रुपये के भाव पर बिके। वहीं एनएसई में इसके शेयरों में 1.81 परसेंट तक की तेजी आई। इस दौरान एसबीआइ के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कोटक महिंद्रा बैंक को यस बैंक के अधिग्रहण के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बताया है। पिछले चार दिन में यस बैंक के शेयरों में 11 परसेंट का इजाफा हुआ है।

सिप्ला : एंटी-डायबिटिक दवा के लिए ब्रांड नाम और ट्रेड मार्क के अधिकार मिलने की सूचना के बाद इस फार्मा कंपनी के शेयरों में तेजी का रुख रहा। बीएसई में कंपनी के शेयर 1.61 परसेंट की तेजी के साथ 466 रुपये के भाव पर बंद हुए। वहीं एनएसई में यह 1.73 परसेंट उछलकर 464.20 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बिके।

वर्लपूल : कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील डिसूजा के इस्तीफा देने के बाद इसके शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई में कंपनी के शेयर 4.19 परसेंट की गिरावट के साथ 2,159.65 रुपये पर बिके। वहीं एनएसई में यह 4.34 परसेंट लुढ़ककर 2,155 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए।

अभी खत्म नहीं होगा छह पैसे प्रति मिनट का आइयूसी चार्ज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दूसरे ऑपरेटर पर आउटगोइंग कॉल के लिए कंपनियां करती हैं एक-दूसरे को भुगतान

दूसरे ऑपरेटर पर आउटगोइंग कॉल के एवज में लगने वाला इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज (आइयूसी) अभी खत्म नहीं होगा। ट्राई ने छह पैसे प्रति मिनट के इस शुल्क को 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रखने का एलान किया है। इससे पहले, आइयूसी को जनवरी, 2020 में ही खत्म करने की बात कही जा रही थी। दूसरे ऑपरेटर के नेटवर्क पर आउटगोइंग कॉल की स्थिति में कंपनियां एक-दूसरे को इस शुल्क का भुगतान करती हैं।

टेलीकॉम उद्योग के संगठन सीओएआइ ने इसे कर्ज में डूबे उद्योग के लिए राहतकारी बताया है। उसका कहना है कि छह पैसे का मोबाइल कॉल टर्मिनेशन शुल्क जारी रखने से ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटरों ने पहले ही इस शुल्क को हाल में कॉल और डाटा दरों में की गई वृद्धि के जरिये समायोजित कर लिया है। इससे पहले ट्राई ने पहली अक्टूबर, 2017 से टर्मिनेशन चार्ज को 14 पैसे से घटाकर छह पैसे किया था। उस समय इसे पहली जनवरी, 2020 से खत्म करने की बात कही गई थी। फिलहाल रिलायंस जियो यह शुल्क सीधे अपने ग्राहकों से वसूल रही है। जियो से किसी अन्य नेटवर्क पर कॉल करने के लिए छह पैसे प्रति मिनट का भुगतान करना पड़ता है। अन्य टेलीकॉम कंपनियां अपने अनलिमिटेड प्लान में सभी कॉल मुफ्त देती हैं। ग्राहकों से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेती हैं। आइयूसी नहीं हटने से एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया को फायदा होने का अनुमान है। अभी इस मद में जियो को सबसे ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। जियो के ग्राहक बड़ी संख्या में अन्य नेटवर्क पर कॉल करते हैं, जिसके एवज में कंपनी संबंधित ऑपरेटर को आइयूसी का भुगतान करती है। इसी कारण से जियो इस शुल्क को खत्म करने की मांग कर रही है।

10 लोगों की मौत हो गई अफगानिस्तान में मंगलवार को एक वाहन के बम की चपेट में आने से। विस्फोट में तीन बच्चे, दो महिलाएं और पांच आदमी मारे गए हैं। हमले की अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

पाकिस्तान और फौजी तानाशाह

पाकिस्तान की विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई है। जनरल अयूब खान, जनरल याह्या खान, जनरल जिया-उल-हक के बाद परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान पर शासन करने वाले चौथे सैन्य कमांडर हैं। कई बार चुनी हुई सरकारों का तख्तापलट करने वाली पाकिस्तानी फौज लगभग 43 साल तक सत्ता में रही। इस दौरान उसने अपनी कट्टरवादी सोच से पाकिस्तान को आतंकिस्तान देश बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आइये जानते हैं पाक में कब-कब रहा सैन्य शासन :

अयूब खान

1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन 11 साल बाद ही जनरल मुहम्मद अयूब खान ने सत्ता हथिया ली और 1958 में खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। पूरे 11 साल तक अयूब खान ने राज किया।

इस दौरान भारत के हाथों पाकिस्तान की करारी हार से अयूब खान की सत्ता पर पकड़ कमजोर होने लगी और 1969 में जनरल याह्या खान ने उन्हें हुकूमत से बेदखल करके पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथों में ले ली।

याह्या खान

25 मार्च, 1969 को राष्ट्रपति का पद संभालने वाले याह्या खान के जमाने में पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में जन्म हुआ और 1971 में भारत के हाथों पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली। याह्या खान को पाकिस्तान की हार का प्रमुख कारण माना गया। 20 दिसंबर, 1971 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। उनसे सभी सेवा सम्मान छीन लिए गए। 1979 तक वह हाउस अरेस्ट में रहे।

जिया-उल-हक

याह्या खान के हटने के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर लोकशाही की बयार चली और जुल्फीकार अली भुट्टो चुनकर प्रधानमंत्री बने, लेकिन जिस जनरल जिया-उल-हक को उन्होंने आर्मी चीफ बनाया, उसी जिया-उल-हक ने 1978 में भुट्टो का तख्तापलट करके खुद ही पाकिस्तान की कमान संभाल ली। साल भर बाद जिआ-उल-हक ने भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। उसके बाद 1988 में जिया-उल-हक की विमान दुर्घटना में मौत होने तक पाकिस्तान में फौजी हुकूमत रही।

परवेज मुशर्रफ

फौजी हुकूमत जाने के बाद चुनाव तो कई बार हुए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा लड़खड़ाता ही रहा। दुनिया ने एक बार फिर पाकिस्तान में फौजी हुकूमत तब देखी, जब 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बेदखल करके आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने सत्ता हथिया ली।

फांसी की सजा की स्थिति

पाक कैदियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा 2018 में काउंटिंग द कंडेम्ड, जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान नामक तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक,

- 2004 से अबतक पाकिस्तान में 4,500 लोगों को मिल चुकी है मौत की सजा।
- 2009 से अबतक दुनिया में कम से कम 19, 767 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। इसी दौरान पाकिस्तान की अदालतों ने 2, 705 लोगों को मौत की सजा सुनाई, जो दुनिया भर में मौत की सजा का 14 फीसद है।

टकराव का कारण बन सकता है फैसला

प्रथम पृष्ठ से आगे

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विशेष अदालत का फैसला पाकिस्तान में सरकार, सेना और न्यायपालिका के बीच टकराव का कारण बन सकता है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इमरान सरकार फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाई कार्ट चली गई थी।

शरीफ का किया था तख्तापलट : जनरल परवेज मुशर्रफ तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की सरकार का तख्तापलट कर 1999 में सत्ता में आए थे। उन्होंने पाकिस्तान पर अगस्त, 2008 तक शासन किया था। मुशर्रफ के सेना प्रमुख रहते ही 1999 में मई से जुलाई तक कारगिल युद्ध हुआ था। सत्ता से बाहर होने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में माना था कि पाकिस्तान आतंकियों को भारत में भेजता है।

उत्तर कोरिया को प्रतिबंधों से राहत दिलाने में जुटे चीन-रूस

प्रयास ▶ दोनों देशों ने सुरक्षा परिषद में की अपने सहयोगी की पैरवी

कोयला, लौह अयस्क और कपड़ों के निर्यात पर लगी पाबंदी हटाने की मांग

संयुक्त राष्ट्र, एपी : चीन और रूस अपने सहयोगी उत्तर कोरिया को प्रतिबंधों से राहत दिलाने के प्रयास में जुट गए हैं। इस कोशिश में इन दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की है कि उत्तर कोरिया से कोयला, लौह अयस्क और कपड़ों के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को खत्म कर दिया जाए। इससे आजीविका संबंधी रोजमर्रा की दिक्कतें झेल रहे उत्तर कोरिया के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

चीन और रूस ने सोमवार को इस संदर्भ में एक प्रस्ताव का मसौदा सुरक्षा परिषद के सदस्यों में वितरित किया। प्रस्ताव में अमेरिका और उत्तर कोरिया में परमाणु मसले पर हुई वार्ता की तारीफ की गई है। साथ ही छह देशों की वार्ता दोबारा शुरू करने की वकालत भी गई है। साल 2003 में उत्तर कोरिया के साथ अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान और रूस ने वार्ता शुरू की थी। सितंबर 2005 में उत्तर कोरिया इस आधार पर समझौते के लिए राजी हुआ था कि सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा लाभ के बदले में वह अपने परमाणु हथियारों को खत्म कर देगा। हालांकि दिसंबर 2008 में अमेरिका के सख्त रुख के चलते समझौता नहीं हो पाया था।

अमेरिका ने सत्यापन के लिए जिस तरीके का प्रस्ताव रखा था, उसे उत्तर कोरिया ने मानने से इन्कार कर दिया था। तब से छह देशों की वार्ता रुकी पड़ी है। रूस और चीन यह प्रस्ताव ऐसे समय लेकर आए हैं, जब अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु वार्ता ठहरी हुई है।

चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग (बाएं) और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमिर पुतिन। फाइल

राष्ट्रपति ट्रंप बोले, उत्तर कोरिया पर है नजर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा, 'हम करीब से नजर रख रहे हैं। उत्तर कोरिया ने अगर कुछ किया तो वो निराशाजनक होगा।' किम ने अमेरिका को अपने रुख में बदलाव लाने के लिए इस साल के आखिर तक अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने रुख नहीं बदला तो उत्तर कोरिया अपना अलग रास्ता अपना लेगा।

विफल हुई कश्मीर पर चीन की चाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की चीन की चाल विफल हो गई है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में एक बार फिर कश्मीर पर एक आंतरिक बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया था, लेकिन फ्रांस समेत दूसरे देशों ने इस प्रस्ताव को विफल कर दिया। लिहाजा मंगलवार को इस तरह की कोई बैठक होने की सूचना नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंगलवार की बैठक को लेकर जो सूचना जारी की है, उसमें भारत, पाकिस्तान या कश्मीर को लेकर कोई जिक्र नहीं है। अगस्त में जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला किया था, उसके कुछ ही दिनों बाद चीन ने इसी तरह की बैठक बुलाई थी।

नई दिल्ली स्थिति कूटनीतिक सूत्रों ने बताया कि चीन की मंशा की सूचना मिलते ही भारत ने सुरक्षा परिषद के तमाम सदस्यों के साथ संपर्क किया। माना जा रहा है कि फ्रांस और अमेरिका ने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला मानते हुए इसे दोनों देशों के बीच आपसी मशविरा से ही सुलझाने का सुझाव दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के साथ ही दूसरे गैर अस्थायी सदस्यों से इस बारे में मदद मांगी।

सिख निशान बॉक्स का मामला खारिज

लंदन, प्रेट्र : लंदन के हाई कोर्ट ने 2021 में ब्रिटेन में होने वाली जनगणना के पर्चे में निशान लगाने के लिए संबंधित पृथक सिख बॉक्स का मामला खारिज कर दिया है। एक ब्रिटिश सिख संगठन ने इस संबंध में न्यायिक समीक्षा अर्जी दाखिल की थी। जस्टिस बेवेर्ली लैंग ने व्यवस्था दी कि आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह जल्दबाजी पूर्ण कदम है और सत्ता के विभाजन पर संसदीय विशेषाधिकार एवं संवैधानिक परंपराओं के विपरीत है। उन्होंने नवंबर में सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस दौरान उन्होंने सिख फेडरेशन (ब्रिटेन) की दलीलें और ब्रिटेन के सचिवालय की जवाबी दलीलें सुनीं। फेडरेशन ने दावा किया था कि सचिवालय द्वारा संसद के सामने यूके ऑफिस फॉर नेशनल स्टेटिक्स के दिसंबर, 2018 के श्वेत पत्र के प्रस्तावों पर आधारित जणगणना आदेश अवैध है।

कारगिल युद्ध के खलनायक परवेज मुशर्रफ

पाकिस्तान में जबरन सत्ता हथियाने वाले सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब अमन का पैगाम लेकर पाकिस्तान में थे, तब मुशर्रफ कारगिल की साजिश रच रहे थे। वहीं आगरा शिखर वार्ता में मुशर्रफ के अड़ियल रवैये के कारण कश्मीर का हल नहीं निकल सका था। भारत के दृष्टिकोण से मुशर्रफ का सैन्य और सियासी सफर महत्वपूर्ण है।

कारगिल युद्ध: कारगिल युद्ध को दो बातों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। एक है, भारतीय सेना के अदम्य शौर्य के लिए तो दूसरा मुशर्रफ की कुटिलता के लिए। माना जाता है कि मुशर्रफ ने अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को परवान चढ़ाने के लिए कारगिल का युद्ध छेड़ दिया। उस समय वह पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे। अपनी आत्मकथा 'इन द लाइन ऑफ फायर' में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी सेना कारगिल युद्ध में शामिल थी। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान इस तथ्य को छिपाता रहा था। मुशर्रफ ने हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर डाल दी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध से हाथ खींचने के लिए कहा था।

आगरा शिखर वार्ता: जुलाई 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जबरन राष्ट्रपति के पद पर काबिज हुए मुशर्रफ की आगरा में मुलाकात हुई। इस शिखर वार्ता में कश्मीर मसले को लेकर मुशर्रफ के साथ सहमति नहीं बन सकी। मुशर्रफ के अड़ियल रवैये के कारण यह वार्ता पटरी से उतर गई थी। वाजपेयी ने मुशर्रफ से कश्मीर में सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कहा था।

संसद हमला: 2001 में ही भारतीय संसद पर हमला हुआ। इस हमले में पाकिस्तान पोषित लश्कर ए तैयबा और जैश ए मुहम्मद जैसे संगठन शामिल थे।

परवेज मुशर्रफ। फाइल

मुशर्रफ एक नजर में

- 11 अगस्त, 1943 को दिल्ली में जन्में
- 1961 पाकिस्तानी सैन्य अकादमी में चयन
- 1998 में सेना प्रमुख बने
- 1999 में नवाज शरीफ को हटा सत्ता पर काबिज हुए
- 2001 में सैन्य प्रमुख रहते स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया
- 2002 में विवादास्पद जनमत संग्रह के बाद पांच साल के लिए राष्ट्रपति बने।
- 2007 में फिर राष्ट्रपति बने।

यह स्वीकारा था कि वो आतंकवादियों को अपने यहां पर ट्रेनिंग देकर भारतीय सेना से लड़ने के लिए भेजते थे।

जब भारत से डर गए मुशर्रफ; मुशर्रफ ने पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को खतरनाक स्तर पर बताया था। उन्होंने कहा था कि यदि पाकिस्तान अपने निकटवर्ती देश पर एक परमाणु बम से हमला करता है तो पड़ोसी देश हमें बीस परमाणु बमों से खत्म कर सकता है।

देशद्रोह का केस

- 3 नवंबर, 2007 को देश में आपातकाल लगाया
- 28 नवंबर को सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा
- 15 दिसंबर मुशर्रफ ने आपातकाल हटाया
- अगस्त 2008 दो प्रमुख सत्ताधारी दलों द्वारा महाभियोग का मामला चलाए जाने की सहमति के बाद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया
- 31 जुलाई 2009 : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ के 3 नवंबर 2007 के फैसले को असंवैधानिक बताया
- 06 अगस्त मुशर्रफ ने अपने खिलाफ आरोपों को बेबुनियाद बताया और ब्रिटेन चले गए
- 23 जनवरी 2012 पाकिस्तान की संसद ने एक संकल्प पारित किया। जिसमें मुशर्रफ के लौटते ही गिरफ्तार करने का निर्णय लिया
- 24 मार्च 2013 मुशर्रफ चुनाव के लिए पाकिस्तान लौटे
- 08 अप्रैल देशद्रोह मामले में मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट का समन
- 12 दिसंबर विशेष अदालत ने मुशर्रफ को मामले का सामना करने के लिए तलब किया
- 02 जनवरी 2014 मुशर्रफ बीमार होकर अस्पताल में भर्ती
- 16 मार्च 2016 मुशर्रफ को विदेश में इलाज कराने की अनुमति मिली
- 11 मई विशेष अदालत ने मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में फरार घोषित किया
- 19 नवंबर 2018 : कोर्ट ने मुशर्रफ के वकील को उन्हें लौटाने के लिए मनाने के लिए कहा
- 31 मार्च, 2019 : सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को 2 मई को देशद्रोह मामले में विशेष अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
- 19 नवंबर : विशेष अदालत ने देशद्रोह मामले में अपनी कार्यवाही समाप्त की और कहा कि 28 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा।
- 27 नवंबर : उच्च न्यायालय ने राजद्रोह के मामले में फैसला सुनाने से विशेष अदालत को रोक दिया।
- 17 दिसंबर : विशेष अदालत ने मुशर्रफ मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई।

'गुलाम कश्मीर का अस्तित्व मिटाने की कोशिश में पाक'

- यूकेपीएनपी के नेता ने पाकिस्तानी पंजाब में विलय का लगाया आरोप
- इस्लामाबाद के कब्जे वाले कश्मीर में स्वतंत्र विधानसभा का है प्रावधान

ज्यूरिख (स्विट्जरलैंड), एएनआइ: पाकिस्तान, गुलाम कश्मीर का अस्तित्व मिटाने की कोशिश में जुटा है। यह आरोप यूकेपीएनपी के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को लगाया। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) के प्रवक्ता नसीर अजीज खान का कहना है कि पाकिस्तान, गुलाम कश्मीर और गिलगिट-बाल्टिस्तान का अवैध रूप से विलय अपने नियंत्रण वाले पंजाब प्रांत में करने की साजिश रच रहा है। बता दें कि इस्लामाबाद के कब्जे वाले कश्मीर का प्रशासन चलाने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्वतंत्र विधानसभा का प्रावधान है, लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पाकिस्तानी हुक्मरान ही यहां पर शासन करते हैं।

जम्मू-कश्मीर सरकार के सेवा और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 11 दिसंबर को जारी आदेश पर खान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इस्लामाबाद के इशारे पर गुलाम कश्मीर के तथाकथित राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से जम्मू-कश्मीर प्रबंधन समूह का नाम बदलकर जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) रखने का आदेश दिया है। यह आदेश गुलाम कश्मीर के प्रधानमंत्री फारुख हैदर खान के मुजफ्फराबाद में दिए गए उस भाषण के बाद जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे गुलाम कश्मीर के अंतिम प्रधानमंत्री हो सकते हैं।

नासिर अजीज के अनुसार, 'गुलाम कश्मीर के पीएम ने अपने उक्त भाषण में कहा था कि पाकिस्तानी प्रशासन ने उनसे स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह पीओके के अंतिम प्रधानमंत्री हैं और उनके बाद इस क्षेत्र में कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा।' अजीज ने कहा कि यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान गुलाम कश्मीर को पंजाब प्रांत और उसके कुछ हिस्से को खैबर पख्तूनख्वा में विलय करने की अवैध रूप से कोशिश कर रहा है। गिलगिट-बाल्टिस्तान के लिए भी पाकिस्तान ऐसी ही साजिश रच रहा है।

तालिबान पर लागू रहेंगे प्रतिबंध

संयुक्त राष्ट्र, आइएएनएस: अमेरिका से शांति वार्ता कर रहे आतंकी संगठन तालिबान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रतिबंध बरकरार रहेगा। सोमवार को अफगानिस्तान से जुड़े प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने के प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद ने मंजूरी दी। प्रस्ताव 2501 के मुताबिक सभी राज्य शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा तालिबान और उससे जुड़े समूह और संस्थाओं पर कार्रवाई करना जारी रखेंगे।

प्रस्ताव में प्रतिबंध समिति का समर्थन करने के लिए निगरानी टीम के उस आदेश को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई, जिसमें प्रतिबंधों को 12 महीने बढ़ाने की बात कही गई है। बता दें कि वर्तमान प्रतिबंधों की मियाद दिसंबर 2019 में खत्म हो रही है। सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के तहत तालिबान से जुड़े समूह, संस्थाओं और व्यक्तियों पर न केवल यात्रा प्रतिबंध लागू होंगे बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकेगी।

कुआलालंपुर सम्मेलन में शिरकत नहीं करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान

- रंग लाया सऊदी अरब का दबाव, खान ने रद की यात्रा
- सऊदी ने मलेशियाई प्रधानमंत्री के बयान पर जताई थी गंभीर आपत्ति
- मुस्लिम देशों के लिए नए प्लेटफार्म की कही थी बात

इस्लामाबाद, एएनआइ : सऊदी अरब के दबाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मलेशिया की अपनी निर्धारित यात्रा को रद कर दिया है। उन्हें बुधवार से कुआलालंपुर में होने वाले इस्लामिक शिखर सम्मेलन में भाग लेना था। अपने इस निर्णय से इमरान ने मलेशियाई समकक्ष को अवगत करा दिया है। राजनयिक सूत्रों के हवाले से जियो न्यूज ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

बता दें कि इससे पहले बताया गया था कि सम्मेलन में इमरान की जगह विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन राजनयिक सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने भी अपनी यात्रा रद कर दी है। इसका आशय यह है कि इस शिखर सम्मेलन से पाकिस्तान पूरी तरह अलग रहेगा।

दरअसल, शनिवार को रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान और इमरान के बीच एक बैठक हुई थी। इस दौरान इमरान ने उन्हें शिखर सम्मेलन में शिरकत के बारे में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी थी। इसी के बाद पाकिस्तान ने सम्मेलन में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सऊदी अरब को बुधवार से शुरू होने वाले कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन में भाग लेने का न्योता नहीं दिया गया है। द न्यूज इंटरनेशनल ने बताया कि सऊदी अरब ने मलेशियाई प्रधानमंत्री के उस बयान पर गंभीर आपत्ति जताई थी, जिसमें उन्होंने इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी) के स्थान पर मुस्लिम देशों के लिए एक नया प्लेटफार्म तैयार करने की बात कही थी। बता दें कि ओआइसी का नेतृत्व सऊदी अरब करता है। इतना नहीं सऊदी अरब के सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कुवैत और बहरीन ने सम्मेलन में कतर के अमीर, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यब एर्दोगन और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के शामिल होने पर आश्चर्य जताया था और कहा था कि ओआइसी के समानांतर मंच बनाने का मकसद सऊदी अरब और उसके सहयोगियों को कमजोर करना है।

इमरान खान। फाइल

अमेरिकी संसद का चुनाव लड़ेंगे भारतवंशी कृष्णा बंसल

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ने की दौड़ में एक और भारतवंशी शामिल हो गए हैं। कारोबारी कृष्णा बंसल ने चुनाव लड़ने का एलान किया है। भारतीय मूल के पीटर मैथ्यू भी प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ने का एलान कर चुके हैं। अमेरिका में इस साल नवंबर में संसदीय चुनाव होने वाले हैं।

बंसल रिपब्लिकन पार्टी की ओर से इलिनोइस की सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सप्ताहांत के दौरान अपने चुनाव अभियान का आगाज करते हुए कहा, 'मैं संसद पहुंचने के लिए चुनाव मैदान में उतरने जा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूं। इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे सपने पूरे किए हैं। अब मैं अमेरिकियों के सपनों को हकीकत बनाने के लिए काम करना चाहता हूं।' बंसल शिकागो मेट्रोपोलिटन इलाके में रहते हैं। उनके चुनाव अभियान की शुरुआत के मौके पर भारतीय मूल की कई जानीमानी हस्तियां भी मौजूद थीं। इस महीने की शुरुआत में सीएनएन टीवी के राजनीतिक विश्लेषक पीटर मैथ्यू ने कैलिफोर्निया से अपनी दावेदारी पेश की थी।

नियमों का उल्लंघन

खाड़ी देशों से अपने हितों को साधने के लिए पाकिस्तान ने होउबारा बस्टार्ड का शिकार करने के लिए जारी किए विशेष परमिट

कतर के अमीर पाक में कर सकेंगे लुप्तप्राय पक्षी का शिकार

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान ने कतर के अमीर और शाही परिवार के नौ सदस्यों को लुप्तप्राय की श्रेणी में आने वाले पक्षी होउबारा बस्टार्ड का शिकार करने के लिए विशेष परमिट जारी किए हैं। जिन जगहों पर इन पक्षियों का शिकार किया जा सकता है वे क्षेत्र सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत में आते हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक एक नवंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 के बीच 10 दिनों की सफारी में 100 होउबारा बस्टार्ड का शिकार किया जा सकता है।

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि उप विदेश मंत्री मोहम्मद अदील परवेज ने 2019-20 के लिए परमिट जारी किए हैं। जिन लोगों को परमिट जारी किया गया है उनमें तेल समृद्ध खाड़ी देश कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी, उनके चाचा, भाई और सात अन्य लोग शामिल हैं। खास बात यह है कि इस कदम के खिलाफ बढ़ती आलोचनाओं के बावजूद पाकिस्तान खाड़ी देशों के शाही परिवारों के सदस्यों को हर साल इन पक्षियों का शिकार करने का परमिट जारी करता है। होउबारा बस्टार्ड के शिकार का प्रयोग पाकिस्तान अरसे से खाड़ी देशों से अपने हितों को साधने के लिए करता रहा है। बता दें कि अपनी घटती आबादी के मद्देनजर यह प्रवासी पक्षी न केवल विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत संरक्षित हैं, बल्कि स्थानीय वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत इसके शिकार पर भी प्रतिबंध है। पाकिस्तानियों को इस पक्षी का शिकार करने की अनुमति नहीं है।

होउबारा बस्टार्ड। फाइल

शर्मिला, लेकिन खूबसूरत होता है होउबारा बस्टार्ड

होउबारा बस्टार्ड पक्षी शर्मीला, लेकिन खूबसूरत होता है और आकार में टर्की चिड़िया जैसा दिखता है। हर साल सर्दियों में ये मध्य एशिया से उड़कर पाकिस्तान आते हैं। इस पक्षी को वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय संधि (बॉन संधि) में शामिल किया गया है। इन पक्षियों का शिकार बाज की मदद से किया जाता है। पिछले दशकों में होउबारा बस्टार्ड की संख्या शिकार और उनकी रिहायशी जगहों के सिकुड़ने से तेजी से कम हुई है, इसीलिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आइयूसीएन) ने भी इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में 'आसानी से शिकार किए जा सकने' वाला पक्षी घोषित किया है। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में पाकिस्तान भी शामिल है।

इस साल दुनियाभर में 49 पत्रकारों की हुई हत्या

- यमन, सीरिया व अफगानिस्तान के संघर्ष प्रभावित इलाकों में कवरेज के दौरान मारे गए ज्यादातर पत्रकार

पेरिस, एएफपी : इस साल दुनिया भर में 49 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। इनमें ज्यादातर यमन, सीरिया और अफगानिस्तान के संघर्ष प्रभावित इलाकों में कवरेज के दौरान मारे गए। हालांकि, यह संख्या पिछले 16 वर्षों के दौरान सबसे कम है। फ्रांसिसी निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसे आरएसएफ के नाम से भी जाना जाता है।

आरएसएफ ने बताया कि पिछले दो दशकों से ज्यादा समय से दुनियाभर में प्रतिवर्ष औसतन 80 पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं। आश्चर्यजनक है कि शांत माने जाने वाले देशों में भी पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं। इस साल अकेले मेक्सिको में 10 पत्रकार मारे गए।

लैटिन अमेरिका में इस साल सबसे ज्यादा 14 पत्रकारों की हत्याएं हुईं। इसके कारण वह पश्चिम एशिया जितना ही खतरनाक साबित हुआ है।

चीन, मिस्र व सऊदी अरब में हुई सबसे ज्यादा पत्रकारों की गिरफ्तारी

इस साल दुनियाभर में करीब 389 पत्रकार गिरफ्तार किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले 12 फीसद ज्यादा है। इनमें करीब आधे की गिरफ्तारी सिर्फ तीन देशों- चीन, मिस्र और सऊदी अरब में हुई। दुनियाभर में 57 पत्रकारों को बंदी भी बनाया गया है, जिनमें ज्यादातर सीरिया, यमन, इराक व यूक्रेन में कैद हैं। बता दें कि ज्यादातर पत्रकारों की मौत आतंकवाद प्रभावित इलाकों में ही आतंकियों द्वारा की जाती है।

ये भी जानिए
विशाखापत्तनम के वीडीसीए स्टेडियम में उच्चतम स्कोर 356 रन है जो भारत ने पाक के खिलाफ बनाया था। यहां न्यूनतम स्कोर 79 रन है जो न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ बनाया था।

अभी शिवम दुबे को और समय देने की जरूरत

मोहिंदर अमरनाथ
रिवर्स स्वीप

चेन्नई में शिमरोन हेटमायर और शाई होप का प्रदर्शन उच्च स्तर का था और उन्होंने इतनी समझदारी से बल्लेबाजी की थी कि मुझे नहीं लगता कि भारतीय गेंदबाजों के पास उन्हें रोकने के लिए कुछ खास था। इस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी ने पुरानी विंडीज टीम की याद दिला दी। वेस्टइंडीज ने अब सीरीज में बढ़त हासिल कर ली है और बल्लेबाजी में वे अच्छे दिख रहे हैं। वे इस जीत से प्रेरित होंगे और अधिक आत्मविश्वास और संकल्प के साथ विशाखापत्तनम में मैच खेलेंगे।

भारतीयों के लिए वास्तव में ऐसा बहुत कुछ नहीं है जिसे गेंदबाजी के मोर्चे पर आजमाया जा सके। योजना के अनुसार नए संयोजनों को आजमाना है और शिवम दुबे की पसंद को दोष देना कठिन है। इस स्तर पर केवल टी-20 खेले जाने के बाद उन्हें समय देने की जरूरत है। शाई होप और शिमरोन हेटमायर शानदार लय में थे और उनको रोकने के लिए दुबे का कार्य कठिन था। बल्लेबाजी में एक बार फिर यह साबित हो गया कि जब कोहली और रोहित स्कोर नहीं करते हैं तब 300 से अधिक का स्कोर खड़ा करना टीम के लिए मुश्किल होता है। उनके आउट होने के बाद स्लॉग ओवरों में भी वेस्टइंडीज के गेंदबाज भारत को कम स्कोर में रोकने में सक्षम थे और उस दौरान भारत की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। हेटमायर जिस तरह की फॉर्म में थे तो उसे देखकर लगता था कि मेहमान 300 से अधिक के स्कोर को भी हासिल कर सकते थे। भारत के लिए बल्लेबाजी में सकारात्मक सिर्फ रिषभ पंत का प्रदर्शन रहा जिन्होंने अर्धशतक लगाया था। उन्होंने टीम में जरूरत पड़ने पर क्रीज पर रुकने का संकल्प दिखाया और टीम के स्कोर बोर्ड को चलाते रहे। श्रेयस अय्यर ने भी उनका अच्छा साथ दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरे मैच में भारतीयों की जोरदार वापसी होगी। आमतौर पर वहां की पिच बेहतर है।

#WhatDrivesYou
EXIDE

मैच नया, लेकिन कहानी पुरानी

दूसरा वनडे आज, 17 साल बाद वेस्टइंडीज के पास भारत को उसके घर में वनडे सीरीज में हराने का मौका

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: विराट कोहली की अगुआई में भारतीय टीम जब बुधवार को विशाखापत्तनम में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में खेलने उतरेगी तो उसके सामने वही पुरानी कहानी होगी, जिससे वह पिछले कुछ समय से जूझती हुई आई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में कोहली की टीम को अपने गेंदबाजी संयोजन से परेशान होना पड़ा था और यही कहानी उसे अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली घरेलू वनडे सीरीज में भी देखने को मिली थी। वेस्टइंडीज के पास भारत को उसके घर में वनडे सीरीज में हराने का मौका है क्योंकि 17 साल बाद पोलार्ड की अगुआई वाली टीम यह जीत सकती है। इससे पहले वेस्टइंडीज ने भारत में 2002-03 में सात मैचों की वनडे सीरीज में 4-3 से जीत हासिल की थी।

भारत हारा तो बनेंगे खराब रिकॉर्ड : कोहली की टीम अगर दूसरा हारती है तो उसके खाते में कई खराब रिकॉर्ड जुड़ जाएंगे। भारत ने 15 साल पहले घर में दो लगातार वनडे सीरीज गंवाई थीं। इसके साथ ही वे अपने घर में कभी भी लगातार पांच वनडे मैच नहीं हारे हैं, लेकिन दोनों चीजें बुधवार को हो सकती हैं। इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया ने इस साल मार्च में भारत को वनडे सीरीज में 3-2 से हराया था और उस सीरीज के अंतिम तीनों मैच भारतीय टीम हार गई थी। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे गंवाने के साथ भारतीय टीम घर में लगातार चार वनडे हार चुकी है। अगर यह मैच भी हार गई तो घर में लगातार दूसरी वनडे सीरीज गंवा बैठेगी।

वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले दूसरे वनडे मैच से पहले मंगलवार को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में अभ्यास सत्र के दौरान कैच पकड़ते भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव ● प्रेट्र

कोहली की कुलचा रणनीति: मेहमान टीम के बल्लेबाजों, खासकर पिछले मैच के शतकवीर शाई होप और शिमरोन हेटमायर ने कुलदीप यादव और रवींद्र सिंह जडेजा को आसानी से खेला था और दोनों गेंदबाजों को कोई विकेट भी हासिल नहीं करने दिया। कोहली को स्लॉग ओवरों में दीपक चाहर और मुहम्मद शमी से गेंदबाजी करानी पड़ी और उनके साथ शिवम दुबे को भी गेंद डालने के लिए दी गई। यही कहानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी जहां टीम को सीरीज गंवानी पड़ी और तब विजय शंकर बैकअप गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल थे। चेन्नई में दोनों टीमों के बीच अंतर यह रहा है कि वेस्टइंडीज के पास सात गेंदबाजों की रणनीति ने उनकी मदद की और पोलार्ड ने हालात का फायदा उठाया, जबकि कोहली के पास इतने विकल्प नहीं थे। शिवम दुबे का वनडे में पदार्पण अच्छा नहीं रहा और उन्होंने 68 रन लुटाए, जबकि नौ रन बनाकर आउट हो गए। अब देखना होगा कि क्या कोहली इस मैच में कुलचा रणनीति के साथ उतरेंगे? क्या वह कुलदीप के साथ चहल को भी अंतिम एकादश में शामिल करेंगे? अगर चहल टीम में आते हैं तो दुबे या जडेजा में से किसी एक को अपनी जगह गंवानी पड़ेगी। जडेजा के अनुभव को देखते हुए उन्हें बाहर रखना मुश्किल है, जबकि दुबे का बाहर होना तय माना जा रहा है। भारतीय गेंदबाजी चेन्नई में पहले मैच में खराब नहीं थी, लेकिन धीमी पिच पर 287 रन बनाने के बावजूद जीत नहीं पाने से टीम प्रबंधन के सामने कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं। लिहाजा पांचवें गेंदबाजी विकल्प को उतारा जा सकता है। जडेजा और कुलदीप ने उस मैच में 10-10 ओवरों में क्रमशः 58 और 45 रन दिए। विशेषज्ञ पांचवें गेंदबाज के विकल्प के रूप में तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर भी हैं। मनीष पांडे छठे नंबर पर केदार जाधव की ही जगह ले सकते हैं। जाधव ने चेन्नई में 33 गेंद में 40 रन बनाए थे, लेकिन दूसरे मैच में पांडे को शामिल करने की संभावना है।

शीर्ष क्रम मजबूत: वेस्टइंडीज का शीर्ष क्रम मजबूत है, जिसमें सुनील अंबरीश, होप और हेटमायर शामिल हैं। अंबरीश के लिए पहला मैच अच्छा नहीं रहा था और वह नौ रन पर आउट हो गए थे। वहीं, होप और हेटमायर ने मैच को एकतरफा बनाते हुए टीम को जीत दिलाई थी। एक बार फिर कैरेबियाई टीम की उम्मीदें इन दोनों बल्लेबाजों पर टिकी होंगी। कैरेबियाई तेज गेंदबाजों शेल्डन कॉटरेल और अल्जारी जोसेफ ने अच्छा प्रदर्शन किया।

पिच रिपोर्ट

विशाखापत्तनम की एसीए-वीडीसीए स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों की मददगार मानी जाती है। यहां 320 रन का स्कोर अच्छा माना जा रहा है और ऐसे में दोनों टीमों के बल्लेबाज इसका फायदा उठा सकते हैं। भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और विराट कोहली के लिए यह पिच रास आने वाली है।

लुइस का खेलना मुश्किल

वेस्टइंडीज को अपने सलामी बल्लेबाज इविन लुइस की कमी दूसरे वनडे मैच में भी खल सकती है। लुइस को भारत के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में फील्डिंग के दौरान बायें पैर के घुटने में चोट लग गई थी, जिसके बाद वह बल्लेबाजी करने भी नहीं उतरे थे। इसके बाद वह पिछले वनडे मैच में भी नहीं खेल पाए थे। अब दूसरे वनडे मैच को लेकर उनके खेलने का फैसला टॉस से पहले लिया जा सकता है।

भुवनेश्वर के सही विकल्प हो सकते हैं उमेश यादव

के श्रीकांत
कलम से

शिमरॉन हेटमायर और शाई होप के बीच हुई विशाल साझेदारी ने सफेद गेंद के क्रिकेट में भारतीय गेंदबाजी की कलई खोल दी है। मैं समझ सकता हूं कि बुमराह और हार्दिक पांड्या की वापसी के साथ यह समस्या बहुत हद तक सुलझ जाएगी, लेकिन बैंच स्ट्रेंथ चिंता का विषय है। मेरे विचार में उमेश यादव भुवनेश्वर कुमार के बेहतर विकल्प हो सकते हैं। वेस्टइंडीज जैसी टीम के खिलाफ हवा में गति काफी अहम है। उमेश थोड़े महंगे साबित हो सकते हैं, लेकिन वह एक या दो विकेट निकाल सकते हैं।

गेंदबाजी संयोजन पर भी नजर दौड़ाने की जरूरत है। शिवम दुबे को फिलहाल ऑलराउंडर नहीं कहा जा सकता। उन्हें पांचवें गेंदबाज के तौर पर कोहली का आत्मविश्वास जीतने के लिए अपनी गेंदबाजी में सुधार करना होगा। कुलदीप यादव और चहल को एक साथ खिलाना भी बुरा आइडिया नहीं है। घरेलू परिस्थितियों में वे एक बल्लेबाज की जगह ले सकते हैं और मुझे लगता शिवम दुबे की जगह विशेषज्ञ बल्लेबाज को टीम में शामिल करना चाहिए। कोई भी टीम जीत की तुलना में हार से ज्यादा सीखती है और मुझे यकीन है कि कोचिंग यूनिट इन सब मुद्दों पर ध्यान देगी। फील्डिंग के स्तर में भी लगातार गिरावट हो रही है। भारत को खेल के अपने तीनों विभागों में सुधार करना होगा। वेस्टइंडीज ने निश्चित तौर पर भारत को नींद से जगा दिया है। हेटमायर अदभुत थे और होप ने भी शानदार प्रदर्शन किया। आतिशी बल्लेबाजों से भरी टीम में होप बेहद शांत और सहज बल्लेबाज हैं। कई बार उनका स्ट्राइक रेट कम हो सकता है, खासतौर से जब उनका साझेदार अच्छी फॉर्म में न हो। कभी डेसमंड हेंस जैसी भूमिका निभाते थे, ठीक वैसी ही भूमिका होप निभा सकते हैं। हार के बावजूद भारत अभी भी आखिरी दो वनडे जीत की दावेदार है।

आज के मैच में ACC KAMAAL का MOMENT कौन जीतेगा?
वोट करने के लिए, लॉग ऑन करें facebook.com/accind
ACC OFFICIAL PARTNER

123 रनों की पारी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप ने भारत के खिलाफ विशाखापत्तनम में पिछले मैच में खेली थी। पिछले साल यहां दोनों टीमों के बीच हुआ मैच टाई रहा था। वेस्टइंडीज को आखिरी गेंद पर पांच रन चाहिए थे और होप ने चौका लगाकर स्कोर बराबर किया था

01 बार ही विशाखापत्तनम में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम पिछले छह वनडे में जीत दर्ज कर पाई है

438 रन विराट कोहली विशाखापत्तनम में बना चुके हैं, जिसमें दो शतक शामिल हैं

2010 के बाद से विशाखापत्तनम में पहली पारी का बल्लेबाजी औसत 275 रन है

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, रिषभ पंत, शिवम दुबे, केदार जाधव, रवींद्र जडेजा, युजवेंद्रा सिंह चहल, कुलदीप यादव, दीपक चाहर, मुहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर।

वेस्टइंडीज: कीरोन पोलार्ड (कप्तान), सुनील अंबरीश, शाई होप, खारे पियरे, रोस्टन चेस, अल्जारी जोसेफ, शेल्डन कॉटरेल, ब्रेंडन किंग, निकोलस पूरन, शिमरोन हेटमायर, इविन लुइस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, कीमो पॉल और हेडन वाल्श जूनियर।

एक बार फिर जसप्रीत बुमराह ने पुराने एक्शन में गेंदबाजी की

विशाखापत्तनम: जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम के वैकल्पिक अभ्यास सत्र में पुराने एक्शन के साथ गेंदबाजी की, जबकि पृथ्वी शॉ ने ट्रेनर निक वेब के साथ अभ्यास किया, लेकिन वह पूरी तरह फिट नजर नहीं आए। बुमराह चोट के कारण बाहर हैं, लेकिन अगले साल न्यूजीलैंड दौरे के लिए उनके फिट होने की उम्मीद है। वहीं, शॉ डोपिंग के कारण आठ महीने का प्रतिबंध झेलने के बाद घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए शानदार वापसी कर चुके हैं। भारतीय टीम प्रबंधन उनके फिटनेस स्तर की समीक्षा से पहले दोनों से बात करेगा। बुमराह को अभ्यास के दौरान भारतीय टीम की जर्सी दी गई। उन्होंने करीब एक घंटे तक रिषभ पंत, मनीष पांडे और मयंक अग्रवाल को गेंदबाजी की। अभ्यास के दौरान विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल नजर नहीं आए। कोच रवि शास्त्री और राष्ट्रीय चयनकर्ता देवांग गांधी की निगरानी में हुए अभ्यास सत्र में बुमराह सहज नजर आए। शॉ ने ट्रेनर वेब से लंबी बातचीत की। उसके बाद उन्हें फील्डिंग कोच आर श्रीधर के दिए गए ऊंचे कैच लपकने को कहा गया।

दिल्ली को खलेगी दादा की कमी

आइपीएल नीलामी

नई दिल्ली, आइएएनएस: सौरव गांगुली इस समय बेशक बीसीसीआइ के अध्यक्ष हों, लेकिन वह हमेशा भारत के उस कप्तान के तौर पर जाने जाते हैं जिसने देश की क्रिकेट को बदला। उनका युवाओं का समर्थन करना राष्ट्रीय टीम में भी कारगर साबित हुआ और दिल्ली कैपिटल्स की टीम में भी।

इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के अगले सत्र की नीलामी गुरुवार को कोलकाता में होनी है और ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) धीरज मल्होत्रा ने कहा है कि 'दादा' की कमी निश्चित तौर पर खलेगी। पिछले सत्र में गांगुली कैपिटल्स के साथ थे। मल्होत्रा ने नीलामी के लिए अपनी रणनीति को लेकर बात की। उन्होंने कहा, 'हमें उनकी (सौरव की) कमी खलेगी। वह न सिर्फ चतुर और तेज प्रशासक हैं, बल्कि बेहतरीन इंसान भी हैं। उनका ड्रेसिंग रूम में होना, डग आउट में होना, टीम में होना, खिलाड़ियों से बात करना, यह सभी प्रेरणात्मक हैं। टीम के खिलाड़ी उनसे काफी प्रभावित हुए थे। यह मायने नहीं रखता कि खिलाड़ी सीनियर है या जूनियर, वह हमेशा हर किसी के लिए उपलब्ध रहते थे। मुख्य कोच रिकी पोंटिंग के साथ उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी और इसलिए उनकी कमी हमेशा खलेगी।' नीलामी में हालांकि टीम के कोच रिकी पोंटिंग भी नहीं होंगे, क्योंकि वह इस समय ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यस्त हैं। सीईओ ने कहा, 'पोंटिंग ने अपनी रणनीति हमें बता दी है। नीलामी में यह बात भी निर्भर करती है कि बाकी फ्रेंचाइजियां क्या करती हैं। हमने पहले ही रणनीति बना ली है और तय कर लिया है कि किस खिलाड़ी पर कितने रुपये खर्च करने हैं। यह सब के साथ मिलकर फैसला लेने की प्रक्रिया होगी। अगर आप हमारी टीम देखेंगे तो हमारे पास अच्छा मिश्रण है और टीम में संतुलन बनाने के लिए हमें एक-दो खिलाड़ियों की जरूरत है। हम कुछ ऑलराउंडर खिलाड़ियों की सूची को देखेंगे और कुछ तेज गेंदबाजों को भी। निश्चित तौर पर हमारी रणनीति कोर टीम को बनाए रखने की होगी।'

सौरव गांगुली फाइल फोटो, प्रेट्र

हम सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे : कोहली

मुंबई: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर (आरसीबी) के कप्तान विराट कोहली ने आइपीएल नीलामी से पहले अपनी टीम के प्रशंसकों को संदेश दिया है। आरसीबी के द्वारा किए गए ट्वीट के अनुसार, कोहली ने प्रशंसकों को विश्वास दिलाया है कि फ्रेंचाइजी सभी पहलुओं पर ध्यान देने वाली है और 2020 सत्र के लिए मजबूत टीम का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा, 'जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी सत्र के लिए नीलामी होने वाली है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रबंधन समूह, माइक (हेसन) और साइमन (कैटिच) बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि आरसीबी के प्रशंसकों को 2016 में उनकी टीम के दूसरे स्थान पर रहने के बाद कुछ मुश्किल साल से गुजरना पड़ा। तब से तीन साल में आरसीबी दो बार अंतिम पायदान पर रही। उन्होंने कहा कि हमने अच्छी टीम बनाने के लिए कुछ चर्चा की है। हमारे पास पहले से ही मजबूत कोर है और हम आपको सुनिश्चित करते हैं कि जिन चीजों की जरूरत है, हम उन सभी पहलुओं पर ध्यान देने वाले हैं।

आइसीसी की महिला वनडे व टी-20 टीम में शामिल मंधाना

दुबई, प्रेट्र: भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की साल की वनडे और टी-20 टीम में शामिल किया गया है।

वनडे टीम में मंधाना के साथ झूलन गोस्वामी, पूनम यादव और शिखा पांडे को भी जगह मिली है, जबकि टी-20 टीम में उनके साथ ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा हैं। 23 साल की मंधाना ने 51 वनडे और 66 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के अलावा दो टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने वनडे और टी-20 में 3476 रन बनाए हैं। इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड 148 रन की पारी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टी-20 क्रिकेटर चुना गया। ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी साल की सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी चुनी गई हैं, जिन्होंने 2019 में 73.50 की औसत से 441 रन बनाने के अलावा 13.52 की औसत से 21 विकेट भी झटके हैं। पेरी को सभी प्रारूपों को मिलाकर दिए जाने वाले साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के तौर पर रशेल हेहोई-फ्लिंट पुरस्कार के लिए भी चुना गया। पेरी ने इस साल सभी प्रारूपों में मिलाकर तीन शतक जड़े हैं, जिनमें से एक महिला एशेज टेस्ट में बनाया। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर हैं। तीन साल में दूसरी बार रशेल हेहोई-फ्लिंट पुरस्कार के लिए चुनी गईं पेरी ने कहा, 'यह शानदार सम्मान है और मैं थोड़ी हैरान हूं, क्योंकि इस साल कई शानदार प्रदर्शन देखने को मिले।' वर्ष के उभरती हुई क्रिकेटर का पुरस्कार थाइलैंड की चानिडा सुथिरयुंग को दिया गया। 26 साल की इस तेज गेंदबाज ने इस साल आइसीसी महिला टी-20 विश्व कप क्वालीफायर में 12 विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलिया की ही मेग लैनिंग को वनडे और टी-20 दोनों टीमों का कप्तान चुना गया। लैनिंग ने कहा कि कई शानदार खिलाड़ियों वाली आइसीसी की साल की वनडे और टी-20 कप्तान चुना जाना बड़ा सम्मान है।

पुरस्कार

- वनडे टीम में झूलन, पूनम और शिखा को भी मिली जगह
- टी-20 टीम में ऑलराउंडर दीप्ति को भी किया गया शामिल

आइपीएल बनाता है रास्ता : चाहर

विशाखापत्तनम, प्रेट्र : तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने मंगलवार को कहा कि उन्हें अपने करियर के शुरू में ही समझ में आ गया था कि सीमित ओवरों की क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देना होगा और आइपीएल भारतीय टीम में जगह बनाने का आसान रास्ता है।

आगरा के रहने वाले चाहर ने राजस्थान की तरफ से रणजी ट्रॉफी पदार्पण पर ही हैदराबाद के खिलाफ 10 रन देकर आठ विकेट लिए थे, लेकिन उन्हें जल्द ही यह अहसास हो गया कि लाल गेंद से 125 किमी की रफ्तार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का उनका सपना पूरा नहीं कर सकती। चाहर ने कहा, 'जब मैंने तेजी हासिल करने के लिए अपने एक्शन बदला तो मुझे अपनी राज्य की टीम में संघर्ष करना पड़ा। मुझे अचानक ही लगने लगा कि भारतीय टीम में जगह बनाने मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। अगर मैं रणजी के भरोसे रहता तो फिर मुझे बहुत सारे मैच खेलने होते, पूरे सत्र खेलना होता और दलीप ट्रॉफी में खेलना होता। यह लंबा रास्ता था लेकिन अगर आप आइपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते हो तो फिर आपको जल्द ही भारत की तरफ से खेलने का मौका मिल सकता है। अपने करियर के उस दौर में मैंने सफेद गेंद की क्रिकेट पर अधिक ध्यान देने का फैसला किया।' उन्होंने कहा, 'जब मैंने रणजी ट्रॉफी में प्रवेश किया तो मैं 125 किमी की रफ्तार से गेंदबाजी करता था। अपनी तेजी बढ़ाने के प्रयास में मैं चोटिल भी रहा। मैं जानता था कि इस तेजी से मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं बने रह सकता हूं। मुझे इसे 140 तक बढ़ाना होगा और इसमें स्विंग को जोड़ना होगा। स्विंग लेती गेंद जो 135 से 137 किमी की रफ्तार से की गई हो वह किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद मुश्किल गेंद होती है। अगर विकेट सपाट है तो 150 किमी की गेंद भी आसानी से खेली जा सकती है।'

उन्होंने कहा, 'लाल गेंद का अगर एक छोर चमकीला है तो वह (रिवर्स) स्विंग लेगी। यही वजह है कि रणजी स्तर पर कई गेंदबाज गेंद को दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। सफेद गेंद से स्विंग चमक के कारण नहीं मिलती। यह आपके एक्शन से मिलती है इसलिए मैंने अपनी तेजी बढ़ाने के साथ इस पर भी काम किया। मैं धीमे बाउंसर अच्छी तरह से करता हूं और मैं अपने यॉर्कर पर काम कर रहा हूं। अब मुझे विश्वास है अगर मेरी गेंदों पर दो छक्के भी लग गए तब भी मैं यॉर्कर कर सकता हूं। वनडे सबसे मुश्किल प्रारूप है। टी-20 में आपका ध्यान रन रोकने पर होता है। उसमें अगर आप विकेट नहीं लेते हो लेकिन चार ओवर में 24 रन ही देते हो तो यह अच्छा विश्लेषण होता है। टेस्ट मैचों में उसके उलट है। आपको हमलावर होना होता है। रन बने तो बने लेकिन आपको विकेट लेने होते हैं। वनडे इन दोनों का मिश्रण है जहां आपको रन भी रोकने होते हैं और विकेट भी लेने होते हैं। मैंने भारत-ए की तरफ से लिस्ट-ए के कई मैच खेले हैं।

विशाखापत्तनम डायरी

होप की नजरें कोहली और रोहित को पछाड़ने पर

विशाखापत्तनम: वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज शाई होप को यकीन है कि भारत के खिलाफ बुधवार को दूसरे वनडे के दौरान उनके कुछ साथी खिलाड़ियों की नजरें गुरुवार को होने वाली आइपीएल नीलामी पर लगी होंगी लेकिन उनका लक्ष्य 2019 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली और रोहित शर्मा को पछाड़ना है। पहले मैच में शतक जमाने वाले होप से जब पूछा गया कि क्या आइपीएल नीलामी उनके जेहन में है, उन्होंने ना में जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'मुझे यकीन है कि कुछ खिलाड़ियों का ध्यान इस पर होगा, लेकिन मेरे लिए यह नहीं है। हम यहां भारत के खिलाफ सीरीज खेलने आए हैं और वही प्राथमिकता है।' होप इस साल वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में विराट कोहली (1292) और रोहित शर्मा (1268) के बाद तीसरे स्थान पर हैं। होप के नाम 1225 रन हैं। उन्होंने कहा, 'एक बल्लेबाज के तौर पर आप अधिकतम योगदान देना चाहते हैं और अगर इससे टीम जीतती है तो अधिक संतोष होता है। उम्मीद है कि हम उनके शीर्ष क्रम के विकेट जल्दी लेंगे।

फुटबॉल बार्सिलोना और रीयल के बीच ला लीगा में आज होगी भिड़ंत, शीर्ष स्थान पर कब्जे की फिराक में दोनों क्लब

आज दिखेगा एल क्लासिको का रोमांच

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: तमाम उठा-पठक के बीच आखिरकार सत्र के पहले एक क्लासिको के लिए दो दिग्गज स्पेनिश फुटबॉल क्लब तैयार हैं। बार्सिलोना के कैंप नाउ में बुधवार देर रात बार्सिलोना और रीयल मैड्रिड की टीमें भिड़ने जा रही हैं जहां दोनों क्लबों की निगाहें जीत के साथ स्पेनिश लीग ला लीगा में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाने पर होगी। ला लीगा की अंक तालिका में दोनों टीमें फिलहाल 35-35 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं और ये तीसरे स्थान पर काबिज सेविया से तीन अंक आगे हैं। एल क्लासिको में जिस टीम को जीत मिलेगी वह सर्दियों की छुट्टियों में तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके जाएगा और खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जाएगा। दो महीने पहले अक्टूबर में यह बहुप्रतीक्षित एल क्लासिको मुकाबला स्थगित कर दिया गया था। कई तारीखों पर चर्चा के बाद आखिरकार 18 दिसंबर की तारीख के लिए दोनों टीमें तैयार हो गई थीं।

हिचकोले खाता प्रदर्शन: मौजूदा सत्र में बार्सिलोना और रीयल मैड्रिड का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। पिछले सप्ताह भी इन दोनों क्लबों का प्रदर्शन भी कुछ वैसा ही रहा। पिछले रविवार को बार्सिलोना को एंटोनी ग्रीजमैन और लुइस सुआरेज के गोल के बावजूद रीयल सोसिएदाद से ड्रॉ खेलना पड़ा था। इसी तरह जिदान की टीम रीयल मैड्रिड भी रविवार को वेलेंसिया के खिलाफ हारते-हारते बची थी। तब गोलकीपर थिबॉट कॉर्टोइस के कॉर्नर पर करीम बेंजमा ने इंजुरी टाइम में गोल करके मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर समाप्त कराया था।

मेसी की मौजूदगी का रोमांच: बेशक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जाने से रोमांच थोड़ा कम हो गया हो लेकिन लियोन मेसी की मौजूदगी इस बार एक क्लासिको में रोमांच पैदा करेगी। पिछले एल क्लासिको मुकाबले में मेसी चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे लेकिन इस बार वह अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार हैं।

अभ्यास सत्र के दौरान रीयल मैड्रिड के मिडफील्डर लुका मॉड्रिक (दायें) और डिफेंडर इडर मिलीटाओ ● एएफपी

इन पर होंगी निगाहें

- बार्सिलोना
  मेसी, सुआरेज, ग्रीजमैन, डि जोंग, मार्क स्टेगन
- रीयल मैड्रिड
  बेंजमा, रॉड्रिगो, मॉड्रिक, रामोस, कॉर्टोइस

बार्सिलोना vs रीयल मैड्रिड
00:30 बजे (देर रात)
प्रसारण: फेसबुक स्थान: कैंप नाउ

पिछले पांच मुकाबले

रीयल मैड्रिड	0	1	बार्सिलोना
रीयल मैड्रिड	0	3	बार्सिलोना
रीयल मैड्रिड	1	1	बार्सिलोना
रीयल मैड्रिड	1	5	बार्सिलोना
रीयल मैड्रिड	2	2	बार्सिलोना

18 गोल बार्सिलोना के स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी ने अपने ला लीगा के 29 एल क्लासिको मुकाबले में किए हैं। इस दौरान उन्होंने नौ गोल करने के मौके भी तैयार किए हैं

05 में से तीन पिछले एल क्लासिको के मुकाबलों में रीयल मैड्रिड को बार्सिलोना के खिलाफ शिकस्त मिली है जबकि दो मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। ऐसे में यह मैच उसके लिए अहम हो जाता है

हर कोई रीयल का दबाव नहीं झेल सकता : वराने

राफेल वराने बहुत छोटी उम्र में ही बेशुमार सफलताओं का स्वाद चख चुके हैं। महज 26 साल की उम्र में वराने ला लीगा, यूरोपियन चैंपियनशिप, फीफा विश्व कप और ना जाने और कई खिताबी जीत में अपनी टीम रीयल मैड्रिड के सदस्य रहे हैं। वराने का मानना है कि रीयल मैड्रिड जैसे क्लब का दबाव झेलना दुनिया के हर फुटबॉलर के बस की बात नहीं है। फ्रांस की विश्व कप विजेता टीम के सदस्य और स्पेनिश फुटबॉल क्लब रीयल मैड्रिड के सेंटर बैक राफेल वराने से अभिषेक त्रिपाठी ने विशेष बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश...

साक्षात्कार

● रीयल मैड्रिड में आने से पहले आपने लेंस क्लब के साथ कुछ साल बिताए। इतनी छोटी उम्र में रीयल जैसे बड़े क्लब के साथ जुड़ने पर आपको कैसा महसूस हुआ?

-मैंने वहां दो साल से भी कम समय बिताए और एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में केवल 24 मैच खेला। सच बात है कि मैं बहुत छोटी उम्र में ही रीयल मैड्रिड में आ गया। यह मेरे जीवन की एक बड़ी चुनौती थी। मैंने हर दिन खेल का लुत्फ उठाने और उन खिलाड़ियों से सीखने की कोशिश की जो यहां काफी समय से हैं और प्रतिभावान हैं। मैंने अपने सपने को पूरा करने, उसका लुत्फ उठाने के लिए काम शुरू कर दिया है। मैंने इतनी कम उम्र में यहां आने के बारे में नहीं सोचा था। मुझे धैर्य की आवश्यकता थी क्योंकि जब आप रीयल जैसे क्लब में आते हैं तो आप आते ही कई मुकाबले नहीं खेल सकते। मुझे हर मौके का ज्यादा ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना था।

● पहली बार आप 2014 के चैंपियंस लीग में फाइनल में खेलने उतरे थे जहां आपकी टीम विजेता बनी। उस पल आपने कैसा महसूस किया?

-इतनी कम उम्र में चैंपियंस लीग जीतने की भावना का वर्णन करना मुश्किल है। वह एक सपने की तरह था और इस तरह के एक बड़े मैच में खेलने को लेकर मैं बहुत दबाव में था लेकिन मैंने उसका आनंद लिया जो एक खूबसूरत याद है।

● आपने बताया कि रीयल में आने के बाद यहां पहले से मौजूद स्थापित खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। किससे आपको सीखने का मौका मिला ?

-मैंने पेपे या सर्जियो रामोस जैसे खिलाड़ियों को देखा, क्योंकि वे डिफेंडर के रूप में खेलते थे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी भी थे, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए एक मिसाल हैं। मैंने इनसे और बाकी लोगों से भी बहुत कुछ सीखा।

● आप बहुत छोटी उम्र में दो बार ला लीगा और चार बार चैंपियंस लीग के अलावा फ्रांस के साथ फीफा विश्व कप भी जीत चुके हैं। क्या आपकी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं या फिर कुछ बाकी हैं ?

-ये सच है कि जब आप किसी चीज को एक बार हासिल कर लेते हो तो उसे दोबारा हासिल करने की आपकी इच्छा होती है। आप हमेशा इसे हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं और आप फुटबॉल की सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी हासिल करने के लिए खेलते हैं। आप हमेशा शीर्ष पर रहना चाहते हैं। मैंने जो भी जीता है, वह सपने के सच होने से कहीं ज्यादा है।

● अब तक के मौजूदा सत्र को आप कैसे देखते हैं ?

-पिछले सत्र में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मेरा मानना है कि हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमने प्री-सीजन में बहुत मेहनत की। टीम अब आश्वस्त है और हम बेहतर खेल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जब तक सब कुछ दांव पर न हो जाए, तब तक आगे बढ़ते रहना चाहिए। रीयल मैड्रिड पर दबाव उतना ही बड़ा है जितना झेला जा सके। यही कारण है कि हर खिलाड़ी रीयल मैड्रिड जैसे क्लब में नहीं खेल सकता और ना दबाव झेल सकता है।

● रीयल मैड्रिड के साथ इस सत्र में आपका लक्ष्य क्या है?

-हमेशा की तरह सभी मुकाबलों को जीतना मेरा लक्ष्य है लेकिन आने वाले मुकाबलों पर ध्यान लगाता सबसे अहम है ताकि सत्र के अंत में आपके क्लब को खिताब जीतने के मौके मिल सकें।

आइपीएल के 2020 सत्र के लिए हम मजबूत टीम तैयार करेंगे और टीम खिताब जीतने की कोशिश करेंगी।
– ब्रेंडन मैकुलम, मुख्य कोच, कोलकाता नाइटराइडर्स

गंभीर बोले, पंत को लगातार अच्छे प्रदर्शन की जरूरत

विशाखापत्तनम, आइएएनएस : पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत को सलाह दी है कि टीम प्रबंधन ने पिछले कुछ समय में उन पर जो भरोसा जताया है अब उन्हें भी अपने बल्ले से लगातार अच्छे प्रदर्शन करने की जरूरत है। गंभीर ने कहा कि पंत तीनों प्रारूपों में खेलते हैं। इससे पता चलता है कि टीम प्रबंधन उन पर भरोसा करता है। उन्हें नियमित तौर अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है।

न्यूज गैलरी

दीपक चुने गए साल के सर्वश्रेष्ठ युवा पहलवान

नई दिल्ली : विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता भारतीय पुरुष पहलवान दीपक पूनिया को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने फ्रीस्टाइल वर्ग में साल (2019) का सर्वश्रेष्ठ पहलवान चुना है। जूनियर से सीनियर वर्ग में आए पूनिया ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतकर भारत के 18 वर्षों के सूखे को खत्म किया था। इसके अलावा उन्होंने इस साल सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी अपने पदार्पण में रजत पदक जीता था। इस सम्मान को पाने के बाद दीपक हैरान हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूं। दुनिया भर के पहलवानों के बीच से चुना जाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। अपने प्रदर्शन में सुधार करने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए यह मेरे लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत है। (प्रेट्र)

युवा खिलाड़ी लक्ष्य करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर

नई दिल्ली : उभरते हुए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) की मंगलवार को जारी ताजा रैंकिंग में पुरुष सिंगल्स में करियर के सर्वश्रेष्ठ 32वें स्थान पर पहुंच गए हैं। लक्ष्य ने रविवार को बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय चैलेंज का खिताब जीता था जो पिछले साल का उनका पांचवां खिताब रहा। 18 वर्षीय लक्ष्य ने ढाका में फाइनल में मलेशिया के लियोंग जुन हाओ को 22-20, 21-18 से हराकर खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स में बीसाई प्रणीत और किदांबी श्रीकांत क्रमश : 11वें और 12वें स्थान पर बरकरार हैं, जबकि पी कश्यप 23वें स्थान पर बने हुए हैं। एचएस प्रणय (26वें), सौरभ वर्मा (28वें), समीर वर्मा (33वें) और शुभंकर डे (44वें) का नंबर है। (प्रेट्र)

मैच रद होने से फेडरर को पहुंची थी तकलीफ

बोगोटा : स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने बताया है कि कोलंबिया में पिछले महीने एलेक्जेंडर ज्वेरेव के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनी मैच के रद होने से मानसिक रूप से तकलीफ में था। पिछले महीने उग्र प्रदर्शन के डर के कारण बोगोटा में होने वाले प्रदर्शनी मुकाबले को आखिरी मिनटों में रद करना पड़ा था। फेडरर ने कहा कि हम अभ्यास करने के लिए कोर्ट पर गए थे और अच्छा अभ्यास कर रहे थे, लेकिन उसके बाद चीजें खराब हो गईं। मैं सोच रहा था कि क्या यह खेलने के लिए सही हालात हैं क्योंकि लोगों को सुरक्षित घर पहुंचना जरूरी था। मुझे पता चला कि हम नहीं खेलेंगे तो मेरे लिए बहुत तनाव की स्थिति थी। (आइएएनएस)

विश्व कप की हार के लिए टीम प्रबंधन जिम्मेदार : युवराज

नजरिया ▶ पूर्व ऑलराउंडर ने कहा, टूर्नामेंट के लिए योजना गलत थी

नई दिल्ली, प्रेट्र : युवराज सिंह ने भारतीय टीम के विश्व कप सेमीफाइनल से बाहर होने के लिए टीम प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व ऑलराउंडर ने कहा कि इस 50 ओवरों के टूर्नामेंट के लिए उनकी योजना पूरी तरह से गलत थी। खिताब का प्रबल दावेदार भारत विश्व कप में नंबर चार पर स्थापित बल्लेबाज के बिना उतरा था, जिससे टीम प्रभावित हुई और विराट कोहली की टीम को सेमीफाइनल से बाहर होना पड़ा।

युवराज ने कहा, 'इस विश्व कप में उन्होंने (अंबाती) रायुडू को बाहर कर दिया। विजय शंकर टीम के साथ गए, जो चोटिल हो गए और फिर पंत को चुना गया। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दोनों पांच वनडे मैच खेले थे। मेरे कहने का मतलब है कि इतने कम अनुभव वाले खिलाड़ी से आप कैसे बड़े मैचों में जीत की उम्मीद करते हैं। मेरी नाराजगी उन चीजों से है, जो थिंक टैंक ने की। दिनेश कार्तिक टूर्नामेंट में बाहर ही बैठे रहे, लेकिन अचानक उन्हें सेमीफाइनल में उतारा गया और महेंद्र सिंह धौनी जैसे खिलाड़ी को सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। यह अव्यवस्था की स्थिति थी। बड़े मैचों में आप ऐसा नहीं कर सकते।' उन्होंने कहा, 'आपके चौथे नंबर के बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर 48 रन था, इसलिए पूरी योजना ही खराब थी क्योंकि वे मानकर चल रहे थे कि रोहित, विराट अच्छी फॉर्म में हैं लेकिन टीमें ऐसे जीत दर्ज नहीं करतीं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, अगर आप उनकी 2003, 2011, 2015 की टीमें देखों तो उनके पास मंझे हुए बल्लेबाज थे इसलिए मेरा मानना है कि रणनीति पूरी तरह से गलत थी।'

रायुडू को भारत का नंबर चार बल्लेबाज माना जा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। युवराज ने कहा, 'रायुडू के साथ जो कुछ हुआ उससे मैं काफी निराश था। वह एक साल से भी अधिक समय तक नंबर चार बल्लेबाज रहे। यहां तक कि न्यूजीलैंड में आखिरी मैच में भी। उन्होंने उस मैच में 90 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच बने थे।'

युवराज सिंह। फाइल फोटो, ट्विटर

आचरण अधिकारी ने कपिल व अंशुमन को पेश होने को कहा

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीसीसीआइ के आचरण अधिकारी डीके जैन ने कपिल देव और अंशुमन गायकवाड़ को हितों के टकराव के आरोप में मुंबई में उनके समक्ष पेश होने को कहा है। हालांकि, ये दोनों क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। सीएसी में कपिल और गायकवाड़ के अलावा महिला टीम की पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी शामिल थीं, जिन्होंने सितंबर में जैन से हितों के टकराव का नोटिस मिलने पर इस्तीफा दे दिया था। यह नोटिस मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता की शिकायत पर जारी किया गया था। सीएसी का अब कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन दोनों पूर्व खिलाड़ियों को 27 और 28 दिसंबर को जैन के सामने पेश होने का नोटिस मिला है। बीसीसीआइ के एक सूत्र ने बताया, 'उन्होंने हालांकि इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आचरण अधिकारी ने उनसे कुछ स्पष्टीकरण मांगा है।'

कपिल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, 'मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास करने के लिए और भी कई महत्वपूर्ण काम हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह एक ऐसा काम (कोच चुनना) था जिसे हमें सौंपा गया था। इसमें कोई टकराव का सवाल कहां है। यह प्रचार पाने का एक अच्छा तरीका है।'

भारत का पहला मैच न्यूजीलैंड से

टोक्यो, प्रेट्र : 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें क्रमशः न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत 25 जुलाई को करेंगी। हॉकी की विश्व संस्था एफआइएच ने अगले साल ओलंपिक में होने वाले हॉकी मुकाबलों की घोषणा मंगलवार को की। इसके मुताबिक भारत की पुरुष और महिला टीमें हॉकी प्रतियोगिता के पहले ही दिन अपना अभियान शुरू करेंगी।

आठ बार की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय पुरुष टीम ग्रुप-ए में न्यूजीलैंड के बाद विश्व नंबर एक ऑस्ट्रेलिया से 26 जुलाई, स्पेन से 28 जुलाई, गत चैंपियन अर्जेंटीना से 30 जुलाई और मेजबान जापान से 31 जुलाई को भिड़ेगी। वहीं महिला टीम भी ग्रुप ए में नीदरलैंड्स से भिड़ने के बाद जर्मनी (27 जुलाई), ग्रेट ब्रिटेन (29 जुलाई), आयरलैंड (31 जुलाई) और दक्षिण अफ्रीका (एक अगस्त) से भिड़ेगी। विश्व रैंकिंग में पांचवें स्थान पर काबिज भारतीय पुरुष टीम ने भुवनेश्वर में खेले गए क्वालीफायर्स में रूस को कुल 11-3 के गोल औसत से हराकर ओलंपिक का टिकट हासिल किया था। वहीं भारतीय महिला टीम रैंकिंग में नौवें स्थान पर काबिज है जिसने क्वालीफायर्स में अमेरिका को कुल 6-5 के गोल औसत से हराकर टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया था।

एयरपोर्ट पर रोबोट करेंगे स्वागत : हेनेडा एयरपोर्ट पर रोबोट अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए आने वाले प्रशंसकों और खेल से जुड़े लोगों का स्वागत करेंगे। हेनेडा एयरपोर्ट जापान का प्रमुख एयरपोर्ट है और यह राजधानी टोक्यो से सबसे करीब एयरपोर्ट भी है। आयोजकों के मुताबिक हेनेडा एयरपोर्ट पर चार रोबोट तैनात किए जाएंगे जिनका मुख्य मकसद सुरक्षा मुहैया करना होगा लेकिन यह मेहमानों को रास्ता भी बताएंगे। ये रोबोट कोई भी खतरा महसूस होने पर सुरक्षा गार्डों को बता देंगे।

ओलंपिक डायरी

विश्व विजेता महिला टीम करेगी मशाल रैली का आगाज

टोक्यो : जापान की 2011 महिला विश्व कप विजेता फुटबॉल टीम आठ साल पहले सुनामी, भूकंप और परमाणु हमले से तबाह हुए फुकुशिमा से टोक्यो ओलंपिक मशाल रिले 2020 का आगाज करेगी। आयोजकों ने मंगलवार को कहा कि मशाल रिले के जापान चरण की शुरुआत 26 मार्च को होगी। यह 121 दिन के सफर में 47 जगहों से गुजरेगी। आयोजकों ने उम्मीद जताई कि फुकुशिमा क्षेत्र के प्राकृतिक आपदाओं के बाद फिर उठ खड़े होने के जीवट को टोक्यो ओलंपिक 2020 से दुनिया को दिखाने में मदद मिलेगी।

मेरी कॉम के साथ निष्पक्ष ओलंपिक ट्रायल चाहती हूं : निखत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- महिला मुक्केबाज ने कहा, इस ट्रायल का टीवी पर प्रसारण होना चाहिए
- आइवीएल में दोनों मुक्केबाजों का मुकाबला हो गया था रद

एमसी मेरी कॉम से भारतीय मुक्केबाजी लीग (आइबीएल) में बहु प्रतीक्षित मुकाबला रद होने के बाद निखत जरीन ने मंगलवार को निष्पक्ष ओलंपिक चयन ट्रायल की मांग करते हुए राष्ट्रीय महासंघ (बीएफआइ) से मुकाबले का सीधा प्रसारण करने के लिए कहा। ओलंपिक ट्रायल्स के तीन स्थान पहले ही तय हो चुके हैं और ऐसे में निखत के पास चौथे और अंतिम स्थान को पाने का मौका था। उसका स्थान इस पर निर्भर था कि वह मंगलवार को आइबीएल में मेरी कॉम के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती है, लेकिन अब जबकि यह मुकाबला नहीं हो रहा है तब निखत ने बीएफआइ से निष्पक्ष फैसला करने की अपील की है।

ट्रायल यहां 27 और 28 दिसंबर को होंगे जिसके लिए प्रत्येक भार वर्ग में चार दावेदार हिस्सा लेंगे। महिलाओं के 51 किग्रा में तीन स्थान पहले ही भरे जा चुके हैं। ज्योति गुलिया और रितु ग्रेवाल ने कन्नूर में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत जीतकर ट्रायल में जगह बनाई जबकि मेरी कॉम ने अक्टूबर में रूस के उलान उदे में महिला विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर अपनी जगह सुरक्षित की थी। निखत ने कहा, 'मैं मेरी कॉम के खिलाफ मुकाबले को लेकर बहुत उत्साहित थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। मैं लीग में इसलिए खेली क्योंकि सभी मुकाबले को टीवी पर देखते हैं। अब मुझे ट्रायल के लिए तैयार होना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि ट्रायल बंद कमरों में न हों और उनका टीवी पर सीधा प्रसारण हो ताकि लोग जान सकें कि मुकाबले में क्या हुआ।'

रणजी ट्रॉफी : दिल्ली 215 रनों पर ढेर

ओंगोले (आंध्र प्रदेश), प्रेट्र : दिल्ली की पारी मंगलवार को यहां हुए रणजी मुकाबले के पहले दिन आंध्र प्रदेश के खिलाफ 215 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई। जवाब में आंध्र ने दिन का खेल खत्म होने तक छह ओवर में दो विकेट पर 16 रन बना लिए थे। दिल्ली शुरुआत से ही आंध्र के सामने संघर्ष करती दिखी। उसके दो बल्लेबाज मात्र 16 रनों पर आउट हो गए। केरल के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद दूसरा मैच खेल रही दिल्ली के सलामी बल्लेबाज कुणाल चंदेला अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके। वह 12 गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद कुंवर बिधुड़ी (22) और नीतिश राणा (51 गेंदों में 51 रन) ने चौथे विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी की। इसके बल्लेबाज ललित यादव ने 104 गेंदों में 50 रन बनाकर पारी को काफी हद तक संभाला। ललित ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। दिल्ली की पहली पारी में 70.5 ओवर में 215 रन पर ही ढेर हो गई।

भारत दौरे के लिए लाबुशाने ऑस्ट्रेलियाई टीम में

क्रिकेट डायरी

मेलबर्न, प्रेट्र : फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज मार्नस लाबुशाने को भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम में पहली बार शामिल किया गया है। लाबुशाने ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करके 58.05 की औसत से रन बनाए। उन्होंने अपने पिछले तीन मैचों में शतक जड़ा। ऑलराउंडर सीन एबॉट की पांच साल बाद टीम में वापसी हुई है। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और स्पिनर एश्टन एगर भी टीम में लौटे हैं। बड़े नामों में ग्लेन मैक्सवेल, उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श और नाथन लियोन टीम में नहीं हैं। ऑस्ट्रेलियाई स्टार जोड़ी स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर टीम में शामिल हैं।

पहला वनडे मुंबई में 14 जनवरी को, दूसरा राजकोट में 17 जनवरी को और तीसरा बेंगलुरु में 19 जनवरी को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता ट्रेवर होंस ने कहा, 'हमें यकीन है कि मार्नस लाबुशाने भारत में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारी वनडे टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा है और टी-20 विश्व कप की तैयारी के लिए यह सीरीज अहम है।' मुख्य कोच जस्टिन लैंगर भारत नहीं जाएंगे। उनकी जगह सहायक कोच मैकडोनाल्ड प्रभारी होंगे।

टीम: आरोन फिंच (कप्तान), सीन एबॉट, एश्टन एगर, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, पीटर हैंड्सकोंब, जोश हेजलवुड, मार्नस लाबुशाने, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, एश्टन टर्नर, डेविड वार्नर, एडम जांपा।

दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं बीमार शिनवारी : पाकिस्तान के बायें हाथ के तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती हैं और श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता मिसबाह उल हक ने मंगलवार को कहा कि उस्मान का इलाज चल रहा है और उसके गुरुवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट में खेलने की संभावना नहीं है। श्रीलंका के तेज गेंदबाज कासुन रजीता भी हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण बाहर हैं।

बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए सिडल को टीम में मिली जगह

सिडनी, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ताओं ने 26 दिसंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए मंगलवार को चुनी गई 13 सदस्यीय टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज पीटर सिडल को शामिल किया है। सिडल को इस साल एशेज सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद बाहर किया गया था। उन्होंने एशेज की तीन टेस्ट मैचों में 42.14 की औसत से सिर्फ सात विकेट लिए थे। कयास लगाए जा रहे थे कि चोटिल जोश हेजलवुड की जगह जेम्स पैटिंसन लेंगे, लेकिन मुख्य चयनकर्ता ट्रेवर होंस ने कहा कि सिडल मेलबर्न क्रिकेट मैदान में टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते है। होंस ने कहा, 'पीटर मेलबर्न में टीम के 13वें खिलाड़ी के तौर पर चुने गए हैं। वह मैच विजेता हैं और उन्हें मेलबर्न मैदान की अच्छी समझ है।'

विविध

गोवा एयरपोर्ट पर रनवे नियंत्रक की सतर्कता से बड़ा हादसा टला

नई दिल्ली, प्रेट्र : गोवा हवाईअड्डे पर मंगलवार की सुबह रनवे नियंत्रक की सतर्कता के कारण बड़ा विमान हादसा टल गया। स्पाइसजेट के विमान की लैंडिंग से ठीक पहले उसके आगे का पहिया (नोज लैंडिंग गियर) खुला हुआ न पाकर रनवे नियंत्रक ने उसे उतरने से रोक दिया। बाद में विमान की एहतियाती लैंडिंग कराई गई। स्पाइसजेट क्यू400 विमान सूरत से गोवा पहुंचा था।

भारतीय नौसेना के प्रवक्ता के अनुसार, 'भारतीय वायुसेना की सतर्क विमान यातायात सेवा ने एक बड़ा हादसा रोक दिया। रनवे नियंत्रक प्रमुख एयरमैन (एयर हैंडलर) रमेश तिग्गा को लैंडिंग करने जा रही स्पाइसजेट की उड़ान एसजी 3568 का अगला पहिया बंद नजर आया था। उन्होंने तुरंत विमान यातायात नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना दी। ड्यूटी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लेफ्टिनेंट कोमोडोर हरमीत कौर ने स्पाइसजेट विमान को लैंडिंग रोक देने को कहा।'

उन्होंने बताया, 'आपात एवं सुरक्षा सेवाओं की सहायता से सुबह 8:05 बजे विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। भारतीय नौसेना विमान यातायात एवं सुरक्षा सेवाओं ने स्पाइसजेट की उड़ान और उसके सभी यात्रियों को गोवा हवाईअड्डे पर एक बड़े हादसे का शिकार होने से बचा लिया।'

उधर, स्पाइसजेट प्रवक्ता ने कहा, 'पायलट को संदेह हो गया था कि नोज लैंडिंग गियर पूरी तरह नहीं खुला है। उसने एटीसी टॉवर को इसकी सचूना दी और उसकी जांच करने का आग्रह किया। जांच के दौरान विमान को कुछ देर के लिए घुमाया गया। एटीसी ने बताया कि नोज लैंडिंग गियर नहीं खुला है।' प्रवक्ता ने बताया कि इस सूचना के बाद मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सभी आपात सेवाएं सक्रिय कर दी गईं और पायलट ने एहतियाती लैंडिंग की। लैंडिंग के समय पाया गया कि नोज गियर खुलकर लॉक हो गया था। इस प्रकार लैंडिंग सामान्य और सुरक्षित रही।

उल्लेखनीय है कि गोवा हवाईअड्डे का संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) करता है। आइएनएस हंस नामक भारतीय नौसेना के इस एयरबेस का इस्तेमाल एक सिविल एंक्लेव की तरह किया जाता है।

गोवा हवाईअड्डे का संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) करता है। (फाइल)

असंसदीय शब्द हटाने की प्रक्रिया की समीक्षा करने पर दिया जोर

राज्य ब्यूरो, देहरादून

लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने कहा कि डिजिटल और सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के विकास को देखते हुए विधायी निकायों की कार्यवाही से असंसदीय अथवा अमर्यादित शब्दों को हटाने की प्रक्रिया की तत्काल समीक्षा की जरूरत है। पीठासीन अधिकारियों के बुधवार से शुरू होने वाले अखिल भारतीय सम्मेलन से एक दिन पहले मंगलवार को विधायी निकायों के सचिवों के सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही।

देहरादून में आयोजित सचिवों के सम्मेलन में लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। 'विधानमंडलों में सभा की कार्यवाही से शब्दों को हटाने की प्रक्रिया की समीक्षा की जरूरत' और 'लोगों तक पहुंचने के लिए विधानमंडलों द्वारा नए उपाय' विषयों पर उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर डिजिटल व सूचना प्रौद्योगिकी का है। ऐसे में इन विषयों की समीक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सदस्यों की क्षमता विकास के लिए सभा के समक्ष विचाराधीन विधेयकों पर संक्षिप्त जानकारी देने को नौ सत्र आयोजित किए गए। एक अन्य पहल के लिए सूचना एवं संचार केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र ने एक माह की अवधि में संसद सदस्यों को 6800 टेलीफोन कॉल की गईं।

राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने कहा कि विधानमंडलों को सरकार और जनता के बीच मजबूत कड़ी के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में अपनी भूमिका की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं के लिए राज्यसभा में कंसल्टेंट इंटरप्रेटर्स को पैनल में रखा गया है। जब और जैसे जरूरत हो, उनकी सेवाओं का लाभ लिया जाता है।

उन्होंने बताया कि राज्यसभा के सभापति के निर्देशानुसार निरर्हता से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान तीन माह में कर दिया जाना चाहिए, ताकि दल परिवर्तन सबंधी कानून का पूरी तरह पालन सुनिश्चित हो सके। सम्मेलन में विधानसभा और विधान परिषदों की कार्यप्रणाली से संबंधित पारस्परिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा के सचिव जगदीश चंद ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। सम्मेलन में लोकसभा, राज्यसभा के अलावा सिक्किम, अरुणाचल, गोवा, बंगाल, नगालैंड, तेलंगाना आदि राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

देहरादून में मंगलवार को विधायी निकायों के सचिवों का सम्मेलन हुआ। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल (दाएं) ने सम्मेलन स्थल में लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव (मध्य) और राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा (बाएं) से मुलाकात की। जागरण

कंगाली में 20 लग्जरी गाड़ियां खरीदेगी पंजाब सरकार

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

- वित्त विभाग के पास पहुंची फाइल, कांग्रेस अपने आठ सांसदों को देगी नई गाड़ियां

पंजाब सरकार भले ही फंड की कमी के कारण मुलाजिमों को समय पर तनख्वाह न दे पा रही हो, लेकिन सांसदों व विधायकों के लिए 20 लग्जरी गाड़ियां खरीदने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए प्रस्ताव वित्त विभाग के पास पहुंच चुका है। विभाग की मुहर लगने के बाद कांग्रेस अपने सांसदों व कुछ विधायकों की पुरानी गाड़ियां बदल देगी।

विधायक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। कुछ विधायकों की गाड़ियां तो चार लाख किलोमीटर तक चल चुकी हैं। विधायक कई बार वित्तमंत्री मनप्रीत बादल के पास अपनी मांग रख चुके है। अभी यह तय नहीं है कि ये गाड़ियां कौन सी होंगी, लेकिन आम तौर पर विधायकों को टोयोटा इनोवा गाड़ियां ही दी जाती हैं, जिनकी कीमत 15 से 23 लाख रुपये के बीच है। पंजाब सरकार की वित्तीय हालत इन दिनों ठीक नहीं है। इस बार कर्मचारियों का वेतन देने का संकट पैदा हो गया था। केंद्र से जीएसटी के 2228 करोड़ मिलने के बाद माना जा रहा है कि अगले माह वेतन समय पर जारी होगा।

रिपेयर के लिए हर साल 55 हजार की लिमिट : वित्त विभाग ने विधायकों की गाड़ियों की रिपेयर के लिए लिमिट फिक्स कर दी है। एक विधायक को गाड़ी रिपेयर के लिए साल में 55 हजार रुपये मिलते हैं। इसमें रिपेयर के साथ-साथ टायर बदलना भी शामिल है। वहीं, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसका खर्च विधायक को अपनी जेब से देना होता है। सरकारी गाड़ियां का इंश्योरेंस नहीं होता। ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट होने की सूरत में तय सीमा 55 हजार रुपये में ही गाड़ी की रिपेयर करवानी होती है।

सरकारी गाड़ी से दिल्ली नहीं जा पा रहे कुछ विधायक

दिल्ली सरकार ने 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी है, जबकि पंजाब के लगभग सभी विधायकों की गाड़ियां 10 साल की अवधि पूरी कर चुकी हैं। इस वजह से विधायक सरकारी गाड़ी से दिल्ली नहीं जा सकते। पिछले दिनों कुछ विधायक दिल्ली बॉर्डर तक तो सरकारी गाड़ी पर ही गए, लेकिन वहां से आगे उन्होंने टैक्सी से यात्रा की। दस साल से पुरानी गाड़ियों का अगर दिल्ली पुलिस चालान कर देती, तो पंजाब सरकार की खासी फजीहत होती।

गाड़ी खरीदने में सांसदों को मिलेगी तरजीह

पंजाब सरकार 20 गाड़ियां खरीदने जा रही है। इनमें से आठ गाड़ियां कांग्रेस सांसदों को दी जाएंगी। बाकी की गाड़ियां 'दबदबा' वाले विधायकों को दी जाएंगी।

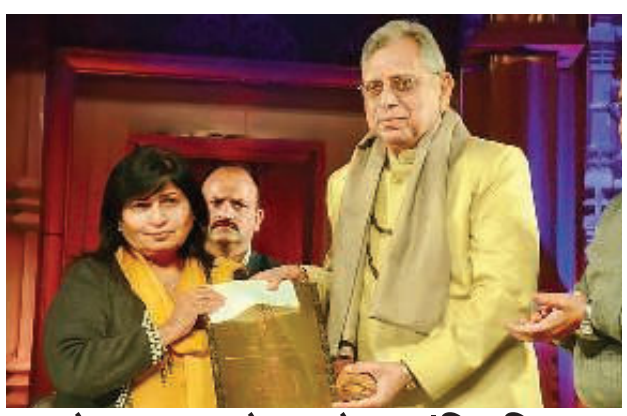

तानसेन सम्मान से नवाजे गए पंडित विद्याधर

ग्वालियर के हजीरा स्थित मोहम्मद गौस मकबरा परिसर में शाम पांच दिवसीय अखिल भारतीय तानसेन समारोह शुरू हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ ने ख्यात शास्त्रीय गायक पंडित विद्याधर व्यास को वर्ष 2019 के राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण से नवाजा।विजयलक्ष्मी साधौ। नईदुनिया

ट्रेन से कटकर महिला व उनकी दो बेटियों की मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : शिवाजी ब्रिज के पास मंगलवार शाम सिरसा की तरफ जाने वाली ट्रेन की चपेट में आकर पांच लोग घायल हो गए। पांचों को उपचार के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक महिला और उनकी दो बेटियों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक अन्य महिला व उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल है।

डीसीपी रेलवे हरेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक मरने वाली महिला का नाम अल्का देवी (36) व उनकी दो बेटियां लवली (13) व प्रिया (8) है। घायल महिला का नाम शांति देवी (38) व उनकी बेटी का नाम नीतू (8) है। पांचों मूलरूप से बिहार के बांका जिले के रहने वाले हैं। घटना शाम 6.20 की है। घायलों का राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है।

कपूरथला में वॉशिंग मशीन में डाल कर ढाई साल के बच्चे की हत्या

जागरण संवाददाता, कपूरथला

पंजाब के कपूरथला के थाना कोतवाली के तहत गांव खुखरैन में राज नाम की महिला ने वॉशिंग मशीन में डालकर पड़ोसी के ढाई साल के बच्चे अधिराज सिंह को मार डाला। आरोपित महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बच्चे की मां सुनीता रानी के बयान पर आरोपित महिला पर केस दर्ज कर लिया गया है।

गांव फरीद सराय की सुनीता रानी भाई गगनदीप की शादी के लिए एक हफ्ते पहले दोनों बेटों को लेकर गांव खुखरैन आई थी। 21 दिसंबर को घर पर शादी है। मंगलवार दोपहर को अधिराज अपने बड़े भाई और पड़ोस में रहने वाली सात साल की बच्ची के साथ खेल रहा था। बच्चे खेलते-खेलते सामने वाले घर में चले गए। कुछ देर बाद बड़ा भाई और बच्ची वापस आ गए, लेकिन अधिराज नहीं आया। तीन बजे परिवार ने बच्चे की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि तीनों बच्चे सामने वाले घर में गए थे। वारदात के वक्त उस घर में सिर्फ महिला राज मौजूद थी। पुलिस ने दो बार घर की तलाशी ली, लेकिन बच्चा नहीं मिला। तलाशी के दौरान आरोपित महिला वॉशिंग मशीन पर कोहनी रखकर खड़ी हो जाती थी। शाम करीब पांच बजे आरोपित को वॉशिंग मशीन से हटाकर तीसरी तलाशी ली तो उसमें बच्चे का शव मिला।

मौसम विशेष

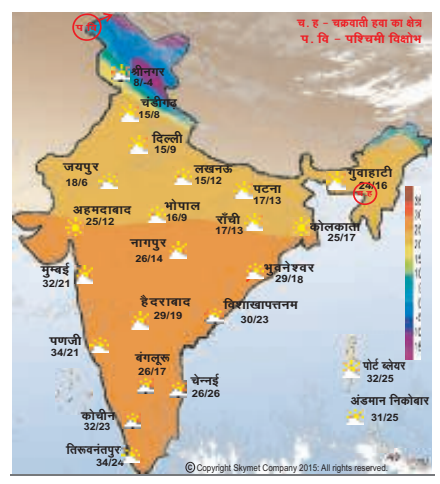

पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाओं के साथ ठंडी सुबह में घना कोहरा छाया रहेगा। दोपहर में कुछ समय के लिए धूप संभव है। दिन ठंडा बना रहेगा। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में सुबह ठिठुरन भरी रहेगी। रात में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा संभव है।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	32/21/व	अहमदाबाद	30/13/व
कोलकाता	25/15/आंबा	बड़ौदा	31/18/आंबा
चेन्नई	30/24/व	नागपुर	25/13/आंबा
हैदराबाद	29/18/आंबा	इन्दौर	29/15/आंबा
बंगलूरू	27/18/आंबा	रांची	28/16/आंबा
त्रिवेन्द्रम	34/24/आंबा	पटना	27/16/आंबा
गुवाहाटी	24/16/आंबा	जमशेदपुर	28/14/आंबा
गंगटोक	08/-3/आंबा	पुणे	31/20/आंबा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 18 दिसंबर 2019
आजकल
16
www.jagran.com

दुनिया का पहला कम्युनिकेशन सेटेलाइट लांच किया गया

1958 में आज ही लांच हुए इस अमेरिकी सेटेलाइट का नाम स्कोर था। अंतरिक्ष में यह सेटेलाइट 35 दिनों तक काम करता रहा। इस पूरे प्रोजेक्ट के जरिये धरती से सेटेलाइट तक सिग्नल भेजना और वहां से सिग्नल को वापस धरती पर भेजना संभव हुआ था।

मुंबई के मरीन ड्राइव का निर्माण शुरू हुआ

1915 में आज ही अरब सागर के किनारे 3 .6 किमी लंबी सड़क मरीन ड्राइव का निर्माण शुरू हुआ था। आधिकारिक तौर पर इसे नेताजी सुभाषचंद्र बोस रोड के नाम से जाना जाता है। मरीन ड्राइव 1920 में बनकर तैयार हुआ था।

विश्व प्रसिद्ध निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग को जन्मदिन मुबारक हो

1946 में आज ही अमेरिका में विश्व प्रसिद्ध हॉलीवुड निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग का जन्म हुआ था। स्टीवन को अपनी फिल्मों के लिए दो बार ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। उनकी तीन फिल्मों जॉज, ईटी और जुरासिक पार्क ने अपने समय में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया था। उनकी कुछ फिल्में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी शामिल हैं। यही नहीं वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्म निर्देशक हैं। उनकी कुल संपत्ति तीन अरब डॉलर से अधिक है। अवतार, शिंडलर्स लिस्ट, म्यूनिच उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में हैं।

इधर-उधर की

पैर में बैंडेज बांधकर ट्रैक पर दौड़ी, जीता गोल्ड मेडल

मनीला,एजेंसी : फिलीपींस की 11 साल की एथलीट की कामयाबी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसने बिना जूते के पैरों में बैंडेज बांधकर गोल्ड मेडल जीता है। दरअसल, इलोइलो प्रांत के स्थानीय स्कूल में इंटर स्कूल एथलीट्स मीट का आयोजन किया गया। इसमें 11 साल की रिया बुलोस ने बिना जूतों के स्कूल की 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर की रेस में हिस्सा लिया। तीनों कैटेगरी में उसने गोल्ड मेडल जीत सबको हैरान कर दिया। रिया की इस सफलता को इलोइलो स्पोर्ट्स काउंसिल मीट के कोच प्रेडीरिक बी वैलेनजुएला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। पोस्ट में रिया ने जूतें नहीं पहने हैं। वह जूतों की जगह पैरों में बैंडेज बांधे दिख रही हैं। कोच के मुताबिक, उसके पास जूते नहीं थे। बैंडेज पर नाइकी लिख लिया था।

शोध अनुसंधान

नींद की गड़बड़ी से माइग्रेन का खतरा

पर्याप्त नींद से ना सिर्फ तन और मन स्वस्थ रहता है बल्कि सेहत से जुड़ी कई समस्याओं से बचाव भी हो सकता है। अब एक नए अध्ययन में पाया गया है कि नींद की गड़बड़ी से माइग्रेन का खतरा हो सकता है। माइग्रेन में सिर के एक हिस्से में तेज दर्द होता है। इसकी तीव्रता घटती और बढ़ती रहती है। अमेरिका के ब्रिघम एंड वूमेंस अस्पताल के शोधकर्ताओं ने अध्ययन में पाया कि माइग्रेन से पीड़ित करीब आधे रोगियों ने नींद की गड़बड़ी की बात कही। यह निष्कर्ष 98 वयस्कों पर किए गए एक अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। यह अध्ययन नींद और माइग्रेन सिरदर्द के बीच संबंध का पता लगाने के लिए किया गया था। अध्ययन की प्रमुख शोधकर्ता सुजैन बर्टिस्क ने कहा, 'हमने नींद के संबंध में जब कुछ खास पहलुओं पर गौर किया तो निम्न नींद का ताल्लुक माइग्रेन से पाया।' -आइएएनएस

पौष्टिक आहार कैंसर रोगियों के लिए मददगार

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि सिर और गले के कैंसर से पीड़ित रोगियों के लिए पौष्टिक आहार मददगार हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट और दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर आहार के सेवन से ऐसे रोगियों में भूख नहीं लगने के बढ़ते खतरे को कम किया जा सकता है। अमेरिका की इलिनोइस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार, सिर और गले के कैंसर की पहचान होने के महज एक साल के अंदर करीब 90 फीसद रोगियों में खाने की इच्छा खत्म होने के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसा ट्यूमर या उपचार के दौरान सर्जरी या रेडिएशन के कारण हो सकता है। यह निष्कर्ष 336 रोगियों पर किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि रेडिएशन उपचार और कीमोथेरेपी का इस तरह का दुष्प्रभाव आम बात है। -प्रेट्र

जलवायु परिवर्तन के कारण पक्षियों के प्रवास में आई तेजी

- अमेरिका की मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने किया दावा
- कहा- बसंत के मौसम में भी घट गई है प्रवासी पक्षियों की संख्या

यह अध्ययन जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के प्रति आगाह करने वाले एक अध्ययन में कहा गया है कि 20 साल पहले की तुलना में जलवायु परिवर्तन के कारण बसंत के मौसम में अब पक्षियों का प्रवास तेजी से बढ़ रहा है और वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक निश्चित मार्ग से होकर गुजरते हैं।

अमेरिका की मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा कि वायुमंडलीय तापमान और प्रवासन का समय निकटता से एक-दूसरे से जुड़ा रहता है, जो इलाके सबसे ज्यादा वार्मिंग के शिकार हैं, वहां से पक्षियों का प्रवास सबसे ज्यादा और तेजी से हो रहा है। उन्होंने रात में घूमने वाले पक्षियों के प्रवासन का अध्ययन करने के लिए यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) के 24 साल के रडार डाटा का विश्लेषण किया।

नेचर क्लाइमेट चेंज नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है कि बसंत के मौसम में भी प्रवासी पक्षियों की संख्या में भारी गिरावट आ गई है।

जैव-विविधता को होगा नुकसान: अमेरिका में कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी (सीएसयू) के शोधकर्ता और इस अध्ययन के सह-लेखक काइल हॉर्टन ने कहा, 'यदि हम पूरे महाद्वीप की बात करें तो पक्षियों के प्रवास के समय में बदलाव बाहरी तौर पर अच्छा हो सकता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले इस बदलाव से दीर्घकाल में जैव-विविधता के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। हॉर्टन ने कहा कि पक्षियों के प्रवास के समय में बदलाव का मतलब केवल यह नहीं है कि प्रवासी जलवायु परिवर्तन के साथ तालमेल बिठा रहे हैं।

आबादी पर पड़ रहा प्रभाव : कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के शोधार्थी और इस अध्ययन के वरिष्ठ लेखक एंड्रयू फ्रांसवर्थ ने कहा कि पक्षी का प्रवास बड़े पैमाने पर बदलती जलवायु की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि यह एक वैश्विक घटना है जिसमें प्रतिवर्ष अरबों पक्षी शामिल होते हैं और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पक्षियों की चाल जलवायु परिवर्तन को ट्रैक करती है। लेकिन जलवायु में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण पक्षियों की आबादी में भी सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है।

प्रभावी कदम उठाने की जरूरत : फ्रांसवर्थ ने कहा ने कहा, 'यदि जलवायु परिवर्तन इसी गति से जारी रहा तो हो सकता है कि भविष्य में कई पक्षी विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएं या विलुप्त हो जाएं क्योंकि हर प्राणी एक सीमा तक ही हमारे वातावरण में होने वाले बदलावों का सह सकता है और उसके अनुकूल खुद को ढाल सकता है। इसलिए यदि हमें जैव विविधता को बनाए रखना है तो ग्लोबल वॉर्मिंग को बढ़ने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे।

ऑस्कर अवार्ड की दौड़ से बाहर हुई फिल्म गली ब्वॉय

- 92वें एकेडमी अवार्ड के लिए नौ श्रेणी में चयनित टॉप-10 फिल्मों की सूची जारी
- फिल्म गली ब्वॉय में रणवीर सिंह ने निभाई थी स्ट्रीट रैपर की भूमिका

13 जनवरी 2020 को की जाएगी एकेडमी अवार्ड्स की घोषणा। फाइल

लॉस एंजिलिस, प्रेट्र : ऑस्कर के 92वें एकेडमी अवार्ड की सभी नौ श्रेणियों में चयनित टॉप-10 फिल्मों की सूची जारी कर दी गई है। बॉलीवुड निर्देशक जोया अख्तर की फिल्म 'गली ब्वॉय' इनमें जगह नहीं बना सकी। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में नामित इस फिल्म में अभिनेता रणवीर सिंह ने स्ट्रीट रैपर की भूमिका निभाई है। एकेडमी अवार्ड्स की घोषणा 13 जनवरी 2020 को की जाएगी, जबकि ऑस्कर समारोह का आयोजन नौ फरवरी को हॉलीवुड में किया जाएगा।

बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की श्रेणी में अब तक सिर्फ तीन बार ही भारतीय फिल्में टॉप-5 में जगह बना सकी हैं। 'लगान' (2001) आखिरी भारतीय फिल्म थी जो टॉप-5 में जगह बना पाई थी। इससे पहले 'मदर इंडिया' (1958) व 'सलाम बॉम्बे' (1989) को भी टॉप-5 में जगह मिल पाई थी। इस श्रेणी के लिए 91 फिल्में चुनी गई थीं। टॉप-10 में जो फिल्में जगह बना पाईं, उनमें पैरासाइट (दक्षिण कोरिया), पेन एंड ग्लोरी (स्पेन), द पेंटेड बर्ड (चेक गणराज्य), ट्रूथ एंड जस्टिस (एस्टोनिया), लेस मिजरेबल (फ्रांस), डोज हू रीमेंड (हंगरी), हनीलैंड (नॉर्थ मेसेडोनिया), कॉर्प्स क्रिस्टी (पोलैंड), बेनपोल (रूस) व अटलांटिका (सेनेगल) शामिल हैं।

सभी शाखाओं के एकेडमी सदस्यों को नॉमिनेशन राउंड में प्रतिभागियों के चयन के लिए आमंत्रित किया गया है। उनसे कहा गया है कि वे अपना मत रखने से पहले टॉप-10 की सभी फिल्मों को जरूर देखें।

इंटरनेशनल फीचर फिल्म के साथ-साथ एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस अवार्ड क शीर्ष-15 फिल्मों की भी सूची जारी की गई है। इसके अलावा म्यूजिक (ओरिजनल स्कोर), म्यूजिक (ओरिजनल सांग), विजुअल एफेक्ट, डॉक्यूमेंट्री फीचर, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट, मेकअप एंड हेयरस्टाइल, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म और लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी की भी सूची जारी की गई है।

वसा कोशिकाओं से बनाया 'पेसमेकर'

तकनीक ▶ ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने खोजी उपचार की नई विधि

विद्युत आवेग के जरिये हृदय की गति को करेगा नियंत्रित

प्रतीकात्मक

ह्यूस्टन, प्रेट्र : शोधकर्ताओं ने मानव शरीर की वसा कोशिकाओं को फिर से प्रोग्राम करके उसे हृदय के पेसमेकर सेल की तरह बनाया है, जो लयबद्ध इलेक्ट्रिक इंपल्स (विद्युत आवेग) के जरिये हृदय की गति को नियंत्रित कर सकता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस तरह से हृदय के उपचार की एक नई विधि का पता चला है। शोध करने वाली टीम में एक भारतीय मूल की शोधकर्ता भी शामिल हैं। 'मॉलीक्युलर एंड सेलुलर कार्डियोलॉजी' में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि नई पेसमेकर जैसी कोशिका हृदय अनियंत्रित रहने की बीमारी की एक वैकल्पिक उपचार बन सकती है और कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक पेसमेकर प्रत्यारोपण जैसे वर्तमान उपचारों की सीमाओं को और विस्तार दे सकती है।

हर साल प्रत्यारोपित होते हैं एक लाख पेसमेकर: जर्नल ऑफ जेरिएट्रिक कार्डियोलॉजी में प्रकाशित हुए एक अन्य अध्ययन के अनुसार, प्रत्येक वर्ष वैश्विक रूप से एक लाख से अधिक कृत्रिम पेसमेकर रोगियों में प्रत्यारोपित किए जाते हैं। इस डिवाइस को छाती में फिट किया जाता है। यह विद्युत आवेग के जरिये हार्ट बीट को सामान्य बनाए रखता है। हालांकि, समय-समय पर चिकित्सकों द्वारा इस डिवाइस की जांच जरूरी होती है क्योंकि ऐसी आशंका रहती है कि एक समय के बाद यह काम करना बंद कर सकती है।

करंट प्रवाहित कर सकती है कोशिका : वर्तमान अध्ययन में अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी की भारतीय मूल की शोधकर्ता सुचि रघुनाथन ने अन्य शोधार्थियों के साथ मिलकर स्टेम कोशिकाओं को हृदय की कोशिकाओं में बदल दिया। ये कोशिकाएं विद्युत प्रवाह (इलेक्ट्रिक करंट) का संचालन भी कर सकती हैं। इससे पहले एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मानव शरीर की वसा कोशिकाओं में रहने वाले स्टेम कोशिकाओं को कार्डियक प्रोजेनिटर सेल्स में बदला था। वर्तमान अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया कि कार्डियक प्रोजेनिटर सेल्स को फिर से प्रोग्राम कर दिल की धड़कन बनाए रखी जा सकती है।

धड़कन को नियमित करता है पेसमेकर: हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह करता है। रक्त की पंपिंग के दौरान ही हमारा दिल भी धड़कता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी बीमारी के कारण दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। दिल अगर ठीक तरह से न धड़के तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। धड़कन की इसी अनियमितता को ठीक करने के लिए एक छोटी-सी डिवाइस लगाई जाती है, जिसे पेसमेकर कहते हैं। इसे रीचार्ज करने के लिए इसकी बैट्री को एक निश्चित समय पर बदलना पड़ता है।

प्राकृतिक नोड जैसी ही होती है इसकी कार्यप्रणाली

शोधकर्ताओं ने कहा, 'इसकी कार्यप्रणाली हृदय की प्राकृतिक नोड कोशिकाओं के समान ही है, जिसे सिनोट्रियल नोड (सैन) कहा जाता है। यह इलेक्ट्रिक कार्डियक कंडक्शन सिस्टम (सीसीएस) का ही एक हिस्सा है।' वैज्ञानिकों ने कहा, 'सैन हृदय का प्राथमिक पेसमेकर है, जो विद्युत आवेग या धड़कन पैदा कर सकता है।' अध्ययन में बताया गया है कि हृदय से जुड़ी कार्डियक पेसमेकर कोशिकाएं सैन के भीतर ही मौजूद होती है। यह एक छोटी-सी संरचना होती है, जिसमें कुछ हजार विशेष पेसमेकर कोशिकाएं शामिल हैं। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि सैन में कोई कमी या खराबी आने पर दिल की धड़कनें अनियमित हो जाती हैं।

'सही नहीं है पहली महिला डॉक्टर की थ्योरी'

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : एक अमेरिकी वैज्ञानिक का दावा है कि दुनिया की पहली महिला फिजिशियन कही जाने वालीं मेरिट पीटह कभी अस्तित्व में नहीं थीं। गौरतलब है कि मेरिट को महिलाओं के चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रेरणा के रूप में एक रोल मॉडल के तौर पर याद किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलराडो के शोधकर्ता जैकब क्वीसिंस्की ने कहा है कि मेरिट की कहानी गलत पहचान का मामला है। एक जासूस की तरह मुझे उनकी कहानी की पड़ताल करनी पड़ी। मैंने हर सिरा खंगाला ताकि पता चल सके कि मेरिट की शुरुआत कैसे हुई और किसने उनके बारे में सबसे पहले बताया। जैकब के मुताबिक उन्हें मेरिट का नाम हर जगह मिला-यहां तक कि शुक्र के एक क्रेटर का नाम भी उन पर है, लेकिन जल्द ही मुझे पता चल गया कि इसका कोई सुबूत नहीं है कि मेरिट का वास्तव में कोई अस्तित्व था। चिकित्सा के इतिहास का अध्ययन करने वाले जैकब का शोध हिस्ट्री आफ मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित हुआ है। जैकब ने शोध में लिखा है कि इसका कोई रिकार्ड नहीं है कि इस नाम का कोई फिजिशियन कभी था। पुरानी राजशाही में उनका नाम जरूर मिलता है, लेकिन मिस्र के प्राचीन चिकित्सकों की किसी सूची में उनका नाम नहीं है। एक अन्य नाम चिकित्सक पेसेसेट का मिलता है जिन्हें भ्रमवश मेरिट पीटह समझ लिया गया।

कर्तव्य के प्रति अनूठा समर्पण

फिलीपींस में डॉक्टरों ने अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। मंगलवार को क्वेजॉन सिटी स्थित नेशनल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आग लग गई। इस दौरान डॉक्टर क्रिसमस पार्टी में व्यस्त थे। लेकिन डॉक्टरों को जैसे ही आग की सूचना मिली, सभी उसी हाल में तत्काल पार्टी छोड़ मौके पर पहुंचकर अग्निशमनकर्मियों के साथ मरीजों की मदद में जुट गए। मरीजों की मदद के दौरान एक चिकित्सक (पार्टी कॉस्ट्यूम में)। फिलहाल आग में कोई हताहत नहीं हुआ है और आग के कारणों की जांच की जा रही है। एपी

उत्तर कोरिया ने दिवंगत नेताओं को किया याद

उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में मंगलवार को लोगों ने किम जोंग इल की आठवीं पुण्यतिथि के मौके पर अपने दिवंगत नेताओं, किम इल सुंग और किम जोंग इल को याद किया और उनकी प्रतिमाओं के समक्ष पुष्प चढ़ाए। किम इल सुंग किम जोंग इल के पिता थे और उत्तर कोरिया पहले शासक थे। इनके बाद किम जोंग इल ने देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। इस समय किम जोंग इल के सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता हैं। एपी

स्क्रीन शॉट

अमिताभ ने रजनीकांत को दी थी राजनीति में न आने की सलाह

ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, सुपरस्टार रजनीकांत, महानायक अमिताभ बच्चन को अपनी प्रेरणा मानते हैं। फिल्म 'गिरफ्तार', 'अंधा कानून' और 'हम' में दोनों साथ नजर आए थे। अब फिल्म 'दरबार' में रजनीकांत करीब 25 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर पुलिस कमिश्नर की भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म अगले साल 10 जनवरी को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी।

सोमवार को मुंबई में 'दरबार' के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अमिताभ के साथ कुछ खास यादों को साझा करने के सवाल पर रजनीकांत ने बताया कि हाल में चेन्नई में दोनों की मुलाकात हुई थी। अमिताभ उन्हें बहुत प्यार करते हैं। साठ की उम्र पार होने के बाद उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत बताई थी। उन्होंने तीन सलाह दी थी। पहली, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। दूसरा, खुद को व्यस्त रखें। लोगों की बातों की परवाह किए बगैर जो करना चाहते हैं, वह करें। घर पर न बैठें और तीसरी सलाह थी कि राजनीति में न जाऊं। पहली दोनों सलाह तो मैं फॉलो कर रहा हूं। लेकिन तीसरी सलाह पर अमल नहीं कर पाया। परिस्थितिवश राजनीति में आना पड़ा। बहरहाल, लोग कहते हैं कि मैं कॉमेडी, एक्शन बहुत अच्छा करता हूं। सही मायने में मैंने यह अमिताभ बच्चन से सीखा है। हिंदी समेत क्षेत्रीय भाषाओं की 160 फिल्मों में काम कर चुके रजनीकांत ने ट्रांसजेंडर का किरदार निभाने की ख्वाहिश जताई है। उनका कहना है कि वह अपने 45 साल के करियर में हर प्रकार की भूमिका निभा चुके हैं, सिर्फ ट्रांसजेंडर नहीं निभाया है।

रिंग में लड़ने के लिए पसीना बहा रहे फरहान अख्तर

राकेश ओम प्रकाश मेहरा निर्देशित फिल्म 'तूफान' में फरहान अख्तर मुक्केबाज की भूमिका निभा रहे हैं। खुद को पर्दे पर एक पेशेवर मुक्केबाज दिखाने के लिए फरहान खूब पसीना बहा रहे हैं। इसके लिए वह अमेरिकी ट्रेनर डोरेल फॉस्टर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। डोरेल ने इससे पहले साल 2001 में मुक्केबाज मुहम्मद अली की बॉयोग्राफिकल फिल्म 'अली' में अभिनेता विल स्मिथ को मुक्केबाजी की ट्रेनिंग दी थी। डोरेल के अनुसार, उन्होंने फरहान को एक मुक्केबाज की तरह प्रशिक्षित किया है। किसी एक्टर को एक नवोदित खिलाड़ी की तरह सिखाना, पर्दे पर मुक्केबाजी को वास्तविकता में दिखाने का सबसे सरल तरीका है। उन्हें यकीन है कि शूटिंग पूरी होने के बाद फरहान एक पेशेवर बॉक्सर की तरह रिंग में लड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि फरहान की अभिनेता वाली मानसिकता को खिलाड़ी वाली मानसिकता में बदलना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। डोरेल के मुताबिक, टीवी पर मुक्केबाजी देखने और वास्तविकता में रिंग में खड़े होकर लड़ने में बहुत अंतर है। क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों को पर्दे पर आसानी से दिखा सकते हैं, लेकिन बॉक्सिंग की वास्तविकता को दिखाने के लिए इसकी बारीकी और तकनीकों को जानना बहुत जरूरी है। 'तूफान' में फरहान का मुकाबला दुनिया के कुछ पेशेवर मुक्केबाजों के साथ होगा। इसके लिए फरहान को हर चीज को एक मुक्केबाज की तरह महसूस करना जरूरी था। डोरेल ने फरहान को एक पेशेवर की तरह रिंग में पंच मारना सिखाया है।

वेब सीरीज में हंसल मेहता बताएंगे हर्षद मेहता की कहानी

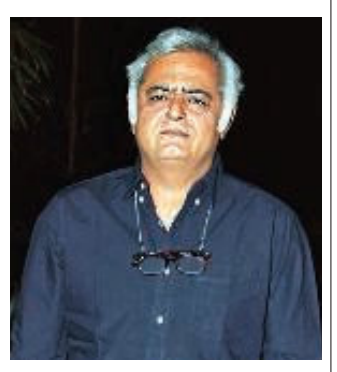

डिजिटल प्लेटफार्म पर अलहदा कंटेंट लाने की होड़ मची है। इस कड़ी में देश की पहली फाइनेंशियल ड्रामा थ्रिलर सीरीज का निर्माण किया जा रहा है। यह सीरीज 1992 में बंबई शेयर बाजार और अन्य वित्तीय घोटालों पर आधारित होगी, जिसे शेयर दलाल हर्षद मेहता ने अंजाम दिया था। पत्रकार सुचेता दलाल ने इस सबसे बड़े शेयर घोटाले का पर्दाफाश किया था। बाद में उन्होंने और देबाशीष बासु ने इस घोटोल पर 'द स्कैम' नामक किताब लिखी थी। इस किताब पर आधारित फाइनेंशियल थ्रिलर 'स्कैम 1992 : द हर्षद मेहता स्टोरी' का निर्माण आदित्य बिड़ला समूह के कंटेंट स्टूडियो अप्लॉज एंटरटेनमेंट द्वारा किया जा रहा है। सीरीज का निर्देशन 'शाहिद' और 'अलीगढ़' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हंसल मेहता कर रहे हैं। इसमें जाने-माने नाट्यकर्मी एवं फिल्म अभिनेता प्रतीक गांधी शेयर दलाल हर्षद मेहता की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वेब शो 'द फैमिली मैन' और 'द रीयूनियन' को लेकर चर्चा में रहीं श्रेया धनवंतरी इस सीरीज में तेज तर्रार और निडर पत्रकार सुचेता दलाल की भूमिका निभाएंगी। वर्ष 1980-90 के दौरान हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह था, जिसने स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल डाली थी। उसने बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर, बैंकिंग लेनदेन में गोलमाल किया था। सीरीज में सतीश कौशिक, अनंत महादेवन, रजत कपूर, निखिल द्विवेदी, केके रैना जैसे कलाकार भी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। हंसल मेहता के मुताबिक, हर्षद मेहता को हम सभी ने एक अद्भुत और अतिशयोक्तिपूर्ण पात्र के रूप में जाना है। मुझे खुशी है कि मैं उसकी कहानी बता पा रहा हूं। हमारी शूटिंग खत्म होने के करीब है। वहीं, इस रोमांचक सीरीज के साथ जुड़कर प्रतीक गांधी भी काफीउत्साहित हैं।

थमेगा दुष्प्रचार

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वाटरलू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया सिस्टम

फर्जी खबरों पर लगाम लगाएगा नया उपकरण

टोरंटो, आइएएनएस : सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली फेक न्यूज यानी फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से लैस एक नया उपकरण तैयार किया है, जो समाचार माध्यमों (टीवी, अखबार, सोशल मीडिया आदि) की खबरों को देखकर यह पता लगा सकता है कि खबर के तथ्य सही हैं या गलत। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस उपकरण का प्रयोग मीडिया संस्थानों में खबरों को तथ्यात्मक रूप से दुरुस्त करने के लिए भी किया जा सकता है।

यह उपकरण कनाडा में वाटरलू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है, जो डीप-लर्निंग एआइ एग्लोरिदम की मदद से खबरों की सत्यता की जांच करता है। वाटरलू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इस अध्ययन के शोधकर्ता अलेक्जेंडर वोंग ने कहा, 'यदि खबर या कहानी लिखने वाला तटस्थ है तो इस बात की संभावना कम करती है कि वह फेक हो। लेकिन कई बार लेखक अपने तथ्यों पर ध्यान नहीं दे पाता और खबर या कहानी को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए भेज देता है। ऐसे में नया उपकरण एक द्वारपाल की भूमिका निभा सकता है। इसमें ऐसी क्षमता है कि यह खबर को पढ़ने के बाद उसकी सत्यता का अनुमान लगा सकता है और तथ्यात्मक रूप से पुख्ता न पाए जाने पर उसे आगे बढ़ने से रोक देता है।' यह अध्ययन कनाडा में आयोजित 'कांफ्रेंस ऑन न्यूरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स' में प्रस्तुत किया गया। शोधकर्ताओं ने कहा कि इस उपकरण को बनाने का उद्देश्य ऐसे ऑनलाइन पोस्ट और समाचारों के प्रसार को रोकना है जो पाठकों को धोखा देने या भ्रमित करने के लिए गढ़े जाते हैं। आमतौर पर राजनीतिक या आर्थिक लाभ के लिए लोग फर्जी खबरों का सहारा लेते हैं।

प्रतीकात्मक

स्वचालित है नया सिस्टम : शोधकर्ताओं ने कहा, 'नया एआइ सिस्टम पूरी तरह स्वचालित है और 90 फीसद झूठी खबरों की आसानी से पहचान कर सकता है।' उन्होंने कहा कि कई बार एक ही खबर अलग-अलग समाचार माध्यमों में अलग-अलग आकड़ों के साथ प्रकाशित और प्रसारित की होती है तो यह तय करना मुश्किल होता है कि कौन-सी खबर के आकड़े सही हैं। ऐसे में नया उपकरण एक बैंचमार्क तय करने वाला हो सकता है।

पॉलिसी में बदलाव से भी मिलता है लाभ : सोशल मीडिया के दौर में कोई भी खबर तेजी से वायरल हो जाती है। उस खबर की सच्चाई जाने बिना उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैलाया जाता है, जिसकी वजह से कई बार हिंसक झड़पों की खबरें भी सामने आती हैं। हालांकि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी खबरें न फैलें इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लगातार अपनी पॉलिसी में बदलाव करते रहते हैं। अब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में नए उपकरणों के जरिये भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही फर्जी खबरों पर लगाम लगाया जा सकेगा।